हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

तालिबानी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के मायने

अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमरीका लगातार पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है और भारत के साथ उसके रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं। विदेश मंत्री जयशंकर के आमंत्रण पर मुत्ताकी अपनी आठ दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। इस यात्रा को इस बात का संकेत समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को फिर से स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और भारत भी अपनी दक्षिण-एशियाई कूटनीति के लिए उसे आगे बढ़ाने की मंशा रखता है।

हालांकि, भारत ने अभी तक तालिबानी शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। भारत सरकार ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पुनर्स्थापित जरूर किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य मानवीय सहायता, व्यापार प्रबंधन और अफगान नागरिकों की सहायता करना है। तालिबानी शासन में अफगानी नागरिकों के अधिकारों की बहाली से संबंधित चिंताओं के बीच मुत्ताकी की इस यात्रा को भारत के लिए चुनौती और अवसर दोनों रूप में देखा जा रहा है। मुत्ताकी की यात्रा का महत्त्व न केवल द्विपक्षीय वार्ताओं तक सीमित है, बल्कि यह दक्षिण एशियाई कूटनीति के परिदृश्य में भारत की प्राथमिकताएं, उसकी प्रतिक्रिया और सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के लिए भी अहम है। इसी क्रम में भारत ने पहली बार बगराम एयरबेस पर अमरीकी दावे के खिलाफ पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ खड़े होने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हालांकि यह भी सच है कि अफगानिस्तान को राजनीतिक मान्यता देने में भारत सरकार को दिक्कत होगी क्योंकि तालिबान ने बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल की थी। लेकिन, दूसरा सच यह भी है कि भारत-अफगानिस्तान के नागरिक संबंध हमेशा से बेहतर रहे हैं। शासन किसी का भी रहे वहां के नागरिक भारत को हमेशा अपना दोस्त समझते रहे हैं। इससे दक्षिण एशिया में भारत को भू-राजनीतिक मजबूत रखने में मदद मिलती रही है। भारतीय कूटनीतिक समीकरणों में अफगानिस्तान की हमेशा खास भूमिका रही है। जबकि हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं।

मुत्ताकी की यात्रा के दौरान भारत अफगानी प्राकृतिक संसाधन, खनिज क्षेत्र, कृषि एवं फल उद्योग, भारत-अफगान ट्रांजिट मार्गों, विशेषकर चाबहार बंदरगाह में अपने लिए संभावनाएं तलाशना चाहेगा। अमरीका ने चाबहार बंदरगाह को दी गई छूट को पिछले दिनों समाप्त कर दिया है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान की कोशिश भारत से राजनीतिक मान्यता प्राप्त करने की होगी। भारत में बसे अफगान नागरिकों, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी मदद, वीजा नीतियों आदि पर भी चर्चा संभव है। अफगानिस्तान को राजनीतिक मान्यता देने से पूर्व भारत अपने प्रभाव से अफगान नागरिक अधिकारों की बहाली का रास्ता खोल सके तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।

समसामयिक: पिछले कुछ चुनावों से महिलाएं पुरुषों के मुकाबले मतदान में ले रही हैं बढ़-चढ़कर हिस्सा

बिहार चुनाव : महिला और युवा वोटर्स पर दारोमदार

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
@patrika.com

> महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी। आलोचनाओं के बावजूद अगर नीतीश इस योजना को जारी रखे हुए हैं तो इसका मतलब यह भी है कि उनका महिला वोटरों पर भरोसा तेजस्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है।

क्या एक बार फिर महिला मतदाताओं का रुख ही बिहार की अगली सियासी तस्वीर का फैसला करने जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा यहां भी दोहराया जाना है? अतीत के अनुभव और सत्ताधारी गठबंधन के दांव तो उसी ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे इसमें युवाओं, विशेषकर पहली बार वोटर बने नौजवानों की भी अहम भूमिका रहने जा रही है। हालांकि मतदाताओं के रुख की हकीकत 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही सामने आ पाएगी।

बिहार के चुनाव में महिलाओं और युवाओं के महत्त्व का अंदाजा दोनों प्रमुख गठबंधनों को है। सत्ताधारी गठबंधन ने महिलाओं को लुभाने में बाजी मार ली है। राज्य में करीब साढ़े तीन करोड़ महिला वोटर हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य के महिला मतदाताओं के करीब 22 फीसद को दस-दस हजार रुपए की रकम दी जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ 21 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा दिया जाना है। बेशक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष शासित राज्यों में ऐसी ही सहयोग देने वाली योजनाओं का कभी रेवड़ी बताकर विरोध करती रही हो, लेकिन अब वह भी ऐसी योजनाओं में भागीदारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की जीत में महतारी वंदन योजना और मध्य प्रदेश की जीत में लाडली बहना योजना की भूमिका को शायद ही कोई दल नकार पा रहा है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब दस जून 2023 को जबलपुर में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी, तब माना जा रहा था कि उनकी सरकार मध्य प्रदेश में अलोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन चुनावी नतीजों ने इस धारणा को बदल दिया। छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया था कि भूपेश बघेल सरकार को हार का स्वाद चखना होगा। लेकिन ऐसा हुआ। माना गया कि सियासी तस्वीर बदलने में बीजेपी की महतारी बंदन योजना का बड़ा हाथ रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की जीत में भी अन्य कारकों के साथ लाड़की बहिन योजना और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की वापसी में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अहम भूमिका रही है।

पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं ने मतदान में पुरुषों के पीछे चलने की अवधारणा को ना सिर्फ खंडित किया है, बल्कि बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा भी ले रही हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 59.69 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया था, वहीं पुरुषों का प्रतिशत महज 54.45 प्रतिशत ही था। बिहार जैसे कम महिला साक्षरता वाले राज्य में ऐसी राजनीतिक जागरूकता को सलाम किया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर करीब 51 प्रतिशत ही है। 2010 के विधानसभा चुनावों से ही बिहार में महिलाएं केंद्र में हैं। तब जहां 51.12 प्रतिशत पुरुष मतदाताओं ने ही अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था, वहीं महिलाओं ने इससे कहीं ज्यादा यानी 54.49 प्रतिशत हिस्सेदारी की थी। इसी तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में भी 53.32 फीसद पुरुषों से आगे 60.48 फीसद महिलाओं ने वोट डाले थे। बिहार में इस बार करीब साढ़े तीन करोड़ महिला मतदाता हैं। जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.92 करोड़ हैं। पलायन का दंश झेल रहे बिहार में वास्तव में पुरुष मतदाता कम हैं। मतदाता सूची में दर्ज नाम वाले भी वोटर परदेस में रोजी-रोटी कमाने को मजबूर हैं।

महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी लागू की थी। आलोचनाओं के बावजूद अगर नीतीश इस योजना को जारी रखे हुए हैं तो इसका मतलब यह भी है कि उनका महिला वोटरों पर भरोसा तेजस्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है। बिहार में इस बार 14 लाख ऐसे नए वोटर जुड़े हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। विधानसभावार आंकड़ों के लिहाज से देखें तो हर विधानसभा में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या औसतन 5761 होती है। विधानसभा में जीत-हार का आंकड़ा बेहद नजदीकी होता है। जाहिर है कि इन नए मतदाताओं पर भी जीत-हार का आंकड़ा निर्भर होगा। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव बार-बार युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी सरकार बनने की हालत में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने का दावा भी कर रहे हैं।

पलायन भी ऐसा मुद्दा है, जो युवाओं के मर्म को छूता है। यही वजह है कि इसे विपक्षी खेमे की ओर से मुद्दा बनाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। बिहार में रोजगार की कमी के चलते यहां के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का रुख करने को मजबूर हैं। प्रशांत किशोर मतदान में युवाओं की ताकत को समझते हैं, शायद यही वजह है कि वे बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यह बात और है कि बिहार की राजनीति भी दबी जुबान से ही सही, इन मुद्दों के साथ खड़ी होने की तैयारी में है। चुनाव आयोग ने बिहार से ही अपने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआइआर की शुरुआत की है। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष इस पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहा है। वोट चोरी की धारणा को इस अभियान के बहाने राहुल गांधी ने नया रुख दिया है। विपक्षी खेमे की कोशिश है कि इस मसले को जिंदा रखा जाए। उसे लगता है कि एक बार इसे छोड़ दिया गया तो वोट चोरी की धारणा ही धीरे-धीरे सवालों के घेरे में आती जाएगी। इसलिए विपक्षी खेमे की कोशिश है कि एसआइआर को बेकार बताकर इस पर सवालिया निशान खड़े करना है। विपक्ष की कोशिश महिलाओं के सम्मान के बहाने नीतीश सरकार को घेरते हुए लोगों का समर्थन हासिल करने की है। जबकि सत्ता पक्ष इसे विपक्ष का दुष्प्रचार बताकर उसे किनारे रखने के प्रयास में जुटा हुआ है।

प्रसंगवश

ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के लिए बनें एकीकृत सुरक्षा नीति

राजमार्गों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी से हो रहे हादसों पर लगाम जरूरी

जयपुर-अजमेर हाइवे पर हाल ही एलपीजी सिलेंडर भरे ट्रक को केमिकल लदे टैंकर ने टक्कर मार दी। जिससे कई सिलेंडर फटे और आग के ऊंचे-ऊंचे गोले आसमान में दिखने लगे। लोगों ने हाइवे से दूर भागकर जान बचाई। इस हादसे में टैंकर चालक जिंदा जल गया। गत वर्ष दिसंबर में भी इसी हाइवे पर ऐसे ही एक हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे। लगता है ऐसे हादसे अब अपवाद नहीं रह गए। राजस्थान में हर साल ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में लापरवाही, तकनीकी खराबी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बड़ी वजहें बन सामने आ रही हैं। केमिकल और गैस टैंकरों के संचालन-परिवहन के नियम तो हैं, लेकिन उनकी पालना पर आंख मूंद ली जाती हैं। ड्राइवरों को खतरनाक पदार्थों के परिवहन का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें बिना सुरक्षा उपायों, उपकरणों के ही लंबी यात्राओं पर भेज दिया जाता है।

राज्य में प्रतिदिन हजारों बैरल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी के अलावा केमिकल भरे टैंकर सड़कों पर दौड़ते हैं। इन्हें इधर से उधर ले जाते चालक कितने प्रशिक्षित हैं, टैंकर कितने सुरक्षा मानकों पर खरे हैं, चालक-परिचालकों के पास ऐसे हादसों के वक्त ध्यान रखने योग्य तकनीकी दक्षता है या नहीं, क्या ड्राइवर्स पूरे आराम के बाद ही वाहन चला रहे हैं या थकान और उनींदगी का सामना कर रहे हैं, हर एक तय दूरी के बाद बड़े अग्निशमन केंद्र और आपातकालीन इंतजाम हैं या नहीं, इन सभी पहलुओं पर गौर करना होगा। वाहनों में रियल-टाइम तापमान और दबाव मॉनिटरिंग सिस्टम भी हों तो खतरों को समय पर भांपकर उचित कदम उठाया जा सकता है।

जरूरत है कि राज्य सरकार ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन के लिए एक एकीकृत सुरक्षा नीति बनाएं, जिसमें प्रशिक्षित चालक, तकनीकी फिटनेस, जीपीएस से गाड़ी की निगरानी, चालकों के लिए विश्राम-स्थल और रेपिड रेस्पॉन्स टीम का बंदोबस्त हो। पर्याप्त सुरक्षा मानक लागू नहीं किए तो जयपुर-अजमेर हाइवे जैसे हादसे लगातार होते रहेंगे। सड़कें तरक्की की प्रतीक हैं, ये आग की लपटों में न लिपटें, ऐसे प्रयास जरूरी हैं। - **जितेंद्र पालीवाल**

jitendra.paliwal@in.patrika.com

बुक इनसाइट

38 लोंद्रेस स्ट्रीट : न्याय की कहानी

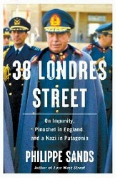

ब्रिटिश लेखक और अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ फिलिप सैंड्स की किताब '38 लोंद्रेस स्ट्रीट' सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं, बल्कि सत्ता, अत्याचार और न्याय के बीच चल रही लंबी लड़ाई की सच्ची कहानी है। लेखक ने इसमें तीन जटिल और आपस में जुड़े प्रसंगों को पिरोया है- चिली के तानाशाह ऑगस्टो पिनोशे, इंग्लैंड में उसका मुकदमा और पैटागोनिया में छिपा एक नाजी अपराधी। किताब का नाम '38 लोंद्रेस स्ट्रीट' उस इमारत से जुड़ा है जो कभी सैंटियागो (चिली) में राजनीतिक कैदियों की पूछताछ और यातना का केंद्र हुआ करती थी। सैंड्स इस पते को प्रतीक बनाते हैं उस दर्द, अन्याय और खामोश सच्चाइयों का, जो सत्ता के दुरुपयोग से जन्म लेते हैं। यह उन साधारण लोगों की कहानी भी है जिन्हें राजनीति और सत्ता ने कुचल दिया, लेकिन जिन्होंने अपने मौन को गवाही में बदल दिया। किताब पढ़ते हुए पाठक एक भावनात्मक सफर से गुजरता है जहां एक ओर राजनीतिक अत्याचार की क्रूरता दिखती है, वहीं दूसरी ओर कानून और नैतिकता की उम्मीद भी झलकती है। सैंड्स का लेखन सरल, लेकिन गहरा है।

फैक्ट फ्रंट

ग्लास फ्लावर : पारदर्शी पंखुड़ियां

ग्लास फ्लावर, जिसे वैज्ञानिक रूप से डिफाइलिया ग्रेई और 'स्केलेटन फ्लावर' कहा जाता है। यह फूल जापान और दक्षिण अमरीका के कुछ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इसकी सबसे अनोखी खासियत है इसकी पंखुड़ियों का बारिश में पारदर्शी हो जाना, जो इसे कांच जैसा चमकदार बनाता है। जैसे ही फूल सूखता है, इसकी पंखुड़ियां फिर से सफेद हो जाती हैं। यह बदलाव प्रकृति की कारीगरी का जीवंत उदाहरण है। यह फूल न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि प्रकृति के साथ अपने अनोखे तालमेल के लिए भी प्रसिद्ध है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी पंखुड़ियों में मौजूद कोशिकाएं पानी के संपर्क में आते ही अपनी संरचना बदल देती हैं जिससे प्रकाश सीधे गुजर जाता है और पंखुड़ियां पारदर्शी दिखाई देती हैं। 'ग्लास फ्लावर' बहुत नाजुक होता है और घने जंगलों की छाया में नमी वाले इलाकों में उगता है। प्रकृति प्रेमी इस फूल को देखने के लिए खास तौर पर इन इलाकों की यात्रा करते हैं। जब यह फूल खिलता है, तो उसकी चमक किसी जादू से कम नहीं लगती।

उपलब्धि अभियानों से बदली विकास की दिशा

अंतरिक्ष अनुसंधानों से खेतों तक विज्ञान की रोशनी

डॉ. रश्मि तिवारी
सीनियर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट, आईआईटी बॉम्बे
@patrika.com

भारत ने जिस तेजी से अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, वह न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में बीते कुछ दशकों में किए गए अभियानों ने देश के विकास की दिशा को ही बदल दिया है। जो कभी केवल अंतरिक्ष अन्वेषण का सपना था, वह आज कृषि, संचार, मौसम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में विकास का आधार बन चुका है।

वर्ष 1975 में जब भारत ने सोवियत संघ की सहायता से अपना पहला उपग्रह 'आर्यभट्ट' प्रक्षेपित किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह पहल एक दिन भारत को अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में अग्रणी बना देगी। आज भारत के पास 135 से अधिक सक्रिय उपग्रह हैं, जिससे वह दुनिया में सातवें स्थान पर है। ये उपग्रह संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि निगरानी और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें संचार उपग्रह (आइएनएसएटी श्रृंखला), रिमोट सेंसिंग उपग्रह (आइआरएस श्रृंखला), नेविगेशन प्रणाली एनएवीआइसी और वैज्ञानिक मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान तथा आदित्य-एल1 शामिल हैं। इन मिशनों से प्राप्त आंकड़ों ने नीति निर्माण, संसाधन प्रबंधन और आपदा पूर्वानुमान के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक का योगदान सबसे गहरा रहा है। इसरो ने 'भारत कृषि सैटेलाइट कार्यक्रम', 'किसान', और 'फसल' जैसे उपक्रमों के माध्यम से खेत-खलिहानों तक विज्ञान पहुंचाया है। रिसोर्ससेट, रिसेट और इनसेट जैसे उपग्रहों से प्राप्त डेटा के आधार पर किसानों को बुवाई के उपयुक्त समय, सिंचाई की आवश्यकता और संभावित सूखे या बाढ़ की चेतावनी दी जाती है। इसरो के रिमोट सेंसिंग और कार्टोसैट उपग्रहों की मदद से भूमि की गुणवत्ता, फसल की सेहत, नमी की स्थिति और कीट प्रकोप की निगरानी की जा रही है।

'फसल' (एफएएसएएल) कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पादन का सटीक अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 2024-25 के रबी सत्र में इसरो ने आठ प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में लगभग 122.7 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान प्रस्तुत किया था, जो कृषि मंत्रालय के वास्तविक आंकड़ों से मेल खाता है। यह अनुमान मिट्टी की नमी, वायुमंडलीय दबाव और फसल की सेहत जैसे सैकड़ों उपग्रह मापों पर आधारित था। उपग्रह आधारित निगरानी के चलते कृषि उत्पादकता में लगभग 8-10% तक की वृद्धि हुई है। संचार क्षेत्र में भी इसरो की उपलब्धियां भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। वास्तव में, भारत के अंतरिक्ष अभियान न केवल अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, बल्कि धरती पर भी एक नई कहानी लिख रहे हैं- बदलाव की, आत्मनिर्भरता की और भविष्य की।

जंगल में शहर: प्राचीन मायन सभ्यता का गवाह

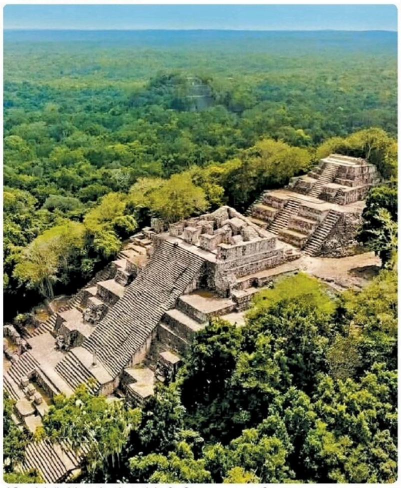

मेक्सिको के कैम्पेचे प्रांत के घने जंगलों के बीच स्थित कालकमूल प्राचीन मायन सभ्यता का एक भव्य शहर रहा है। हवाई दृश्य से झलकती इसकी विशाल संरचनाएं और मंदिर सदियों पुरानी संस्कृति, ज्ञान और वास्तु-कौशल की गवाही देते हैं। आज भी इसका अधिकांश हिस्सा हरियाली के नीचे छिपा है।

अनदेखी धारा 406 और 420 की संधि गलत

दो धाराओं का पुराना साथ, विधि व्यवस्था पर आघात

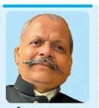

हेमंत नाहटा
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
@patrika.com

सुप्रीम कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुका कि छल के अपराध की धारा 420 आइपीसी तथा अमानत में खयानत की धारा 406 आइपीसी (अब धारा 316 (2) व 318(4) बीएनएस) का अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं आ सकता। दोनो अपराधों में दिन-रात का अंतर है। इस बारे में स्पष्ट विधि के बावजूद पुलिस दोनों धाराएं एक साथ लगाकर एफआइआर दर्ज करती है, गिरफ्तारी करती है, न्यायालय से रिमांड लेती है और अनुसंधान के बाद दोनों धाराओं में एक साथ आरोप पत्र भी पेश कर देती है। मजिस्ट्रेट न्यायालय भी दोनों धाराओं के अपराध का एक साथ प्रसंज्ञान लेकर दोनों धाराओं में चार्ज फ्रेम करने के पश्चात ट्रायल भी आरंभ कर देते है।

आंकड़ों के अनुसार केवल राजस्थान में ही वर्ष 2020 से जून 2024 के बीच लगभग 75000 एफआइआर में दोनों धाराएं एक साथ लगाई गईं और उनमें दस हजार आरोप पत्र न्यायालयों में पेश किए गए, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विधि की व्याख्या की उपेक्षा का स्पष्ट उदाहरण है। पूरे देश में इसका क्या हश्र हुआ होगा, वह अकल्पनीय है। यदि स्वेच्छा से आरोपी का भरोसा कर उसको संपत्ति सौंपी गई हो और मालिकाना हक देने वाले का ही रहा हो, तब वापस मांगने पर बेईमानीपूर्वक संपत्ति हड़प जाने की स्थिति में धारा 406 आइपीसी का अपराध बनता है, लेकिन पुलिस खरीद-बेचान के सौदे में आरोपी को दी गई विक्रय प्रतिफल की राशि को भी अमानत में खयानत मानकर गिरफ्तारियां कर रही है। आरोपी द्वारा मात्र कालांतर में अपना प्रॉमिस पूरा करने में असफल रहने पर या कालांतर में बेईमानीपूर्ण आशय उत्पन्न हो जाने पर धारा 420 का अपराध गठित नहीं होता, बल्कि वह संविदा भंग का सिविल केस है। इन मूलभूत बिंदुओं पर संवैधानिक न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधिक स्थिति पुलिस व अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर पूरी तरह से देखी ही नहीं जा रही है। संविदा भंग जैसे मामलों में आरोपी को जेल भेजा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब निर्णय में गंभीर क्षोभ प्रकट करते हुए कहा कि इतने वर्षों बाद भी पुलिस व न्यायालय दोनों धाराओं में अपराधों के मध्य अंतर को नहीं समझ सके हैं तथा शिखर केमिकल केस में तो स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि न्यायालय में ही विधि का शासन सुरक्षित नहीं रहेगा तो सारे देश में न्याय व्यवस्था का अंत हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत पुलिस व अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी रूप से लागू है मगर उनकी अनुपालना नहीं होने पर जिम्मेवारी तय कर न्यायिक अवमानना की कार्यवाही नहीं की जाती। यदि विधि विरुद्ध गिरफ्तारियों और हिरासत का दुष्चक्र नहीं रुकता है, तो इसकी समाज को भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

आपकी बात

बाजार संगठनों से समन्वय जरूरी

त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए अग्रिम योजना, सूचना प्रसार, व्यवस्थित पार्किंग और आपातकालीन सेवाएं जैसे उपाय करने चाहिए। प्रशासन और बाजार संगठनों को मिलकर कार्य करना चाहिए।
- **रोहित सोलंकी**, पिपरिया, नर्मदापुरम

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'त्योहारों के समय बाजारों में भीड़ प्रबंधन के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए?' ऑनलाइन भी देखें।
इसे स्कैन करें https://shorturl.at/z5EyH

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।
ईमेल करें: edit@epatrika.com

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक

मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाएं

डॉ. मिलिंद कुमार शर्मा
प्रोफेसर, एमबीएम यूनिवर्सिटी, जोधपुर
@patrika.com

> *मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आधुनिक जीवनशैली के चलते तनाव, असंतोष और प्रतिस्पर्धा जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। छात्र, कर्मचारी और गृहिणियां सभी किसी न किसी प्रकार के मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। डिजिटल लत व सामाजिक अलगाव जैसी नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।*

बीते कुछ वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों में मानसिक असंतुलन, तनाव, अवसाद, चिंता और आत्महत्या जैसी घटनाओं का बढ़ना अत्यंत दुखद है। ऐसे में यदि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े शैक्षणिक कार्यक्रम सभी सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किए जाएं, तो यह न केवल इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति करेगा अपितु समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

जैसे-जैसे भारत आर्थिक और तकनीक के क्षेत्र में उतरोतर प्रगति कर रहा है मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आधुनिक जीवनशैली के चलते तनाव, असंतोष और प्रतिस्पर्धा जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। छात्र, कर्मचारी, अधिकारी और गृहिणियां सभी किसी न किसी प्रकार के मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर यदि क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, बिहेवियरल साइंस, रिहैबिलिटेशन स्टडीज और न्यूरोसाइंस जैसे विषयों को प्रोत्साहन दिया जाए तो न केवल प्रशिक्षित विशेषज्ञ तैयार होंगे अपितु ये संस्थान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों, अनुसंधानों और समुदाय सेवा के सक्रिय केंद्र भी बन सकेंगे। यह विशेष शिक्षा विद्यार्थियों को यह समझने में सहायक होगी कि जीवन की चुनौतियों का सामना किस प्रकार संयमित और संतुलित रूप से किया जा सकता है। सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा से समाज और शिक्षा दोनों को भला होगा। इससे शिक्षकों और छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप परीक्षा के दबाव, असफलता या प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ने वाले तनाव और आत्महत्या जैसी घटनाओं में कमी आने की प्रबल संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के समग्र विकास और कल्याण पर विशेष बल दिया गया है और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा अथवा विशेष शिक्षा उसी दिशा में एक सशक्त प्रयास सिद्ध हो सकता है।

डिजिटल व सोशल मीडिया युग में बर्नआउट, डिजिटल लत और सामाजिक अलगाव जैसी नई मानसिक चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित विशेषज्ञों की बड़ी मांग देखी गई है। यदि उच्च शिक्षण संस्थान स्तर पर पर्याप्त संख्या में ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जाएं तो भारत न केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है अपितु वैश्विक स्तर पर भी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर का मानक ढांचा भी जन सामान्य की जानकारी में नहीं है। साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय पुनर्वास परिषद और स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया भी काफी लंबी और जटिल है, जिससे नए पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने में सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों जो कि पहले से संसाधनों की कमी से जूझ रहें हैं हिचकिचाते हैं। इस विषय में कॅरियर बनाने की युवाओं में रुचि भी कम दिखाई पड़ती है।

इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब सरकार, विश्वविद्यालय और नियामक संस्थाएं साथ मिलकर एक समन्वित रणनीति बनाएं। विश्वविद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहां पढ़ाई और परामर्श दोनों गतिविधियां साथ-साथ चलें। निसंदेह भारत जैसे विशाल और युवा राष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मात्र एक शैक्षणिक सुधार नहीं अपितु सामाजिक निवेश है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि युवाशक्ति को संतुलित, उत्पादक और मानवीय बनाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा के केंद्र में रखना अनिवार्य होगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 201

दूरसंचार में मजबूत कदम

नई दिल्ली में चल रहे दूरसंचार सम्मेलन में स्वदेशी 4 जी स्टैक और भारत में डिजिटल क्रांति प्रमुख विशेषताओं के रूप में उभरकर सामने आए हैं। 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस' का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियों को रेखांकित किया और भारत में निवेश, निर्माण और नवाचार की समयबद्धता को उजागर किया। तकरीबन 15 साल पहले के कथित 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले और वर्ष 2007 में हचिसन एस्सार के अधिग्रहण के बाद वोडाफोन पर अतीत से प्रभावी कर या फिर कंपनियों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) से जुड़े शुल्क पर सरकार बनाम उद्योग जगत जैसे विवादों को छोड़ दिया जाए तो भारत का दूरसंचार क्षेत्र कंपनियों के लिए काफी कामयाबी लाने वाला रहा है।

वैसे तो उद्योग जगत पर विपरीत असर डालने वाली कई नीतियों और निर्णयों को या तो बाद में सरल किया गया या फिर उन्हें वापस ले लिया गया लेकिन हाल के दिनों में कुछ नई समस्याएं सामने आई हैं। उदाहरण के लिए उद्योग जगत के कुछ प्रमुख प्रतिनिधियों ने डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए नियामकीय व्यवस्था के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। देश में दूरसंचार नियमों को लगातार बदलते डिजिटल जोखिमों के साथ तालमेल वाला बनाने की जरूरत है। हालांकि इस बात पर अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है कि स्पैम कॉल्स और संदेशों के लिए किसे जिम्मेदार बनाया जाए। सरकार, नियामक और उद्योग जगत तीनों इस पर अलग-अलग नजरिया रखते हैं।

चुनौतियों के बावजूद देश का दूरसंचार क्षेत्र तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में बेहतर रहा है। स्वदेशी 4जी टेक्नॉलजी स्टैक के साथ दुनिया के पांच खास देशों में शामिल होना ऐसा ही एक उदाहरण है। इस स्टैक के लिए सी-डॉट ने कोर नेटवर्क का विकास किया, तेजस नेटवर्क्स ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) मुहैया कराया और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने सिस्टम इंटीग्रेटर का काम किया। भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और स्वीडन ने 4जी मोबाइल टेक्नॉलजी स्टैक विकसित किया है। उपयोगकर्ताओं के लिए इसका अर्थ होगा तेज और विश्वसनीय मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और उम्मीद है कि यह स्वदेशी तकनीक देश को राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ और डिजिटल संप्रभुता प्रदान करेगी। 4जी स्टैक का एक और लाभ यह है कि इसके सॉफ्टवेयर-प्रथम डिजाइन के कारण भविष्य में इसे 5जी इन्फ्रास्ट्रक्चर में उन्नत किया जा सकता है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए काम में लगाया गया यह स्वदेशी 4जी स्टैक अब निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा है।

4जी स्टैक जैसे तकनीकी नवाचार के बीच भारत ने 5जी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब देश के हर जिले में 5जी की सुविधा है। सितंबर तक देश में 36.5 करोड़ लोग 5जी सेवाओं का उपयोग कर रहे थे। लॉन्च होने के तीन साल के भीतर यह उल्लेखनीय आंकड़ा है। देश में कुल दूरसंचार क्षेत्र की पहुंच भी एक सकारात्मक संकेतक है, जो 86.4 फीसदी पर है, और कई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत इसमें अभी भी वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्रामीण भारत से अपेक्षित है, जहां टेलीघनत्व 59.3 फीसदी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 134.5 फीसदी तक पहुंच चुका है।

दूरसंचार उपकरणों का घरेलू निर्माण और उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई के कारण भारत से इनका रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात, इस क्षेत्र की सफलता की कहानी में नया आयाम जोड़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 2014 से अब तक मोबाइल फोन उत्पादन 28 गुना और निर्यात 127 गुना बढ़ा है। हालांकि, दूरसंचार क्षेत्र को अग्रणी बनाए रखने के लिए सेवा प्रदाताओं की वित्तीय स्थिति मजबूत होना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भारत के निजी दूरसंचार क्षेत्र में दो कंपनियों का दबदबा कायम होने की बढ़ती चिंता का समाधान जरूरी है। दूरसंचार कंपनियों को अपने टैरिफ की संरचना को व्यवस्थित करना होगा, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दरों में से एक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दूरसंचार सम्मेलन में कहा कि एक जीबी वायरलेस डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह मॉडल उद्योग के लिए टिकाऊ नहीं हो सकता।

विनय सिन्हा

पूंजीगत व्यय में इजाफे की असल तस्वीर

सरकार के पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी के पीछे कुछ ऐसे रुझान हैं जिनका बारीकी से परीक्षण किया जाना आवश्यक है। बता रहे हैं एके भट्टाचार्य

केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में हाल में हुए इजाफे का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या वास्तव में ऐसे खर्च में तेज उछाल आई है? यकीनन नियंत्रक महालेखाकार द्वारा जारी आंकड़े यही दिखाते हैं कि अप्रैल-अगस्त 2025 की अवधि में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 4.31 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 3 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 43 फीसदी अधिक है।

आश्चर्य नहीं कि इसे एक ऐसी सकारात्मक घटना माना गया जिससे आने वाले महीनों में मदद मिल सकती है और वृद्धि को बल मिल सकता है। खासतौर पर ऐसे समय में जबकि निजी क्षेत्र अभी भी नई परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का इच्छुक नहीं नजर आ रहा है। यह याद रहे कि पिछले पांच साल में पहली बार सरकार ने 2025-26 में पूंजीगत व्यय में एक अंक में महज 6.5 फीसदी वृद्धि का अनुमान जताया है। परंतु आरंभिक पांच महीनों में अग्रिम खर्च किए जाने से वर्ष के बाकी 7 महीनों के दौरान पूंजीगत व्यय में राहत रहेगी। इससे यह 8 फीसदी की कमी को भी वहन कर सकता है और इसके बावजूद 11.21 लाख करोड़ रुपये के बजट लक्ष्य को हासिल कर सकता है।

इस राहत के बावजूद इन आंकड़ों पर करीबी नजर डालें तो मिलीजुली तस्वीर नजर आती है। जुलाई में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 10 फीसदी से अधिक की कमी आई और 2025-26 के पहले चार महीनों में ऐसे व्यय में कुल इजाफा कम होकर 33 फीसदी रह गया लेकिन अगस्त में हुए तेज इजाफे ने परिदृश्य में सुधार किया है। परंतु जब हम यह विश्लेषण करते हैं कि 43 फीसदी इजाफा कैसे हुआ तो अधिकांश विश्लेषकों द्वारा दिखाया गया उत्साह कम हो जाएगा। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को अधोसंरचना क्षेत्र में खपाने को लेकर चिंताएं दूर नहीं होतीं। केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में भी दो व्यापक घटक हैं। पहला घटक है केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों को इक्विटी की मदद से दिया जाने वाला पूंजीगत समर्थन। दूसरा घटक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को दिए गए ऋण और उधार से संबंधित है। इनमें राज्य भी शामिल हैं। वर्ष2025-26 में केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय योजना कुछ हद तक ऋण और उधार पर निर्भर है जो कुल पूंजीगत व्यय का 20 फीसदी है। इसके विपरीत वर्ष2024-25 में यह हिस्सेदारी 18 फीसदी थी। वर्ष 2021-22 में जब मौजूदा पूंजीगत व्यय चक्र शुरू हुआ था, ऋण और उधार की हिस्सेदारी महज 9.9 फीसदी थी।

केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय योजना में ऋण और उधार की हिस्सेदारी में वृद्धि के दो संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, योजनाओं के तहत पूंजीगत व्यय के रूप में योग्य माने जाने वाले कार्यों के लिए ऋण के रूप में धन जारी करना अपेक्षाकृत आसान होता है। जमीन पर परियोजनाओं को लागू करने के लिए पूर्व योजना की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी के कारण अक्सर देरी होती है और वास्तविक व्यय में गिरावट आती है। दूसरा, ऋण का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाता है और यह उनके द्वारा वादा किए गए सुधारों की श्रृंखला को लागू करने से जुड़ा होता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि उच्च पूंजीगत व्यय योजना राज्यों में सुधारों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में अधोसंरचना विकास होगा, जो केवल केंद्र की पहल पर नहीं बल्कि राज्यों की अपनी पहलों के तहत भी किया जाता है।

वर्ष 2025-26 के आरंभिक पांच महीनों में भी यही हुआ। ऋण और उधार के रूप में केंद्र के पूंजीगत व्यय में 175 फीसदी का इजाफा हुआ और यह 1.09 लाख करोड़ रुपये रहा। वर्ष2024-25 की समान अवधि में यह 40,000 करोड़ रुपये था। स्पष्ट है कि उच्च पूंजीगत व्यय से राज्यों तथा अन्य संस्थानों को लाभ मिला है। आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्यों को पूंजीगत व्यय का हस्तांतरण अप्रैल-अगस्त 2025 में 78 फीसदी बढ़कर 51,509 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। इन ऋण और उधार का संबंध पूंजीगत परियोजनाओं के क्रियान्वयन से है। परंतु वह थोड़ा जटिल मुद्दा हो सकता है जिसकी बाद में करीबी पड़ताल करनी होगी। ध्यान रहे कि बिना इस ऋण और उधार के पहले पांच महीनों में पूंजीगत व्यय में इजाफा करीब 23 फीसदी था। यह अभी भी अच्छा खासा इजाफा है और भविष्य की वृद्धि पर इसका सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए।

लेकिन किन क्षेत्रों ने इस प्रकार के व्यय में वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है? रेलवे नहीं, जिसमें पूंजीगत व्यय में केवल 8 फीसदी की एकल-अंकीय वृद्धि हुई और यह 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। सड़कों और राजमार्गों में भी केवल 11 फीसदी की वृद्धि हुई, जो 1.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। वहीं, आवास और शहरी क्षेत्र में 4 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई और यह 9,781 करोड़ रुपये रह गया। परमाणु ऊर्जा पर पूंजीगत व्यय में भी 6 फीसदी से अधिक की कमी आई है। अधोसंरचना क्षेत्र में इकलौता क्षेत्र जिसके पूंजीगत व्यय में तेज इजाफा देखने को मिला है, वह है दूरसंचार जहां व्यय इन पांच महीनों में बढ़कर 17,853 करोड़ रुपये हो गया। अन्य जिन क्षेत्रों को इस अवधि में उच्च पूंजीगत व्यय हासिल हुआ वे हैं: रक्षा, पुलिस, पूर्वोत्तर विकास, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। एक आश्वस्त करने वाली घटना यह है कि कम से कम इस वर्ष अगस्त तक, सरकार को अप्रत्याशित या बिना योजना वाले व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में रखे गए पूंजीगत व्यय का अधिक उपयोग नहीं करना पड़ा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए पूंजीगत व्यय में इजाफा एक दिलचस्प आंकड़ा है। अप्रैल-अगस्त 2025 में इस विभाग का पूंजीगत व्यय बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये हो गया जबकि 2024 की समान अवधि में यह केवल 335 करोड़ रुपये था। कुल मिलाकर देखें तो अकेले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग इन पांच महीनों के कुल पूंजीगत व्यय इजाफे में एक तिहाई से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि विभाग के पूंजीगत व्यय में यह इजाफा भारतीय खाद्य निगम को उधार मुहैया कराने से संबंधित है। खाद्य निगम इस सहायता से खाद्यान्न की खरीद करता है। इससे ऐसी आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह व्यय उस सब्सिडी के बदले समायोजित किया जाता है, जिसे सरकार खाद्य वितरण पर वहन करती है।

यदि यही इसका स्पष्टीकरण है, तो इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की पूंजीगत व्यय योजना की गुणवत्ता पर और भी सवाल खड़े करती है। कुल मिलाकर, केंद्र की पूंजीगत व्यय वृद्धि दर स्वस्थ बनी हुई है, लेकिन इस वृद्धि की संरचना को गहराई से जांचना आवश्यक है ताकि यह बेहतर समझा जा सके कि इसका आर्थिक विकास पर प्रभाव कितना असरदार होगा।

बैंक और बीमा कंपनियां शिकायतों पर गंभीर

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

कई बार पेंशन या अन्य सेवाओं के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं और बाद में ऊपरी स्तर से हस्तक्षेप के बाद ही ऐसे मामलों का समाधान हो पाता है। ऐसे कई तथ्य और इनसे जुड़े आंकड़े हैं जो बैंकों और बीमा कंपनियों के बहीखाते में नजर नहीं आते हैं। इनके प्रभाव काफी व्यापक होते हैं जो लोगों के मन में इन संस्थानों की विश्वसनीयता के बारे में असर डाल सकते हैं।

सक्षम निगरानी से बैंकिंग एवं बीमा संस्थानों में उत्पीड़न, खराब सेवाएं और मनमाना व्यवहार जैसी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। दूसरी तरफ, उदासीनता और सहानुभूति का अभाव अविश्वास पैदा कर सकते हैं जिससे उपभोक्ता अंततः इनसे दूर जाने लगते हैं।

इस संदर्भ में प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है। यह सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान करने की क्षमता के आधार पर मंत्रालयों का पदानुक्रम (रैंकिंग) तय करता है। सितंबर में जारी डीएआरपीजी की नवीनतम रिपोर्ट (अगस्त के आंकड़ों पर आधारित) में कहा गया है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड करीब 500 पंजीकृत शिकायतों के साथ 42 मंत्रालयों- विभागों में रैंकिंग में पहले पायदान पर रहा। इसके बाद दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, भू-संसाधन विभाग और विद्युत मंत्रालय का नंबर आया। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) का बीमा प्रभाग 12वें पायदान पर और इसका बैंकिंग प्रभाग 14वें स्थान पर है। डीएआरपीजी मंत्रालयों एवं विभागों को दो श्रेणियों समूह 'ए' और समूह 'बी' में विभाजित करता है। पहले समूह में 500 या इससे अधिक शिकायतों वाले विभाग और दूसरे समूह में 500 से कम शिकायतों वाले विभाग आते हैं। इसकी नवीनतम रिपोर्ट की दूसरी श्रेणी में 48 मंत्रालय-विभाग शामिल हैं। डीएफएस का पेंशन सुधार विभाग इस सूची में शीर्ष पर है जबकि इसके बाद आयुष मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग और नीति आयोग आते हैं। डीएआरपीजी प्रशासनिक सुधार एवं लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए जवाबदेह है, खासकर, वे जो केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत काम करने वाला डीएआरपीजी केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के काम-काज पर नजर रखता है। इसने संबंधित मंत्रालयों की निगरानी में आने वाली इकाइयों की रैंकिंग तय करने के लिए शिकायत निवारण एवं आकलन सूचकांक (जीआरएआई) तैयार किया है। यह सूचकांक कार्य कुशलता, प्रतिक्रिया, विशिष्ट ज्ञान एवं संगठनात्मक प्रतिबद्धता आदि मोर्चों पर स्कोर तय करने के लिए सीपीजीआरएएमएस डेटा का इस्तेमाल करता है। इसकी शुरुआत डीएआरपीजी ने जून 2007 में की थी और यह पोर्टल सभी केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है। इसका मोबाइल ऐप्लिकेशन भी उपलब्ध है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) से जुड़े मोबाइल ऐप के जरिये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में मोबाइल आधारित शासन व्यवस्था बढ़ाने के लिए 'उमंग' का विकास किया है। उमंग के जरिये देश के सभी नागरिक पूरे देश में ई-सरकारी सेवाएं (केंद्र से लेकर स्थानीय सरकारी निकायों तक) ले सकते हैं। शिकायतों की स्थिति का पता एक विशिष्ट पंजीयन आईडी द्वारा लगाया जा सकता है, जो शिकायत दर्ज करने के समय प्राप्त होता है। अगर कोई शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है। मंत्रालयों की रैंकिंग इस बात से तय होती है वे समस्याओं का समाधान किस तरह करते हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए ग्राहकों के लिए अच्छी बात यह है कि डीएफएस द्वारा शिकायतों के निवारण में निरंतर सुधार दिख रहा है। इसका बैंकिंग प्रभाग भी अपने रैंक में तेजी से सुधार कर रहा है और अप्रैल में 24वें स्थान से सुधर कर यह अगस्त में 14वें स्थान पर पहुंच गया। इसी अवधि के दौरान बीमा प्रभाग की रैंकिंग भी 30वें स्थान से सुधर कर 12वें स्थान पर पहुंच गई। इसके पेंशन सुधार प्रभाग का प्रदर्शन शानदार रहा है जो अप्रैल में 14वें स्थान से अगस्त में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। अगस्त 2025 में डीएफएस ने 74.38 फीसदी शिकायतों का निपटारा किया और कुल 60.22 फीसदी अपीलों की भी सुनवाई की। बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी 22,013 शिकायतें थीं जिनमें से 16,985 का निपटारा गया है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप में डीएफएस अधिकतम संख्या में शिकायतें दर्ज होने की चुनौती की सामना कर रही है। विश्व बैंक की ग्लोबल फिनडेक्स 2025 के अनुसार भारत में 89 फीसदी वयस्क लोगों के पास वित्तीय खाते हैं। सितंबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कम से कम 56.6 करोड़ लोगों के पास बैंक खाते हैं। वित्तीय खंड में शिकायतों का निपटारा करना आसान नहीं है क्योंकि ये बैंक शाखाओं के देर से खुलने से लेकर कंपनी ऋण से जुड़े पेचीदा मामलों, प्रोसेसिंग फीस और आवास ऋण सहित कई बातों से संबंधित होते हैं।

एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि 155 शिकायतों को छोड़कर डीएफएस ने सारी शिकायतों का निपटारा खुद तय 21 दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर किया है। समयसीमा जीआरएआई का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता कितने समय तक समाधान पाने के लिए धैर्य रख सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केवल 24 शिकायतों के निपटारे में निर्धारित 21 दिन से अधिक समय लग गया। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और निजी बैंकों के मामले में 89 शिकायतों के निपटारे में 21 दिनों से अधिक समय लग गया। डीएआरपीजी ने अपील के निष्पादन के लिए 30 दिनों की समयसीमा तय की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी अपीलों का निपटारा 30 दिनों के भीतर कर दिया था जबकि एनबीएफसी एवं निजी बैंकों के पास आईं 20 अपीलों का निपटारा निर्धारित समयसीमा के भीतर नहीं हो पाया।

विभिन्न मंत्रालयों के लिए जीआरएआई सूचकांक के मानदंड अलग-अलग हैं। डीएफएस के लिए यह चार मानदंडों पर आधारित है। इनमें कार्य दक्षता 45 फीसदी भारांश रखता है और इसका निर्धारण 21 दिनों के भीतर समाधान, समाधान में लगने वाले औसत समय और विचाराधीन मामलों के आधार पर होता है। प्रतिक्रिया (फीडबैंक) को 30 फीसदी योगदान मिलता है जो संतोषजनक टिप्पणियों, दायर अपील की संख्या पर आधारित है। संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी को 15 फीसदी भारांश दिया जाता है जिसके लिए अति आवश्यक शिकायतों का अनुपात और वर्गीकरण की पर्याप्तता को आधार बनाया जाता है। संगठनात्मक प्रतिबद्धता को 10 फीसदी भारांश मिलता है जिसका निर्धारण कर्मचारी आवंटन बनाम प्राप्त शिकायतों के आधार पर होता है।

डीएफएस ने हाल में इसे बैंकिंग एवं बीमा इकाइयों के लिए समायोजित किया है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान से जुड़ा मानदंड हटा दिया है और 55 फीसदी भारांश कार्य दक्षता, 35 फीसदी प्रतिक्रिया और 10 फीसदी संगठनात्मक प्रतिबद्धता को दिया गया है।

मासिक रैंकिंग से बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच ग्राहक सहायता (कस्टमर केयर) के मोर्चे पर प्रतिस्पर्द्धा काफी बढ़ गई है। सीपीजीआरएएम पोर्टल को बैंकों एवं बीमा कंपनियों के ग्राहक सेवा प्लेटफॉर्म से जोड़कर बेशक समयसीमा अवधि और घटाई जा सकती है। इससे सीपीजीआरएएम पर सौंपी शिकायतें वास्तविक समय में अलग-अलग इकाइयों तक सीधे पहुंचने में मदद मिलेगी। इसी दौरान, प्रणाली को वाजिब शिकायतों की पहचान कर उन्हें अक्सर इरादतन भेजी जाने वाली शिकायतों के बीच अंतर करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इससे भारतीय वित्तीय प्रणाली को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान अधिक केंद्रित करने, उनके त्वरित निपटारे और ग्राहकों (जिनके लिए वे अस्तित्व में आए हैं) को आश्वस्त करने में मदद मिलेगी।

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

डाक विभाग की कमियों को दूर किया जाए

विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। इस दौरान सरकार और डाक विभाग इससे संबंधित योजनाओं और डाक विभाग के अन्य कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं। दुनिया में डाक का विस्तार हो और यह सुगम हो इसके लिए विश्व के लगभग 22 देशों ने 9 अक्टूबर, 1874 को एक संधि पर हस्ताक्षर कर जनरल पोस्टल यूनियन का गठन किया था। भारत 1 जुलाई, 1876 को पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। भारत गांवों का देश है तथा आज भी यहां काफी हद तक डाक प्रणाली की बहुत जरूरत और अहमियत है क्योंकि देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां कोरियर सर्विस नहीं है वहां डाक विभाग ही लोगों के पत्र और दूसरे बहुत से सामान पहुंचाता है। गांवों तक बैंकों का विस्तार करना मुश्किल है इसलिए डाक विभाग के जरिये ही लोग पैसे भेजने का काम करते हैं। आज के युग में डाक विभाग की अहमियत मंद पड़ने लगी है जिसे देख सरकार डाक विभाग को बैंकिंग काम में लाने लगी है। डाक विभाग में लोग बचत खाते खुलवा सकते हैं और कई सरकारी योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना आदि का लाभ ले सकते हैं। देश में डाक विभाग भी नई तकनीक अपना रहा है। इसका मनीआर्डर अब इलेक्ट्रॉनिक हो जाने के कारण पहले के मुकाबले जल्द पैसा पहुंच जाता है। स्पीड पोस्ट के जरिये पत्रों को भी जल्दी गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। फिर भी डाक विभाग में कुछ कमियां अभी भी बाकी हैं। बैंक के मुकाबले डाक विभाग में तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। पैसे निकालने के लिए डाक विभाग की एटीएम भी अधिक नहीं हैं। सरकार को डाक विभाग का आधुनिकीकरण और इसमें नई तकनीक का विस्तार भी बैंकों की तर्ज पर जल्दी करना चाहिए जिससे डाक विभाग का अस्तित्व बचा रहे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

विश्व डाक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रयागराज में स्कूली छात्राओं ने डाक घर के बाहर सेल्फी ली

भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था जरूरी

प्रशासन व आमजन के पारस्परिक सहयोग से ही भगदड़ हादसों को टाला जा सकता है। आयोजन स्थल पर भीड़ प्रबंधन हेतु उचित व्यवस्था करना व लापरवाही हेतु जवाबदेही तय होनी चाहिए। पुलिस अकेले भीड़ पर काबू नहीं रख सकती है जब तक कि आम जनता स्वयं अपनी रक्षा हेतु सावधान नहीं है। उन्हें व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना होगा ।

गजानन पांडेय, हैदराबाद

भीड़ प्रबंधन की रियल टाइम निगरानी जरूरी

भगदड़ हादसों को रोकने के लिए सुनियोजित भीड़ प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए कार्यक्रम स्थल की क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश न दें। प्रवेश और निकास द्वार चौड़े और स्पष्ट होने चाहिए। भीड़ की गति और घनत्व की रियल-टाइम निगरानी के लिए सीसीटीवी और सेंसर का उपयोग करें। आपातकाल के लिए स्पष्ट निकासी मार्ग और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की टीम अनिवार्य है। सुरक्षा नियमों का सख्त पालन और लोगों में जागरूकता फैलाना दीर्घकालिक समाधान है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैनबरा में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (बाएं) तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस (दाएं) से मुलाकात की। राजनाथ ने रिचर्ड से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा की तथा सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन की संभावना पर विचार-विमर्श किया।

प्रेरणा

अपने सुख-दुख अनुभव करने से पहले हम खुद उन्हें चुनते हैं। - **खलील जिब्रान**, कवि

संपादकीय

देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा सुदर्शन चक्र

सुरक्षा का हमारा अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र अन्य देशों के कवच जैसे इजराइल के आयरन डोम, ब्रिटेन के स्काई सेवर या फिनलैंड के डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम्स से अलग और बहु-आयामी होगा। दुनिया के लगभग दस देशों- जिन्होंने बाहरी हमलों से बचने के लिए सुरक्षा कवच विकसित किया हैं या कर रहे हैं- में से अधिकांश इजराइल के भरोसे हैं या आंशिक रूप से राडार, जमीनी सर्विलांस और मानवीय प्रतिक्रिया के सहारे हैं। लेकिन भारत का यह चक्र 7000 राडार और 52 नए समर्पित सैटेलाइट्स के जरिए एक समेकित और एआई-सक्षम संचार नेटवर्क और उस वेपन-सिस्टम से जुड़ा होगा, जिसमें अति-उच्च शक्ति वाले लेजर से अनचाहे मिसाइल, ड्रोन या अन्य शत्रु-प्रक्षेपित हथियार को देखने के तत्काल बाद नष्ट करने की क्षमता होगी। इसमें कुछ वेपन्स तो विदेश से खरीदे जाएंगे, लेकिन संचार और उसका समेकन शुद्ध रूप से भारतीय होगा। इसमें डीआरडीओ या ऐसी अन्य संस्थाओं की और कुछ निजी क्षेत्र के उपक्रमों की भी भूमिका होगी। भारत की समस्या अन्य देशों खासकर यूरोपीय देशों से अलग है। सुरक्षा कवच के लिए इसका क्षेत्र यूरोप के देशों से कई गुना बड़ा है। कई हजार किमी तक के क्षेत्र पर दिन-रात नजर रखना दुरूह और श्रमसाध्य है। देश तभी चैन की निंदा सो सकता है, जब तकनीकी के नए वरदान अपना काम अहर्निश करते रहें।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

इस दौर में श्रवण-रस का अर्थ है समाधान का मार्ग

कथावाचन हुनर नहीं, जिम्मेदारी है। आज कथावाचकों की स्टार-वैल्यू लोगों की आंखों में चुभ रही है। सांसारिक व्यक्ति को निंदा में ही रस आता है। बड़े-बड़े संत इस निंदा-शस्त्र से आहत होते रहे हैं। लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिन्हें कथा-सत्संगों से मार्गदर्शन मिल रहा है। अब सावधानी कथावाचकों को भी रखनी पड़ेगी। इनका आचरण लगातार निरीक्षण और परीक्षण से गुजर रहा है। लोग टिप्पणी करते हैं कि कथाओं में किस्से-कहानी, नाच-गाना, इसके अलावा क्या होता है। ये कथावाचक के विवेक पर निर्भर करता है कि इनका कितना उपयोग करे और क्यों करे। अगर कथावाचक अपना महत्व, ज्ञान स्थापित कर रहा है और श्रोता को उसकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, तो यह भी तमाशे की श्रेणी में होगा। इस दौर में श्रवण-रस का मतलब है समाधान का मार्ग। कथा कोई भी हो, उसकी भाषा 'प्रॉब्लम-शूटर' होनी चाहिए। अशांत, बेचैन, परेशान लोग कथाओं से समाधान चाहते हैं। अब समाधानकारी सत्संग ही स्वीकार होगा। •Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

टु द पीपुल • वर्कफोर्स में लाखों युवा, पर काम नहीं है

शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा संकट है

रोजगार

डेरेक ओ ब्रायन
राज्यसभा में टीएमसी के नेता
office@derek.in

एसआईआर। भ्रष्टाचार। जातिगत समीकरण। पलायन। शिक्षा : जी हां, बिहार अपनी बात कहने से कुछ ही हफ्ते दूर है। विशेषज्ञ, पर्यवेक्षक और अंधेरे में तीर चलाने वाले चुनाव विश्लेषक रणनीति और रुख का विश्लेषण कर रहे हैं। अगले कुछ हफ्तों में आपके पड़ोसी, स्नातक के दूसरे वर्ष में पढ़ रही आपकी भतीजी और आपके चाचा चुनाव विशेषज्ञ बन जाएंगे। लेकिन इन सबमें एक शब्द के बारे में होने वाली जरूरी बातचीत खो-सी गई है। वह शब्द है- बेरोजगारी।

गौतम शर्मा (बदला हुआ नाम) ने हाल ही में मुझसे बातचीत की। बीस साल का यह मृदुभाषी युवक एक टैक्सी कंपनी के लिए गाड़ी चलाता है। उन्होंने मुझे बताया : मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा काम करूंगा। मैं वेब-विश्लेषक बनना चाहता था। मैंने बी-टेक की डिग्री भी हासिल की। लेकिन कॉलेज प्लेसमेंट में सफल नहीं हो सका। मेरे दोस्त के पिता ने मुझे एक अच्छी-खासी फर्म में नौकरी दिलाने में मदद की। तनख्वाह से किराया और कुछ बुनियादी मासिक खर्चे ही निकल पाते थे। बचत की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब मैं कार चलाकर लगभग 40,000 प्रति माह कमा लेता हूं- जो मेरी पहले की कमाई से ज्यादा है।

आज भारत अपने सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना कर रहा है : शिक्षितों की बेरोजगारी। 2018 में राजस्थान में भृत्य के 18 पदों के लिए 12,000 से ज्यादा लोगों ने साक्षात्कार दिया। उम्मीदवारों में इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। ये हमारे देश की हकीकत है! 2024 में हरियाणा में संविदा सफाई कर्मचारी के रूप में नौकरी के लिए 46,000 से ज्यादा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों ने आवेदन किया था। एक और स्याह हकीकत!

एक छात्र भारत के किसी शीर्ष सरकारी कॉलेज में चार साल बिताता है, डिग्री के लिए लगभग दस लाख रु. चुकाता है, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। 2024 में, आईआईटी से स्नातक करने वाले हर पांच में से दो छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला। यह पैटर्न एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य शीर्ष संस्थानों में भी दिखाई दे रहा है। सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार पिछले साल दस में से एक से ज्यादा स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगार थे। महिलाओं के लिए तो स्थिति और बदतर है। हर पांच में से एक महिला स्नातक और स्नातकोत्तर के पास कोई नौकरी नहीं थी।

हर साल 70 से 80 लाख युवा वर्कफोर्स में प्रवेश करते हैं। लेकिन स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए उचित वेतन वाली अच्छी नौकरियां कहां हैं? हालांकि कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, फिर भी कंपनियां नौकरियों में कटौती कर रही हैं। देश की तीन प्रमुख आईटी कंपनियों के आंकड़ों से पता चलता है कि उन्होंने 2024 में लगभग 64,000 नौकरियों की छंटनी की है। चार सबसे बड़ी कंपनियों में नेट व्हाइट-कॉलर रोजगार की वृद्धि दर 2023 में पांच साल पहले की तुलना में लगभग आधी रह गई है।

एक हायरिंग प्लेटफॉर्म ने हाल ही में बताया कि हर पांच में से चार इंजीनियरिंग स्नातकों और लगभग आधे बिजनेस स्कूल स्नातकों को इंटर्नशिप का प्रस्ताव ही नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य भारत की शीर्ष 500 फर्मों में एक करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करना था। हकीकत क्या है? आवेदन करने वालों में से 5% से भी कम को इंटर्नशिप मिल पाई। सरकार का अनुमान है कि बेरोजगारी दर लगभग 4-6% है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुल बेरोजगारों में दो-तिहाई शिक्षित युवा हैं। हाल ही में, रॉयटर्स ने दुनिया के 50 शीर्ष स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों का सर्वेक्षण किया, जिनमें से 70% ने कहा कि भारत की बेरोजगारी दर गलत बताई जा रही है और यह वास्तविक पैमाने को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है। पीएलएफएस द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में तो प्रति सप्ताह एक घंटा भी काम करने को रोजगार माना जाता है!

हर साल 70 से 80 लाख युवा वर्कफोर्स में प्रवेश करते हैं। लेकिन उचित वेतन वाली अच्छी नौकरियां कहां हैं? हालांकि कॉर्पोरेट मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा गया है, फिर भी कंपनियां नौकरियों में कटौती कर रही हैं।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 2020 में एक इंजीनियर का औसत वार्षिक वेतन 33,000 रु. प्रति माह था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से पता चला है कि वेतनभोगी पुरुषों का वास्तविक वेतन 395 रु. प्रतिदिन और महिलाओं का 295 रु. प्रतिदिन था। हाल में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 12,000 से अधिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और 14,000 से अधिक बेरोजगार व्यक्तियों ने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' जरूर देखें। यह उत्तर भारत के एक गांव के दो लड़कों की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो नौकरी और सम्मान की तलाश में हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं। इस लेख के सहायक शोधकर्ता धीमंत जैन, प्रभाकर कुमार, आयुष्मान डे हैं)

विश्लेषण • छोटे क्षेत्रीय दल चुनावों को प्रभावित करते हैं

बिहार चुनाव में छोटे दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है

सियासत

संजय कुमार
प्रोफ़ेसर और चुनाव विश्लेषक
sanjay@csds.in

भले अभी तक यह कोई नहीं जानता कि बिहार में कितने दल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम 2020 के मुकाबले इस बार मैदान में बहुत अधिक दलों को देखें तो इसमें अचम्भे की बात नहीं। 2020 में 211 दलों ने हिस्सा लिया था। इस बार प्रशांत किशोर की चर्चित जन स्वराज पार्टी के अलावा तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल, आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे की हिन्द सेना पार्टी जैसे नवगठित दल भी चुनाव में उतर सकते हैं।

बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ने के दो कारण हैं। पहला कारण तो साफ है। पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना निर्दलीय प्रत्याशी से कहीं अधिक होती है। अंततः, उम्मीदवार जीतने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और यही कारण है कि वे पार्टी टिकट पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। दूसरा कारण इतना सहज नहीं। भले कोई बिहार चुनाव को द्विध्रुवीय मान रहा हो, लेकिन असल में यह दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि दो गठबंधनों के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला है। और हम जानते हैं कि गठबंधनों में छोटे क्षेत्रीय दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उम्मीदवारों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि वे किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी की जीत की संभावना सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बहुत कम होती है। 1977 से अब तक बिहार चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि उस चुनाव में बहुत कम निर्दलीय ही निर्वाचित हो पाए। 1977 में 324 सदस्यीय विधानसभा में महज 24 यानी (7.4%) निर्दलीय ही जीतकर आए। 2020 में तो चकाई सीट से सिर्फ सुमित कुमार सिंह ही एकमात्र निर्दलीय विधायक बने। 2015 का चुनाव भी ऐसा ही था, जब 243 में से 4 ही निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए। यहां यह ध्यान रखना होगा कि बिहार से झारखंड राज्य के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 रह गई थी। 1977 से अब तक 1990 का चुनाव ही ऐसा रहा था, जब 324 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सर्वाधिक 30 निर्दलीय जीत कर आए थे।

बिहार के चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दलों की लगातार बढ़ती संख्या का एक अन्य कारण यह भी है कि छोटे क्षेत्रीय दल भाजपा, कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों और जदयू, राजद जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों की चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1995 के बाद से हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के परिणामों पर सावधानी से गौर करें तो पता चलता है कि वास्तव में बिहार के चुनावों में दो गठबंधनों के बीच ही द्विध्रुवीय टक्कर होती है, ना कि दो राजनीतिक दलों के बीच। 2020 का पिछला विधानसभा चुनाव ही देखें तो चार प्रमुख राजनीतिक दलों में से राजद को 23.1%, भाजपा को 19.5%, जदयू को 15.4% और कांग्रेस को 9.5% वोट मिले थे। जबकि छोटे क्षेत्रीय दलों ने कुल मिलाकर 23.9% वोट हासिल कर लिए थे। इनमें से कुछ एनडीए और कुछ महागठबंधन के सहयोगी थे।

प्रमुख राजनीतिक दलों और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा हासिल किए गए मतों की बात करें तो 2015 का चुनाव भी थोड़ा अलग था। भाजपा ने सर्वाधिक 24.4% वोट हासिल किए। इसके बाद राजद को 18.4%, जदयू को 16.8% और कांग्रेस को 6.7% वोट मिले। 2010 के विधानसभा चुनाव परिणाम में अंतर केवल यही था कि तब जदयू 22.6% वोट लेकर चुनावी दौड़ में सबसे आगे थी। उसके बाद राजद ने 18.8%, भाजपा ने 16.5% और कांग्रेस ने 8.4% वोट हासिल किए। इन सभी चुनावों में छोटे क्षेत्रीय दलों ने कुल वोटों का 20-24% हिस्सा हासिल किया था।

भले कोई बिहार चुनाव को द्विध्रुवीय मान रहा हो, लेकिन असल में यह दो राजनीतिक दलों के बीच नहीं, बल्कि दो गठबंधनों के बीच द्विध्रुवीय मुकाबला है। और गठबंधन में छोटे क्षेत्रीय दलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बिहार के विभाजन से पहले 1995 और 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में छोटे क्षेत्रीय दलों को और भी अधिक समर्थन मिला था। 1995 के चुनाव में तो छोटे क्षेत्रीय दलों को 28.9% वोट मिले, जबकि 2000 में इन दलों ने 28.1% वोट प्राप्त किए। बिहार में बड़ी संख्या में मौजूद छोटे क्षेत्रीय दल अकेले भले ही अधिक तादाद में सीटें न जीतें, लेकिन एक ऐसे राज्य में जहां गठबंधन चुनावी मॉडल बन चुका है, इन छोटे क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बड़े दलों के बिखरे हुए वोटों को उनके पक्ष में लाने में मदद करते हैं, ताकि एक मजबूत समर्थन आधार तैयार किया जा सके। यह बताता है कि बिहार के चुनावी मुकाबले में राजनीतिक दलों की संख्या क्यों बढ़ रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

ब्रांड से सबक | टेस्ला, अमेरिकी ईवी कंपनी

2008 में वेतन देना मुश्किल हो गया था, रिस्क लिया इनोवेशन किया, अब सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला

2008, क्रिसमस के ठीक एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर की शाम। टेस्ला मोटर्स के सीईओ इलॉन मस्क खुशी के मारे जोर-जोर से चीख रहे थे। यह खुशी इसलिए थी क्योंकि मस्क 4 करोड़ डॉलर का फंड जुटाने में सफल हो गए थे। यह वह दौर था कि अगर उस समय यह फंड नहीं मिलता तो कंपनी दो दिन बाद कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं दे पाती। वह दिवालिया हो सकती थी। उस वक्त टेस्ला की पहली कार रोडस्टर डिलीवर हो रही थी, लेकिन लागत और देरी ने कंपनी को खोखला कर दिया। उनके पास फाइनेंस के रूप में कुछ लाख डॉलर ही बचे थे। दरअसल टेस्ला मोटर्स के मुख्य निवेशक वैंटेजपॉइंट कैपिटा के प्रतिनिधि एलन साल्जमैन टेस्ला को पारंपरिक कंपनियों के लिए बैटरी सप्लायर बनाने की मांग पर अड़े थे, लेकिन मस्क इस रणनीति के खिलाफ थे। कंपनी का फंड रुक गया जबकि नकदी की कमी के चलते स्टाफ की कटौती करनी पड़ी। नए मॉडल के लॉन्च को आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि संघर्ष के उन दिनों में मस्क की जिद, जोखिम लेने की क्षमता और सही समय पर कड़े फैसलों ने न केवल टेस्ला को दिवालिया होने से बचा लिया बल्कि आज यह कंपनी रोज नए इतिहास गढ़ रही है। आज ब्रांड से सबक में पढ़िए कहानी उसी टेस्ला मोटर्स की।

वर्तमान स्थिति

आज 120 लाख करोड़ रुपए की कंपनी

टेस्ला मोटर्स का वर्तमान में मार्केट कैप करीब 120 लाख करोड़ रुपए है। फिलहाल यह करीब 50 देशों में कारोबार कर रही है। इसकी गाड़ियों के मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाय और साइबर ट्रक करीब पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के वैश्विक बाजार में टेस्ला का मार्केट शेयर करीब 25 प्रतिशत है। 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने करीब 3.36 लाख गाड़ियां बेची हैं। कंपनी का फोकस फिलहाल वैश्विक विस्तार और ब्रांड रिवाइवल पर है।

सबक क्यों- एक समय दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, आज 120 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कंपनी है।

40 हजार गाड़ियां हर माह बेच रही है टेस्ला अभी दुनिया में

50 से अधिक देशों में इस समय कारोबार कर रही है कंपनी

2025 में जुलाई में टेस्ला ने मुंबई में पहला शोरूम खोला

600 से अधिक कारों की बुकिंग देश में हो चुकी है सितंबर तक

टेस्ला कंपनी टेस्ला रोडस्टर नाम की कार अंतरिक्ष में भी भेज चुकी है।

ऐसे मुश्किल दौर में पहुंची

1. **कार डिलीवरी में देरी, बढ़ी हुई लागत-** टेस्ला की पहली कार रोडस्टर बाजार में उतरने वाली थी। बैटरी पैक आर्किटेक्चर, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन सबकुछ पहली बार हो रहा था। इससे टाइम लाइन बढ़ी, जिससे लागत अधिक हुई। कैश ज्यादा खर्च हुआ।
2. **वैश्विक मंदी-** 2008 की वैश्विक मंदी में ईवी जैसे खर्चीले सेगमेंट के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हुआ। वहीं मस्क व कंपनी के को-फाउंडर एबरहार्ड के बीच विवाद ने भी फंड जुटाने में असर डाला।
3. **गो-टु-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी-** टेस्ला ने डीलरशिप की जगह डायरेक्ट सेल्स मॉडल चुना। इससे लॉजिस्टिक, सर्विस और चार्जिंग का पूरा नेटवर्क खुद बनाना पड़ा, जिससे खर्च बढ़ा।
4. **ऑटो इंडस्ट्री की अनिश्चितता-** उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता पर भारी संशय था। पारंपरिक ऑटो कंपनियां भी संकट से गुजर रही थीं।

इस तरह की वापसी

1. **46 करोड़ डॉलर की सरकारी मदद-** अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 2009/10 में मस्क की कंपनी को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कार्यक्रम के तहत 46 करोड़ डॉलर का लोन कम ब्याज पर दिया। यह कंपनी के लिए 'लाइफलाइन' साबित हुआ।
2. **आईपीओ से जुटाया पैसा-** कंपनी 2010 में 17 डॉलर प्रति शेयर के हिसाब से आईपीओ लाई। इससे कंपनी ने 22 करोड़ डॉलर जुटाए, जिससे कंपनी की माली हालत सुधरी।
3. **प्रोडक्ट इनोवेशन-** टेस्ला ने हाई क्वालिटी की बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर तकनीक विकसित की, जिससे कारें लंबी दूरी तक चलने लगीं। इस इनोवेशन ने टेस्ला को ईवी उद्योग का दिग्गज बना दिया।
4. **ब्रांडिंग, ग्लोबल विस्तार-** टेस्ला ने ब्रांड को फ्यूचरिस्टिक और क्लासी बनाया। स्टाइलिश और टेक्नोलॉजी फोकस्ड कारों की पहचान बनाई।

अमेरिकी आविष्कारक के सम्मान में रखा था 'टेस्ला' नाम

शुरुआत : दो इंजीनियरों ने रखी थी टेस्ला मोटर्स की नींव

टेस्ला मोटर्स की नींव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्क टार्पेनिंग ने 2003 में रखी थी। दोनों को लगा कि इलेक्ट्रिक वाहन ही भविष्य हैं। ईवी सेगमेंट में भविष्य को देखते हुए दोनों ने कंपनी स्थापित की। एक ऐसी कार कंपनी, जो बैटरी, सॉफ्टवेयर मोटर टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दे। 2004 में मस्क निवेशक के रूप में जुड़े।

गिरावट : मंदी और ईवी पर संशय ने बिगाड़ दी थी आर्थिक स्थिति

2007-08 की मंदी के चलते कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। इलेक्ट्रिक कारों के बारे में संशय के चलते फंडिंग प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। कंपनी ने स्टाफ में कटौती की। मॉडल एस की लॉन्च में देरी की। फंडिंग राउंड तक असफल रहे। ऐसे में वित्तीय संकट इतना गहरा गया कि कंपनी कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ हो गई।

ऐसे पड़ा नाम : एबरहार्ड ने अमेरिकी आविष्कारक निकोला टेस्ला के सम्मान में टेस्ला नाम दिया था। निकोला ने एसी इलेक्ट्रिक मोटर की खोज की थी।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : इसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी चीन की बीवायडी, अमेरिका की रिविआन, फॉक्सवैगन जीएम मोटर्स और फोर्ड हैं।

पीपुल भास्कर | कैवल्य वोहरा | क्विक कॉमर्स जेप्टो के सह-संस्थापक

स्कूल के दिनों में ही एप बनाने लगे थे कैवल्य, 18 की उम्र में स्टैनफोर्ड छोड़ा, उनका मंत्र- स्पीड ही सक्सेस

2020, कोविड-19 धीरे-धीरे देश में फैल रहा था। लोग एक-दूसरे के पास आने और छूने से डर रहे थे। ऐसे में ज्यादातर लोग ग्रॉसरी डिलीवरी एप से सामान मंगाने लगे, लेकिन ग्रॉसरी मिलने में 3 से 4 दिन का समय लग रहा था। लोगों में खीझ बढ़ रही थी। खासकर बैचलर्स के लिए यह इंतजार मुश्किल था। लोगों की इसी परेशानी को 18-19 साल के एक युवा ने बिजनेस आइडिया में बदल दिया। वे युवा हैं 22 वर्षीय कैवल्य वोहरा।

कैवल्य बताते हैं कि मुझे समझ आ गया था देश में क्यू कॉमर्स का भविष्य सुनहरा है। उन्होंने अपने साथी आदित पलीचा के साथ मिलकर क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो की नींव रखी। यह स्टार्टअप 2023 में यूनिकॉर्न बन गया था।

हालांकि ऐसा नहीं है कि यह सफर आसान था। अपने स्टार्टअप के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसलिए सबसे पहला विरोध तो घर से शुरू हुआ। कैवल्य बताते हैं कि एक बार तो उनकी मां ने रोते हुए आदित से कहा था कि उसने बेटे का ब्रेनवॉश कर दिया है। हालांकि एक बार पैरेंट्स के मानने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी सोच है कि स्पीड ही सफलता है। कैवल्य को तकनीक और प्रोग्रामिंग में गहरी रुचि बचपन से थी। उन्हें नए-नए टेक स्टार्टअप आइडिया पर काम करना आज भी पसंद है।

कैवल्य फिटनेस के शौकीन हैं। सप्ताह में तीन दिन जिम जाते हैं। खास बात कि वर्क आउट के दौरान करीब एक घंटे वे किसी भी तरह के गैजेट का इस्तेमाल नहीं करते। रोज 10 मिनट ध्यान लगाते हैं।

चर्चा में क्यों- हुरुन इंडिया 2025 की अरबपतियों की सूची में सबसे युवा के रूप में शामिल हुए हैं। संपत्ति करीब 4,480 करोड़ रुपए है।

बाइक राइडिंग के भी शौकीन हैं कैवल्य

कैवल्य की मां आज भी पूछती हैं क्या वे कॉलेज की डिग्री के लिए दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कैवल्य जीवन का बहुत सुंदर दौर जीने से चूक रहे हैं।

जन्म : 15 मार्च 2003 (22 वर्ष) बेंगलुरु, कर्नाटक
शिक्षा : दुबई कॉलेज, दुबई से स्कूल की पढ़ाई।
सम्पत्ति : 4,480 करोड़ रु. (हुरुन इंडिया के अनुसार)

शुरुआत

पिता इंजीनियर, मां गृहिणी हैं

कैवल्य का जन्म बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता इंजीनयर और मां गृहिणी हैं। कुछ समय के लिए उनका परिवार दुबई चला गया, जिसके बाद उनकी शुरुआती पढ़ाई दुबई के कॉलेज से हुई। कैवल्य बताते हैं स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही रोजमर्रा में सामने आने वाली समस्याओं के लिए हल ढूंढने लगे थे। उनका एक भाई देव जयदीप वोहरा है।

आदित का साथ

स्कूल की पढ़ाई के दौरान बन गए दोस्त

कैवल्य और आदित की मुलाकात दुबई कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों का ही झुकाव टेक्नोलॉजी और बिजनेस की ओर था। क्लास प्रोजेक्ट्स, डिबेट और विभिन्न स्कूल एक्टिविटी के दौरान उनकी समझदारी और आइडिया-शेयरिंग की ट्यूनिंग जम गई। कैवल्य जहां टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं वहीं आदित डिबेट और स्टोरी टेलिंग में माहिर हैं।

करियर

किराना कार्ट से लेकर जेप्टो की स्थापना तक

कैवल्य ने मित्र आदित पलीचा के साथ मिलकर 2020 में पहले 'किरानाकार्ट' नामक कंपनी बनाई थी। उस मॉडल में किराना स्टोर्स से साझेदारी कर सामान 45 मिनट के भीतर डिलीवर करने की योजना थी, बाद में उन्होंने इस मॉडल को बदलकर 'जेप्टो' को नींव रखी। ऐसे क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी का दावा करता है।

रोचक : स्कूल की अंडर-19 बास्केटबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं कैवल्य

खास : स्कूल के दिनों में ही बना लिया था 'गोपूल' प्लेटफॉर्म

- कैवल्य को तकनीक में रुचि बचपन से ही थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कंप्यूटर सोसायटी की शुरुआत कर ली थी।
- स्कूल के दिनों में ही 'गोपूल' नामक स्टार्टअप शुरू किया था। यह एक कार पूलिंग प्लेटफॉर्म जैसा आइडिया था, जिसे उन्होंने अपनी स्कूल की जरूरतों को देखते हुए बनाया था।

उपलब्धि : फोर्ब्स एशिया की '30 अंडर 30' सूची में शामिल

- कैवल्य पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी काफी रुचि रखते हैं। वे स्कूल की अंडर-19 बास्केटबॉल टीम के कप्तान रहे।
- फोर्ब्स एशिया की '30 अंडर 30' की सूची में भी उन्हें शामिल किया जा चुका है।
- कंपनी जल्द ही आईपीओ लाकर इसे सार्वजनिक बनाने पर विचार कर रही है।

विवाद भी : डिलीवरी कर्मियों पर दबाव का आरोप

- कुछ आलोचकों ने कहा है कि '10 मिनट डिलीवरी' मॉडल डिलीवरी कर्मियों पर दबाव बढ़ाता है। और यह श्रम करने की मानवीय कठिनाइयों को अनदेखा करता है।
- मुंबई के धारावी स्थित जेप्टो के वेयरहाउस का लाइसेंस स्वच्छता मानकों का पालन न करने के कारण जून में निरस्त कर दिया गया था।

संपादकीय

“इतिहास गवाह है, एक के बाद एक टैरिफ लगने से व्यापार युद्ध छिड़ता है, जिसमें जीतता कोई नहीं, पर उपभोक्ता पिस जाता है।
-मार्क मैकिनन

साझेदारी का नया युग

ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में कुछ खिंचाव-सा दिख रहा है, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का भारत दौरा कई वजहों से ऐतिहासिक है। गौरतलब है कि यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्टार्मर का पहला भारत दौरा है। उनके साथ 125 सदस्यीय भारी-भरकम व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी है, जो ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें वहां के अग्रणी उद्योगपति, उद्यमी, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं। स्टार्मर की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मिसाइल करार के अलावा सैन्य प्रशिक्षण समझौता भी हुआ है, जिसमें भारतीय वायु सेना के जांबाज ब्रिटेन के वायु सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खुलने संबंधी समझौता देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से यकीनन महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन ने जुलाई में जिस समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, उसे खुद स्टार्मर ने दूसरे देशों के साथ हुए ऐसे समझौतों से ज्यादा सशक्त और विकास का लॉन्चपैड तक बताया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में, यह कह कर कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, स्टार्मर ने साफ संकेत दिया कि उन्हें इस यात्रा की अहमियत का भली-भांति अंदाजा है। संयुक्त घोषणा में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों में आयात की लागत घटेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ भारतीय उत्पादों को भी विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। जाहिर-सी बात है कि इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती मिलेगी। हालांकि, दोनों देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि

छोटे और मध्यम उद्यमों को भी इस समझौते का फायदा हो, ताकि आर्थिक विकास समावेशी बन सके। अगर स्टार्मर वीजा के नियमों में राहत देने की भी घोषणा करते, तो यह अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा के नियमों को सख्त किए जाने से सबसे ज्यादा आहत भारतीयों के लिए राहत की बात होती, लेकिन ब्रिटेन की घरेलू राजनीति को देखते हुए इसकी उम्मीद वैसे भी कम ही थी।

टैरिफ के जवाब में नए बाजार की खोज

अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न रणनीतिक अनिश्चितता के जवाब में भारत बातचीत, बाजार विविधीकरण और घरेलू समर्थन पर केंद्रित एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। यह इसी रणनीति की ताकत है, जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अब तक के सबसे बड़े व्यापारी बेड़े के साथ भारत आने के लिए आकर्षित किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा 25 फीसदी शुल्क लगाने के बाद 25 फीसदी अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने से भारतीय निर्यात बाजार पर काफी गहरा असर पड़ा है, जो फिलहाल आंकड़ों में भले न दिख रहा हो। इसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापार एक जटिल चुनौती में बदल गया है, जबकि कभी मजबूत व्यापारिक संबंध था। कुछ भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी तक शुल्क थोपे जाने से इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में पहले से ही महसूस किया जाने लगा है, जिसने केंद्र सरकार और उद्योग जगत को तेजी से आर्थिक गिरावट को कम करने के लिए रणनीतिक कदम उठाने पर मजबूर किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है, ऐसे में उच्च शुल्क ने विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा की हैं। समुद्री खाद्य (झींगा) निर्यात को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका भारतीय झींगे का सबसे बड़ा बाजार है। पारस्परिक व एंटी डंपिंग शुल्कों सहित बढ़ते टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को अलाभकारी मूल्यों का सामना करना पड़ रहा है। झींगों को भेजे जाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिसके कारण बिना बिके माल का भंडार जमा हो रहा है और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है। अमेरिकी खरीदार कथित रूप से वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ

उच्च शुल्कों का सामना कर रहे तिरुपुर और सूरत जैसे विनिर्माण केंद्रों के निर्यातकों ने बताया कि वे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण न कर पाने के कारण नए अमेरिकी ऑर्डर रोक रहे हैं। इससे रोजगार पर खतरा पैदा होता है और मौजूदा ऑर्डरों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका के भारतीय हीरे और जड़ाऊ आभूषणों का सबसे बड़ा बाजार होने के नाते रत्न एवं आभूषण का क्षेत्र लड़खड़ा रहा है, और उद्योग निकाय 50 फीसदी टैरिफ को 'कयामत का दिन' बता रहे हैं। निर्माता अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए दुबई और मेक्सिको जैसे

वैकल्पिक विनिर्माण और व्यापार केंद्रों की तलाश कर रहे हैं। टैरिफ वृद्धि से भारत के ऑटो पार्ट्स निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होगा, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों और भारी मशीनरी के कलपुर्जे, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले काफी नुकसान होगा।

टैरिफ से निर्यात में कमी आने का खतरा है, जिससे घरेलू अधिशेष पैदा होगा और कृषि उत्पादों की कीमतें गिर सकती हैं। बासमती चावल और कपास जैसी वस्तुएं अत्यधिक जोखिम में हैं, और शुरुआती अनुमानों से निर्यात में कमी और भविष्य में उत्पादन क्षेत्र में कमी का संकेत मिल रहा है। मजबूत घरेलू मांग, लचीले सेवा निर्यात और कुल जीडीपी में निर्यात की अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि पर समग्र रूप से मध्यम प्रभाव माना जा रहा है, पर रिजर्व बैंक और एडीबी जैसे प्रमुख संस्थानों ने 'टैरिफ के जोखिमों' का हवाला देते हुए विकास पूर्वानुमानों को घटाया है। अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न 'रणनीतिक अनिश्चितता' के जवाब में, भारत बातचीत, बाजार विविधीकरण और घरेलू समर्थन पर केंद्रित एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा व्यक्त भारत का आधिकारिक रुख 'रचनात्मक है, न कि आक्रामक', लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्र 'न तो झुकेगा और न ही कभी कमजोर दिखेगा।'

गतिरोध को सुलझाने और टैरिफ को कम करवाने के लिए भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि व्यापार वार्ता महत्वपूर्ण चरण में है। यह वार्ता जटिल है, जिसमें व्यापार से जुड़े पारस्परिक टैरिफ और भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क जैसे दोहरे मुद्दे शामिल हैं।

भारत अमेरिका के साथ अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच जैसे पेचीदा मुद्दों पर बात कर रहा है। नई दिल्ली अपने घरेलू किसानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए भारत अपनी टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास कर रहा है। एक ही प्रमुख बाजार पर निर्भरता के जोखिमों को समझते हुए भारत अपनी दीर्घकालीन रणनीति के तहत बाजार और उत्पाद का विविधिकरण कर रहा है।

भारतीय निर्यातक तेजी से नए गंतव्यों का रुख कर रहे हैं। इसमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, पश्चिम एशिया, आसियान और अफ्रीका जैसे बाजारों के साथ गहरा जुड़ाव भी शामिल है। सरकार अपने उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच सुनिश्चित करने की खातिर यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दे रही है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था को सहयोगात्मक रूप से बहाल करने तथा वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिक्स जैसे संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की वकालत की जा रही है। सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और सॉफ्टवेयर, जो नए अमेरिकी टैरिफ से काफी हद तक अछूते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बफर प्रदान करते रहेंगे। कमजोर उद्योगों पर तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार लक्षित राहत उपायों पर विचार कर रही है। हालांकि, कुछ निर्यातकों को बड़े वित्तीय सहायता पैकेज की उम्मीद थी, पर सरकार लक्षित हस्तक्षेप कर रही है।

विचाराधीन उपायों में कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार के लिए छोटे ऋण पैकेज, ब्याज-मुक्त ऋण, और लालफीताशाही कम करने तथा निर्यातकों की लागत कम करने के लिए नीतिगत सुधार शामिल हैं। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल जैसी नीतियों की जरूरत बढ़ रही है। इसका लक्ष्य उच्च तकनीक वाले आयातों का विकल्प बनने के लिए तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना और लचीली वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एक ज्यादा जरूरी कड़ी बनना है, जिससे पारंपरिक केंद्रों से हटकर विविधीकरण की इच्छुक कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। भारत की मजबूत घरेलू खपत और मजबूत सार्वजनिक/निजी निवेश को आधारभूत ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों को सहने में सक्षम बनाएगी।

भारत की रणनीति की सफलता न केवल उसके प्रमुख निर्यात उद्योगों के तात्कालिक भाग्य को निर्धारित करेगी, बल्कि एक अधिक लचीले और रणनीतिक रूप से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की उसकी क्षमता को भी निर्धारित करेगी।

त्योहार

समय बदल रहा है पैमाने भी बदलें

करवा चौथ आस्था से जुड़ा पर्व है। इस पर सवाल उठाने के बजाय पैमाने बदलने पर बात होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पर्वों की उजास तो बची रहे, पर उनसे जुड़ी बंदिशें टूटें।

पर्व-त्योहारों के मौसम में आस्था का रंग ही नहीं, उपहास का बेरंग बर्ताव भी खूब देखने को मिलता है। व्रत-उत्सवों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देने का व्यवहार बहुत आम है। अपनों की कुशलकामना से जुड़े उत्सवों को लेकर खूब नकारात्मकता देखने को मिलती है। कमोबेश हर त्योहारी रीति-रिवाज का मजाक बनाया जाता है। कभी महिलाओं के शोषण की बात, तो कभी पुरातनपंथी सोच का हवाला देकर इन अनुष्ठानों को उपहास का विषय बना दिया जाता है।

उपवास से बिगड़ती सेहत का हवाला देकर भी चेताया जाता है और रूढ़िवादी सोच की जकड़न के प्रति सजग रहने का भय भी परोसा जाता है। अफसोस कि जमीनी मुद्दों को छोड़ नकारात्मकता और विरोध का यह अजब-गजब कोलाहल तीज-त्योहारों का उपहास उड़ाने तक ही सिमट गया है।

यह सच है कि रूढ़िवादी सोच स्त्री जीवन के लिए दंश रही हैं। कई परंपरागत पर्वों के रिवाज महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखने की सोच से जुड़े रहे हैं, पर सच यह भी है कि समय के साथ ऐसे व्रत-उपवास करने से जुड़ी परंपराओं को निभाने के तरीके काफी बदल गए हैं। इनसे जुड़ी आस्था के मायने भी अब नए रंग में दिख रहे हैं। बावजूद इसके इन बदलावों को दिल से स्वीकारने के बजाय उससे जुड़े नकारात्मक पक्षों को साझा करने की मानो होड़ लगी रहती है। सोशल मीडिया के सभी मंचों पर अब स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दे कम और पर्व-त्योहारों के विरोध की बातें ज्यादा साझा की जाती हैं, जबकि ऐसे पर्वों को मनाने के मामले में आई सहजता को भी गहराई से समझा जाना चाहिए, जो महिलाएं मन से इन्हें मानना चाहती हैं, उनके विचारों का भी मान किया जाना चाहिए।

मोनिका शर्मा

दुखद है कि हम टूटते परिवारों और बिखरते सामाजिक ताने-बाने में संबंधों को थामने और साधने का काम कर रहे रीति-रिवाजों का सकारात्मक पक्ष देखना ही भूल रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहेजने के मोर्चे पर चिंता करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि सुखद दांपत्य भी भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। करवा चौथ जैसे पारंपरिक पर्व भी आपसी जुड़ाव को ही पोसते हैं। साथ ही परंपरागत रिवाजों से जुड़ाव रखना आज कोई मजबूरी नहीं है। अपनों और अपने परिवार की खुशहाली की कामना संग अगर त्योहार मन से मनाए जाते हैं, तो क्या बुरा है? खासकर तब, जबकि आज मान्यताओं के मायने भी बदल गए हैं। अहोई अष्टमी जैसा व्रत कभी बेटों के आयुष्य की कामना से जुड़ा था। आज माताएं बेटे-बेटी के भेद से दूर अपने बच्चों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा में भी सुखद परिवर्तन नजर आते हैं।

नई पीढ़ी के पति, अपनी पत्नी की निष्ठा, समर्पण और प्रेम की कद्र करना सीख गए हैं। घर-परिवार में पत्नी की भूमिका को खुलकर सराहने लगे हैं। पत्नी गृहिणी हो या कामकाजी, उसकी जद्दोजहद को समझते हैं। सुखद है कि औपचारिकताओं के परे हमारे परंपरागत पर्व मन की रीत से जुड़ गए हैं। वहीं विरोध की मानसिकता आज भी इन पर्वों के पुरातन स्वरूप तक ही सिमटी है। जरूरी है कि समय के साथ आए इन बदलावों को मान दिया जाए, ताकि भविष्य में पर्वों की उजास तो बची रहे, पर उनसे जुड़ी बंदिशें टूटें। ध्यान रहे कि तार्किक बातों के बजाय अंध विरोध करने की प्रवृत्ति भी स्त्री जीवन के लिए दंश ही है।

यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है

वृद्धावस्था कठिन समय नहीं है, बल्कि यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है, जो पहले के दिनों की बनावटी तात्कालिकताओं से मुक्त है। यह जीवन भर के विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ने का वक्त है।

अस्सी साल! मुझे यकीन नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूं कि जीवन अब शुरू होने वाला है, लेकिन फिर एहसास होता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ-न-कुछ सीखते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने जीवन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरा आखिरी समय आए, तो मैं फ्रांसिस क्रिक की तरह काम करते हुए मरूं। जब उन्हें बताया गया कि उनका कोलन कैंसर लौट आया है, तो उन्होंने बस एक मिनट के लिए दूर देखा और फिर अपने पुराने विचारों में डूब गए। कुछ हफ्तों बाद जब उनसे निदान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'जिस चीज की शुरुआत होती है, उसका अंत भी होता है।' जब उनकी मृत्यु 88 साल की उम्र में हुई, वह तब भी अपने सबसे रचनात्मक काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मेरे पिता, जो 94 साल तक जिए, अक्सर कहते थे कि अस्सी का दशक उनके जीवन के सबसे आनंददायक दशकों में से एक था। मैं भी महसूस करने लगा हूं कि मानसिक जीवन और दृष्टिकोण में संकुचन नहीं, बल्कि विस्तार होता है। वृद्धावस्था तक पहुंचते-पहुंचते हम सफलताएं और त्रासदियां, उतार-चढ़ाव, क्रांतियां और युद्ध, महान उपलब्धियां और गहरी अस्पष्टताएं सब कुछ देख चुके होते हैं।

ओलिवर सॉक्स

मुड़-मुड़ के देख

मैं कल्पना कर सकता हूं, कि एक सदी कैसी होती है, जो मैं 40 या 60 की उम्र में नहीं कर सकता था। मैं वृद्धावस्था को ऐसा कठिन समय नहीं मानता, जिसे किसी तरह झेलना पड़े, बल्कि यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है, जो पहले के दिनों की बनावटी तात्कालिकताओं से मुक्त है। अब मैं जो चाहूं उसे तलाश सकता हूं, और जीवन भर के विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जीवन से थक गया हूं। इसके विपरीत, मैं बहुत जीवंत महसूस करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो समय बचा है, उसमें मैं अपनी दोस्ती को गहरा करूं, जिन्हें मैं प्यार करता हूं, उन्हें अलविदा कहूं, और लिखूं। अगर मुझमें ताकत है, तो यात्रा करूं, समझ और अंतर्दृष्टि के नए स्तर हासिल करूं।

दूसरी पारी

60 वर्षीय हरिया चाचा समेत कई बुजुर्ग पशोपेश में हैं। रेपो रेट घटने के बाद बैंकों ने एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज में कटौती कर दी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए डेट फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माने जाते हैं।

एफडी के अलावा भी कई विकल्प हैं

एफडी पर ब्याज दर घटने की चिंता के बीच विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बुजुर्ग डेट फंड में निवेश कर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं

साठ की उम्र पार कर चुके हरिया चाचा की जिंदगी पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से चलती है। उनकी पुरानी एफडी मैच्योर हो चुकी है। नई एफडी कराने बैंक गए, तो पता चला कि ब्याज दर घट गई है। हरिया चाचा जैसे ही लाखों बुजुर्गों के मन में सवाल है कि एफडी नहीं, तो क्या?

रेपो रेट-एफडी कनेक्शन : बैंक एफडी लंबे वक्त से बुजुर्गों का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। लेकिन ब्याज दरों में कमी से यह पहले जितना आकर्षक नहीं रह गया। रिजर्व बैंक ने 2025 में अब तक तीन बार में रेपो रेट में एक फीसदी की कटौती की। इससे रेपो रेट 6.5 से घटकर 5.5 फीसद पर आ गया। अगस्त की बैठक में नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट वह दर है, जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जब ये दरें घटती हैं, तो बैंक ग्राहकों को सस्ता कर्ज देते हैं। लेकिन बचत करने वालों को जमा पर मिलने वाला ब्याज भी गिर जाता है।

एफडी के ब्याज में आगे और कटौती संभव: रेपो रेट में कटौती के साथ बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों पर कैंची चलाई। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, 2025 की कटौतियों से पहले बैंक आम नागरिकों को सात दिन

से 10 साल तक की रेगुलर एफडी पर 3.5 से 7 फीसदी के बीच की ब्याज दे रहा था, जो अब 6.45 फीसदी पर आ गया है। एक से दो साल के बीच और दो से तीन साल के बीच की एफडी दरें 0.55 फीसदी घटकर अब क्रमशः 6.25 तथा 6.45 प्रतिशत रह गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों से 0.50 फीसदी तक अधिक ब्याज मिलता है। ये दरें तीन करोड़ रुपये से कम रकम की एफडी के लिए हैं। आम तौर पर बैंक रेपो रेट में कटौती का प्रभाव धीरे-धीरे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अगर बैंक अपनी ब्याज दरों में रेपो रेट के बराबर कमी करते हैं, तो आने वाले वक्त में एफडी दरों में और कटौती संभव है।

रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बढ़ी : अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.25 फीसदी (25 आधार अंक) की कटौती की, और संकेत दिया कि 2025 के अंत तक कुल 50 आधार अंक की अतिरिक्त ढील दी जा सकती है, जबकि 2026 में केवल 25 आधार अंक कटौती की उम्मीद है। फेड की कटौती और आगे के रोडमैप को देखते हुए रिजर्व बैंक पर एक बार फिर नीतिगत दरों को घटाने का दबाव बन सकता है। इसके अतिरिक्त, खुदरा महंगाई आरबीआई के 2-6 फीसदी के दायरे में बनी हुई है। यह भी रेपो रेट में कटौती की संभावना को मजबूत कर रही है।

एक्सपर्ट की सलाह : फिनवाइज की संस्थापक प्रतिभा गिरीश बताती हैं कि एफडी की ब्याज दरें घटने से डेट फंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माने जाते हैं। एक से तीन साल तक के निवेश को डेट फंड, तीन से पांच साल में जरूरत पड़ने वाले पैसों को हाइब्रिड फंड और पांच साल या उसके बाद काम आने वाले पैसों को इक्विटी फंड में रखना चाहिए। नियमित आय या इमरजेंसी फंड के तौर पर बुजुर्ग एक से तीन साल के नजरिये से शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। इनमें एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।

क्या हैं डेट फंड?

डेट फंड, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, जो निश्चित आय वाले साधनों-जैसे कॉरपोरेट व सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। डेट फंड को निश्चित आय वाले फंड या बॉन्ड फंड भी कहते हैं। डेट फंड में निवेश करने पर कम लागत, स्थिर रिटर्न, अधिक लिक्विडिटी और उचित सुरक्षा जैसे फायदे मिलते हैं। डेट फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो नियमित आय चाहते हैं, लेकिन जोखिम से बचते हैं। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं।

बुजुर्गों के पास डेट फंड के विकल्प

सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम वर्गीकरण के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की लगभग 16 श्रेणियां हैं। इनमें ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड और गिल्ट फंड शामिल हैं।

कौन-सा फंड बेहतर?

16 फंडों में से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन-से फंड अच्छे हैं, यह जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश के समय और लक्ष्य पर निर्भर करता है। प्रतिभा गिरीश बताती हैं कि छोटी अवधि के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिक 'इनकम प्लस आर्बिटाज फंड ऑफ फंड' में निवेश कर सकते हैं। यह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड श्रेणी में आता है, जो डेट और आर्बिटाज म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करता है और डेट से बेहतर रिटर्न, इक्विटी जैसे टैक्सेशन और कम उतार-चढ़ाव का फायदा देता है। बुजुर्गों को लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और गिल्ट फंड से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें उतार-चढ़ाव की ज्यादा आशंका है।

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम

- बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफॉल्ट का जोखिम, अगर जारीकर्ता ब्याज या मूलधन चुकाने में असमर्थ हो।
- फंड का रिटर्न महंगाई दर से कम होने पर आपके निवेश को नुकसान पहुंच सकता है।
- आर्थिक अनिश्चितता या नीतिगत बदलाव जैसी बाजार अस्थिरता डेट फंड को प्रभावित कर सकते हैं।
- डेट फंड सुरक्षित हैं, लेकिन वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद ही निवेश करें। क्योंकि किसी निवेश से पहले उसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 137 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका की गरिमा को बचाना होगा

मनोज कुमार अग्रवाल

देश की शीर्ष अदालत के शीर्ष न्यायमूर्ति को लक्ष्य कर एक 72 वर्षीय गैर अपराधिक प्रवृति और चरित्र वाले वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जूता उछालना बेहद गंभीर और असामान्य घटना है लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? असहमति होना अलग बात है लेकिन इस असहमति के प्रतिकार बतौर इस तरह की अपमान जनक प्रतिक्रिया के मूल में छिपे कारणों को तलशना होगा। देश की न्याय व्यवस्था जिस शुचिता और पारदर्शिता का प्रतिबिंब होनी चाहिए क्या वह परिलक्षित हो रहा है? दरअसल पिछले कुछ दशकों में न्यायपालिका के स्वरूप में सुधार के स्थान पर गिरावट दृष्टिगत हो रही है लगातार बैंच मामलों के तथ्यों से इतर उपदेशक बतौर अनावश्यक मनमानी टिप्पणी कर रहीं हैं यदि अदालत में कोई अधिवक्ता मामले के तथ्यों से अलग नजीर दे तो उसे यही अदालत और न्यायमूर्ति समय की बर्बादी करार देते हैं जबकि स्वयं केस के तथ्यों की सीमा को पार कर टिप्पणी करते हैं यह दोहरा रवैया बैंच और बार के बीच टकराव पैदा करता है नुपूर शर्मा व खजुराहो की प्रतिमा समेत कई मामलों में बेंच ने केस के तथ्यों से बाहर अशोभनीय टिप्पणी कर मर्यादा और गरिमा को तोड़ा है। यहां आपको बता दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी कालेजियम से कुछ इने गिने जजों के परिवार के नाती पोते ही जज बनते हैं न्यायपालिका में उच्च पदस्थ होकर मनमानी करते हैं सत्ता और विपक्ष दोनो को खुश रखते हैं और रिटायर्मेंट के बाद का भी सरकारी सीट विभिन आयोगों में बने रहने का अवार्ड पाते हैं।जिस तरह सत्ता धारी दल लगातार वोटर्स को लुभाने के लिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन बनाने में लगे रहते हैं ठीक उसी तरह न्यायपालिका की बेंच सत्ता और विपक्ष के साथ अपना संतुलन बैठा कर चलने के लिए काम करती है। यहां गौरतलब है कि जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही पारदर्शिता और ईमानदारी से नही है वह क्या न्याय करेंगे? वह कहीं न कहीं पूर्वाग्रही होंगे। विषय से हट कर अनाप शनाप टिप्पणी करते हैं न्यायमूर्ति बनकर भी अपनी जाति धार्मिक मान्यता से ऊपर नहीं उठते बल्कि अपने कारनामों के बचाव के लिए इनका कवच ओढ़ लेते हैं। देश की अदालतों में साढे चार करोड़ मुकदमे पेंडिंग है लेकिन एक आतंकी के लिए रात को घर मे अदालत लगाकर आदेश जारी करते हैं एक न्यायाधीश के आवास के कमरे में बोरों में करोड़ों की करेंसी जलती मिलती है लेकिन कानून के हाथ बंधे हुए हैं और उन जज साहब पर कार्यवाही नही होती है। इनके बच्चे विदेशों में पढते है गर्मियों की छुट्टिया मनाने के लिए एक माह अदालत बंद कर देते हैं ये माडर्न राजा हैं जो न्याय के नाम पर इंसाफ़ के नाम पर मनमानी करते हैं।भगवान के लिए भी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं और इसी का परिणाम है कि आम आदमी का भरोसा अदालत और न्यायपालिका से टूट रहा है। हमारा सुझाव है कि देश में सभी नागरिकों से रायशुमारी करानी चाहिए कि नागरिकों को मौजूदा न्यायपालिका और उसके कर्ता धर्ता अदालत जजों पर कितना विश्वास है? मै दावा करता हूं कि नतीजे बेहद भयावह होंगे और इस समूचे सड़ चुके सिस्टम की पोल खोल देंगे। इस देश में यदि मीलार्ड अपना काम समयबद्ध और ईमानदारी से करते तो न भ्रष्टाचार होता न अराजकता होती न सांप्रदायिकता होती न तुष्टिकरण होता इस सबका जिम्मेदार यही काले लबादे में सुरक्षित इमारतों में वातानुकूलित भवनों में बैठे आधुनिक मीलार्ड है जो खुद को भगवान से बड़ा मानते हैं और कभी खेत खलिहान किसान गरीब गाँव चौपाल पंचायत ब्लॉक सार्वजनिक वाहन रेल रोडवेज बस से यात्रा सरकारी स्कूल से पढ़ाई सरकारी अस्पताल में इलाज पुलिस चौकी थाने में पुलिस का व्यवहार तहसील आरटीओ में सरकारी कामके भ्रष्टाचार से कभी दूर का भीवास्ता नही पडा होता है ये लोग न आम जनमानस से आते हैं न आम आदमी की परेशानियां समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने उस माहौल को न देखा न भुगता जिस से नब्बे फीसदी आम आदमी रोजाना भुगतता है झेलता है। ये न्याय की कुर्सी पर बैठ कर कैसे न्याय कर सकते हैं? इस देश के सभी हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों के आवास और उनके परिवार की संपत्ति पर एक साथ प्रभावी जांच कराने की जरूरत है सारी ईमानदारी सामने आ जाएगी बोरों में नोट रखने वाले जज साहब से भी बड़े मगरमच्छ सामने आ सकते हैं लेकिन किसी सत्ता में इतना दम नहीं है जो गौमुख से गंगा की सफाई शुरू कर सके लिख तो और भी ज्यादा सकता हूँ लेकिन इस राजनीतिक सामाजिक न्यायिक तंत्र से ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद नहीं है और ऐसे माहौल में जहां निठारी कांड के करीब बीस बच्चों के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए गरीब मजदूर परिवार उन्नीस साल तक अदालत के चक्कर काटने के बाद आरोपियों को अदालत द्वारा सबूत के अभाव में बरी करने पर ठगे खड़े रह जाते हैं। जहां एक सौ रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी को माथे पर लगा रिश्वत का कलंक हटाने के लिए 47 साल बाद अदालत से न्याय मिलता है लेकिन इस बीच उसकी पत्नी मर जाती है परिवार तबाह हो जाता है। ऐसे एक दो नही हजारों नजीर है जो चीख चीख कर बताते हैं कि न्याय आम आदमी के लिए एक जीवन में हासिल करना टेढ़ी खीर है वास्तव में जज साहब सही कहते हैं एक बारगी भगवान किसी की करुण आर्त पुकार सुन सकते हैं लेकिन अदालत नहीं । लोकतंत्र के चार स्तम्भों में मैं सबसे खराब हालत न्यायपालिका की मानता हूं वकालत के साढे तीन दशक के सफर में मैंने इसे नजदीक से देखा है अनुभव किया है। अभी हमारी न्यायिक प्रणाली में बहुत सुधार की जरूरत है इसमें बहुत पारदर्शिता और बदलाव लाने की जरूरत है।। हमारी न्यायिक व्यवस्था को अधिवक्ता के अप्रिय अपमान जनक व्यवहार से सबक लेकर बदलाव की प्रेरणा लेनी चाहिए।

गलत हुआ तो क्या? वजह जानना जरूरी

आरती कुमारी

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो हुआ, वह पूर्णतः गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोकतांत्रिक देश में विरोध के तरीके और भी बहुत हैं। देश की सर्वोच्च न्याय संस्था के मुखिया के साथ इस तरह की हरकत सीधे-सीधे न्याय प्रकिया पर हमला है। सीजेआई ने भी उदार हृदय दिखाकर नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो निसंदेह न्यायिक अधिकारी के सरल स्वभाव की नई नजीर बनेगा। निसंदेह इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, पर अब जब हो ही गई तो अब इस पर भी चिंतन जरूरी है। न्यायालय देश के प्रत्येक उस व्यक्ति की सबसे बड़ी उम्मीद है जो हर तरह की व्यवस्था से आहत है। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही हो। न प्रशासन सुन रहा हो और न सरकार। तब उम्मीद की एकमात्र रोशनी की किरण यहीं से प्राप्त होने की होती है। न्यायालय द्वारा कहा गया हर एक शब्द पत्थर की लकीर होता है। हर एक शब्द अक्षय बन जाता है। हजारों, लाखों नाउम्मीद लोगों को उस एक शब्द से न्याय की आस बंध जाती है। तभी तो साफ सुनने को मिलता है कि कोई बात नहीं यहां सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट तो मेरी बात सुनेगा। भारत एक धर्मपरायण देश है। विभिन्न प्रकार की धार्मिक आस्थाओं का यहां प्रभाव है। देश का बहुत बड़ा तबका धर्म-कर्म के सार्थक-निरर्थक कथन पर खड़ा होने में देर नहीं लगाता। धर्म के प्रति समर्पण हमारा सामान्य स्वभाव है। भगवतगीता में कहा गया है कि –

श्रद्धावान्ल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।

भाव है कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इन्द्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधनपारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम-शान्ति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह चाणक्य नीति का प्रसिद्ध श्लोक है –

यो धर्मं सत्त्वसंपन्नं सततं चानुपश्यति
न स पापेषु लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा॥"

जो व्यक्ति सत्त्वसंपन्न होकर हमेशा धर्म का पालन करता है, वह कमल के पत्ते की तरह जल से अछूता रहता है, उसी तरह वह पापों में नहीं लिप्त होता। आचार्य चाणक्य के अनुसार, धर्म मनुष्य का स्वाभाविक कर्तव्य और नैतिक आचरण है, जो उसे समाज में अपनी भूमिका निभाने और दूसरों के लिए सही कार्य करने में मदद करता है। धर्म के बिना जीवन निरर्थक है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने यश को अमर कर सकता है, क्योंकि धर्म ही उसे मृत्यु के बाद भी जीवित रखता है। सत्य, प्रिय और हितकर वाणी का प्रयोग ही धर्म है, और दान-पुण्य तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही वास्तविक धर्म है। ऐसे में धर्म के प्रति देश में अगाध आस्था है। इसके देश में बहुत से उदाहरण हैं। युनेस्को की विश्व धरोहरों में अपना विशेष स्थान रखने वाले खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका पर सीजेआई के बयान में कितनी सच्चाई है। इस पर चर्चा करना अब बेमानी है। पर जिस तह से इसका प्रसार हुआ इससे धर्मप्रेमियों में नाराजगी की कोई कमी नही रही। हालांकि यहां यह भी बात गौर करने लायक है कि बयान से विवाद खड़ा होने के बाद सीजेआई ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां इस संदर्भ में थीं कि वह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहां एक बात का ध्यान रखना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जमाना आज सोशल मीडिया का है। मिनटों में एक शब्द पर बवाल हो जाता है। बिना जांचे परखे व्यूज के चक्कर में फॉरवर्ड करने की गति सूर्य की रोशनी से भी तेज गति पकड़ लेती है। जब तक सत्यता सामने आए तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब बात समाज या धर्म की हो तो उसका लाभ लेने वालों की कोई कमी नहीं। आपदा में अवसर की तरह सुप्तप्राय शक्तियां निद्रा त्याग पक्ष-विपक्ष दो धड़ों में खड़ी होने में देर नहीं लगाती हैं। इसलिए निवेदन न्याय प्रणाली से भी है कि जब बात किसी आस्था या धर्म की हो तब शब्दों का चयन किसी तरह के विवाद को जन्म देने वाला न हो। शब्दों का बहुत बड़ा भंडार है। संस्कृत के महाकवि भारवि द्वारा रचित किरातार्जुनीयम् की ये पंक्तियां आज के समय पर बड़ी सार्थक प्रतीत होती है। विदधीत् न क्रियामविवेकः सहसा परमापदां पदम्। इसके अनुसार किसी कार्य को अनायास नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी आपदाओं का परम या आश्रय स्थान होती है।

सीजेआई गवई और राकेश किशोर मामला कहां जाकर थमेगा

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा उसके संविधान और न्यायपालिका में बसती है, जहां समानता, स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालय को इसी आत्मा का रक्षक कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह प्रश्न बार-बार उठ रहा है कि क्या यह रक्षक संस्था सभी समुदायों के लिए समान रूप से न्यायसंगत है? जब मुद्दे बहुसंख्यक समाज, हिन्दू परंपराओं या सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े होते हैं, तो न्यायिक रवैया अक्सर असहज और असंतुलित दिखाई देता है।

जनहित याचिका : उद्देश्य से औपचारिकता तक- भारत में जनहित याचिका (पीआईएल) की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी ताकि समाज के हाशिये पर खड़े लोगों को भी न्याय का दरवाजा खुला मिले। 'लोकस स्टैंडी' की दीवार को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों को न्याय की प्रक्रिया में भागीदार बनाया। किंतु धीरे-धीरे यह औजार राजनीतिक और विमर्शजनित हथियार बन गया। आज अदालतें कई बार ऐसी याचिकाओं को 'पॉपुलिस्ट' या 'पब्लिसिटी-सीकिंग' बताकर खारिज कर देती हैं। इसी पृष्ठभूमि में सीजेआई गवई और अधिवक्ता राकेश किशोर विवाद तथा अश्विनी उपाध्याय की लगातार खारिज होती याचिकाएँ यह संकेत देती हैं कि बहुसंख्यक समाज से जुड़े मुद्दों को न्यायपालिका किस दृष्टि से देखती है। जब कोई वकील समान नागरिक संहिता, अवैध धर्मांतरण या मंदिर प्रबंधन में राज्य नियंत्रण जैसे विषय उठाता है, तो अदालत प्रायः उन्हें "राजनीतिक एजेंडा" बताकर किनारे रख देती है।

हिन्दू विषयों पर अदालत की असहजता- वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने संविधान के मूल सिद्धांतों समानता, धर्मनिरपेक्षता और एकरूप न्याय व्यवस्था को आधार बनाकर दो सौ से अधिक जनहित याचिकाएँ दाखिल कीं। परंतु इन याचिकाओं का परिणाम लगभग एक सा रहा या तो खारिज या टिप्पणी के साथ स्थगन। कई बार आरोप लगता है कि अश्विनी उपाध्याय जैसे वकील 'संपूर्ण समाज' के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन, यह आरोप केवल हिन्दू विषयों अथवा बहुसंख्यक हितों की याचिकाओं तक ही क्यों सीमित है? जब विभिन्न समुदायों, अल्पसंख्यकों, सामाजिक वंचितों या अन्य संवेदनशील वर्गों की सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं राजनीतिक रंग लिए सामने आती हैं, तब अदालत चिंतित या सतर्क नहीं दिखती। इससे न्याय का दोहरा मापदंड की ओर इशारा होता है। वास्तव में यहां सोचने एवं विमर्श का विषय यह है कि ये वही न्यायालय है जोकि अल्पसंख्यक समुदाय, जातीय भेदभाव या आरक्षण जैसे विषयों पर जब सुनवाई करती है, तो अत्यंत संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और समयबद्ध रवैया अपनाती है। आज यही विरोधाभास समाज में न्याय के दोहरे मापदंड की छवि बनाता है।

संवैधानिक धर्म और न्यायपालिका की जिम्मेदारी- भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 14, 15 और 25 में समानता, भेदभाव-निषेध और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इन अनुच्छेदों की चेतना यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से जुड़ा हो, कानून की नजर में समान रहेगा। न्यायपालिका की भूमिका इन अनुच्छेदों की रक्षा करना है, न कि उन्हें समाजशास्त्रीय संतुलन के तराजू में तौलना। यदि न्यायपालिका यह मानकर चलती है कि "बहुसंख्यक समाज स्वतः सशक्त है," तो वह संविधान की मूल आत्मा से भटक जाती है। क्योंकि संविधान ने शक्ति का वितरण धर्म या जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकता की समानता के सिद्धांत पर किया है। न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह समान संवेदनशीलता के साथ हर वर्ग की सुनवाई करे। यदि अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा न्याय का कर्तव्य है, तो बहुसंख्यक की न्यायसंगत माँगों की उपेक्षा भी उतनी ही असंवैधानिक है। यही "संवैधानिक धर्म" (Constitutional Morality) का वास्तविक अर्थ भी है कि न्याय केवल कमजोर के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए समान रूप से सुनिश्चित हो।

संस्थागत असंतुलन और बार काउंसिल की भूमिका- वकीलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी यह असंतुलन दिखाई देता है।

मेष राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, इससे आपके कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। किसी कार्य को पूरा करने में पुरानी कम्पनी का अनुभव काम आएगा।

वृष राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाये रखें, जल्द ही भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालेंगे, बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। लवमेट एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। छात्रों को थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। सफलता के योग बने हुए हैं। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है।

मिथुन राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपनी बातों से किसी को प्रभावित कर देंगे। समाज में किये गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे, जिससे आपको गर्व होगा। शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ होगा। स्टूडेंट अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, जल्द ही सफलता मिलेगी।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका कोई काम जो काफी दिनों से रुका था, आज पूरा हो जाएगा। साथ ही आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ सकता है।

सिंह राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। मानवहित में किये गये कार्यों के कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत पर ध्यान देंगे। व्यवसायिक गतिविधियां मन मुताबिक चलेंगी। काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। अवसर मिलने पर उसका फायदा उठाएं।

कन्या राशिः आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। किसी से बहस की स्थिति बन सकती है, ऐसे में मौन रहना बेहतर होगा। पब्लिक प्लेस पर छवि खराब न होने दें। लवमेट के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होगा।

तुला राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके काम करने के तरीकों से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। बातचीत के दौरान अपनी निजी बातें शेयर न करें। जिस काम की शुरुआत करेंगे, वह समय पर पूरा होगा।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। मित्रों से मन की बात शेयर करने से सुकून मिलेगा। आपको नई जानकारियां भी हासिल होंगी। रिश्तेदार से शुभ संदेश मिलेगा, जिससे खुशी दोगुनी होगी। बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, लेकिन कॉम्पटीशन के दौर में कार्य करने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे और तारीफ करेंगे।

धनु राशिः आज आपका दिन सामान्य रहेगा। निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। भावनाओं में आकर कोई फैसला न लें। ज्यादा काम के कारण थकान हो सकती है।छोटी-छोटी परेशानियां जल्द दूर होंगी। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। व्यापार में मिली जिम्मेदारियों को सफलता से निभाएंगे। फर्नीचर व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा।

मकर राशिः आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। शाम का समय माता-पिता के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिससे अच्छा समाधान मिलेगा। किसी काम की शुरुआत करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना बेहतर होगा। समाज में किये गए कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा। कोई विश पूरी होगी जिससे खुशी मिलेगी।

कुम्भ राशिः आज का दिन परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। काम को लेकर आपके सपने काफी हद तक पूरे होंगे। स्वयं को साबित करने के लिए बेहतर दिन है। परिवार में सामंजस्य से शांति का माहौल रहेगा। प्रकृति के बीच समय बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक होगी।

मीन राशिः आज का समय आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक समस्या हल होगी और रुके काम में गति आएगी। सकारात्मक लोगों की सलाह फायदेमंद होगी। मेहनत का उचित फल जल्द मिलेगा। अफवाहों पर ध्यान न दें। ऑफिसियल यात्रा संभव है, जो शुभ होगी। जीवनसाथी के साथ डिनर प्लान करेंगे। छात्रों के लिए सफलता का दिन साबित होगा, बस थोड़ी और मेहनत करें।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण - मिथिला से मगध तक 'सेमीफाइनल' की होगी जंग

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा हो चुकी है। राज्य की राजनीति एक बार फिर जातीय समीकरण, विकास के दावे और गठबंधनों की रणनीतियों के बीच नई दिशा खोज रही है। 06 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जो बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों को कवर करेगा। यह चरण इसलिए खास है क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा, भाजपा का वैचारिक गढ़ बेगूसराय, और राजद का पारंपरिक क्षेत्र मिथिलांचल शामिल हैं। यह चरण एक तरह से "सेमीफाइनल" कहा जा सकता है, क्योंकि इसके परिणाम राज्य की सत्ता का रुख तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इस चरण में बिहार के मिथिलांचल, तिरहुत, सीमांचल और मगध क्षेत्र आता है, जिनकी राजनीतिक धारा जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन से गहराई से जुड़ी रही है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें शामिल हैं मधेपुरा के आलमनगर, बिहारीगंज, सिहेश्वर (एससी), मधेपुरा। सहरसा के महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, सोनबरसा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान (एससी), गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले। मुजफ्फरपुर के गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहा (एससी), सकरा (एससी), कुढ़नी, कांटी, पारू, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। गोपालगंज के बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे (एससी), हथुआ। सीवान के सीवान, दरौली (एससी), जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंदा, बड़हरिया, गोरियाकोठी, महाराजगंज। सारण के एकमा, मांझी, परसा, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा (एससी), अमनौर, सोनपुर। वैशाली के वैशाली, महुआ, हाजीपुर, लालगंज, राजापाकड़ (एससी), राघोपुर, महनार, पातेपुर (एससी)। समस्तीपुर के कल्याणपुर (एससी), वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा (एससी), हसनपुर। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर, बछवारा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी (एससी)। खगड़िया के अलौली (एससी), खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता। मुंगेर के तारापुर, मुंगेर, जमालपुर। लखीसराय के सूर्यगढ़ा, लखीसराय। शेखपुरा के शेखपुरा, बरबीघा। नालंदा के अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर (एससी), इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत। पटना के मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारीशरीफ, पालीगंज, विक्रम (एससी), मसौढ़ी (एससी)। भोजपुर के संदेश, बरहड़ा, जगदीशपुर, शाहपुर, आरा, अगिआंव (एससी), तरारी। बक्सर के ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर (एससी)। यह भौगोलिक विस्तार बिहार के सामाजिक ताने-बाने की विविधता को दिखाता है। उत्तर में गंडक और कोसी की धरती, मध्य में ऐतिहासिक मगध, और दक्षिण में औद्योगिक मुंगेर और शेखपुरा, सब एक साथ इस चुनावी समर में शामिल हैं। मिथिलांचल (दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर) का इलाका सदैव राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील रहा है। यहां की राजनीति यादव-मुस्लिम-अति पिछड़ा गठजोड़ पर टिकी रही है। 2020 में राजद ने इस इलाके में शानदार प्रदर्शन किया था। तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल में युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया था। दूसरी ओर, नीतीश कुमार ने अपने 'सात निश्चय' और महिला सशक्तिकरण योजनाओं को आधार बनाया है। जदयू के 'मुखिया से मुख्यमंत्री' अभियान ने गांवों में संगठन को मजबूत किया है। इस बार भी जदयू का फोकस महिला मतदाताओं और लाभार्थी वर्ग पर है, विशेषकर सहायता समूहों, छात्राओं और जल-जीवन-हरियाली मिशन से लाभान्वित महिलाओं पर। इस चुनाव में कोसी और कमला नदियों के किनारे बाढ़ और विस्थापन का मुद्दा, युवाओं के पलायन और रोजगार की कमी, शिक्षा संस्थानों की बदहाली (खासकर दरभंगा विश्वविद्यालय क्षेत्र) और एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी लड़ाई है। दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर के 28 विधानसभा क्षेत्रों में राजद को 2020 में 18 सीटें, जबकि एनडीए को 10 सीटें मिली थीं। इस बार भाजपा और जदयू दोनों ने अपनी रणनीति बदली है। भाजपा हिन्दू वोटों के ध्रुवीकरण और प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि जदयू स्थानीय विकास कार्यों को केंद्र में रख रही है। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली को बिहार की राजनीति का हृदय कहा जाता हैं। गंडक क्षेत्र का यह इलाका भाजपा और जदयू के पारंपरिक प्रभाव वाला रहा है। गोपालगंज और सीवान में राजद की जड़ें गहरी हैं, लेकिन सारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक भाजपा का सांगठनिक नेटवर्क बहुत मजबूत है। राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजप्रताप यादव का इस इलाके से भावनात्मक जुड़ाव अब भी कायम है। राघोपुर और महुआ जैसी सीटें यादव-मुस्लिम समीकरण से बंधी हुई हैं। लेकिन वैशाली, सारण और गोपालगंज के शहरी क्षेत्रों में भाजपा की विचारधारा ने नए मतदाताओं को आकर्षित किया है। छपरा और हाजीपुर में एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सीवान-गोपालगंज में राजद बनाम भाजपा का सामाजिक मुकाबला होगा। युवा वोटर और प्रथम बार मतदाताओं की भूमिका अहम होगी। भाजपा का जोर केंद्र की योजनाओं और पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने का है। वहीं राजद का फोकस सामाजिक न्याय और गरीबों की आवाज होगी। जबकि जदयू की रणनीति, जातीय संतुलन और महिला वोट रहेगी। तिरहुत क्षेत्र की राजनीति हमेशा 'जातीय रसायन' से तय होती है। राजपूत, भूमिहार, यादव और मुसलमान चारों वर्ग यहां निर्णायक हैं। 2020 में एनडीए ने इस क्षेत्र की 42 सीटों में से 27 जीती थीं। इस बार माहौल कुछ बदला है, भाजपा को एलजेपी (रामविलास पासवान गुट) की दखल से चुनौती मिल सकती है, खासकर वैशाली और समस्तीपुर के इलाकों में। मगध, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, यह क्षेत्र जातीय रूप से सबसे विविध है। यहां का सामाजिक समीकरण है भूमिहार और ब्राह्मण यह भाजपा के पारंपरिक समर्थक हैं। वहीं यादव, राजद का वोट बैंक है। यहां कुशवाहा, पासवान और अति पिछड़ा वर्ग निर्णायक होते हैं। यहां के मुसलमान राजद और वामदलों के साथ होते हैं। नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा इस चरण में शामिल है। यह उनके लिए प्रतिष्ठा की सीटें हैं। दूसरी ओर, पटना ग्रामीण और भोजपुर बेल्ट भाजपा के मजबूत किला माना जाता है। बेगूसराय में भाजपा की विचारधारा और संघ की शाखाओं का गहरा असर है। यह इलाका इस बार भाजपा-जदयू गठबंधन के लिए सबसे बड़ा परीक्षण क्षेत्र होगा। यहां के मतदाता विकास को तो देखते हैं, पर स्थानीय नेतृत्व और जातीय समीकरण दोनों पर विचार करते हैं। बेरोजगारी और औद्योगिक ठहराव (मुंगेर, बेगूसराय, बक्सर में), कृषि संकट और नदी तटबंध की समस्या (खगड़िया, बेगूसराय), बाढ़ और जलजमाव (पटना ग्रामीण बेल्ट), कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा होगा। 2020 में एनडीए ने यहां 40 में से 27 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार विपक्ष ने रणनीति बदली है। महागठबंधन ने कांग्रेस और वामदलों को सक्रिय भूमिका में रखा है। सीपीआई-एमएल ने भोजपुर और बक्सर में अपने जनाधार को मजबूत किया है। इस चरण में चुनावी लड़ाई पूरी तरह दोध्रुवीय है। एनडीए (भाजपा + जदयू + हम) बनाम महागठबंधन (राजद + कांग्रेस + वामदल)। हालांकि कुछ सीटों पर एलजेपी (पासवान गुट) और वीआईपी (मुखिया गुट) के उम्मीदवार त्रिकोणीय मुकाबला बना सकता है। एनडीए की रणनीति होगी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरा और नीतीश के विकास मॉडल का संयोजन। लाभार्थी योजनाएं (हर घर नल, उज्ज्वला, पीएम आवास) होगी। महिला वोट बैंक पर विशेष फोकस रहेगा। एनडीए एकता का संदेश देगा कि "डबल इंजन सरकार से डबल विकास" हुआ है। महागठबंधन की रणनीति होगी सामाजिक न्याय और बेरोजगारी का मुद्दा। महंगाई, भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों पर हमला। वाम दलों की मदद से ग्रामीण इलाकों में मजबूती। "युवाओं की सरकार" और "न्याय यात्रा" का नारा। एलजेपी (पासवान गुट) का बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया में प्रभाव रहेगा। वीआईपी (मुखिया गुट) का मधेपुरा और सहरसा के कुछ इलाकों में असर रहेगा। सीपीआई-एमएल भोजपुर, बक्सर, आरा और जहानाबाद के इलाकों में सक्रिय रहेगा। इन दलों की उपस्थिति कई सीटों पर निर्णायक हो सकती है, खासकर जहां जीत-हार का अंतर 5000 वोटों से कम रहता है। बिहार की राजनीति में अब महिला वोटर सिर्फ "सहायक" नहीं, बल्कि "निर्णायक" बन चुकी हैं। 2020 के चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से 3.5% अधिक रहा था। नीतीश कुमार ने इस वर्ग पर गहरा निवेश किया है, साइकिल और पोशाक योजना, आरक्षण में 50% तक की भागीदारी, आंगनवाड़ी और सहायता समूहों को सशक्तिकरण। राजद ने भी इस बार "महिला न्याय मंच" बनाकर प्रचार तेज किया है। तेजस्वी यादव की पत्नी रेचल यादव और राबड़ी देवी महिला रैलियों में सक्रिय हैं।

सुभाषित — जो मनुष्य समयानुकूल तुरन्त विचार कर सकता है और उसपर आचरण करता है, वह पुरुष सुखको प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्यका नाश कर देता है। ❐ भीष्म पर्व

सोयाबीन उत्पादकोंके दबावमें ट्रम्प

ट्रम्पपर अमेरिकी सोयाबीन उत्पादकोंका जबरदस्त दबाव है। ट्रम्प प्रशासनने घोषणा की है कि वह प्रभावित किसानोंको १२ अरब डालरतककी आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। यही वजह है कि ट्रम्प भारतपर लगातार टैरिफके जरिये दबाव बना रहे हैं। परन्तु भारत अमेरिकी सोयाबीनके लिए अपने बाजार नहीं खोल रहा है।

❐ पुष्परंजन

आलू-प्याज जैसी फसल जब मंडीसे भी कोई नहीं उठाता, किसान क्या करता है। किसान उसे ट्रैक्टर ट्रालीपर लादकर मोहल्ले-मोहल्ले माइकसे आवाज लगाता है-पचास रुपयेके पांच किलो आलू ले लो। प्याज ले लो। इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपतिकी हालत ठीक उसी किसानकी तरह हो गयी है। ट्रम्प भी 'सोयाबीन ले लो' की विश्वव्यापी गुहार लगा रहे हैं। ट्रम्पपर अमेरिकी सोयाबीन उत्पादकोंका जबरदस्त दबाव है। ट्रम्प प्रशासनने मंगलवारको घोषणा की कि वह प्रभावित किसानोंको १२ अरब डालरतककी आपातकालीन सहायता प्रदान करेगा। कृषिमंत्री सन्नी पर्ड्यूने कहा कि यह योजना, यूएसडीएके कमोडिटी कार्यक्रमके माध्यमसे किसानोंको अस्थायी राहत प्रदान करेगी। इस बीच ट्रम्प चीन, यूरोपीय संघ और अन्य देशोंके साथ दीर्घकालिक नीतिपर बातचीत करेंगे। १२ अरब डालरका भुगतान बिना अमेरिकी कांग्रेसकी स्वीकृतिके। यह भी ट्रम्पके लिए मुश्किल हालात हैं।

> **ट्रम्पकी व्यापार टीम चाहती है कि भारतके कृषि बाजारको अमेरिकी उत्पादोंके लिए पूरी तरहसे खोल दिया जाय। लेकिन भारत सरकार ट्रम्पकी खुशीके लिए किसानोंका अहित नहीं कर सकती। अमेरिकी कृषि उत्पादोंके लिए बाजार खोलनेके सवालपर मोदी सरकार देशके खिलाफ नहीं जायेगी। वर्ष २०२०-२४ में भारतमें लगभग १३०.५ लाख मीट्रिक टन सोयाबीनका उत्पादन था, जो देशके कुल तिलहन उत्पादनका लगभग एक-तिहाई है। ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और चीनके बाद भारत दुनियाका पांचवां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बन गया है।**

ट्रम्पने अपने पहले कार्यकालके दौरान, किसानोंको २३ अरब डालरसे अधिकको व्यापार सहायता देनेके लिए सीसीसीका इस्तेमाल किया था। कमोडिटी क्रेडिट कारपोरेशन (सीसीसी), अमेरिकी कृषि विभाग 'यूएसडीए' की वित्तपोषण इकाई है। यह अमेरिकी राजकोषसे ३० अरब डालरतक उधार ले सकता है और किसी भी शुद्ध घाटेकी भरपाई बादमें यूएस कांग्रेस (संसद) की हामीसे विनियोजित की जाती है। जबसे ट्रम्प आये हैं, सीनेट पांच बार वित्तीय प्रस्ताव खारिज कर चुका है। इलिनोइस विश्वविद्यालय अर्बाना-शैंपेनके एसोसिएट प्रोफेसर जोनाथन कोप्पेसने एक मेलके जरिये जानकारी दी-इस फंडसे जो पैसा निकलता है, हर साल शरद ऋतुमें फिरसे भर दिया जाता है, लेकिन शटडाउनके कारण इसे फिरसे नहीं भरा गया है। अर्थात् यहां खजाना खाली है। ट्रम्पने बार-बार कहा है कि हमारा प्रशासन टैरिफसे होने वाली आयका इस्तेमाल किसानोंकी सहायताके लिए करेगा। लेकिन किसानोंको इस तरहके सीधे भुगतानकी वैधानिक सीमा ३५ करोड़ डालर है। जरूरत १२ अरब डालरकी है और ट्रम्पकी क्षमता ३५ करोड़ डालर देनेभरकी है। मामला, सचमुच बुरा फंसा है। अमेरिकी सोयाबीनके सबसे बड़े विदेशी खरीदार चीनने आखिरी बार मई, २०२५ में अमेरिकी सोयाबीन खरीदी थी। सितम्बरमें शुरू हुए इस फसलके मौसमके लिए उसने कोई सोयाबीन नहीं खरीदी है। राष्ट्रपति ट्रम्पने सोया किसानोंको समझाया कि हम अब भी पेइचिंगके साथ सोयाबीन समझौतेका प्रयास कर रहे हैं। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक, सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीजके स्कॉट कैनेडीने सोमवारको एक सार्वजनिक कार्यक्रममें कहा कि चीनके पास दुनियाभरसे सोयाबीन खरीदनेका ऑप्शन रहता है। चीनपर ५५ प्रतिशत टैरिफ लगाना अमेरिकी अर्थव्यवस्थाके लिए विशेष रूपसे अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि टैरिफके स्तरको फिरसे कम करनेकी आवश्यकता है। चीनी राष्ट्रपति शीने ट्रम्पको सबक सिखानेके वास्ते ब्राजील और अर्जेंटीनाको सोयाबीनका आर्डर देना शुरू किया है। चीनी वस्तुओंपर ट्रम्पके टैरिफके जवाबमें, चीनने अप्रैलमें अमेरिकी सोयाबीनपर २५ प्रतिशत शुल्क लगाया, जिससे उनकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता और कम हो गयी। चीनके अलावा अमेरिकी सोयाबीनके शीर्ष आयातकोंमें मेक्सिको, यूरोपीय संघ, जापान और इंडोनेशिया शामिल हैं। अमेरिकी किसान वियतनामसे लेकर नाइजीरियातक खरीदारोंकी तलाश कर रहे हैं। पिछले माह आयोवाके रिपब्लिकन गवर्नर किम रेनॉल्ड्स, जो सोयाबीनकी खेतीपर अत्यधिक निर्भर एक अमेरिकी राज्य है, एक प्रतिनिधिमंडलके साथ भारत आये थे, जिसमें आयोवाके कृषि सचिव माइक नाइग और राज्यके कृषि और व्यावसायिक नेता शामिल थे। इलिनोइस सोयाबीनका प्रमुख उत्पादक राज्य है, लेकिन आयोवा, नेब्रास्का और मिनेसोटा भी बड़े उत्पादक हैं। ट्रम्पकी व्यापार टीम चाहती है कि भारतके कृषि बाजारको अमेरिकी उत्पादोंके लिए पूरी तरहसे खोल दिया जाय। लेकिन भारतमें किसान वोट बैंकको ट्रम्पकी खुशीमें आहुति देनेका जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती। इसलिए अमेरिकी कृषि उत्पादोंके लिए बाजार खोलनेके सवालपर मोदी सरकार कोई फैसला जल्दबाजीमें नहीं लेना चाहती। वर्ष २०२३-२४ में भारतमें लगभग १३०.५ लाख मीट्रिक टन सोयाबीनका उत्पादन होनेका अनुमान लगाया गया था, जो देशके कुल तिलहन उत्पादनका लगभग एक-तिहाई है। परिणामस्वरूप, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और चीनके बाद भारत, दुनियाका पांचवां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बन गया है। फिर भी भारतने २०२३-२४ में ६.२५ लाख टन सोयाबीनका आयात किया था। भारतमें सोयाबीन उगानेवाले प्रमुख राज्य मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना हैं। सोयाबीनका सेवन दूधके विकल्पके रूपमें पीने या पूरकके रूपमें भी करते हैं। पौष्टिक होनेके साथ-साथ सोयाबीनके कुछ अन्य लाभ और उपयोग भी हैं। इसे परिष्कृत करके सोया तेल निकाला जाता है और इसका उपयोग पर्यावरणके अनुकूल ईंधन, मोमबत्तियां, क्रेयॉन और इंजन लुब्रिकेंट बनानेके लिए किया जाता है। वर्ष २०२५ की शुरुआतसे भारतके पड़ोसी देश बंगलादेशने अमेरिकासे ४,००,००० मीट्रिक टनसे ज्यादा सोयाबीनका आयात किया है। इसी तरह जून, २०२५ में, वियतनामने अमेरिकी सोयाबीन निर्यात परिषदके साथ एक समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर किये, जिसमें सोयाबीन, मक्का और गेहूं सहित १.४ अरब डालरसे अधिकके अमेरिकी कृषि उत्पाद खरीदनेका संकल्प लिया गया। अमेरिकी सोयाबीन एसोसिएशनके एक प्रतिनिधिमंडलने अफ्रीकामें मछलीके चारेमें सोयाबीनके उपयोगको बढ़ावा देने और पश्चिम अफ्रीकी देशको एक प्रमुख कृषि व्यापार भागीदारके रूपमें पुन: स्थापित करनेके लिए अगस्तमें नाइजीरियाका दौरा किया था। ३५ प्रतिशत सोयाबीनकी पैदावार वाला ब्राजील नंबर वन पायदानपर है। अमेरिका २८ प्रतिशत, अर्जेंटीना १२ प्रतिशत, चीन पांच प्रतिशत, भारत तीन प्रतिशतके आसपास हैं। लेकिन अमेरिकी किसान अब सोयाबीनकी खेतीका रकबा घटाने लगे हैं।

यूएसडीएका अनुमान है कि विपणन वर्ष २०२५-२६ के लिए सोयाबीनकी बुवाई ३१ लाख एकड़ घटकर ८४ लाख एकड़ रह जायगी। इस कमीके बावजूद पैदावार ५०.७ बुशल प्रति एकड़से बढ़कर ५२.५ बुशल प्रति एकड़ होनेकी उम्मीद है। एक बुशल गेहूं या सोयाबीन २७.२२ किलोग्रामके बराबर होता है। सोयाबीन किसान जिस तरह ट्रम्पके गलेकी हड्डी बन गये, संभव है नवम्बर, २०२६ के मिड टर्म इलेक्शन आते-आते सत्तारूढ़ रिपब्लिकन अलोकप्रिय हो जाय तो क्या, भारतीय रणनीतिकार ३ नवम्बर, २०२६ तक ट्रम्प प्रशासनके जरिये होनेवाले कृषि-व्यापार समझौतेको टालते रहना चाहते हैं। ऐसा होना भी चाहिए!

सिमटते अन्त्योदय संकल्प

अरबोंकी बहुसंख्यक संख्याके साथ गरीबोंके मूल जीविकााधिकारोंके हननका सत्य देशकी अर्थसंपन्नताको विरोधाभासी बनाया जा रहा है। आर्थिक विकासका तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्षसे है। शासनको इस दिशामें निर्विवाद विचार-विमर्श करना होगा।

❐ विकेश कुमार बडोला

कुछ दिन पहले एम३एम हुरुन इंडियाने भारतके सबसे ज्यादा अमीर लोगोंकी २०२५ की सूची जारी की है। सूचीके अनुसार इस वर्ष देशमें अरब उद्यमियोंकी संख्या ३५८ हो गयी। धनिकोंमें प्रथम स्थानपर हैं मुकेश अंबानी और उनके परिवारके पास ९.५५ लाख करोड़की संपत्ति है। दूसरे स्थानपर हैं गौतम अडानी और उनका परिवार, जो ८.१५ लाख करोड़की संपत्तिपर अपने स्वामित्ववाले शेयरधारक हैं। पिछले कई वर्षोंसे ये दोनों उद्योगपति सर्वोच्च धनी भारतीयोंकी सूचीमें एकता स्थान परिवर्तन करते हुए प्रथम और द्वितीय स्थानपर स्थापित हैं। इस बार तीसरे स्थानपर हैं प्रकाश नादर गणतंत्र, जिसमें पहली बार तीसरे सबसे अमीर भारतीय होनेका अवसर प्राप्त हुआ है। इनके पास २.८४ लाख करोड़की संपत्ति है। नव सूचीमें वे भारतके सबसे अमीर और शीर्ष दस धनिकोंमें सबसे युवा ४४ वर्ष के हैं। चेन्नई रेजिडेंट कैसल पैलेसके संस्थापक ३१ सालके श्रीनिवास श्रीनिवासन २१,१९० करोड़ रुपयेकी संपत्तिके साथ सबसे युवा अमीर बने हैं। सूचीमें सूचीबद्ध ३५८ अरबपतियोंके पास जो चल-अचल सम्पत्तियां और सम्पत्तियां हैं, उनकी कुल कीमत भारतीय संपत्तिके लगभग सभी हिस्सोंके बराबर है। विश्वमें सबसे अमीर देश, पिछले कई तिमाहियोंसे निरन्तर पांच प्रतिशत मूल्य वृद्धिके साथ पुष्ट होती भारतीय अर्थव्यवस्था, वस्तु एवं सेवा करकी अधिकतम क्षमता और दो कम कीमतकी करकी घोषणाके बाद, भारतमें अरब बौद्धोंकी संख्याका समाचार एक व्यापक दृष्टिकोणके साथ तो देशवासियोंको गौरवबोधसे संतृप्त कर सकता है, अन्य अरब वैज्ञानिकोंकी तुलनामें जब जीविका हीन और जीविकाके दोनों प्रकारके प्रमुख निर्धनोंकी वास्तविकता सम्मुख सामने आती है तो अर्थभेदका दुर्बोधन भी होता है। यह सत्य देशमें धनिकों निर्धनोंके मध्यमें बढ़ते वास्तविक अमूर्तका दोष भी दर्शाता है। देशमें श्रमिक वर्ग निम्न मध्यम परिवारसे संबंध बनाये रखनेवाली अधिलेखित आर्थिक रूपमें अब भी स्वावलंबी नहीं बनी है। इस कुल मानवसंख्यामें जो जीविका अनुपयोगी हैं, वे तो अर्थपरम्परासे जुड़े हुए हैं। आज भी लघु-दीर्घ-मध्यममें कई निजी कर्मचारी, रजिस्ट्रार, अंशकालिक कर्मचारियोंके संयुक्त जीविकाका संकट खड़ा हो गया है। कई कर्मचारी कार्य करते हैं, लैपटॉप भी वेतन विलंब और वेतनभोगीसे यात्रा करते हैं। शासन द्वारा स्थापित श्रमिक न्यायालय एवं तंत्र नि:शक्ती बनाये गये स्टॉक हैं। वर्तमानमें आशासाकीय निजी कर्मचारियोंके निर्धारित जीविका अधिकार, वेतन और रोजगारके अधिकार और कई अन्य सहायक प्रोत्साहन संस्थागत अधिकार गहन संकटमें हैं। निजी और निजी कम्पनियोंके साथ लघु कार्य अनुबंध, एकल स्वतंत्र कर्मचारी और अन्य क्रेता-विक्रेताओंके पदसे जुड़े लोगोंको एक निर्धारित समयपर उनका वेतन नहीं मिलता है। वर्षोंतक वे एक ही कीमतपर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। इसके विपरीत ऐसे करोड़ों-करोड़ कर्मचारी, बेरोजगार, रोजगाररत लोगोंकी तुलनामें लाखोंकी संख्यामें श्रमिक कर्मचारियोंका मूल वेतन और सहायिकियां भिन्न-भिन्न हैं। पिछले दिनों ही कैनेडरिया शासकने फार्ची कर्मचारियोंके नाममात्रमें वृद्धि की है। इस परिस्थितिमें शासनके संबंधमें स्वामित्वकी कमी हो जाती है, क्योंकि जब उद्योगके स्वामित्व और सेवाओंके मूल्यमें कमी होती है तो उद्योगके स्वामित्व और स्वामित्वके स्वामित्वमें कमी होती है, लेकिन वस्तु और सेवा करके कम मूल्यके तहत वस्तु और सेवा करके बननेकी आवश्यकता होती है। यदि शा.शा.शा. ने केन्द्रमें कर्मचारियोंके कल्याणका ध्यान रखा तो केन्द्रमें कर्मचारियोंके मूल वेतन और वेतनमें वार्षिक नियमित वृद्धि क्यों नहीं हुई। क्या दस्तावेजी कर्मचारी और निजी क्षेत्रमें आवश्यक वस्तु एवं सेवाएं और विलासी वस्तु-सेवाओंके मूल्यमें अंतर होता है। जब निजी क्षेत्रमें कर्मचारियोंके वेतन और सहायक भत्तोंके भंडारके लिए स्मारक-सेवाओंका मूल्य एक होता है तो फिर निजी क्षेत्रमें रखे गये कर्मचारियोंके वेतन और सहायक भत्तोंके वर्षोंसे निर्मित स्मारक-सेवाओंका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है। निजी क्षेत्रके सक्षम, सक्षम और अर्थसंपन्नके लिए कर्मचारी-कम्पनियोंको अपने कर्मचारियोंका आर्थिक-मौद्रिक कल्याण करनेके लिए प्रेरित-प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जा रहा है। उद्योग जगत के पूंजीपति-कम्पनी स्वामियोंको दंड का पालन न करनेके लिए कर्मचारियोंके साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है। अरबोंकी बहुसंख्यक संख्याके साथ गरीबोंके मूल जीविकााधिकारोंके हननका सत्य देशकी अर्थसंपन्नताको विरोधाभासी बनाया जा रहा है। आर्थिक विकासका तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्षसे है। शासनको इस दिशामें निर्विवाद विचार-विमर्श करना होगा।

हालांकि गत दस-ग्यारह वर्षोंमें देशमें सर्वोच्च निर्धनताकी परिभाषामें उल्लेखनीय सुधार भी शामिल हैं। सैकड़ों लोग केन्द्रीय शासनकी अनेक जन-कल्याणकारी योजनाएं, गरीबी रेखासे नीचे गरीबीसे मुक्तिकर जीवनकी अंतिम आवश्यकताएं प्राप्त करनेमें सफल लोग भी शामिल हैं। ऐसे जन-कल्याणका वितरण भारतके मूल वास्तविक निवासियोंकी तुलनामें अवैध घुसपैठ कर आया है और वर्षोंसे भारतमें रह रहे विदेशियोंको अधिक है। इन ऑर्केस्ट्राकी स्थापना न हो, शासनको इस दिशामें भी कुछ क्रांतिकारी कार्यकारी निर्णय लिया जायगा। जब देश-दुनियामें भारतकी अर्थव्यवस्थामें वृद्धिके कारण अच्छे-बुरे दोनों प्रकारके प्रभाव पैदा हो रहे हैं, तब भारतके अरब निवेशकोंकी संख्यामें भी वृद्धिका समाचार प्रत्यक्ष रूपमें है तो लोगोंको नुकसान होता है और उन्हें देशके संदर्भमें गौरवानुभूतिसे भी जोड़ा जाता है। विभिन्न खंड अरबकी जनगणनाके साथ देशमें जीवनकी मुख्य आवश्यकताओंके लिए गरीबों और निजी क्षेत्रोंमें जीविकोपार्जनके लिए संघर्ष करना पड़ता है, श्रमजीवियोंके दर्जनों निम्न मध्य जातिके लोगोंको उनका यथोचित पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। श्रमिक श्रमिक प्रतिदिन नये-नये धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल एसोसिएट्स एसोसिएशनके आगमनके बाद सेवा प्रदाता सूचना-प्रौद्योगिकीके क्षेत्रमें भी लाखों लोगोंके सामान्य और विशिष्ट कार्य मूल्यांकनसे जुड़े हुए सामान या तो समाप्त हो गये हैं या फिर शेष संकटसे घिरी हुई हैं। निजी क्षेत्रमें एक्जीक्यूटिव घंटोंमें तो निरन्तर वृद्धि जारी है, पोर्टफोलियोमें पोर्टफोलियो और निवेशकोंका प्रोत्साहन पहलेकी तरह अत्यंत सीमित है। इन रिजालैंडमें अरब निवेशकोंकी संख्यामें हो रही वृद्धि हो रही है या उद्योगकी निरन्तर प्रगति, सार्वजनिक जीवन बोधको अंत्योदयके अनुभवसे शुरू की गयी है।

आत्मबोध

दक्षिणेश्वर काली मंदिर

❐ भवानी बंदोपाध्याय

देशमें कई ऐसे शानदार मंदिर हैं, जो सदियोंसे लोगोंकी आस्थाका केन्द्र रहे हैं। हिन्दू धर्ममें मां कालीको शक्तिकी देवी माना जाता है, इन्हींमें से एक दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है। यह मंदिर कोलकातासे थोड़ी ही दूरीपर, गंगा नदीके पूर्वी किनारेपर बसा है। मां कालीको समर्पित यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्थाका केन्द्र है, बल्कि बंगालकी संस्कृति और कलाको भी दर्शाता है। मंदिरकी सुंदर बनावट और शांत वातावरण लोगोंको आकर्षित करता है। दक्षिणेश्वर मंदिरकी नींव १९वीं शताब्दीमें रानी रासमणिने रखी थी। रानी रासमणि काशी जाकर पूजा करना चाहती थीं, लेकिन एक रात मां कालीने उन्हें सपनेमें दर्शन देकर यहीं गंगा किनारे एक भव्य मंदिर बनानेको कहा। इसके पश्चात उन्होंने लगभग २०-२५ एकड़ जमीन खरीदी और साल १८४७ में मंदिर निर्माण शुरू हुआ। लगभग आठ साल बाद ३१ मई, १८५५ को मंदिरका उद्घाटन हुआ। इस अवसरपर एक लाखसे ज्यादा ब्राह्मणोंको आमंत्रित किया गया था। मां कालीका यह दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालकी नवरत्न शैलीमें बना है, जिसमें नौ गुंबद हैं। मुख्य मंदिर तीन मंजिला है। मंदिरके गर्भगृहमें मां कालीका रूप भवतारिणीके रूपमें विराजमान है। मूर्तिमें मां काली, भगवान शिवके वक्षपर खड़ी हैं और यह चांदीके कमलपर स्थापित है, जिसमें १००० पंखुड़ियां हैं। मंदिर परिसरमें १२ छोटे-छोटे शिव मंदिर हैं, जिनमें काले पत्थरके शिवलिंग स्थापित हैं। इसके अलावा यहां एक राधा-कृष्ण मंदिर भी है, जो श्रद्धालुओंके आकर्षणका केन्द्र है। दक्षिणेश्वर मंदिर केवल पूजाका स्थान ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधनाका भी केन्द्र है। इस मंदिरमें महान संत श्रीरामकृष्ण परमहंसने १४ सालतक साधना की थी। मंदिर परिसरमें स्थित पंचवटी, बकुलतला घाट और नहबात खाना जैसी जगहें उनकी साधनासे जुड़ी यादें संजोये हुए हैं। कोलकातामें दक्षिणेश्वर काली मंदिर ५१ शक्तिपीठोंमेंसे एक है। यहां आनेवाले श्रद्धालुओंपर मांकी असीम कृपा बनी रहती है। लोग यहां रोग, कष्ट और मनकी परेशानीसे मुक्तिकी कामना करते हैं और देवीसे रोग-दोषसे मुक्ति, सुख-समृद्धिकी प्रार्थना करते हैं। प्राचीन कहानीके अनुसार माता सतीने अपने पिता दक्षके यज्ञमें अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिये थे। यह देखकर भगवान शिव बहुत दुखी हुए और माता सतीके शरीरको उठाकर पूरे ब्रह्मांडमें घूमने लगे। इससे सृष्टिका संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णुने अपने सुदर्शन चक्रसे माता सतीके शरीरको टुकड़ोंमें बांट दिया। जहां-जहां उनके शरीरके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर उस जगहपर बना है, जहां माता सतीके दाहिने पैरकी अंगुलियां गिरी थीं। इसलिए यह जगह बहुत पवित्र और शक्तिशाली मानी जाती है।

मोदी-स्टार्मर वार्ता

इस वर्ष जुलाईमें भारत और ब्रिटेनके बीच मुक्त व्यापार समझौतेपर हस्ताक्षरके बाद तीन महीनेके अन्दर ही ब्रिटेनके प्रधान मंत्री कीर स्टार्मरका अपने बड़े प्रतिनिधिमण्डलके साथ भारतके दो दिवसीय दौरेपर आना दोनों देशोंके बीच सम्बन्धोंकी प्रगाढ़ता और बढ़ते आपसी भरोसेका मजबूत प्रमाण है। स्टार्मरका यह दौरा ऐसे समय हुआ है, जब भारत और अमेरिकाके बीच छिड़े टैरिफ जंगसे आपसी रिश्तोंमें कटुता उत्पन्न हुई है। इससे पूरी दुनिया विशेष रूपसे अमेरिकाको बड़ा सन्देश गया है। महाराष्ट्रके राजभवनमें गुरुवारको प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटिश प्रधान मंत्री स्टार्मरकी गर्मजोशीके साथ मुलाकात और द्विपक्षीय सम्बन्धोंको और मजबूत बनानेसे सम्बन्धित मुद्दोंपर भी सार्थक वार्ता हुई। स्टार्मरने घोषणा की है कि ब्रिटेनके नौ विश्वविद्यालयोंके परिसर भारतमें खुलेंगे। स्टार्मर और मोदीने राजभवनमें बातचीतके दौरान ट्रेड एग्रीमेण्टपर हस्ताक्षर भी किये। मोदीने कहा कि इस समझौतेसे दोनों देशोंके बीच आयात आसान होगा। इससे कारोबार बढ़ेगा और युवाओंको रोजगार भी मिलेंगे। दोनों नेताओंमें बातचीतमें व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा जैसे मुद्दोंपर सार्थक वार्ता हुई। साथ ही दोनों नेताओंने 'विजन २०३०' के तहत भारत-ब्रिटेनके रिश्तोंको मजबूत बनानेपर भी जोर दिया। स्टार्मरने यह भी कहा कि भारतकी सफलतामें ब्रिटेन भागीदार बनना चाहता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम भारतकी आर्थिक और वित्तीय राजधानी मुम्बईमें मिल रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि भारतका लक्ष्य २०२८ तक दुनियाकी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। मुक्त व्यापार समझौता आर्थिक विकासको बढ़ावा देनेवाला लांच पैड है। मोदीका विजन २०४७ तक भारतको विकसित देश बनाना है। इसीलिए मैं इस सप्ताह अपने साथ रिकार्ड १२६ ब्रिटिश व्यवसायोंको भारत लाया हूं। प्रधान मंत्री मोदीने कहा कि भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार हैं। हमारे सम्बन्धोंकी नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानूनके शासन जैसे साझा मूल्योंमें निहित है। भारत और ब्रिटेनके बीच यह बढ़ती साझेदारी वैश्विक स्थिरता और आर्थिक प्रगतिके लिए महत्वपूर्ण आधार रही है। वस्तुत: ब्रिटेनके प्रधान मंत्री स्टार्मरकी यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जायगी। इससे दोनों देशोंके बीच आपसी रिश्तोंको नयी ऊंचाई मिलेगी और आपसी सहयोगका दायरा भी बढ़ेगा।

बेटियोंको बड़ी नसीहत

प्राचीन समयसे शिक्षाका केन्द्र रहे काशीसे उत्तरकी राज्यपाल आनन्दी बेन पटेलने छात्र-छात्राओंको जो सन्देश दिया है वह सराहनीय और उन्हें प्रगति पथपर आगे बढ़नेकी प्रेरणा देनेवाला है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके संसदीय क्षेत्र वाराणसीमें आयोजित काशी विद्यापीठके दीक्षान्त समारोहमें कुलाधिपतिकी हैसियतसे राज्यपालने महिलाओं और बेटियोंकी सुरक्षापर चिन्ता व्यक्त करते हुए यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वे कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें, जिससे उनका भविष्य सुखमय और सुरक्षित रहे। आजके दौरमें जिस तरहकी समाजमें विकृति आ गयी है उसे देखते हुए बेटियोंको अत्यधिक सतर्क और सजग रहते हुए लिव इन रिलेशनका रास्ता न चुननेकी नसीहत उचित और अनुकरणीय है। राज्यपालका यह कहना भी बेटियोंके लिए विचारणीय है कि यदि बेटियां लिव इन रिलेशनमें जायंगी तो उनकी घर-गृहस्थी तो बर्बाद होगी ही, उनके ५०-५० टुकड़े भी हो सकते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आयी हैं, जो बेहद कष्टदायी है। इनसे सबक लेनेकी जरूरत है। आजका समाज ऐसा है जो आम खाकर गुठलियां फेंक देता है। इस सम्बन्धमें शिक्षण संस्थानों और परिवारकी भी महती जिम्मेदारी है कि बेटियोंको लिव इन रिलेशनके दुष्परिणामोंसे आगाह करें। विश्वविद्यालयोंमें छात्राओंको जागरूक किया जाना चाहिए। लिव इन रिलेशनमें रहनेवाली ऐसी तमाम लड़कियां हैं जो नाबालिग थीं और गर्भवती थीं, जिनका इस्तेमाल किया गया था और फिर छोड़ दिया गया था। ऐसी बेटियोंको न तो ससुराल पक्षने अपनाया, न ही मायके पक्षने और इनका जीवन नर्क बनकर रह गया। गुमराह हो चुकी और लिव इन रिलेशनसे खुशहाल जीवनका सपना संजो रही ऐसी बेटियोंको जागरूक करनेकी जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी शिक्षण संस्थानों और परिवारकी है। बेटियोंको भी आत्मसम्मानको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी तभी विकृत समाजसे स्वयंको बचाया जा सकता है।

लोक संवाद

ठण्डमें जोड़ोंका रखें विशेष ख्याल

महोदय,-अक्तूबरका महीना शुरू होते ही मौसममें हल्की ठंडक घुलने लगती है। यही सर्द हवाएं हड्डियोंमें खिंचाव और दर्दका कारण भी बन जाती हैं। कई लोगोंको सुबह उठते ही शरीरके अलग-अलग हिस्सों खासकर घुटनों, कंधों और पीठमें दर्द महसूस होने लगता है। यह परेशानी उन लोगोंमें ज्यादा देखी जाती है, जिन्हें पहलेसे गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियोंकी बीमारियां हैं। ऐसेमें सुबह उठते ही कुछ आदतें अपनाकर आप इन समस्याओंसे काफी हदतक बच सकते हैं। सर्दियोंमें ब्लड सर्कुलेशन धीमा रहता है, जिससे शरीर अकड़ा हुआ महसूस होता है। ऐसेमें बिस्तरसे उठनेसे पहले हल्की स्ट्रेचिंग करनेसे शरीरको धीरे-धीरे वार्मअप मिल जाता है। आप बिस्तरपर ही रहकर टखनों, घुटनों, कलाईयों और कूल्होंको धीरे-धीरे मोड़ें और सीधा करें। इससे जोड़ोंमें जमी जकड़न कम होगी और दिनकी शुरुआतमें हड्डियोंको लचीलापन मिलेगा। ठंडके मौसममें आलस्य बढ़ जाता है, जिससे शरीर कम गतिशील हो जाता है। ऐसेमें हर सुबह कुछ मिनटकी हल्की कसरत बेहद फायदेमंद होती है। एक्सरसाइज शुरू करनेसे पहले वार्मअप करना जरूरी है, ताकि शरीरकी मांसपेशियां लचीली हों और चोटकी संभावना कम हो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हड्डियोंमें गर्माहट बढ़ती है, जिससे दर्द और अकड़नसे राहत मिलती है। सर्दियोंमें ठंडा पानी हड्डियों और मांसपेशियोंकी अकड़न बढ़ा सकता है। इसलिए सुबह गुनगुने पानीसे स्नान करना सबसे अच्छा उपाय है। यह न केवल ब्लड सर्कुलेशनको सुधारता है, बल्कि सूजन और दर्दको भी कम करता है। गर्म पानी शरीरकी तंग मांसपेशियोंको आराम देता है और आपको दिनभरके लिए ऊर्जावान बनाता है। सर्दियोंमें हड्डियोंकी सेहत बनाये रखनेके लिए खानपानपर विशेष ध्यान देना जरूरी है। अपनी डाइटमें शामिल करें। हल्दी और सौंठ, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणोंसे भरपूर होती हैं। विटामिन-ए हड्डियोंके लिए जरूरी है। सूरजकी हल्की धूप लें। ओमेगा-३ फैटी एसिड, जोड़ोंके दर्द और सूजनको कम करनेमें मदद करता है। कैल्शियमके लिए दूध, तिल और पनीरका सेवन करें। सर्दियोंमें प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीरको पानीकी जरूरत नहीं होती। पानीकी कमीसे शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है, जिससे जोड़ोंकी चिकनाई कम हो जाती है और दर्द बढ़ सकता है। इसलिए ठंडमें भी गुनगुना पानी या सूप पीते रहें, ताकि शरीरमें नमी बनी रहे और हड्डियां स्वस्थ रहें। **-डा.जगतपाल सिंह, वाया ईमेल।**

उपभोक्तावादी सोचके चलते दहेज प्रवृत्तिको बढ़ावा

❐ डा. ओ.पी. त्रिपाठी

मोदी सरकारके दौरान संप्रग सरकारकी तुलनामें भारत अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हुआ है राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबीके आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या और दंगे जैसे संगीन अपराधोंमें २००४ से २०१४ के बीच संप्रग सरकारके दौरान २२ फीसदीकी वृद्धि हुई, जबकि उसके बाद मोदी सरकारके दौरान इसमें २९ फीसदीकी गिरावट दर्ज की गयी।एनसीआरबीकी 'भारतमें अपराध २०२३' रिपोर्टमें कहा गया है कि २०२३ में दहेज निषेध अधिनियमके तहत १५,४८९ मामले दर्ज किये गये, जबकि २०२२ और २०२१ में यह संख्या क्रमश: १३,४७९ और १३,५६८ थी। आंकड़ोंके अनुसार हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या और दंगेके १.४५ लाख केस २०१४ में दर्ज किये गये थे, जबकि २०२३ में इनमें केवल १.०२ लाख केस ही दर्ज किये गये, जो २००४ में दर्ज १.१८ लाख केससे भी कम है। इसी हफ्ते एनसीआरबीने भारतमें अपराधोंका २०२३ की रिपोर्ट जारी की है। २००४ में देशमें दुष्कर्मके १८,२३३ मामले दर्ज किये गये, जो २०१४ में दोगुना बढ़कर ३६,७३५ हो गये, जबकि एनडीए सरकारके दौरान अगले नौ सालोंमें इसमें १९ फीसदीकी गिरावट आयी और २०२३ में कुल २९,६७० मामले दर्ज किये गये। दहेज हत्यामें भी संप्रग सरकारके दौरान २००४ में ७०२६ की तुलनामें २०१४ में ८४५५ मामले दर्ज किये गये, जो २० फीसदी अधिक है। वहीं मोदी सरकारके दौरान इसमें २७ फीसदीकी गिरावट आयी और २०२३ में दहेज हत्याके कुल ६,१५६ मामले दर्ज किये गये। विपक्ष लगातार मोदी सरकारके दौरान नफरत बढ़नेके आरोप लगाता रहा है। लेकिन एनसीआरबीके आंकड़े दूसरी कहानी कह रहे हैं। २१वीं सदीको ज्ञानकी सदी कहा जा रहा है और हम रूढ़िवादी सोलहवीं सदीमें जी रहे हैं। लड़कियोंके साथ यदि परिवार व्यवस्थामें भेदभाव होता है और भ्रूण हत्याकी प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसके मूलमें भी दहेजका अभिशाप ही है। लगातार खर्चीली होती उच्च शिक्षा व्यवस्थामें बेटियोंकी शिक्षापर बड़ा खर्च करनेके बाद यदि मां-बापको दहेज देना पड़ता है तो यह शर्मनाक स्थिति है। हालांकि पिछले कुछ समयसे पारिवारिक विवाद एवं अन्य कारकोंको दहेजका मामला बनानेके कुछ मामले अदालतोंकी चिन्ताका भी विषय रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद समाजमें दहेजके लिए उत्पीड़नकी घटनाएं कटु सत्य है। यह भी एनसीआरबीकी रिपोर्टका यथार्थ है कि देशमें हर रोज दहेजके लिए हत्याएं दर्ज हो रही हैं। बेटियोंको पढ़ाने तथा सरकारों द्वारा उनके सशक्तिकरणके तमाम प्रयासोंके बावजूद दहेजका दानव यदि अट्टहास कर रहा है तो यह हमारे समाजकी असफलता ही कही जायगी। निस्संदेह, हमारे समाजमें सोचमें बदलाव लानेकी जरूरत है। एक समय नारा लगाया जाता था कि दुल्हन ही दहेज है। इस नारेको हकीकत बनानेकी जरूरत है। कहीं न कहीं इस संकटके मूलमें पितृसत्तात्मक सोच भी जिम्मेदार है, जिसमें स्त्रियोंको वाजिब हक न देकर उन्हें कमतर आंका जाता है। इस बातपर विचार किया जाना चाहिए कि दहेज प्रथा उन्मूलनके लिए सख्त कानून होनेके बावजूद इस कुप्रथापर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। आखिर क्यों दहेज निषेध अधिनियमके अंतर्गत मामले लगातार बढ़ रहे हैं। समाजमें साक्षरता वृद्धि और जागरूकता अभियानोंके बावजूद स्थिति जसकी तस है। विडंबना यह है कि दहेज उत्पीड़नके ज्यादातर मामले बड़े हिन्दी प्रदेशोंमें सामने आये हैं। रिपोर्टके अनुसार साल २०२१ से २०२३ तक उत्तर प्रदेशमें महिलाओंके खिलाफ अपराधके मामले बढ़े हैं। वर्ष २०२१ में महिला अपराधोंकी संख्या ५६०८३ थी, जो वर्ष २०२२ में बढ़कर ६५७४३ हो गयी। प्रदेशमें वर्ष २०२३ में ३३ महिलाओंके साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं दुष्कर्मके बाद हत्याके मामले दर्ज किये गये। इसी तरह ३५५६ महिलाओंके साथ दुष्कर्मके मामले दर्ज हुए। इनमें ३०१ नाबालिग बच्चियोंके साथ बलात्कारके मामले सामने आये। दुष्कर्मके प्रयासके १४० केस दर्ज हुए। यूपीके बाद बिहार दूसरे नम्बरपर है। रिपोर्टमें दी गयी जानकारीके मुताबिक राजधानी दिल्लीमें २०२३ में महिलाओंके खिलाफ अपराधके कुल १३,००० से अधिक मामले सामने आये। २०२२ में १४,१५८ मामले थे और २०२१ में १३,९८२ मामले दर्ज किये गये थे। दिल्लीने १९ मेट्रो शहरोंमें दहेज हत्या और बलात्कारके सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये हैं। हालांकि रिपोर्टमें ये भी बताया गया है कि दिल्लीमें प्रति लाख आबादीके परिप्रेक्ष्यमें अपराध दर १४.४ प्रतिशत रही, जो इंदौर और जयपुरसे कम है। भारतके संविधानकी सातवीं अनुसूचीके तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्यके विषय हैं और महिलाओंके विरुद्ध अपराधकी जांच और अभियोजन सहित कानून और व्यवस्था बनाये रखने, नागरिकोंके जीवन और संपत्तिकी सुरक्षाकी जिम्मेदारी मुख्य रूपसे संबंधित राज्य सरकारों की है। भारतका संविधान समानताके अधिकारकी गारंटी देता है और महिलाओंके विरुद्ध सभी प्रकारके भेदभावको समाप्त करने तथा उनके समग्र सशक्तिकरणको सुनिश्चित करनेके लिए राज्य द्वारा सकारात्मक हस्तक्षेपका भी प्रावधान करता है। संवैधानिक प्रावधानोंमें व्यक्त दृष्टिकोणको ध्यानमें रखते हुए, भारतीय दंड संहिता, १८६०, दहेज निषेध अधिनियम, १९६१, घरेलू हिंसासे महिलाओंका संरक्षण अधिनियम, २००५ और बाल विवाह निषेध अधिनियम, २००६ जैसे विभिन्न कानून बनाये गये हैं, जो महिलाओंके समक्ष लैंगिक असमानता, भेदभाव और हिंसाके मुद्दोंको संबोधित करते हैं। इसके अलावा भारत सरकारने हिंसा प्रभावित महिलाओंके लिए वन स्टॉप सेंटर, टोल फ्री टेलीफोनिक शॉर्ट कोड १८१ पर चलनेवाली महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कठिन परिस्थितियों या अभावका सामना करने वाली महिलाओंके लिए स्वाधार गृह, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली जो आपातकालीन प्रतिक्रियाके लिए एक अखिल भारतीय एकल नंबर ११२, मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है, आठ शहरोंमें सुरक्षित शहर परियोजनाएं, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियोंके लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, पुलिस स्टेशनोंपर महिला सहायता डेस्ककी स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण आदि सहित विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, नियमित रूपसे शिकायतोंके निबटारेके अलावा, घरेलू हिंसाके मामलोंकी रिपोर्ट करनेके लिए एक समर्पित ह्वाट्सएप नंबरके माध्यमसे संकटग्रस्त महिलाओंकी सहायता करता है। एनसीडब्ल्यू सोशल मीडियापर घरेलू हिंसासे संबंधित शिकायतोंका भी संज्ञान लेता है। एनसीडब्ल्यू द्वारा प्राप्त शिकायतोंपर पीड़ितों, पुलिस और अन्य अधिकारियोंके साथ समन्वय करके तत्काल सहायता प्रदान करनेके लिए कारवाई की जाती है। समाजमें उपभोक्तावादी सोचके चलते भी दहेजकी प्रवृत्तिको बढ़ावा मिल रहा है। हमें विचार करना होगा कि समाजमें दहेजके संकटकी जड़ोंपर कैसे प्रहार किया जाय। राष्ट्रका विकास तबतक एकांगी ही रहेगा, जबतक आधी दुनियाको समाजमें सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। दहेजके मामलोंमें न्याय भी शीघ्र देनेकी आवश्यकता है। आज जरूरत इस बातकी है कि बेटियोंको आर्थिक रूपसे आत्मनिर्भर बनाया जाय, ताकि वे समाजमें सम्मानजक ढंगसे बिना किसीपर निर्भर रहकर जीवनयापन कर सकें।

दुर्घटनाओं में होती मौतें

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अट्ठारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप के चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं। यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने में बाधक हैं। जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके। साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता। जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं।

चुनावी रेवड़ियां बांटने के खतरे

विश्वनाथ सचदेव

(वरिष्ठ पत्रकार)

सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा इस तरह की नकद राशि बांटना क्या सरकार के पैसों से चुनाव जीतना नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न रखा जाए, और यदि यह अपराध है तो फिर इसकी कोई सजा तय क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछा तो यह भी गया है कि सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटना भी क्या एक तरह से रेवड़ी बांटना नहीं है? आश्वासन वाली राजनीति कोई नयी चीज नहीं है। और ऊपरी तौर पर देखें तो यह उतनी गलत भी नहीं लगती। आखिर जनता के हित की बात सोचना सरकार का काम है, और जनता को वित्तीय सहायता देकर जनता की सहायता ही तो की जाती है। पर सवाल उठता है कि जनता की यह 'मदद' सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले ही याद क्यों आती है? सवाल यह भी उठाना चाहिए कि राजनीति में 'तोहफे' बांटने की यह परंपरा अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आनी चाहिए?

बिहार में चुनावों की तारीखें घोषित होने के साथ ही 'राजनीतिक रिश्वतखोरी' की बातें चलने लगी हैं। राजनीतिक रिश्वतखोरी यानी मतदाता को रेवड़िया बांटकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए लुभाना। कहा यह भी जा रहा है कि चलो अब कुछ दिन रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं से तो पीछा छूटेगा। यहां रेवड़ियों का मतलब वह 'मुफ्त की सेवाएं' हैं जिनका लालच देकर राजनेता मतदाता को बरगलाते हैं। पहले बिजली-पानी जैसी जीवनोपयोगी चीजें मतदाता को दी जाती थीं, देने का वादा किया जाता था, और अब तो यह नकद पैसा बांटा जा रहा है। बिहार सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में दस हजार रुपये जमा करवा कर इस रेवड़ी संस्कृति को एक नया आयाम दे दिया है। एक करोड़ महिलाओं का मतलब एक करोड़ परिवारों तक पहुंचना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर यह सीधी रिश्वत है।

सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा इस तरह की नकद राशि बांटना क्या सरकार के पैसों से चुनाव जीतना नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न रखा जाए, और यदि यह अपराध है तो फिर इसकी कोई सजा तय क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछा तो यह भी गया है कि सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटना भी क्या एक तरह से रेवड़ी बांटना नहीं है? आश्वासन वाली राजनीति कोई नयी चीज नहीं है। और ऊपरी तौर पर देखें तो यह उतनी गलत भी नहीं लगती। आखिर जनता के हित की बात सोचना सरकार का काम है, और जनता को वित्तीय सहायता देकर जनता की सहायता ही तो की जाती है। पर सवाल उठता है कि जनता की यह 'मदद' सरकारों और राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले ही याद क्यों आती है? सवाल यह भी उठाना चाहिए कि राजनीति में 'तोहफे' बांटने की यह परंपरा अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आनी चाहिए?

चुनाव से कुछ अरसा पहले, या वैसे भी, हमारी सरकारें जनता की मदद की घोषणाएं शुरू कर देती हैं और मीडिया में इसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तोहफे के रूप में प्रचारित किया जाता है। कुछ ही साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री ने बिहार में खुले आम तोहफों की बोली लगायी थी। एक चुनाव-सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, 'कितने दूं, दस करोड़?, सौ करोड़?, हजार करोड़? या लाख करोड़?' उनकी घोषणा पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था, निश्चित रूप से इस तोहफे का कुछ असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा होगा। पर चुनावी लाभ के लिए जनता के पैसों के तोहफे इस तरह बांटने की घोषणा क्या विद्रूप पहल नहीं मानी जानी चाहिए? सच तो यह है कि इसे तोहफा या उपहार कहना ही गलत है। यह अनुचित आर्थिक लेन-देन ही हैझ और रिश्वत देना या लेना दोनों अपराध हैं! इस अपराध की सजा क्यों तय नहीं होती? इस सवाल का सीधा-सा जवाब यह है कि यह अपराध सबकी मिली-भगत से हो रहा है। राजनेताओं को, सरकारों को, राजनीतिक दलों को रेवड़ियां बांटने, या कहना चाहिए रिश्वत देकर अपना काम निकालने का यह एक आसान तरीका लगता है। ऐसे में पारस्परिक लाभ के इस सौदे में भला किसी को कुछ गलत क्यों लगेगा?

पर यह गलत परंपरा है जन-कल्याण की योजनाएं बनाना, उन्हें ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करना सरकारों का काम है। पर यह काम चुनावों से ठीक पहले ही क्यों? एक करोड़ महिलाओं को बिहार की नीतीश सरकार द्वारा दस हजार रुपये देने और विपक्ष द्वारा पच्चीस सौ रुपये प्रति माह देने का वादा करने में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहा जा सकता है कि इस तरह की घोषणाएं वर्तमान या भावी सरकार की रीति-नीति बताती हैं, पर बताने की यह आवश्यकता चुनावों के समय पर ही किसी को याद क्यों आती है?

ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल पहले कभी उठे नहीं हैं। उठते रहे हैं ये सवाल, पर राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित इन सवालों को उठाने वाली नैतिकता पर अक्सर हावी हो जाता है। कभी महिला मतदाताओं को साड़ियां बांटकर तमिलनाडु की जयललिता ने वोट के लिए रिश्वत की इस परंपरा की शुरूआत की थी। द्रमुक के ही करुणानिधि ने दो रुपये किलो चावल बांटकर इस शुरूआत को चुनाव जीतने की एक कला के रूप में विकसित किया। फिर तो जैसे देश के अलग-अलग हिस्सों में इस कला को निखारने की एक प्रतिस्पर्धा ही चल पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत की ओर किसी का ध्यान न गया हो। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस 'रेवड़ी संस्कृति' को मुद्दा बनाया था। पर जल्दी ही उन्हें यह अहसास हो गया कि यह संस्कृति तो स्वयं उनके लिए भी लाभदायक है और वे भी लाभ लुटाकर लाभ कमाने की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गये।

अब तो हमारे राजनीतिक दल यह सोचना भी नहीं चाहते कि इस प्रतियोगिता में राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है–यह घाटा खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। यही सब देखते हुए यह मांग भी उठी थी कि मुफ्त संस्कृति वाली इस राजनीति के वित्तीय अनुशासन के बारे में भी कुछ नियम-कायदे बनने चाहिए। कहा यह भी गया कि चुनाव घोषणापत्रों में ऐसी युक्तियों-योजनाओं के साथ उन पर होने वाले व्यय का ब्योरा भी दिया जाना चाहिए, यह भी बताया जाना चाहिए कि इन योजनाओं पर होने वाले खर्च की व्यवस्था कैसे होगी। इस संदर्भ में रसोई घर की मुफ्त सिलेंडर वाली योजना के हश्र की बात भुलाई नहीं जानी चाहिए।

इस बात का भी लेखा-जोखा होना चाहिए कि मुफ्त सिलेंडर कैसे मिलेंगे और कैसे मिलते रह सकेंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता दिख भी नहीं रहा।

यहां यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस संदर्भ में हस्तक्षेप किया था। न्यायालय ने तो यह भी कहा था कि राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में ऐसी योजनाओं की घोषणा को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पर, जो होना चाहिए, और जो हो रहा है, हमारी राजनीति में उसमें बहुत अंतर है। यह अंतर कब और कैसे पटेगा, पता नहीं। लेकिन यह तय है कि हमारे राजनेता इस बारे में लगातार सक्रिय हैं कि यह अंतर मिटाने की बात ही न हो। वे मानते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इसलिए, राजनीति की रेवड़ी संस्कृति के बारे में कभी-कभार बात तो कर ली जाती है, पर इस संस्कृति के खतरों से बचने की आवश्यकता किसी को महसूस नहीं होती।

राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है की राजनीति की यह घटिया संस्कृति समाप्त हो, पर राजनीतिक आवश्यकता इस नैतिकता को कहीं पीछे छोड़ देती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हमारे नेता तो यह भी जानते हैं कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता हैझबिहार में चुनावों की तारीख की घोषणा के ठीक पहले मेट्रो लाइन के उद्घाटन का लालच मुख्यमंत्री छोड़ नहीं पाये। सुना है, यह लाइन अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है! स्पष्ट है, राजनीतिक स्वार्थ किसी भी अनुशासन को स्वीकार नहीं करते।

नई सरकार की राह तकता बिहार

ललित गर्ग

(वरिष्ठ स्तंभकार)

बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। मतदान की तिथियों की घोषणा के साथ ही लोकतंत्र का यह महायज्ञ आरंभ हो चुका है, जिसमें करोड़ों मतदाता दो चरणों में दिनांक 6 और 11 नवंबर को अपने मत के माध्यम से राज्य की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि विचार और व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है। बिहार लंबे समय से जिस पिछड़ेपन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अराजकता की बेड़ियों में जकड़ा रहा है, उससे मुक्ति का यह अवसर है। 14 नवंबर को मतगणना के साथ बिहार में नई सरकार की तस्वीर सामने होगी, लेकिन राज्य में सियासत जिस तरह आकार ले रही है, मतदान तक कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यह धरती कभी बुद्ध की करुणा और चाणक्य की नीति की जननी रही है, लेकिन आज वही बिहार कानून व्यवस्था की विफलताओं, जातिवाद की जंजीरों और विकासहीनता की विवशताओं से जूझ रहा है। सड़कें टूटी हैं, शिक्षा व्यवस्था जर्जर है, चिकित्सा तंत्र कमजोर है, और रोजगार की तलाश में हर साल लाखों युवा अपनी मातृभूमि छोड़ने को विवश हैं। ऐसे में यह चुनाव एक सामाजिक जागृति का अवसर भी है, जब मतदाता केवल चेहरे नहीं, चरित्र और चिंतन को वोट देंगे।

राजनीतिक दल अपनी-अपनी घोषणाओं, वादों और दृष्टि-पत्रों के साथ मैदान में हैं। कोई ह्लनया बिहारह्व बनाने का नारा दे रहा है, तो कोई ह्लविकसित बिहारह्व का। लेकिन सवाल यह है कि क्या घोषणाओं से बिहार का भाग्य बदलेगा, या फिर यह चुनाव भी परंपरागत नारों और जातीय समीकरणों के हवाले हो जाएगा? यह समय है कि जनता दलों से नहीं, दिशा से जुड़ाव करे; नारे से नहीं, नैतिकता से संवाद करे। पिछले दो दशकों से नीतीश कुमार बिहार का चेहरा बने हुए हैं और यह चुनाव भी अलग होता नहीं दिख रहा। मूल सवाल यही है कि क्या नीतीश को एक और मौका जनता देगी? राज्य में एनडीए ने उन्हें आगे कर रखा है और महागठबंधन से सीधी टक्कर मिल रही है। 2005 से नीतीश कुमार बीच के कुछ समय को छोड़ कर सत्ता पर काबिज हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार शपथ ली और कई बार पाला बदला। गठबंधन के साथी बदलते रहने और कम सीटों के बावजूद मुख्यमंत्री वही बने। इसके पीछे उनकी अपनी 'सुशासन बाबू' की छवि भी है, लेकिन अब इसे चुनौती मिल रही है। पहली बार नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं, कानून-व्यवस्था का मामला भी चिंता बढ़ाने वाला है।

विकास पर जोर के बावजूद बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक कारक है। हर पार्टी की चुनावी रणनीति समुदाय आधारित लामबंदी से गहराई से प्रभावित है। दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए ओर महागबंधन सीट बंटवारे की बातचीत में उलझे हैं। 243 विधानसभा सीटों में से गठबंधन में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किसे कोन-सी सीट मिलेगी, यह विवाद का विषय है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ था- इस बार समीकरण में प्रशांत किशोर की जन सुराज भी है, जो भ्रष्टाचार ओर पलायन का मुद्दा उठाए हुए हैं। कुछ और भी नये राजनीतिक दल मैदान में हैं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुदृढ़ता की है। आए दिन होने वाली अपराध घटनाएं और अराजकता ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। एक ऐसा शासन चाहिए जो भयमुक्त समाज दे सके, जहां नागरिक सुरक्षित महसूस करें, जहां अपराध पर अंकुश हो और न्याय त्वरित मिले। विकास तभी संभव है जब विश्वास का माहौल बने।

बिहार की राजनीति में इस बार कई नए दल और कई पुराने चेहरे नए दल के साथ दिखाई देने वाले हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी 'जनसुराज', तेजप्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही है।प्रशांत किशार की पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजर है। तेजप्राताप यादव तेजस्वी यादव को कितना झटका देते है, यह चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। साथ ही यह भी तय होगा कि कौन सी पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाती है कौन नहीं?

यह चुनाव केवल विधानसभा की सीटें तय नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि क्या बिहार अपनी पुरानी परछाइयों से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ पाएगा या नहीं। राज्य का विकास, कानून व्यवस्था एवं रोजगार का मुद्दा भी पक्ष-विपक्ष के बीच एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। हालांकि पिछली सरकारों के दौर में बिहार बदहाली के दौर से काफी निकल चुका है और विगत दो दशक में यहां की स्थितियां काफी बदली है। इस बार बिहार चुनाव बदला-बदला होगा, इसकी आहट उन घोषणाओं से भी मिलती है, जो नीतीश सरकार ने की हैं। महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पहली बार इस पैमाने पर ऐलान किए गए हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने पूछा है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जनता वादों पर भरोसा करती है या बदलाव संग जाती है ?

सियासी स्थिति का आकलन करें, तो बिहार में लगभग बीस साल शासन के बावजूद नीतीश कुमार की ताकत को कोई भी खारिज नहीं कर रहा है। भाजपा पूरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है, ताकि सत्ता बनी रहे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन अभी नहीं, तो कभी नहीं वाले अंदाज में जोर लगा रहा है। लोकतंत्र की इस परीक्षा में बिहार एक नई इबारत लिख सकता है-एक ऐसा बिहार जो शिक्षित हो, संगठित हो, और सजग हो। जहां राजनीति सेवा का माध्यम बने, संघर्ष का नहीं; जहां सत्ता संवेदना की भाषा बोले, स्वार्थ की नहीं। बिहार का यह जनादेश वास्तव में इतिहास रच सकता है-यदि जनता जाति नहीं, न्याय को चुने; वादा नहीं, विश्वास को चुने।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 10-10-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP12 User: cci Time: 10-09-2025 22:46 Color:

> बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह गठबंधन बनाए रखे और संबंधों का समझदारी से प्रबंधन करे।
>
> – चाणक्य

दोनों का फ़ायदा

पीएम नरेंद्र मोदी ने जुलाई में ब्रिटेन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को जहां छोड़ा था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा उसे वहीं से लेकर आगे बढ़ी है। भारतीय पीएम ने ब्रिटेन को स्वाभाविक साझेदार बताया, तो स्टार्मर ने नई दिल्ली के साथ साझेदारी को ग्रोथ का लॉन्चपैड। टेक्नॉलजी, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति दोनों ही देशों के लिए अहम है।

मोदी-स्टार्मर मुलाकात

डील से आगे । कीर स्टार्मर ब्रिटेन के उद्योग जगत के शीर्ष चेहरों के साथ भारत आए। उनका प्रतिनिधिमंडल जितना बड़ा है, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात के दौरान हुई घोषणाएं। दो महीने पहले ही दोनों देशों के बीच एक विस्तृत आर्थिक और व्यापार समझौता - CETA हुआ है। यह दौरा उस डील को जल्द लागू करने में मदद करेगा। इसके लिए एक जॉइंट कमिटी बनाने का ऐलान हुआ है। स्टार्मर ने अपनी इस इच्छा को खुलकर जाहिर भी कर दिया है।

दोनों को मुनाफा । ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर भारत औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% करेगा। वहीं, भारत से ब्रिटेन निर्यात होने वाले 99% उत्पादों पर टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव है। इस समझौते से दोनों यहां के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। दोनों के बीच करीब 56 अरब डॉलर का व्यापार है, जिसे 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है।

दबाव का जवाब । भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग ऐसे समय बढ़ रहा है, जब अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय उद्योग जगत दबाव में है, खासतौर पर भारत का टेक्सटाइल उद्योग। आशंका है कि चीन और बांग्लादेश पर कम टैरिफ के चलते भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में अगले साल 10% तक की गिरावट आ सकती है। ब्रिटेन के साथ हुई डील से इस घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और शोध । स्टार्मर के दौरे ने टेक्नॉलजी-इनोवेशन, शिक्षा, निवेश, स्वास्थ्य और शोध में सहयोग के नए दरवाजे खोले हैं। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालय अब भारत में कैंपस खोल सकेंगे। ट्रंप की वीजा पॉलिसी को देखते हुए भारतीय स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। उनके लिए जब बाहर जाने के रास्ते संकरे हो रहे हैं, तब इस कदम से अपने ही देश में नए मौके बनेंगे। इससे रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा।

नए विकल्प । पीएम मोदी और स्टार्मर, दोनों ही अगर द्विपक्षीय समझौतों को ऐतिहासिक मान रहे हैं, तो इसकी वजह मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं। दोनों पर अमेरिका का दबाव है और इन मुलाकातों ने उनको नए विकल्प दिए हैं, जिसका निश्चित तौर पर फायदा वॉशिंगटन के साथ बात करते समय होगा।

तिराहा

जूते का दर्शन

सुधर्मा ने घर-दफ्तर आने वालों के लिए अब फीते वाले जूते पहनने का नियम बना दिया है, ताकि निकालने में लगने वाले वक्त से सामने वाले को बचने का वक्त मिल सके। सुखनंदन मुस्कराते हुए बोले, 'प्रिये! जूता तो सहनशीलता का प्रतीक है। कीचड़, पानी, कांटा - कहीं हो, बिना उफ किए पैर सुरक्षित रखता है। इस पर इतना क्रोध?' 'मेरा बस चले तो जूते को अस्त्र घोषित कर प्रतिबंधित कर दूं', सुधर्मा के स्वर में नाराजगी थी। सुखनंदन बोले, 'तुम्हें जूते का दर्शन समझना होगा।

प्रेम शंकर मिश्र

लोग सिर से पांव तक भले ढके हैं, लेकिन, मर्यादा व विचार से नंगे हैं। इसका दोष बेचारा जूता झेल रहा।' सुधर्मा के चेहरे पर कई प्रश्न उभरे, जिस पर उत्तर का क्रम शुरू हुआ। 'देखो! मनुष्य की जेब में दमड़ी व पांव में जूता साथ आए। फिर यह चमड़ी और दमड़ी के बीच खड़ा हो गया। दमड़ी से हारे लोग चमड़ी खींच कर जूता बनाने की धमकी देने लगे।' सुधर्मा की उत्सुकता बढ़ गई, 'जूता समर्थ का है तो वह सिर व सिंहासन पर रखकर पूजा जाता है। जूता कमजोर पर चले तो वह सुधार की प्रक्रिया है, क्योंकि सिस्टम का जूता उसकी खुराक बन चुका है। यही जूता समर्थ पर पड़ जाए, तो लोक और तंत्र, सब खतरे में आ जाता है। ऐसा नहीं कि हर जूता चोट देता है, जूता चांदी का हो तो मार खाने वाला, मारने वाले का जूता और पैर - दोनों सहलाता है। जूता मंडप से चोरी हो तो आह्लाद, मंदिर से चोरी हो तो आस्था व कानून-व्यवस्था पर आघात। जूते की ताकत देखो - चलाने वाले को उसकी पेशागत योग्यता के लिए कोई नहीं जानता था, लेकिन, चलते ही उसके पक्ष-विपक्ष में तर्कों के जूते निकल पड़े। वैसे यह प्रसिद्धि हासिल करने में उसे दशकों लग जाते। इसलिए, जरूरत जूता कसने की नहीं, आचरण की कसौटी कसने की है', सुखनंदन ने बात खत्म की।

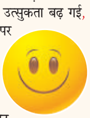

एकदा

संकलन : ललित गर्ग

नज़रिया बदला

सन 1945 की बात है, गुजरात के डाकोर स्थित श्रीरणछोड़जी मंदिर में महाराष्ट्र के संत नरहरी महाराज का हरिकीर्तन चल रहा था। कीर्तन के बाद उन्होंने घोषणा की, 'अब उस्ताद रजाक हुसैन का संगीत कार्यक्रम होगा।' यह सुनकर कुछ लोग विरोध करने लगे, 'मंदिर में मुस्लिम गायक! यह तो अधर्म है।' नरहरी महाराज ने तबले को उठा लिया और विरोध करने वालों के पास गए, फिर शांत स्वर में पूछा, 'यह क्या है?' विरोध करने वाले लोगों ने कहा, 'तबला।' महाराज ने पूछा, 'यह किससे बना है?' उत्तर मिला, 'लकड़ी और चमड़े से।' 'और चमड़ा किससे बनता है?' 'जानवर की खाल से।' महाराज मुस्कराए और बोले, 'फिर वही चमड़ा जब जूते में हो तो अपवित्र, और जब तबले में हो तो पवित्र क्यों?' सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज ने समझाया, 'धर्म वस्तु में नहीं, भावना में है। चमड़ा नहीं, हमारा दृष्टिकोण अपवित्र है। जो वस्तु प्रभु के नाम का साधन बन जाए, वह स्वयं पवित्र हो जाती है।' उन्होंने आगे कहा, 'उस्ताद रजाक हुसैन को मुसलमान नहीं, मनुष्य समझो और उनके संगीत में ईश्वर की उपासना देखो।' इसके बाद संगीत गूंजा, पर अब वह केवल स्वर नहीं था, एक संदेश था - सच्चा धर्म वह है जो भेद नहीं करता, बल्कि भेद-भाव मिटाता है।

अफ़ग़ानी एयरबेस को लेने के अमेरिकी इरादे के ख़िलाफ़ भारत खड़ा हुआ

बगराम पर बनते नए अलायंस

तालिबान ने साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद से पहली बार विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के रूप में तालिबान सरकार का कोई प्रतिनिधि भारत आ रहा है। यह जितनी बड़ी खबर है, उतना ही बड़ा घटनाक्रम है भारत का अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को कब्जे में लेने के इरादे का विरोध करना।

भाषा सिंह

दो बड़े कदम । भारत ने इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन के वक्तव्य का समर्थन किया। इसमें बिना बगराम एयरबेस का नाम लिए अमेरिकी मंशा का विरोध किया गया है। अमेरिकी हितों से टकराने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह दूसरा बड़ा कदम है। इससे पहले चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी भारत ने इस्राइल के खिलाफ जारी बयान पर हस्ताक्षर किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी का सितंबर में चीन जाना और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होना भी ट्रंप को रास नहीं आया था।

नई साझेदारी । हालांकि भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवतावादी और विकास संबंधी कार्यों में अफगानिस्तान का सहयोग कर रहा है। इस लिहाज से भी तालिबान के विदेश मंत्री का पहली बार भारत आना नए किस्म के संवाद और साझेदारी की शुरुआत का संकेत हो सकता है।

संयुक्त बयान । मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की सातवीं बैठक में भारत, अफगानिस्तान, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल ने भी शिरकत की। इसमें जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि अफगानिस्तान और पड़ोसी देशों में पश्चिमी देशों द्वारा अपने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात करने की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के हित में नहीं हैं।

क्षेत्रीय गठबंधन । इसमें यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान को स्वतंत्र, एकीकृत और शांतिपूर्ण देश के तौर पर स्थापित करने के लिए भी ये सारे देश मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाली एक और बात है कि ये तमाम देश अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ऐसे किसी काम के लिए नहीं होने देंगे, जिससे इलाके की सुरक्षा खतरे में पड़े। कुल मिलाकर, बिना कहे ही कह दिया गया कि ये देश अमेरिका के बगराम एयरबेस लेने के खिलाफ हैं। इसमें भारत का चीन-रूस-पाकिस्तान के संग खड़े होना नए क्षेत्रीय गठबंधन की ओर इशारा करता है।

भारत-अफगान रिश्ते

- मॉस्को की बैठक में चीन-रूस के साथ रहा भारत
- पहली बार तालिबानी विदेश मंत्री नई दिल्ली आ रहे
- दक्षिण एशिया को लेकर विदेश नीति में बड़ा शिफ्ट

वर्चस्व की लड़ाई । दुनिया के इस हिस्से में कूटनीतिक संबंध कितनी तेजी से बदल रहे हैं, इसका आभास मॉस्को में हुई इस बैठक में हुआ। मुत्ताकी के नेतृत्व में पहली बार अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने ऐसी किसी बैठक में भागीदारी की है। रूस के अफगानिस्तान में अपने हित हैं। 2001 में अमेरिका ने नैटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला बोला, उसे तबाह किया। 20 साल बाद, 2021 में अमेरिका ने अचानक वापसी कर ली।

बगराम का महत्व । अब एक दिन ट्रंप फिर कहते हैं कि उन्हें बगराम वापस चाहिए। बगराम, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से 50 किलोमीटर दूर इस देश का सबसे बड़ा एयरबेस है।

अप्रत्याशित समर्थन । ट्रंप के प्रस्ताव को तालिबान ने सिरे से नकार दिया। जब अफगानिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया, तब शायद अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इस तरह से भारत सहित तमाम देश अफगानिस्तान के पक्ष में आ जाएंगे। यह भारत की विदेश नीति में बदलाव का सूचक है, जिसमें दक्षिण एशिया की जमीनी स्थिति को देखते हुए कदम उठाने की मंशा दिखती है।

नई नीति । भारत में पिछले कई दशकों से 'तालिबान' शब्द एक वैचारिक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में तालिबानी शासन के विदेश मंत्री का भारत यात्रा पर आना और उसके साथ नए सामरिक समीकरण स्थापित करना वाकई हमारी विदेश नीति का दिलचस्प नया अध्याय है।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं)

जापानी शिक्षा व्यवस्था में ख़ास है 'सिनरिन-योकु'

शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता शिक्षा और समग्र विकास की संकल्पना के साथ 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से छात्रों को तैयार करने का दिशानिर्देश करती है। हमारे गुरुकुलों में आदिकाल से ही ज्ञान-विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में असंख्य प्रयोग होते रहे हैं। शिक्षा में वास्तविक अनुभवों का उपयोग अत्यावश्यक है। प्रकृति का विशाल प्रांगण इसके लिए सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराता है।

जय प्रकाश पाण्डेय

सिनरिन-योकु । जापानी शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक जीवन पर आधारित गतिविधि 'सिनरिन-योकु' का प्रचलन है। सिनरिन का अर्थ है- वन, और योकु का मतलब है - स्नान, यानी वन-स्नान। बच्चों को अपने आस-पास के पार्क, झील, पहाड़, समुद्र, खेत-खलिहान पर ले जाया जाता है, जहां वे प्रकृति को स्वाभाविक रूप से फील करें, सुनें और देखें। इन सबसे शरीर, मन, दिमाग का प्रकृति से एक संबंध स्थापित होता है, जिससे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है।

पहाड़-पगडंडी । पुस्तक पगडंडी में एक यात्रा वृतांत है, जिसमें उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों, झरने, उछलते-कूदते नदी-नाले, इतिहास, भूगोल, लोक-संस्कृति और वहां के सीधे-सादे लोगों की कहानी है। हिमालय की वादियों का एक-एक पत्थर बोलता है। चीड़, देवदार के पेड़ों की प्रत्येक पत्ती शरारत करती है और इसकी हरियाली आप में प्राण डाल देती है। यात्रा के इस क्रम में छात्रों ने इसे महसूस किया है जो पुस्तक के माध्यम से पाठकों तक भी पहुंचता है।

विंटर लाइन । पुस्तक में दृश्यों का पूरा कैनवस पठनीय एवं रोचक है। पहाड़ों की रानी मसूरी से लेकर नाग-

कॉमनरूम

AI Image

टिब्बा, मुनस्यारी, चारधाम यात्रा और फूलों की घाटी तक एक अविस्मरणीय दुनिया है। मसूरी में जाड़ों की शाम में क्षितिज पर लाल रंग की गहरी रेखा पूरे आसमान पर फैल जाती है, जिसे विंटर लाइन के नाम से जानते हैं। स्विट्जरलैंड और मसूरी में ही विंटर लाइन का मनमोहक नजारा देखा जा सकता है।

कक्षा से बाहर । पगडंडियां मन के कोमल तंतुओं को छूती हैं। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षा में कला-एकीकरण, खेल, खिलौनों और प्रकृति को नवीन शिक्षण-पद्धति के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्लासरूम से बाहर भी सिखाने का प्रयास होना चाहिए। सभी विषय एक-दूसरे से संबंधित हैं, जो जीवन और समाज के अनेक पहलुओं को जोड़ने का काम करते हैं।

सर्वोत्तम रास्ता । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गतिविधि आधारित शिक्षण में 5E- इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सपीरिएंस, एक्सप्रेस और एक्सेल का मंत्र दिया है। बच्चे रुचि के हिसाब से विभिन्न गतिविधियों में इंगेज हों, एक्सप्लोर करें। इन गतिविधियों एवं घटनाओं को विभिन्न दृष्टिकोण से अनुभव से सीखें। फिर रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना सीखें। इन सब को मिला कर ही सर्वोत्तम बनने का रास्ता बनता है।

(लेखक शिक्षा मंत्रालय के पूर्व डायरेक्टर हैं)

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

रुकिए ज़रा! इस भागती दुनिया में ठहरना भी है

नजीब शाह

हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर कोई दौड़े जा रहा है। जिंदगी का यह रूप हमें यूनान की पौराणिक कथाओं के राजा Sisyphus की याद दिलाता है। उसे देवताओं ने दंड स्वरूप यह काम दिया था कि वह एक भारी पत्थर को पहाड़ी पर चढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह शिखर के पास पहुंचता, पत्थर फिर नीचे लुढ़क जाता। हम आधुनिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमारी मेहनत भी अक्सर Sisyphus के अंतहीन और निरर्थक श्रम जैसी लगती है - लगातार दौड़ना, लक्ष्य पाना, फिर वही दोहराना, लेकिन सच्ची संतुष्टि या विश्राम कभी नहीं मिलना।

आज हम भी कुछ ऐसे ही हैं - हर दिन नए लक्ष्य, नई योजनाएं, नए संघर्ष। और इसी बीच, असली जीवन चुपचाप गुजरता चला जाता है। इस निरंतर भागमभाग में आनंद, सहजता और आत्म-संतोष कहीं खो गया है। लगभग 2400 वर्ष पहले सुकरात ने चेतावनी दी थी कि अत्यधिक व्यस्त जीवन के रूखेपन से सावधान रहो। उनकी यह चेतावनी आज के समय में और अधिक प्रासंगिक लगती है। आधुनिक लेखक आंद्रे स्मार्ट कहते हैं कि आलस्य एक खोई हुई कला है।

AI Image

प्राचीन ताओ दर्शन में इस समस्या का एक गहरा उत्तर है - wu-wei, जिसका जिसका अर्थ है 'सहज कर्म' या 'प्रयासहीन क्रिया'। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ न किया जाए, बल्कि यह कि चीजों को उनके स्वाभाविक प्रवाह में चलने दिया जाए। एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कब तैरना है और कब बस प्रवाह को स्वीकार करना है। यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही संतुलन जीवन की सबसे गहरी समझ है।

यही सिद्धांत हमारे वैदिक परंपरा के ध्यान में भी झलकता है। ध्यान शब्द का मूल meditatum है, जिसका अर्थ है गंभीरता से विचार करना। इसमें हम अपनी चेतना को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं और बाहरी विकर्षणों को मिटा देते हैं। यह निष्क्रिय लगने वाली क्रिया हमारे मन को शांत और शरीर को स्वस्थ करती है।

आधुनिक जीवन में लक्ष्य बनाना आवश्यक है, लेकिन उनसे चिपक जाना आत्मविनाश का कारण बन जाता है।

कांटे की बात

तेजस्वी यादव, RJD नेता

समाह की शख्सियत

किताबों को ज़िंदगी से जोड़ रहीं गीतांजलि

*एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के पक्ष में एक आवाज मुखर है, उनकी पत्नी **गीतांजलि जे. आंग्मो** की। उनके लिए मुश्किलों का सामना नई बात नहीं। बना-बनाया करियर छोड़कर जब उन्होंने सोनम का साथ देने का फैसला किया, तभी से वह हर संघर्ष में साझीदार रही हैं।*

समय के साथ बदलती भूमिकाएं

मैनेजमेंट की स्टूडेंट, आध्यात्मिक साधक, उद्यमी या फिर एक्टिविस्ट... गीतांजलि को किसी एक भूमिका में बांधना संभव नहीं। भुवनेश्वर के जेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मार्केटिंग और फाइनैंस में MBA किया है उन्होंने। वह 'हीलियस बुक्स', 'ओम हॉस्पिटल्स', 'ओम ट्रस्ट और 'लव योर लिवर फाउंडेशन' की संस्थापक हैं। बतौर entrepreneur उन्होंने एजुकेशन, हेल्थकेयर और वेलनेस पर काम किया है।

बदल रहीं पढ़ाई का तरीका

कॉरपोरेट करियर छोड़कर 2017 में उन्होंने HIAL की शुरुआत करने में सोनम की मदद की। इस संस्थान का मकसद है शिक्षा को असल जिंदगी से जोड़ना। 2022 में उन्हें वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

मीम बहार

कोई पढ़े है युद्ध कला तो किसी को भाए डीलिंग। मीम बनाकर देखा हमने, आए कैसी फीलिंग।

सीटों से कहीं ज़्यादा है माले का प्रभाव

हेमंत राजौरा

बिहार की राजनीति में इस बार दोनों गठबंधनों के बीच छोटे-छोटे दलों की बड़ी भूमिका होगी। इसका कारण है इन छोटे दलों का सीमित, लेकिन निर्णायक वोट बैंक। यह वोटबैंक नजदीकी सियासी संघर्ष में संतुलन बनाता है। इन्हीं दलों में एक है माले यानी CPI-ML।

समर्पित कार्यकर्ताओं का दल

बिहार में माले का प्रभाव उसकी सीटों की संख्या से अधिक उसके काडर-बेस, जनआंदोलनों और वैचारिक मजबूती के कारण है। माले हमेशा से सीमित प्रभाव, लेकिन ठोस ताकत की पार्टी रही है। कई विधानसभा क्षेत्रों में उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में माले ने वाम दलों के साथ मिलकर 98 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन केवल 3 सीटें जीत पाई। सीख यह थी कि अकेले वाम दलों के साथ मिलकर लड़ना माले के लिए लाभकारी नहीं है।

यह निर्णायक मोड़ था। 2020 के विधानसभा चुनाव में माले ने महागठबंधन के साथ 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से 12 सीटें जीतीं। यह 63% स्ट्राइक रेट थी, जो पूरे महागठबंधन में सबसे अधिक थी। राज्य भर में माले को 3.16% वोट मिले। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि माले ने उन इलाकों में जीत दर्ज की, जहां RJD और कांग्रेस कमजोर थीं। माले ने गठबंधन को जमीनी कार्यकर्ता की ताकत दी। साल 2020 का विधानसभा चुनाव निर्णायक था। माले की जड़ें 1960-70 के दशक के नक्सलबाड़ी आंदोलन में हैं। भोजपुर, आरा, जहानाबाद, सासाराम जैसे इलाकों में सामाजिक संघर्षों के बीच माले उभरी। 1989 में पहली बार वह मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में उतरी और इंडियन पीपल्स फ्रंट (IPF) के नाम से चुनाव लड़कर रामेश्वर

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

प्रसाद को आरा से सांसद बनाया। यह उसके चुनावी सफर की शुरुआत थी। माले ने अपना राजनीतिक और सामाजिक आधार मुख्य रूप से दलित, महादलित और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बीच तैयार किया। एक समय माले ने कोयरी जैसी ओबीसी जातियों के बीच भी प्रभाव बनाया था, खासकर आरा, रोहतास, पटना और औरंगाबाद में। हालांकि 1990 के दशक में RJD के उभार के बाद यह आधार खिसकने लगा। RJD ने माले से आए नेताओं को महत्वपूर्ण पद देकर अपने साथ जोड़ लिया। IPF से जुड़े चार विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, के.डी. यादव, उमेश सिंह और सूर्यदेव सिंह RJD में शामिल हो गए।

चुनौतियां कम नहीं

अब जब RJD उसी गैर-यादव पिछड़े और दलित वोट को अपने पाले में करने की मशक्कत कर रही है, तो माले कुछ इलाकों में उसका काम आसान करती है। फिर भी माले के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बिहार की राजनीति मुख्य रूप से जातीय समीकरणों पर टिकी हुई है, जबकि माले की राजनीति वैचारिक और वर्गीय है। इसलिए उसे अपने वर्गीय अजेंडे को जातीय राजनीति के साथ जोड़ना पड़ता है। माले की पकड़ ग्रामीण और संघर्षशील समाज पर मजबूत है, लेकिन शहरी मध्यवर्ग और नए मतदाताओं में उसका प्रभाव अभी सीमित है। BJP द्वारा राष्ट्रवाद और विकास का नैरेटिव भी माले के वर्ग संघर्ष वाले नैरेटिव से टकराता है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

बेजोड़ प्रदर्शन

भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन कर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। एक समय था जब हम एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रहा करते थे, मगर अब पूरी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जिस खिलाड़ी की जब जरूरत होती है, वह टीम के लिए अपना योगदान देकर टीम को मुसीबत से बाहर निकाल देता है। एशिया कप में यह देखने को मिला कि हर युवा खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बधाई की हकदार है टीम इंडिया।

– **साजिद अली**, ईमेल से

readersmail.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

Machine Translated by Google

दाँत और तनाव

केरल द्वारा वन्यजीव अधिनियम में किए गए बदलावों से राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय प्रभावित होंगे

कश्मीर वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करने का एराला का निर्णय (संरक्षण) अधिनियम, 1972, पर्यावरण शासन पर संघीय विमर्श में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वन्य जीव संरक्षण (केरल संशोधन) विधेयक, 2025, राज्य को वे शक्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करता है जो अब तक केंद्र सरकार के पास सुरक्षित थीं। हालाँकि यह महत्वाकांक्षा एक दर्दनाक, जीवंत संकट में निहित है, लेकिन केंद्र-राज्य मतभेदों को दरकिनार करने का प्रयास, पारिस्थितिक विवेक और संघीय स्वायत्तता के बीच तनाव को उजागर करता है।

विधेयक में यह दावा किया गया है कि राज्य यह तय कर सकता है कि अनुसूची II का कोई पशु कब 'पीड़क' बन गया है, और इस प्रकार विशिष्ट क्षेत्रों और अवधियों के लिए उस अनुसूची के तहत सुरक्षा खोने के लिए उत्तरदायी है। यह मुख्य वन्यजीव वार्डन को किसी भी ऐसे पशु को, जिसने किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया हो, मारने, बेहोश करने, पकड़ने या स्थानांतरित करने का आदेश देने की शक्ति भी प्रदान करता है। राज्य के खेतों, बस्तियों और जंगलों के घने क्षेत्र में जंगली सूअरों के साथ हिंसक टकराव हुए हैं। केंद्रीय अधिनियम के तहत जंगली सूअर को 'पीड़क' घोषित करने के लिए विधानसभा के प्रस्ताव और नई दिल्ली के मंत्रीगण के दौरे निष्फल साबित हुए हैं। पूर्व में वन क्षेत्रों में मानव बस्तियों के निरंतर विस्तार के संदर्भ में, इस परिवर्तन से पशु व्यवहार के बजाय मानवीय प्रगति से उत्पन्न घातक परिणामों के सामान्य होने का जोखिम है। यह कहा गया है कि, केंद्र की 'पीड़क' घोषित करने की शक्ति का प्रयोग अक्सर पारदर्शी मानदंडों या विशिष्ट पारिस्थितिकी और दबावों का सामना करने वाले राज्यों के साथ समय पर संवाद के बिना वीटो के रूप में किया गया है। इस प्रकार केरल की हताशा एक संघीय आलोचना है।

हालाँकि, उसी कुंद शक्ति को राज्य को सौंप देने से अपने आप में अस्पष्टता की बुराई का समाधान नहीं होता। एक न्यायशास्त्र जो परिस्थितियों से जुड़ा है, उसे यह अवश्य पूछना चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुईं और क्या गैर-घातक विकल्प विश्वसनीय रूप से समाप्त हो गए थे। केंद्रीय अधिनियम की धारा 62 अंधाधुंध वध को संरक्षण आधार रेखाओं को नष्ट होने से बचाने के लिए मौजूद है। वन्यजीव समवर्ती सूची में आता है और केंद्रीय अधिनियम के विरुद्ध किसी भी राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि उस परीक्षण को केंद्र बनाम राज्य के रूप में तैयार किया जा सकता है, तो यह इस बारे में भी है कि क्या केरल का सहारा राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों को हस्तांतरित रूप में फिर से बनाता है। एक बचाव योग्य समझौता आधारों को संरक्षित करेगा, अर्थात, आधारभूत सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में कोई कमी नहीं; स्पष्ट, तेज़ प्रक्रियाओं के रूप में राज्य-स्तरीय सीमाएँ बनाना; गैर-घातक टूलकिट और जवाबदेह, डेटा-संचालित सीमाएँ हस्तांतरित करना; और सह-अस्तित्व को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहनों को समायोजित करना। तब तक, जंगली सूअर को 'पीड़क' घोषित करना या बोन-नेट मकाक को केंद्रीय अधिनियम की अनुसूची I से अनुसूची II में डालना, राजनीतिक समय हासिल करने के साथ-साथ, उस चक्र को और गहरा करने का जोखिम पैदा कर सकता है जिसमें शासन की विफलता घातक शॉर्टकट को जन्म देती है। अगर तात्कालिकता वास्तविक है, तो यह सुनिश्चित करने का दायित्व भी वास्तविक है कि गति तर्क का स्थान न ले ले और संघीय विकेंद्रीकरण संघीय त्याग में न बदल जाए।

विस्फोटों को रोकें

भारत को विस्फोटकों से निपटने वाली इकाइयों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना चाहिए

टी आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले के वी. सवारम गांव में एक रिक्रैकर इकाई में हुआ विस्फोट, जिसने आठ लोगों की जान ले ली, दीपावली से पहले के हफ्तों में हर साल होने वाली दुर्घटनाओं की श्रृंखला में सबसे ताजा घटना है। यह इकाई जिले की उन 18 रिक्रैकर निर्माण इकाइयों में शामिल थी, जिनका लगभग एक महीने पहले सुरक्षा ऑडिट हुआ था। इकाइयों को जिला कलेक्टर द्वारा लाइसेंस जारी किए गए थे। जिले में पहले के वर्षों में भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है। रिक्रैकर निर्माण पर तीन दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया है और नए सिरे से सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट में कोई विसंगति नहीं पाई गई और कोई लाल झंडा नहीं उठाया गया। 18 रिक्रैकर निर्माण इकाइयों के अलावा, जिले में 18 अन्य इकाइयाँ हैं जो सीजन के दौरान पटाखे थोक में खरीदती और बेचती हैं पटाखे बनाने के लिए रसायनों का इस्तेमाल करने वाली इकाई में 10 लोग काम कर रहे थे, तभी बिजली के तार के फटने से विस्फोट हो गया और एक दीवार ढह गई। अधिकारियों द्वारा मृतकों की पहचान करना मुश्किल होना, रिकॉर्ड रखने में हुई गड़बड़ी की ओर इशारा करता है। इसके अलावा, कोनासी-मा गोदावरी बेसिन में स्थित है, जहाँ व्यापक जल-विद्युत

तेल और गैस की ड्रिलिंग और पाइपलाइनों सहित परिवहन कार्य। अगर आग की दुर्घटनाएँ इन सुविधाओं तक फैल जाएँ तो विनाशकारी हो सकती हैं।

तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में पटाखा निर्माण कोई प्रमुख आर्थिक गतिविधि नहीं है।

इसलिए, जागरूकता का स्तर और जांच हमेशा उच्च नहीं होती है, और कोनासीमा ऐसा ही एक मामला प्रतीत होता है। इन इकाइयों को लाइसेंस देने वाली नोडल एजेंसी पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) है, जिसके पास विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लाइसेंसिंग के विभिन्न स्तर हैं। आग को ईंधन, हवा और प्रज्वलन के स्रोत की आवश्यकता होती है। पटाखा निर्माण इकाइयों में कई दहनशील पदार्थ होते हैं, जो ईंधन हैं, यही वजह है कि आग के स्रोत पूरी तरह से अनुपस्थित होने चाहिए। यह इस कारण से भी है कि बिजली के उपकरण और स्विच-बोर्ड को उच्च आग सुरक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए और आंतरिक रूप से आग लगने से बचाना चाहिए। यहां तक कि अगर कोई बिजली की आग लग भी जाए, तो यह उन क्षेत्रों में नहीं फैलनी चाहिए जहां विस्फोटक रसायनों का उपयोग किया जाता है। PESO प्रोटोकॉल में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत यह है कि बिजली के उपकरण केवल तभी संचालित किए जा सकते हैं जब कोई मानव मौजूद न हो यह दुर्घटना दर्शाती है कि देश भर में ऐसी सभी इकाइयों के लिए पीईएसओ के उच्च-स्तरीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को ईमानदारी से लागू करना आवश्यक है।

भारत का मानसिक स्वास्थ्य संकट, चीखें और जख्म

अमल चंद्रा

एक लेखक, नीति विश्लेषक और स्तंभकार हैं

नैमिषा

संस्थापक हैं और यूथोक्रेसी के सीईओ और निर्माण कर रहे हैं Umeed, an Artificial खुफिया-संचालित मानसिक स्वास्थ्य सहायता मंच

I n Shahjahanpur, Uttar Pradesh, a young

हाल ही में एक दंपत्ति ने अपने चार महीने के बेटे को ज़हर देकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने अपने घर और कार को बेचकर कर्ज़ चुकाने की इच्छा जताई थी। कुछ महीने पहले, मीडिया में खबरें आईं थीं कि देश के कोचिंग हब कहे जाने वाले राजस्थान के कोटा में कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। इन त्रासदियों को अलग-अलग विसंगतियों के रूप में देखते हुए, ये भारत में एक संकट को उजागर करती हैं - एक गंभीर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संकट जो गाँवों, शहरों, कक्षाओं, बोर्डरूम, खेतों और घरों तक फैला हुआ है।

पूरे भारत से डेटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की भारत में

आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI) 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,71,418 आत्महत्याएं हुईं - पिछले वर्ष से 0.3% की वृद्धि। फिर भी, प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर आत्महत्या की दर में 0.8% की मामूली गिरावट आई, जो दर्शाता है कि जनसंख्या वृद्धि ने मामले बढ़ने की गति को पीछे छोड़ दिया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और केरल में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सभी मौतों का 40% से अधिक हिस्सा था। शहरी जीवन के दबाव को दर्शाते हुए, शहरों में ग्रामीण भारत की तुलना में आत्महत्या की दर लगातार अधिक रही। पुरुषों ने सभी पीड़ितों का 72.8% हिस्सा बनाया, जिससे लिंग आधारित आर्थिक और सामाजिक तनाव का पता चला। पारिवारिक समस्याएँ लगभग एक तिहाई (31.9%) आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं

कृषि क्षेत्र में संकट बरकरार है, 10,786 किसानों ने आत्महत्या की है, जो 2023 में दर्ज कुल आत्महत्याओं का लगभग 6.3% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम है। ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए। लेकिन एक व्यापक संकट भी है - 2014 से अब तक 1,00,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 1995 और 2015 के बीच, लगभग 2,96,000 मामले कर्ज़, फसल की विफलता, बाज़ार के झटकों और संस्थागत उपेक्षा के कारण हुए। गृहिणियाँ और देखभाल करने वाली महिलाएँ, जिनमें ज़्यादातर महिलाएँ हैं, समान रूप से अदृश्य हैं, जो अवसाद, वैवाहिक संकट और घरेलू हिंसा की उच्च दर का सामना करती हैं, लेकिन सामाजिक आँकड़ों में उनका ज़िक्र नहीं होता।

इसी पृष्ठभूमि में, हममें से एक को, एक साधारण सुबह, अचानक अस्तित्व का बोझ असहनीय लगा—बीमारी या थकान से नहीं, बल्कि इस सुन्न कर देने वाले एहसास से कि हर छोटी-बड़ी हरकत, जैसे दाँत ब्रश करना या किसी संदेश का जवाब देना, अब अर्थहीन हो गई थी। फ्रिज में खाना रखा था, काम चल रहा था, और कोई संकट नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी भारीपन बेकाबू था। उस शांत घबराहट भरे पल में, किसी से बात करने से ज़्यादा सुरक्षित लगा किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्लेटफ़ॉर्म से संपर्क करना।

तकनीक इंसानी संगति से ज़्यादा सुलभ क्यों लगती है? यह एक ऐसा पल था जिसने एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर किया: अनगिनत भारतीय एल्गोरिदम पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मदद के लिए कोई और नहीं है। यह तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि मानवीय विफलता है।

लगभग 23 करोड़ भारतीय अवसाद और चिंता से लेकर द्विध्रुवी विकार और मादक द्रव्यों के सेवन जैसी मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। फिर भी, गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाँच में से चार से ज़्यादा लोगों को कलंक, लागत और पेशेवरों की भारी कमी के कारण कोई औपचारिक देखभाल नहीं मिल पाती। जीवन भर में यह बीमारी 10.6% तक पहुँच जाती है, और इलाज में 70% से 92% तक का अंतराल रहता है। सामाजिक आत्महत्या की दर स्थिर प्रतीत होने के बावजूद, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि प्रति 1,00,000 लोगों पर 16.3 मौतें होती हैं, जो भारत के भारी मानसिक स्वास्थ्य बोझ को दर्शाता है।

इन संख्याओं के पीछे ऐसे जीवन छिपे हैं, जैसे एक युवा विश्वविद्यालय छात्रा, जिसने एक नोट छोड़ने के बाद पुल से छलांग लगा दी थी, जिसमें उसने कहा था कि वह "अयोग्य" महसूस करती है - एक ऐसा शब्द जो छात्रावासों, कार्यालयों और अपठित संदेशों में चुपचाप गूंजता है, और मौन निराशा को दर्शाता है।

व्यवस्था में खामियाँ: भारत की मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रति एक लाख लोगों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सकों की उपलब्धता के साथ, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूनतम 1.7 से काफी कम है, और आदर्श तीन से भी बहुत दूर है। इसके अलावा, नर्सों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी कमी है, और देखभाल दुर्लभ है। स्कूलों और कॉलेजों में, "परामर्श" का अर्थ अक्सर हज़ारों छात्रों के लिए एक अंशकालिक शिक्षक होता है; कोचिंग केंद्रों और विश्वविद्यालयों में, सहायता नाममात्र की होती है और उसके लिए पर्याप्त धन नहीं होता। कागज़ों पर, कानून प्रगतिशील प्रतीत होते हैं: मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (2017) ने आत्महत्या को अपराध से मुक्त कर दिया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की गारंटी दी, जबकि राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022) का लक्ष्य मौतों को 10% तक कम करना था। फिर भी, आत्महत्याएँ बढ़ी हैं।

स्कूल-आधारित मनो-सामाजिक सहायता योजना, मनोदर्पण, काफी हद तक निष्क्रिय बनी हुई है, और 47 स्नातकोत्तर मनोचिकित्सा विभाग और 25 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत होने के बावजूद, वेतन और प्रशिक्षण में भारी अंतर बना हुआ है। यहाँ तक कि ₹270 करोड़ का मानसिक स्वास्थ्य बजट भी काफी हद तक खर्च नहीं किया गया है, जिससे नीतियाँ खोखले वादे बनकर रह गई हैं।

आज, लाखों भारतीय एआई उपकरणों की ओर रुख कर रहे हैं चैटजीपीटी के रूप में — भरोसे से नहीं, बल्कि अकेलेपन से। ओपनएआई के सीईओ, सैम ऑल्टमैन ने खुद स्वीकार किया है कि कई युवा उपयोगकर्ता इस प्लेटफ़ॉर्म को एक चिकित्सक या जीवन प्रशिक्षक की तरह मानते हैं, भले ही इसमें गोपनीयता, संकटकालीन हस्तक्षेप या गोपनीयता की गारंटी का अभाव हो। यह निर्भरता तकनीकी विश्वास को नहीं, बल्कि संस्थागत पतन को दर्शाती है। एआई मदद कर सकता है। लेकिन बिना नियमन के, यह वास्तविक, सुरक्षित मानवीय देखभाल का एक खतरनाक विकल्प बन सकता है।

सरकार को मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और परामर्श को सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाना चाहिए

भारत को मानसिक स्वास्थ्य को एक आपात स्थिति के रूप में देखना चाहिए, न कि एक बाद की बात के रूप में। सरकार को मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए और एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन करना चाहिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और महिला एवं बाल कल्याण को स्वतंत्र वित्त पोषण और स्पष्ट जवाबदेही के साथ कवर करे। पाँच वर्षों के भीतर, लक्ष्य प्रत्येक 1,00,000 लोगों पर कम से कम तीन से पाँच मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता का होना चाहिए, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती के लिए विस्तारित प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके।

परामर्श को एक सार्वजनिक ढाँचा बनना चाहिए, दान नहीं। हर स्कूल, कॉलेज, ज़िला अस्पताल और कृषि ब्लॉक में एक पूर्णकालिक प्रशिक्षित परामर्शदाता या सीधे संपर्क वाला परामर्शदाता होना चाहिए, जिसका वित्तपोषण केंद्रीय बजट से हो। इसे गैर-सरकारी संगठनों या सद्भावना पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सार्वजनिक अभियानों को मदद मांगने वालों की छवि को धूमिल करना चाहिए, उनके उबरने की कहानियाँ साझा करनी चाहिए और संकट के बारे में बातचीत को सामान्य बनाना चाहिए।

उच्च जोखिम वाले समूहों के लिए विशेष पहुँच की आवश्यकता है जैसे किसान, गृहिणियां, छात्र, दुर्व्यवहार से बचे लोगों और देखभाल करने वालों के लिए। किसानों के लिए, परामर्श को ऋण मुक्ति और आजीविका सहायता के साथ-साथ जारी रखना होगा। गृहिणियों, जो अक्सर अलग-थलग रहती हैं, को समुदाय-आधारित चिकित्सा नेटवर्क की आवश्यकता होती है।

कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल निरंतर, संस्थागत और निवारक होनी चाहिए।

ऑनलाइन सहायता के संबंध में , साथ ही, भारत को डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को तत्काल विनियमित करना चाहिए।

भावनात्मक-समर्थन ऐप्स और एआई टूल्स को गोपनीयता जोखिमों का खुलासा करना चाहिए, अनिवार्य अस्वीकरण शामिल करने चाहिए, संकट-प्रतिक्रिया पुनर्निर्देशन को शामिल करना चाहिए, और लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों तक रीयल-टाइम पहुँच प्रदान करनी चाहिए। जब तक मज़बूत नैतिक और कानूनी ढाँचे मौजूद नहीं होंगे, तब तक ऐसे उपकरण योग्य मानवीय देखभाल का स्थान नहीं ले सकते।

दांव पर सिर्फ़ ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि देश का नैतिक और सामाजिक ताना-बाना भी लगा है। आत्महत्या भारत के 15-29 साल के युवाओं में मौत का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है और दुनिया भर में महिलाओं की आत्महत्या से होने वाली मौतों में देश का हिस्सा अनुपातहीन है। मानसिक बीमारी का इलाज न होने पर 2030 तक भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की जीडीपी का नुकसान हो सकता है—नियोक्ता पहले ही अनुपस्थिति, नौकरी छूटने और बर्नआउट के कारण सालाना 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान उठा रहे हैं। हर आत्महत्या, हर टूटन एक खामोश आवाज़, एक टूटा हुआ परिवार और एक छोटा सा भविष्य है।

हममें से हर किसी ने उस सुकून को महसूस किया है जब कोई व्यक्ति या कोई व्यवस्था ये महत्वपूर्ण शब्द कहती है: "आप मायने रखते हैं"। अगर भारत सचमुच आधुनिक, प्रगतिशील और मानवीय बनना चाहता है, तो उसे चुपचाप खत्म हो रही ज़िंदगियों को बचाकर यह साबित करना होगा।

भारत को एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता है

इसे बनाएं।

एक वकील, पूर्व विधान पार्षद हैं संसद सदस्यों के सहायक (LAMP) फेलो (2024-25), और वर्तमान में संसदीय, विधायी और नीति शोधकर्ता

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस विश्व में मानसिक बीमारी की व्यापकता पर प्रकाश डालता है - एक वर्ष से भी अधिक समय से।

दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग (वैश्विक जनसंख्या का 13%) मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं। भारत भी इसका एक हिस्सा है, जहाँ 13.7% लोग आजीवन मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हैं।

भारत ने ऐतिहासिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को कानूनी रूप से प्राथमिकता दी है, जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार की गारंटी देता है, आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है, बीमा कवरेज को अनिवार्य बनाता है और रोगी की गरिमा और स्वायत्तता को सुनिश्चित करता है। यह कानून मानसिक बीमारी से प्रभावित लगभग 20 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। सुखदेव साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मानसिक स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुदृढ़ किया, जिससे सरकार सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो गई। सरकार का जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) लगभग 767 जिलों को कवर करता है, जो परामर्श, बाह्य रोगी सेवाओं और आत्महत्या रोकथाम तक पहुँच का विस्तार करता है और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकरण के एक महत्वपूर्ण प्रयास का संकेत भी देता है।

टेली मानस का शुभारंभ, एक 24X7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर ने 20,05,000 से ज़्यादा टेली-परामर्श सत्रों को संभव बनाया है, जिससे वंचित क्षेत्रों में पहुँच में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, मनोदर्पण जैसे स्कूल-आधारित सरकारी कार्यक्रम देश भर में 11 करोड़ छात्रों तक पहुँच चुके हैं।

भारत में बाधाएँ लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2015-16 से पता चला है कि विभिन्न विकारों के उपचार में 70%-92% का अंतर है, और अवसाद और चिंता जैसे सामान्य विकारों में यह अंतर 85% है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल की कमी बनी हुई है; प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक और 0.12 मनोवैज्ञानिक होने के कारण, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के उन दिशानिर्देशों से पीछे है जिनके अनुसार प्रति 1,00,000 लोगों पर कम से कम तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए।

हालाँकि डीएमएचपी ने अपना दायरा बढ़ाया है, फिर भी विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि देश भर के विभिन्न राज्यों में डीएमएचपी का कामकाज खराब है। कमियाँ दवा की उपलब्धता तक भी फैली हुई हैं, जहाँ अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवश्यक मनोविकार नाशक दवाओं के स्टॉक की कमी की रिपोर्ट करते हैं। पुनर्वास सेवाएँ, जो स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण हैं, देश भर में पहचानी गई ज़रूरतों का 15% से भी कम पूरा करती हैं। गहरा कलंक अभी भी मौजूद है क्योंकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि 50% से ज़्यादा भारतीय मानसिक बीमारी के लिए व्यक्तिगत कमज़ोरी या शर्म को ज़िम्मेदार मानते हैं। इन विफलताओं के परिणामस्वरूप लाखों लोग इलाज शुरू होने से पहले ही उपचार से बाहर हो जाते हैं या उन्हें आंशिक रूप से ही पूरा कर पाते हैं, जिससे विकलांगता और आर्थिक नुकसान बना रहता है, जिसका अनुमान 2030 तक सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है।

अब प्रतिक्रियाएँ बड़े पैमाने पर खंडित मानसिक स्वास्थ्य पहल हैं

मानसिक विकारों की वैश्विक व्यापकता है लगभग 13.6%, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम में मानसिक स्वास्थ्य उपचार में 40%-55% का अंतर है। हालाँकि यह अंतर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भारत के 70%-92% से काफ़ी कम है। ये देश अपने वार्षिक बजट का 8%-10% मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित करते हैं; भारत में यह केवल 1.05% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD)-11 निदान पुस्तिका में जटिल अभिघातजोत्तर तनाव विकार (PTSD), दीर्घकालिक शोक विकार और गेमिंग विकार जैसी उभरती हुई स्थितियाँ शामिल हैं—ये सभी भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीतियों और दिशानिर्देशों में अनुपस्थित हैं, इसलिए, अनुकूलित देखभाल मॉडल सीमित हैं।

इन देशों ने मध्यम स्तर के मानसिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को अपनाया है जो लगभग 50% परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं; भारत में, कार्यबल शहरी विशेषज्ञ डॉक्टरों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ सार्वभौमिक हैं और बीमा कवरेज 80% से अधिक है, जबकि भारत में यह 15% से कम है। डिजिटल और स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम उन्नत देशों में 20%-30% आबादी तक पहुँचते हैं, जबकि भारत का टेली मानस, देश में 53 टेली मानस के साथ, आशाजनक होने के बावजूद, सभी क्षेत्रों में व्यापक पहुँच की आवश्यकता है। ये देश वास्तविक समय में कैस्केड निगरानी के लिए मज़बूत मानसिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणालियाँ भी बनाए रखते हैं, जिनका भारत में बड़े पैमाने पर अभाव है, क्योंकि यहाँ डेटा संग्रह की प्रक्रियाएँ खंडित हैं और धन की कमी है।

भारत में सामाजिक-राजनीतिक कलंक की गहरी जड़ें जमी हुई हैं, जो राजनीतिक प्राथमिकता और नवीन नीतिगत गति को सीमित कर रही हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और श्रम के लिए जिम्मेदार मंत्रालयों में भिन्नता बनी हुई है, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहल खंडित हो रही है।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान निधि कुल स्वास्थ्य अनुसंधान बजट से भी बहुत कम है, जिससे साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में बाधा आती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़ते बजटीय आवंटन के बावजूद, कुल स्वास्थ्य व्यय का 1.05% हिस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित न्यूनतम 5% की तुलना में अपर्याप्त है। विशेषज्ञ-केंद्रित मॉडलों के प्रभुत्व को देखते हुए, मध्य-स्तरीय प्रदाता भूमिकाओं के प्रति प्रतिरोध के कारण कार्यबल की कमी और भी बदतर हो गई है।

इसके अलावा, ग्रामीण आबादी, जो भारत की जनसांख्यिकी का 70% है, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी का सामना कर रही है।

उठाए जाने वाले कदम

इस अत्यंत अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत को व्यापक नीतिगत सुधार करने होंगे।

सरकार को मानसिक स्वास्थ्य बजट को कुल स्वास्थ्य व्यय के कम से कम 5% तक बढ़ाना चाहिए, बुनियादी ढाँचे, कार्यबल भर्ती और दवा आपूर्ति को सुविधाजनक बनाना चाहिए। मध्य-स्तरीय प्रदाता प्रशिक्षण और तैनाती को बढ़ाने से शहरी-ग्रामीण असमानताएँ कम होंगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन के न्यूनतम कार्यबल घनत्व को पार किया जा सकेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य के पूर्ण एकीकरण से देश भर में सुलभ और किफायती देखभाल सुनिश्चित होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आईसीडी-11 विकारों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय निदान नियमावली और नीतियों को अद्यतन करने से उभरती मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए केंद्रित हस्तक्षेप संभव होगा।

जिला और राज्य स्तर पर सम्बद्ध बजट के साथ कठोर कैस्केड-आधारित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करने से जवाबदेही में सुधार हो सकता है, उपचार छोड़ने वालों पर नज़र रखी जा सकती है और लक्षित संसाधन आवंटन को दिशा दी जा सकती है।

कलंक-विरोधी अभियानों का विस्तार, विशेष रूप से स्कूलों और कार्यस्थलों में, और यह सुनिश्चित करना कि 2027 तक 60% से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता पहुँच जाए, शीघ्र सहायता प्राप्त करने को प्रोत्साहित करेगा। अंततः, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और श्रम नीतियों को संरेखित करते हुए मज़बूत अंतर-मंत्रालयी समन्वय एक एकीकृत मानसिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तैयार कर सकता है, जिससे तालमेल और परिणाम अधिकतम हो सकते हैं।

द टटर्सटूदएडिटर

ओशियल की टिप्पणियाँ

यह जानकर आश्चर्य होता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को सभी चुनावों की जननी बताया है।

लोकतंत्र में हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसे बड़ा या छोटा नहीं कहा जा सकता। साथ ही, चुनाव भारतीय आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को शुद्धिकरण प्रक्रिया बताना एक चौंकाने वाला बयान है। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास करती है और इसे शुद्धिकरण प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता।

बालासुब्रमण्यम पावनी, सिकंदराबाद

यह दवा क्यों?

इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद विश्वस्तरीय मानकों को पूरा करें तथा फार्मा-संदूषण किस प्रकार विश्व की फार्मेसी के रूप में भारत की स्थिति को प्रभावित करेगा।

हालाँकि, इससे भी बड़ी बात यह है मुद्दा — भारत में कफ सिरप के प्रति लोगों का बेवजह जुनून। इस कॉकटेल का बाज़ार क्यों है? मीठे सिरप के आधार पर बनाई गई दवा, जो कफ निस्सारक और कफ निस्सारक के रूप में उपलब्ध है? क्या 'खांसी' क्या यह भारतीय कस्बों और शहरों में वायु प्रदूषण के बड़े और अनसुलझे मुद्दे की ओर इशारा करता है?

डॉ. ज्योति सिंह, नई दिल्ली

सुधार और स्पष्टीकरण

पहले पन्ने पर छपी रिपोर्ट, "हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से बस के कुचलने से 15 लोगों की मौत" (8 अक्टूबर, 2025), में अनुग्रह राशि ₹2 लाख होनी चाहिए थी, न कि ₹1 लाख।

पाठक संपादक की राय से टेलीफोन: +91-44-28576347/28576300; ई-मेल: readereditor@thehindu.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में पूरा डाक पता और पूरा नाम या नाम के साथ प्रारंभिक अक्षर अवश्य होने चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
पटना। शुक्रवार • 10 अक्टूबर • 2025
www.rashtriyasahara.com

आर्थिक नगरी के नए युग की उड़ान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ है। लगभग 19650 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह एयरपोर्ट न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की विकास गाथा में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। देश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक-छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट-पर लंबे समय से यात्रियों और उड़ानों का अत्यधिक दबाव था। ऐसे में नवी मुंबई एयरपोर्ट का बनना इस दबाव को कम करने के साथ-साथ देश की उभरती अर्थव्यवस्था को पंख देने का काम करेगा। जिससे आर्थिक नगरी की उड़ान बेहतर हो सकेगी। मुंबई पहले से ही व्यापार, उद्योग और वित्त का केंद्र मानी जाती है। अब जब उसके पास दूसरा विश्वस्तरीय एयरपोर्ट होगा, तो न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी,

बल्कि निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए नए अवसर भी खुलेंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट के माध्यम से दक्षिण मुंबई से लेकर रायगढ़ और पुणे क्षेत्र तक की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यह क्षेत्र अब आईटी, पर्यटन, व्यापारिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो सकता है। यह परियोजना न केवल भौतिक अवसंरचना का विस्तार है, बल्कि एक नए आर्थिक क्षेत्र की नींव भी है। इस एयरपोर्ट के संचालन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार सृजित होंगे। निर्माण से लेकर हवाई सेवाओं, होटल उद्योग, परिवहन और व्यापार तक हर क्षेत्र को गति मिलेगी। साथ ही, यह पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक आधुनिक परियोजना मानी जा रही है, जिसमें सौर ऊर्जा और हरित तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे भारत की ग्रीन एविएशन की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। परंतु हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह चुनौतियां भी है-स्थानीय निवासियों का पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार और स्थानीय निकायों को संवेदनशील और पारदर्शी रहना होगा। केवल ढांचागत विकास ही नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है ताकि विकास समावेशी हो। इस एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ मुंबई की उड़ानें अब और ऊंची होंगी। यह परियोजना न्यू इंडिया की उस सोच का प्रतीक है, जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। मुंबई-जो कभी सपनों का शहर कही जाती थी-अब विश्व स्तरीय संपर्क के साथ एक नई दिशा में बढ़ रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि भारत के विकास की नई राह है-जहां आसमान अब सिर्फ उड़ानों का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है।

प्रशंसनीय पहल

उत्तर प्रदेश में हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए योगी सरकार का ऐलान वाकई सराहनीय है। योगी आदित्यनाथ की सरकार 1 अगस्त से 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं' का विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। यह विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितम्बर तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। दरअसल, देशभर में बिना हेलमेट लगाए बाइक चालकों की मौत का आंकड़ा व्यापक है। देश में साल 2021 में हेलमेट न पहनने के कारण लगभग 47,000 लोगों की मौत हुई, जो कि हर घंटे चार लोगों की मौत के बराबर है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हेलमेट न पहनने के खतरनाक परिणामों को दर्शाते हैं, खासकर दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए, जहां मौतें अक्सर हेलमेट के इस्तेमाल से रोकी जा सकती है। राज्य सरकार के इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला

प्रशासन के अधिकारी मिलकर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, मगर सड़कों पर कुछ दिनों के अभियान के बाद हालात पहले की तरह लापरवाही भरे दिखने लगते हैं। कई बार तो जुर्माने से बचने के लिए युवा तबका बाइक को ज्यादा तेज गति से भगाने लगता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। शायद इसी बात को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि इसका लक्ष्य नागरिकों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईंधन तभी, जब हेलमेट सिर पर हो। बहरहाल, सरकार को इस नियम को कायदे से लागू करवाने के लिए जरूरत से ज्यादा मशक्कत करने की कवायद करनी पड़ेगी। काफी अरसा पहले दूरदर्शन में हेलमेट की महत्ता और लोगों की जान की कीमत को लेकर एक विज्ञापन दिखाया जाता था। वैसे भी एक बात सभी को समझनी चाहिए कि बिना सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किए कोई भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए कार सवार के लिए सीट बेल्ट और बाइक सवार के लिए हेलमेट का इस्तेमाल जीवन रक्षा की गारंटी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला निःसंदेह प्रशंसनीय है।

कटाक्ष/सहीराम

हैप्पी बर्थ डे

आरएसएस के सौवे बर्थ डे पर मीडियावालों ने भाजपा के नए-नवेलों ने, नौकरशाहों ने और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज ने कुछ-कुछ इसी अंदाज में उसकी बलैया ली जैसे बच्चे के बर्थ डे पर ली जाती है कि तुम जीओ, हजारों साल। बदले में उन्हें सत्ता के केक का स्वाद चखने को मिला और साथ में यह आश्वासन भी कि सत्ता की माल-मलाई भी वक्त आने पर जरूर मिलेगी। बल्कि मौका देखकर मुन्ना भाई ने तो गांधीवाद का पाठ पढ़ाते-पढ़ाते स्वयंसेवकों की ऐसी तारीफ की जिन्हें सुनकर ऊपर गोडसे तो ऐसे ठट्ठाकर हंसे कि गांधीजी भी चौंक गए। बोले-क्या हुआ बेटा, तुमने फिर कोई निशाना लगा दिया क्या! एकदम सटीक- गोडसे से गांधीजी को चिढ़ाते हुए कहा-देखो तुम्हारा चेला मुन्ना भाई कैसे स्वयंसेवकों के गुण गा रहा है। गांधीजी मुस्कुराए और जाकर सीनियर दत्त साहब को धीर बंधाने उनके साथ बैठ गए। सीनियर दत्त साहब की रूलाई फूट गयी-बापू, मैं क्या करूं इस लड़के का, टाडा से और ड्रग्स से तो मैं निकाल लाया था इसे। पर अब तो मैं हूं नहीं, क्या होगा इसका। खैर, स्वयंसेवकों ने मुन्नाभाई का ऐसे स्वागत किया जैसे कह रहे हों कि अब आया न लाइन पर।

उधर कांग्रेस से दलबदलकर भाजपा में शामिल हुए एक नए-नवेले भाजपाई को जब घरवालों ने गणवेश में देखा तो बीवी की हंसी छूट गयी और बच्चे हैरान रह गए। बीवी ने कहा-यह क्या भेष बना रखा है? नेताजी ने कहा-शाखा में जा रहा हूं। बेटी ने कहा-यह कौन सा स्कूल है, जहां अभी भी खाकी पैंट और सफेद शर्ट चल रही है। उन्होंने कहा-चुप कर गनीमत है कि पैंट है, वरना दो साल पहले यह सब करना पड़ता तो खाकी निक्कर ही पहननी पड़ती। और यह काली टोपी क्या है-बेटे ने कहा और फिर एकदम मुन्ना भाई के अंदाज में बोला-एकदम मामू लग रहे हो। एक झापड़ दूंगा-नेताजी ने कहा-गधा कहीं का। बीवी ने बच्चों को समझाया-नहीं बच्चो, पापा का मजाक नहीं बनाते। फिर वह नेताजी की तरफ मुखातिब हुयी और अपनी हंसी रोकते हुए बोली-अच्छा यह तो बताओ, जहां जा रहे हो, वह है क्या बला। कोई मीटिंग है, कोई जलसा-जुलूस है, भाषण देना है, धरने पर बैठना है। कुछ तो बताओ। अरे यूं समझो भागवान-नेताजी ने कहा-कि बर्थडे पार्टी है। किसकी-सारे घरवाले एकदम से पूछ बैठे। अरे वो भाजपा का पितृसंगठन है न-नेताजी ने कहा- आरएसएस, उसका हैप्पी बर्थडे है। अच्छा-बेटे ने फिर मजाक किया-तो माल उड़ाने जा रहे हो पापा! अरे माल उड़ाने के लिए ही तो यह गणवेश धारण किया है बेटा-नेताजी ने कहा। पर मामू लग रहे हो एकदम-बेटे ने फिर चिढ़ाया। झापड़ लगेगा-नेता जी ने फिर आंखें तरेरी!

महिलाओं की बेहतरी का नया दौर शुरू

महिलान्मुखी नीतियां

डॉ. शालिग्राम सिंह

देश आपातकाल से पांच दशक आगे निकल चुका है। ऐसे में समाज, राजनीति और लोकतंत्र का साझा विमर्श कई नए महाने खोल रहा है। लिहाजा नई वैश्विक परिस्थितियों के बीच आज भारत के समकाल और देशकाल को देखना खासा दिलचस्प है। यह भी कि इस वर्ष जब आखिरी विधानसभा चुनाव के रूप में बिहार में नई सरकार चुनी जानी है तो जयप्रकाश आंदोलन के भी पचास वर्ष पूरे हो रहे है। ऐतिहासिक रूप से बिहार इस आंदोलन का एक तरह से एपिक सेंटर था। इन पांच दशकों में जरूर गंगा में बहुत पानी पानी बह चुका है, पर समय के इस बहाव के बीच कुछ चीजें स्थिर भी हुई है और वे नई मिसालें और मानदंडों के साथ हमारे समय में लोकनीति और विकास को व्याख्यायित कर रही है। इस बात की बड़ी अहमियत है कि जिस बिहार में आकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र देश-दुनिया को दिया, आज उस सूबे की धरती पर महिलाओं ने एक बड़ी मूक क्रांति को सच कर दिखाया है। यह क्रांति महिला सशक्तीकरण की इकहरी समझ से आगे कई मायनों में सर्व-समावेशी है और इससे इस प्रदेश की महिलाओं के साथ ग्रामीण इलाकों में विकास और बदलाव का एक सर्वथा नया दौर सामने आया है। इस लिहाज से इन दिनों मख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की खासी चर्चा हैं। आकार के लिहाज से यह देश की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, जिसने न सिर्फ सामाजिक बदलाव की जमीन को मजबूत किया है, बल्कि इसे महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का सर्वथा नया दौर शुरू हुआ है।

गौरतलब है कि बीते 26 सितंबर को जब यह योजना शुरू हुई तो 75 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके कुछ ही दिन बाद 25 लाख और महिलाओं को इसमें जोड़ा गया और उनके भी खाते में पैसे पहुंचे। इसी तरह तीसरे चरण में 21 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़ीं। इस तरह 75 लाख का आंकड़ा देखते-देखते एक करोड़ 21 लाख पर पहुंच गया। राज्य क्या देश के स्तर पर पर भी यह संख्या ऐतिहासिक तौर असाधारण है। महिलाओं को यह राशि स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए दी जा रही है।

वस्तुतः चुनाव से पूर्व होने वाली तमाम तरह की अव्यावहारिक और हवाई घोषणाओं से अलग बिहार सरकार ने कैबिनेट स्तर पर बीते कुछ महीने में कई अहम फैसले लिए है। इस क्रम में जो बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है, वह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। राज्य सरकार ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं की स्थिति और जरूरत को समझते हुए न सिर्फ फ्रेम किया, बल्कि इसके शीघ्र क्रियान्वयन को लेकर भी वह लगातार गंभीर रही। योजना के तहत जिन महिलाओं को दस हजार रुपए की मदद मिली है, उन्हें छह महीने बाद मूल्यांकन पर खरा उतरने पर दो लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। साफ है कि एक ऐसे दौर में जब मुफ्त की रेवड़ी बांटकर सत्ता में आने का सियासी फार्मूला बढ़-चढ़कर आजमाया जा रहा है, बिहार सरकार की यह योजना महिला सशक्तीकरण और महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के बड़े लक्ष्य को सामने

रखकर आगे बढ़ रही है।

बात महिला सशक्तीकरण की हो रही है तो यह जान लेना जरूरी है बिहार में नीतीश सरकार की सबसे सफल योजनाओं में जीविका है। विश्व बैंक की मदद से वर्ष 2006 में शुरू इस योजना के बूते आज राज्य में एक करोड़ 40 लाख से अधिक महिलाएं 11 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जीविका दीदी के रूप में पहचान बना चुकी है। ये महिलाएं सिलाई, बुनाई, कृषि, पशुपालन, किराना दुकान, मसाला निर्माण, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन जैसे छोटे-छोटे उद्योगों के जरिए न केवल अपनी आमदनी बढ़ा रही है, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही है। आज की तारीख में जीविका देश में महिला स्वरोजगार का सबसे बड़ा समूह है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जीविका के ही मॉडल का विस्तृत रूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीविका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। इन महिलाओं को सरकार की आर्थिक मदद स्वरोजगार शुरू करने, छोटे-मोटे बिजनेस शुरू करने या वर्तमान में चल रहे व्यवसायों को बढ़ाने में सहायता के उद्देश्य से दी जा रही है। इससे बड़ी किसी योजना की सफलता और उपयोगिता क्या होगी कि इसके लिए 1.05 करोड़ जीविका दीदियों ने, जबकि 1.40 लाख से अधिक महिलाओं ने समूह से जुड़ने के लिए आवेदन किया।

जो लोग बिहार की राजनीतिक-सामाजिक स्थिति को कम से कम बीते दो दशकों से गौर से देख रहे है, वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस विवेक की जरूर दाद देते है कि इन वर्षो में उन्होंने सूबे की महिलाओं को सिर्फ मतदाता नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन की धुरी बनाया। भूले नहीं है लोग कि देश में मंडल और कमंडल की राजनीति के अश्वमेध का घोड़ा एक साथ दौड़ा तो बिहार की जनता ने राजनीति से जुड़े सामाजिक सरोकारों का तार्किक चुनाव किया। आज इस बात को लेकर एक बड़ी आम स्वीकृति है कि बीते दो दशक में राजनीतिक स्थिरता के साथ बिहार ने विकास और सामाजिक बदलाव की जो राह पकड़ी है, वो अपनी यात्रा में तो लंबी है ही, देश के सामने परिवर्तन, विकास और राजनीति का एक संतुलित मॉडल भी है। इस मॉडल के नायक निस्संदेह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिनकी मौजूदगी आज प्रदेश में हर राजनीतिक गठजोड़ के लिए अपरिहार्य बनी हुई है। उनकी मौजूदगी एक तरफ सांप्रदायिकता के खिलाफ सद्भाव की राजनीति का आश्वासन है, तो वहीं महिलाओं और अति पिछड़ों के कल्याण को लेकर बीते दो दशक में उन्होंने सफलता की एक लंबी पटकथा लिखी है।

नए विकासवादी अभिप्रायों और लक्ष्यों के साथ बिहार को लेकर इस रूप में चर्चा का आज की तारीख में महत्व इसलिए भी है कि इससे विकास के साथ सामाजिक बदलाव के लक्ष्य को साधने वाली राजनीति की भूमिका नए सिरे से रेखांकित होती है। यह भूमिका हमारा ध्यान उस मूक क्रांति की तरफ ले जाती है जिसके बारे में बीते दो दशक में कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से लेकर विश्व मुद्रा कोष तक ने विमर्श और समकालीन नैतिक दरकार के लिहाज से काफी कुछ कहा और लिखा है। यहां तक कि दुनियाभर की सरकारों के बीच कोरोना महामारी के बाद यह नैतिक दरकार उनकी नीतिगत प्राथमिकता की एक बड़ी कसौटी बन चुकी है। बिहार आज इस कसौटी पर खरा उतरता दिख रहा है तो यह देश में राज्यों के नए वर्ग चरित्र का भी उद्घाटन है। इस चरित्र के साथ हम बदलते देश-समाज के साथ राज्यों की नई बन रही पहचान को देख सकते हैं। यह पहचान विकास के साथ सामाजिक बदलाव के ऊंचे लक्ष्य को जिस तरह स्पर्श कर रही है, वह शानदार है। खासतौर पर बिहार के लिए यह गर्व की बात है कि देश में पंचायतीराज व्यवस्था और नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण सबसे पहले देने वाले इस सूबे के पास आज महिला स्वावलंबन का अपना मॉडल तो है ही, सुशासन के रूप में नीति और राजकाज का साफ-सुथरा विवेक भी है।

(लेखक के निजी विचार हैं)

देश के एक तिहाई स्कूली बच्चे लेते हैं निजी कोचिंग

- देश के करीब एक तिहाई स्कूली बच्चे निजी कोचिंग का सहारा लेते हैं। यह प्रवृत्ति शहरों में ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा कराए गए व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर शिक्षा सर्वेक्षण (सीएमएस) में यह खुलासा हुआ है
- सर्वेक्षण के मुताबिक, सरकारी स्कूल पूरे भारत में शिक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और देश के विद्यालयों में नामांकित कुल छात्रों में 55.9 प्रतिशत हिस्सेदारी सरकारी विद्यालयों की है
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा पिछला व्यापक शिक्षा सर्वेक्षण (75वां दौर) जुलाई, 2017 से जून, 2018 के बीच किया गया था

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

कूटनीति की बलिहारी। जिस लाल कालीन पर भारत का स्वागत हुआ, उसी पर उसके पुराने दुश्मन का भी किया गया, काहे कि उनने नट की चुतराई से चीन और अमेरिका दोनों को अपने हित में नाथ लिया है।

मृणाल पांडे, पत्रकार
@MrinalPande1

यथार्थ के युग प्रवर्तक लेखक

पुण्यतिथि

अनुराग शुक्ल
वरिष्ठ पत्रकार

पं भारतीय साहित्य के आकाश में अनेक नक्षत्रों ने अपनी प्रतिभा से प्रकाश फैलाया, परंतु उनमें एक नक्षत्र ऐसा है जिसकी चमक आज भी अक्षुण्ण है - वह है कथा सम्राट मंशी प्रेमचंद। उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य को न केवल नई दिशा दी, बल्कि समाज के हर वर्ग की भावनाओं, संघर्षों और पीड़ाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से स्वर दिया। प्रेमचंद का साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण है जिसमें भारत के जनजीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, जबकि 'नवाब राय' और बाद में 'प्रेमचंद' उनका साहित्यिक नाम बना। बचपन से ही प्रेमचंद का जीवन संघर्षो से भरा रहा। उनके पिता मुंशी अजायब राय और माता आनन्दी देवी थी। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तभी मां का निधन हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिससे प्रेमचंद को स्नेह का अभाव महसूस हुआ। गरीबी के कारण उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कठिन परिस्थितियों में प्राप्त की। वाराणसी के क्वींस कॉलेज से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे चलकर अंग्रेज़ी में स्नातक की डिग्री ली। नौकरी की, परंतु साहित्य सेवा के कारण उन्होंने सरकारी बंधनों से मुक्त होकर लेखन को ही जीवन का लक्ष्य बनाया।

प्रेमचंद की साहित्यिक यात्रा उर्दू कहानी 'सोज़-ए-वतन' से आरंभ हुई, जो 1908 में प्रकाशित हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे देशभक्ति भड़काने वाला साहित्य मानकर जब्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू से हटकर हिंदी में लेखन प्रारंभ किया और 'मुंशी प्रेमचंद' नाम से अमर हो गए। उनकी पहली हिंदी कहानी 'सौत' थी, परंतु प्रसिद्धि 'पूस की रात', 'ईदगाह', 'नमक का दरोगा', 'कफ़न' और 'शतरंज के खिलाड़ी' जैसी कहानियों से मिली। उन्होंने हिंदी कहानी को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम बनाया। प्रेमचंद के उपन्यास उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण और सामाजिक सरोकारों के प्रमाण है। उनके प्रमुख उपन्यासों में 'सेवासदन', 'निर्मला', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि', 'प्रेमाश्रम', 'गोदान' और 'गबन' शामिल है। 'सेवासदन' (1918) - इस उपन्यास में उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता और समाज में स्त्रियों की स्थिति पर गहरी चोट की। नायिका सुमन के माध्यम से उन्होंने समाज की पाखंडपूर्ण नैतिकता को उजागर किया।

'निर्मला' (1927) - बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर केंद्रित यह उपन्यास हृदय को झकझोर देता है। 'रंगभूमि' (1925) - अंधे नायक सूरदास के माध्यम से प्रेमचंद ने औद्योगिक पूंजीवाद और किसान वर्ग के शोषण का यथार्थ चित्रण किया। 'गबन' (1931) - इसमें उन्होंने मध्यमवर्गीय युवकों की नैतिक दुविधा को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। 'गोदान' (1936) - प्रेमचंद का शिखर उपन्यास है। यह भारतीय ग्रामीण जीवन, किसान की व्यथा और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सबसे सजीव चित्र है। होरी महतो का चरित्र भारतीय किसान का प्रतीक बन चुका है, जो जीवनभर मेहनत करता है पर सुख नहीं पाता। यह उपन्यास प्रेमचंद की विचारधारा, उनकी संवेदना और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का चरम उदाहरण है। माना जाता है कि राम चरित मानस के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाना वाला यह कृति है।

प्रेमचंद की कहानियां समाज के सबसे निचले तबके से लेकर उच्चवर्ग तक के जीवन की सच्ची झलक देती है। 'ईदगाह' में छोटे हामिद की त्याग भावना हो, 'पूस की रात' में किसान हल्कू की दारुण स्थिति, 'कफ़न' में गरीबी से जूझते बाप-बेटे की ह्मदय विदारक कथा, या 'नमक का दरोगा' में ईमानदारी का संघर्ष - हर कहानी यथार्थ की गूंज बनकर सामने आती है। उनकी कहानियों की भाषा सरल, भावपूर्ण और जनमानस के निकट है। प्रेमचंद ने साहित्य को 'जीवन का दस्तावेज़' माना और कहा 'साहित्य समाज का दर्पण नहीं, बल्कि उसका पथप्रदर्शक होना चाहिए।'

उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, सामंतवाद, बाल विवाह, दहेज, और शोषण जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनकी लेखनी में मजदूर-किसान वर्ग की आवाज़ थी। उन्होंने कहा था-'हमारा साहित्य उस समाज के काम का नहीं, जो आरामकुर्सियों पर बैठकर जीवन का रस लेता है, बल्कि उस समाज के काम का होना चाहिए जो मिट्टी में पसीना बहाता है।' उनके लेखन ने हिंदी साहित्य को यथार्थवाद की दिशा दी, जिससे प्रेरित होकर आगे चलकर रेणु, यशपाल, नागार्जुन, अमृतलाल नागर, और फणीश्वरनाथ 'रेणु' जैसे लेखकों ने सामाजिक यथार्थ पर लेखन किया।

प्रेमचंद का जीवन 8 अक्टूबर 1936 को समाप्त हुआ, पर उनकी साहित्यिक विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 14 उपन्यास, अनेक निबंध और संपादकीय लेख लिखे। सत्यजीत रे ने उनके शतरंज के खिलाड़ी पर प्रसिद्ध फिल्म बनाई, जो प्रेमचंद के यथार्थ दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुंशी प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं, बल्कि युगद्रष्टा थे। उन्होंने अपनी कलम से समाज की आत्मा को छुआ, किसानों की पीड़ा, स्त्रियों के आँसू और गरीबों की बेबसी को शब्दों में ढाला। वे साहित्य में मानवता के पुजारी थे - जिन्होंने कहा था कि वह साहित्य निरर्थक है जो मनुष्य को बेहतर न बनाए। उनका जीवन सादगी, संघर्ष और सेवा का प्रतीक है। प्रेमचंद आज भी जीवित है - अपने शब्दों में, अपने पात्रों में, और उस हर ह्मदय में जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। वास्तव में, वे भारतीय साहित्य के अमर दीपक है, जो सदैव यथार्थ और मानवीय मूल्यों की राह को आलोकित करते रहेंगे

अपरिग्रह | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

महाभारत के वनपर्व में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद प्रसिद्ध है। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे। उनमें से एक प्रश्न यह था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य का पालन है। युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि मनुष्य चाहे कितना भी विद्वान या बलवान क्यों न हो, यदि वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसी कर्तव्यनिष्ठा के कारण युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए।

निस्संदेह, कर्तव्य का बोध ही मनुष्य को महान बनाता है। कर्तव्य का अर्थ है वह कार्य जो धर्म, नीति और जीवन मूल्यों के अनुसार उचित और आवश्यक हो। जैसे जीवमात्र के प्रति सेवा-करुणा, समाज व राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध, गुरू के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति साधना और परमात्मा के प्रति निष्ठा। ये सभी सदाचारी कर्तव्य मनुष्य के जीवन को उच्च बनाते हैं। कर्तव्य का बोध मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यही बोध उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। मनुष्य को केवल अपने सुख-दुःख तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे यह समझना चाहिए कि उसके कर्म समाज, परिवार और संपूर्ण जगत को प्रभावित करते है। यही कारण है कि धर्मग्रंथों ने बार-बार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का स्मरण कराया है।

इसके विपरीत अकर्तव्य का अर्थ है ऐसे कार्य जो धर्म, नीति और सत्य के विरुद्ध हों। जैसे किसी को छलना, हिंसा करना, अन्याय करना, असत्य बोलना या अपने उत्तरदायित्व से पलायन करना। ये सभी अकर्तव्य जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन और उसके साथियों का उदाहरण इसी का साक्षी है। उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का पथ अपनाया और अंत में विनाश का भागी बने। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो कर्त्तव्य और अकर्तव्य के बोध से युक्त होता है, वह सभी अशुभों से मुक्त हो जाता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का सही बोध विवेक से आता है। विवेक मनुष्य को यह समझने की शक्ति देता है कि कौन-सा कार्य उचित है और कौन-सा अनुचित। जब विवेक सो जाता है, तब मनुष्य स्वार्थ और मोह के कारण अकर्तव्य में फँस जाता है। इसलिए साधना, सत्संग और शास्त्र-अध्ययन से विवेक जाग्रत करना आवश्यक है। महंत स्वामी महाराज कहते है-मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह अपने प्रत्येक कार्य को धर्म और नीति के कसौटी पर कसकर करे।

रीडर्स मेल

जागरूक बनें आमजन

भले ही हमारा देश आधुनिक और तकनिकी युग में सफर कर रहा परंतु अंधविश्वास की कु-नजर आज भी कहीं न कहीं हावी है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चार बच्चों के साथ सो रहे दंपति को सांप ने डस लिया। अस्पताल ले जाने की बजाय पड़ोसियों ने झाड़ फूंक में ही समय गंवा दिया और जिससे पति-पत्नी की मौत हो गई। अक्सर अंधविश्वास की वजह से लोगों की जीवन लीला समाप्त होती है, जबकि अब देश में सर्प दंश का आसानी से उपचार संभव है। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। सबक यही होना चाहिए कि सतर्कता और सूझबूझ से हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, न कि झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र या अंधविश्वास के भरोसे रहना चाहिए। समाज में जो प्रबुद्ध लोग हैं और डॉक्टरी पेशे में हैं, उन्हें भी इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।

राम निवास, वैशाली, बिहार

सोशल मीडिया पर कम वक्त दें

सोशल मीडिया ने हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा घेर लिया है इससे जीवंत संवाद सिकुड़ता जा रहा है। आज अधिकांश लोग दिन की शुरु आत से लेकर रात तक मोबाइल स्क्रीन पर ही उलझे रहते हैं। एक ओर यह हमें सूचनाएं, सुविधा और वैश्विक संपर्क देता है वहीं यह मानवीय रिश्तों में दूरी भी पैदा कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग जितना अधिक समय बिताते हैं उतना ही वे वास्तविक संवाद और व्यक्तिगत मुलाकातों से दूर होते जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल सेवाओं ने सुविधा तो दी है, लेकिन इसके कारण बाजार, पड़ोस और समाज से मिलने-जुलने के मौके कम हुए हैं। इस कमी से धीरे-धीरे अकेलेपन की भावना गहराने लगती है। मानवीय संबंध जब केवल आभासी और संवाद में पसंद तक सीमित हो जाते हैं तब आत्मीयता और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर होने लगता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से सामाजिक बिखराव और मानसिक थकान बढ़ रही है।

रवि प्रकाश, दिल्ली

हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़े

यह पत्र 'प्रशंसनीय पहल' से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं अभियान निस्संदेह सराहनीय है, और इस तरह का अभियान पूरे देश में चलना चाहिए ताकि सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दिया जा सके। दुर्भाग्यवश भारत पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु के मामले में सबसे ऊपर आता है तो इस तरह के अभियान से दुपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में जागरूकता आती है, और उन्हें यह अहसास होगा कि हेलमेट कितना जरूरी है, लेकिन इस अभियान के ध्येय की सफलता के लिए सबसे अहम यह है कि हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि यह पता लगे की इस नियम का कड़ाई से पालन हो भी रहा है या सिर्फ यह कागजों तक ही सीमित है, और इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करा जाए कि हेलमेट भी मानकों के अनुसार ही पहना जा रहा है क्योंकि कभी-कभी देखा जाता है कि सिर्फ दिखाने के लिए कुछ लोग क्रिकेट खेल में प्रयोग किया जाने वाला या फिर कोई हल्का सा हेलमेट पहन लेते हैं ताकि पुलिस उनको पकड़े नहीं।

बलराम, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 20, अंक 6798 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

पाक आतंकवाद और कांग्रेस

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवम्बर 2008 के मुम्बई आतंकवादी हमले की याद दिलाकर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ की गई कारस्तानियों की फैहरिस्त खोल दी है। अपने जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान का भारत के प्रति रुख दुश्मनी भरा ही रहा है जबकि भारत का नजरिया अपने सभी पड़ोसियों के प्रति प्रेम भाव का रहा है। वर्ष 2008 में तो पाकिस्तान ने सारी सीमाओं को लांघ दिया था और मुम्बई शहर में खुलेआम कत्लोगारत का बाजार गर्म कर दिया था, जिसमें 167 देशी- विदेशी नागरिक मारे गये थे। इस घटना से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सकते में आ गया था क्योंकि जिन लोगों ने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया था वे पाकिस्तान से ही जल मार्ग से कराची से मुम्बई पहुंचे थे।

श्री मोदी का कहना है कि इस जघन्य कांड का विरोध तब भारत ने सैनिक जवाब देकर नहीं किया जबकि इसकी वक्ती जरूरत थी। बेशक पाकिस्तान की इस कार्रवाई के जवाब में भारत मुंहतोड़ सैनिक कार्रवाई वैसी ही कर सकता था जैसी कि श्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद हुई पाक की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ की और पाकिस्तान के घर में घुस कर उसे कई बार सबक सिखाया। 2008 नवम्बर महीने में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुम्बई में यह जघन्य कांड किया तो इसके विदेश मन्त्री महमूद कुरैशी भारत की चार दिन की राजकीय यात्रा पर आये हुए थे। उनकी भारत की सरजमीं पर मौजूदगी के दौरान ही मुम्बई में यह घटना घटी थी। तब भारत के विदेश मन्त्री भारत रत्न स्व. प्रणव मुखर्जी थे। श्री मुखर्जी ने महमूद कुरैशी को बैरंग इस्लामाबाद वापस लौटा दिया था। कुरैशी ने तब कहा था कि इस काम में पाकिस्तान का सीधा हाथ नहीं है, बल्कि कुछ गैर सरकारी लोगों (नान स्टेट एक्टर) का यह काम है। भारत ने पाकिस्तान के इस कथन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि उसकी फौज के साये में पाकिस्तान में आतंकवादी फलफूल रहे हैं जो समय–समय पर भारत में आतंकवाद फैलाते रहते हैं और निरीह नागरिकों की जान लेते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या उस समय 2008 में हुकूमत पर काबिज मनमोहन सरकार मुम्बई हमले का सैनिक कार्रवाई करके जवाब देना चाहती थी? तो इसका जवाब हमें 'हां' में मिलेगा परन्तु कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ तत्व ऐसे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं चाहते थे। उस समय के अखबारों में इस तरह की खबरें भी छपी थीं कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह सैनिक कार्रवाई के प्रबल पक्षधर थे मगर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था और विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जी पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई थी कि वह कूटनीतिक मोर्चे पर यह लड़ाई लड़ें। स्व. मुखर्जी ने तब इस मोर्चे पर ऐसा समां बांध दिया था कि पाकिस्तान के एक आतंकवादी देश घोषित होने की नौबत आ गई थी। इस्लामी दुनिया के देशों से लेकर राष्ट्रसंघ तक में पाकिस्तान अकेला पड़ गया था। तब श्री मुखर्जी ने अपने कनिष्ठ सहयोगी विदेश राज्य मन्त्री श्री ई. अहमद को राष्ट्रसंघ में भेजकर यह ऐलान कराया था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अपना नाम बदल कर दहशतगर्दी में लगे रहना चाहते हैं। स्व. ई. अहमद केरल मुस्लिम लीग के सदस्य थे जिसका तब कांग्रेस से केन्द्र में गठबन्धन था। श्री मुखर्जी ने अपना काम पूरी निष्ठा के साथ किया था।

> **भारत ने पाकिस्तान के इस कथन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था और कहा था कि उसकी फौज के साये में पाकिस्तान में आतंकवादी फलफूल रहे हैं जो समय–समय पर भारत में आतंकवाद फैलाते रहते हैं और निरीह नागरिकों की जान लेते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या उस समय 2008 में हुकूमत पर काबिज मनमोहन सरकार मुम्बई हमले का सैनिक कार्रवाई करके जवाब देना चाहती थी? तो इसका जवाब हमें 'हां'' में मिलेगा परन्तु कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ तत्व ऐसे थे जो पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई नहीं चाहते थे।**

मगर कांग्रेस नेता श्री पी. चिन्दम्बरम ने पिछले दिनों एक साक्षात्कार में कहा कि उस समय विदेश मन्त्रालय की सलाह पर पाकिस्तान पर सैनिक कार्रवाई को टाल दिया गया जो पहली नजर में सही नहीं लगता है। सैनिक कार्रवाई न करने का फैसला विदेश मन्त्रालय का नहीं था क्योंकि प्रधानमन्त्री खुद चाहते थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाये। जाहिर है कि कार्रवाई न करने का फैसला कांग्रेस में ही कहीं बहुत ऊपर से लिया गया था। तब इस प्रकार की खबरें भी छपी थीं कि यदि पाकिस्तान को सैनिक जवाब दिया गया तो प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंह की लोकप्रियता बहुत बढ़ जायेगी। मगर श्री चिदम्बरम ने सारी बात विदेश मन्त्रालय पर ही डाल दी। तब से लेकर आज तक कोई इस सच को नहीं जानता कि 26 नवम्बर 2008 के बाद कांग्रेस के आला नेताओं के बीच क्या हुआ था? हां इतना जरूर हुआ था कि तत्कालीन गृहमन्त्री श्री शिवराज पाटील का इस्तीफा ले लिया गया था और उनके स्थान पर श्री पी. चिदम्बरम को गृह मन्त्रालय सौंप दिया गया था तथा श्री मुखर्जी को वित्त मन्त्री बना दिया गया था। इसके बाद 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को अच्छी विजय मिली और इसके 206 सांसद जीते। इन चुनावों में अमेरिका के साथ हुआ परमाणु समझौता एक मुद्दा बना जिसके असली कर्णधार श्री मुखर्जी ही थे। मगर यह सवाल अपनी जगह खड़ा रहा कि पाकिस्तान को 26 नवम्बर की घटना का मुंहतोड़ सैनिक जवाब क्यों नहीं दिया गया। जबकि विदेश मन्त्री रहते हुए श्री मुखर्जी ने ये सबूत पूरी दुनिया को दे दिये थे कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी फौज पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविर चला रहे हैं और वहां दहशतगर्दों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। श्री चिदम्बरम का यह कहना कि अमेरिका और कुछ अन्य विश्व शक्तियों के कहने पर भारत ने सैनिक कार्रवाई नहीं की, भारत की संप्रभुता पर समझौता करने की भाषा मानी जायेगी।

उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं...

गीता पाढा

"स्वयं के लिए तो धन सभी कमाते हैं,
पर विरले ही हैं जो परमार्थ अपनाते हैं,,
मानवता की सेवा को जो सबसे बड़ा धर्म बताते हैं,
वहीं तो इस दुनिया में फ़रिश्ते कहलाते हैं,,
वो दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर मुस्कराहट सजाते हैं,
और देश के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाते हैं...।"

हिल्सा और जामदानी की कहानी

कलम-दवात
कुमकुम चड्ढा

बंगलादेश के बारे में सोचते ही जामदानी साड़ियां और हिल्सा मछली याद आती है, इसलिए जब भारत में बंगलादेश के उच्चायुक्त एम. रियाज़ हामिदुल्लाह ने इन दोनों का जश्न मनाया तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

यह आयोजन दो अलग-अलग अवसरों पर हुआ- पहला दिल्ली के क्राफ्ट्स म्यूज़ियम में और दूसरा उच्चायुक्त कार्यालय परिसर में। पहले अवसर पर माफजर अली और उनकी पत्नी मीरा, आर्किटेक्चरल रिस्टोरर और डिजाइनर सुनीता कोहली जैसी हस्तियों की मौजूदगी रही, जबकि दूसरे अवसर पर वे लोग उपस्थित थे जो हिल्सा मछली का आनंद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसे हामिदुल्लाह ने खासतौर पर बंगलादेश के दोस्तों और शुभचिंतकों के लिए मंगवाया था।

वास्तव में, मेहमानों ने देखा कि मछली को कैसे स्केल किया जाता है, काटा जाता है और फिर स्वादिष्ट रेसिपी के अनुसार पकाया जाता है। और निश्चित रूप से, संदेश का स्वाद भी लाजवाब था, जिसे चखकर हर कोई प्रसन्न हो उठा।

हिल्सा मछली या ईलिश माछ बंगलादेश की राष्ट्रीय मछली है, दरअसल इसे वहां "राष्ट्रीय गर्व" भी माना जाता है। भारत में यह बंगालियों की पसंदीदा मछली बनी हुई है, हालांकि यह ओडिशा, त्रिपुरा और असम समेत कई अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय है। "जितनी अधिक हड्डियां होंगी, मछली उतनी ही स्वादिष्ट होगी," हामिदुल्लाह ने कहा।

यह महंगी मछली है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में कहा जाता है कि "इसे खाने के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच देना चाहिए।" बंगाल में विवाह समारोहों के दौरान यह कभी-कभी वर के परिवार से वधू के परिवार को पारंपरिक उपहार के रूप में दिया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और यह खुशहाली तथा समृद्ध भविष्य का प्रतीक है। हालांकि यह परंपरा बंगलादेश में अभी भी जारी है, भारत के पश्चिम बंगाल में हिल्सा की जगह तेजी से रोहू मछली ले रही है, क्योंकि हिल्सा अब न तो सस्ती है और न ही आसानी से उपलब्ध।

जहां तक साड़ियों की बात है, प्रदर्शनी में 150 साल पुराने कीमती नमूने भी शामिल थे, जो इतिहास और उनकी महत्वपूर्णता की झलक देते थे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कारीगरों के कार्य और बुनाई प्रदर्शनी में रखे गए थे, जिनमें

पारंपरिक डिज़ाइन जैसे पुष्पाकृति, नेट और तिरछे पैटर्न को दिखाया गया। जामदानी साड़ी के बारे में कहा जाता है, "इसे पहनें और उसमें खो जाएं।"

यह एक फूल और उसके फूलदान के बारे में है। इसका नाम दो फ़ारसी शब्दों से लिया गया है: "जम" अर्थात फूल और "दानी" अर्थात फूलदान। यह नाम जामदानी की जटिल पुष्पाकृतियों और कपड़े पर बुनाई की नज़ाकत को पूरी तरह समेटता है।

इतिहास के दृष्टिकोण से भी जामदानी साड़ियों की कहानी उतनी ही आकर्षक है। जामदानी साड़ियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, लगभग 2000 साल पुरानी। ढाका में उत्पन्न हुई ये साड़ियां आज भी आधुनिक बंगलादेश का अभिन्न हिस्सा हैं। एक समय में प्रमुख वस्त्र उत्पादन केंद्र रहा ढाका, जामदानी साड़ियों के इस आकर्षक इतिहास का प्रतीक है। यहीं जामदानी कपड़ों की जड़ें गहराई से जमीं- एक ऐसा प्रयास जिसमें मेहनत और समर्पण की झलक मिलती है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी बुनने में कभी-कभी छह महीने से लेकर तीन साल या उससे भी अधिक समय लग जाता है।

जामदानी साड़ियां कई प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय ढाकाई, खादी और बंगाली जामदानी हैं। नाम अपने आप अर्थ स्पष्ट कर देते हैं: ढाकाई साड़ी ढाका की मूल साड़ी है, बंगाली साड़ी बंगाल की और खादी की उत्पत्ति जैविक है। हज़ार बुटी इन जामदानी साड़ियों में सबसे विख्यात मानी जाती है।

यदि उच्चायुक्त और सुनीता कोहली के बीच यह आकस्मिक बातचीत न होती तो शायद यह प्रदर्शनी यहां कभी आयोजित नहीं होती। कोहली के शब्दों में, यह "धागों में बंधी कविता" थी। हामिदुल्लाह ने समय न गंवाते हुए इस विचार को सच कर दिखाया। "यह एक संयोगपूर्ण क्षण से जन्मा था," उन्होंने कहा और उस शिल्प के लिए भावनाओं को छिपाए बिना दिखाया, जो बंगलादेश की सबसे प्रसिद्ध बुनाई है।

हामिदुल्लाह भारत के लिए अनजान नहीं हैं और न ही भारत उनके लिए अपरिचित है। वे पहले यहां छात्र के रूप में आ चुके हैं। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच चुने गए विकल्प में उन्होंने भारत का चयन किया और वर्षों बाद वे बंगलादेश के उच्चायुक्त के रूप में लौटे। उच्चायुक्त कार्यालय में भी उन्होंने 2003 में कार्य किया था। इसलिए, जब वे कहते हैं कि "मैं किसी ट्रक ड्राइवर के ढाबे में खाना चाहता हूं, किसी फैंसी एयर-कंडीशंड ढाबे में नहीं," तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे कहते हैं, "मैं असली गर्मी और धूल महसूस करना चाहता हूं और सड़क किनारे गोलगप्पे भी खाना चाहता हूं।" हामिदुल्लाह को फतेहपुर सीकरी से लौटते समय हाइवे पर मक्की की रोटी और मूली का साग खाना भी याद है। "उसका कोई मुकाबला नहीं।" अगर उनसे पूछा जाए कि क्या वे इसे हिल्सा से बदलेंगे, तो उनका जवाब है: "आहा... हिल्सा एक अलग कहानी है।" जैसे ढाका की बारिश, जिसे वे घर से दूर रहते हुए गहराई से याद करते हैं।

नेपाल में लोकतंत्र की राहें आसान नहीं

जेन-जेड का अप्रत्याशित हिंसक आंदोलन मुश्किल से 48 घंटे तक चला, लेकिन इसने नेपाल में ज़बरदस्त उथल-पुथल मचा दी।

नेपाल गहरे शोक, क्रोध और सामूहिक अनिश्चितता के दौर में डूब गया। इसने खुद को अभी -अभी संभालना शुरु किया है।

आठ और नौ सितंबर, 2025 को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सोशल मीडिया नियमन के खिलाफ जेन-जेड के आंदोलन में 75 लोग मारे गए और 2,000 से ज़्यादा घायल हुए।नेपाल के वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ (एफएनसीसीआई) के अनुसार, हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आगजनी की घटनाओं के चलते निजी संपत्ति को लगभग 57.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। निजी क्षेत्र नेपाल की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 81 प्रतिशत योगदान देता है और कुल नौकरियों में से 86 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं।

सरकारी भवनों और ऐतिहासिक धरोहरों को हुए नुकसान का आकलन अभी जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय (सिंहदरबार), ऐतिहासिक संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति कार्यालय (राष्ट्रपति भवन) को हुए नुकसान की लागत सरकार ने अभी सार्वजनिक नहीं की है।

इन घटनाओं के बाद 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब तक उन्होंने आठ मंत्रियों को नियुक्त करते हुए दो बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। अंतरिम सरकार को अगले छह महीनों के भीतर स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय आम चुनाव कराना है। सरकार ने पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया है जो मानवाधिकार उल्लंघनों और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान की जांच करेगा। आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है।

गृह मंत्री द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अब आगजनी या चोरी की शिकायतें दर्ज नहीं की जाएंगी क्योंकि आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। आलोचकों का कहना है कि इससे नियमित आपराधिक न्याय प्रक्रिया की भूमिका कमजोर होती है। इससे पहले जनआंदोलन-प्रथम (1990) और जनआंदोलन-द्वितीय (2006/2007) के दौरान बने कई आयोगों की सिफारिशें लागू नहीं की गई थीं, जिससे आक्रोश को बल मिला। अंतरिम सरकार के समक्ष अब मुख्य चुनौतियां आगामी आम चुनाव कराना और नया मतदाता पंजीकरण अध्यादेश लागू करना है, ताकि विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले युवा भी मतदान कर सकें। मतदाता नामांकन की अवधि 90 दिन है। प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग से परामर्श कर मार्च 2026 में चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति ने भी राजनीतिक दलों से भेंट कर उन्हें चुनाव में भाग लेने की सलाह दी है।

प्रधानमंत्री के चुनाव कराने के वादे के बावजूद युवाओं में मतभेद बने हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे डिस्कॉर्ड पर कई असंगठित समूह उभरे हैं। कुछ समूहों ने पहले सेना प्रमुख और बाद में राष्ट्रपति से संवाद की कोशिश की। कुछ युवा मौजूदा राजनीतिक दलों में सुधार की वकालत कर रहे हैं, जबकि अन्य संविधान संशोधन और प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमंत्री की मांग कर रहे हैं। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने प्रदर्शनों के दौरान शांति की अपील की थी लेकिन इसके बाद से वे चुप हैं। युवाओं के बीच मतभेद बने रहने पर चुनाव में हिंसा की आशंका जताई जा रही है।युवा अब स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की बजाय अपना राजनीतिक दल पंजीकृत कराने पर भी विचार कर रहे हैं। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक सहित पांच लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं। सीपीएन-यूएमएल ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यदि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित लगती है तो दल इसका विरोध करेंगे। प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के बाद 486 पुलिस इकाइयों पर हमले और 1,247 हथियारों की लूट की घटनाएं सामने आई हैं। 28 जेलों से लगभग 15,000 कैदी फरार हुए, जिनमें से केवल आधे वापस लौटे हैं। कुछ कैदी भारत सीमा पार करने के बाद नई दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था तीन अंगों-नेपाल पुलिस, नेपाल सशस्त्र बल और नेपाल सेना—में विभाजित है, लेकिन इनमें समन्वय की कमी देखी गई। पुलिस ने आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन अन्य बलों की तैनाती में देरी हुई। इन हालात में चुनाव कराना अंतरिम सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।

सरकार को अराजकता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कानून का पालन सुनिश्चित करना होगा। नेपाल को स्थायित्व के लिए अपने पड़ोसियों सहित अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी आवश्यकता है।

(सोम निरौला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)

डिजिटल प्रणालियां भारत की संसदीय प्रक्रियाओं को कुशल और समावेशी बना रही हैं

ब्रिजटाउन, (एजेंसी): लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों से आग्रह किया कि वे प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करते हुए और डिजिटल डिवाइड की समस्या का समाधान करते हुए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विवेकपूर्ण और नैतिक उपयोग को बढ़ावा दें ।बारबाडोस में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 68वें सम्मेलन के दौरान 'प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: डिजिटल परिवर्तनों के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाना और डिजिटल डिवाइड को दूर करना' विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए, बिरला ने कहा कि आपसी सहयोग से और जानकारी साझा करते हुए यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रौद्योगिकी अवरोध न बनकर सेतु की

भूमिका निभाए । उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास और ई-संसद के उपयोग से हमारे संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण में बड़े पैमाने पर बदलाव आए हैं ।

उन्होंने उल्लेख किया कि ई-संसद पहल, ई-लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे लोकतन्त्र में नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ रही है । बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई-आधारित डिजिटल प्रणालियाँ भारत की संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और समावेशी बना रही हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों को बताया कि एआई-आधारित अनुवाद, एआई-सक्षम ई-लाइब्रेरी और स्पीच-टू-टेक्स्ट रिपोर्टिंग जैसी प्रणालियां संसदीय प्रक्रियाओं को अधिक सफल और समावेशी बना रही हैं। आगामी डिजिटल पहलों के बारे में बताते हुए, बिरला ने कहा कि निकट भविष्य में, "संसद भाषिणी" जैसी रियल-टाइम एआई अनुवाद प्रणालियों से प्रत्येक संसद सदस्य को अपनी भाषा में संवाद करने में मदद मिलेगी, जो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मज़बूत बनता है जब देश के नागरिक अपनी संसद से गहराई से जुड़े होते हैं।

ऑटोइम्यून बीमारियों की जड़ तक पहुंचा विज्ञान

आकाश चोपड़ा

मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में मानव जीवन को बेहतर बनाने और बीमारियों से लड़ने में मदद की है। इसी कड़ी में मैरी ई. ब्रंको, फ्रेड राम्सडेल और डॉ. शिमोन साकागुची को पेरीफेरल इम्युनिटी से संबंधित अपनी खोजों के लिए 2025 के लिए मेडिसिन क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। सोमवार को इसकी घोषणा की गई है। तीनों को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी। 64 वर्षीय ब्रंको सिएटल में इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी में वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक हैं। वहीं 64 वर्षीय रामसडेल सैन फ्रांसिस्को में सोनोमा बायोथेरेप्यूटिक्स के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इसके अलावा 74 वर्षीय साकागुची, जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में इम्यूनोलॉजी फ्रंटियर रिसर्च सेंटर में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं।

क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर दुश्मनों (कीटाणुओं और रोगाणुओं) से लड़ते हुए ग़लती से अपनों (शरीर के अंगों) पर हमला क्यों नहीं कर देता? इसे ही इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) का संतुलन कहते हैं और इस महत्वपूर्ण पहेली को सुलझाने के लिए, इस साल 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी-जापानी तिकड़ी को दिया गया है।

समाधान: इन तीनों वैज्ञानिकों ने रेगुलेटरी टी सेल्स नामक कोशिकाओं की खोज की। ये कोशिकाएं 'ट्रैफिक पुलिस' की तरह काम करती हैं, जो हमारी हमलावर इम्यून कोशिकाओं को रोकती हैं और उन्हें अपने ही शरीर पर हमला करने से मना करती हैं। यह संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया ही पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस कहलाती है। यह शोध बताता है कि शरीर अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है ताकि वह माइक्रोब्स से भी लड़ सके और ऑटोइम्यून बीमारियों से भी बचा रहे। यह खोज केवल अकादमिक नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। इस कार्य का अधिकांश भाग 1980 और 1990 के दशक में किया गया था और इन खोजों का प्रभाव स्व-प्रतिरक्षा रोगों, कैंसर और अंग प्रत्यारोपण के उपचार पर पहले से ही पड़ रहा है।

प्रतिरक्षा प्रणाली, बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को निष्क्रिय करके शरीर की बीमारियों से रक्षा करती है। इस प्रक्रिया की कुंजी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता है-विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिन्हें टी-कोशिकाएं

कहा जाता है-रोगजनक और मेजबान शरीर की कोशिकाओं के बीच अंतर करने की क्षमता। जब यह ठीक से नहीं होता तो यह स्व-प्रतिरक्षी रोगों का कारण बनता है, जिसमें टी-कोशिकाएं शरीर की अपनी कोशिकाओं को नुक्सान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। एक स्वस्थ शरीर में ऐसा क्यों नहीं होता, यह नोबेल पुरस्कार विजेताओं को पता चल पाया। टी-कोशिकाओं को अपने दृष्टिकोण में चयनात्मक होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन यह प्रशिक्षण पूर्ण नहीं है। साकागुची ने टी-कोशिकाओं के एक विशेष समूह की पहचान की, जिन्हें नियामक टी-कोशिकाएं या टी-रेग कहा जाता है, जो अन्य टी-कोशिकाओं की गतिविधि को दबा देती हैं। यदि उनमें शरीर के अपने ऊतकों पर हमला करने की प्रवृति होती है। ब्रुनको और रामस्डेल ने बाद में उस जीन की खोज की जो कुछ टी-कोशिकाओं को टी-रेग के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है। साथ मिलकर वे प्रतिरक्षा प्रणाली की पूरी तस्वीर पेश करते हैं। मैरी ब्रंको और फ्रेड राम्सडेल ने 2001 में दूसरा बड़ा रिसर्च किया। उन्होंने यह पता लगाया कि एक खास चूहे की नस्ल ऑटोइम्यून रोगों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी।

उन्होंने पाया कि इन चूहों में फॉक्सपी3 नामक जीन में म्यूटेशन था। इसके अलावा, उन्होंने दिखाया कि इसी जीन में इंसानों में म्यूटेशन होने पर गंभीर ऑटोइम्यून रोग आईपीईएक्स होता है। दो साल बाद, साकागुची ने इन रिसर्च में यह भी जोड़ा कि फॉक्सपी3 जीन उन सेल्स के विकास को कंट्रोल करता है, जिन्हें उन्होंने 1995 में पहचाना था। ये सेल्स, जिन्हें अब रेगुलेटरी टी-सेल्स कहा जाता है, दूसरे इम्यून सेल्स की निगरानी करती हैं और तय करती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही ऊतकों को नुक्सान न पहुंचाए। दरअसल, हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों-लाखों सूक्ष्मजीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्मजीव अलग-अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखाने की क्षमता विकसित कर ली है जिससे इम्यून सिस्टम को यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 'टी-रेग' की गतिविधि को नियंत्रित करने से यह प्रक्रिया सुचारू हो सकती है। कैंसर में, कभी-कभी विपरीत प्रक्रिया होती है। कैंसरग्रस्त कोशिकाएं बहुत अधिक 'टी-रेग' को आकर्षित करती हैं, जिससे सामान्य टी-कोशिकाएं, जिन्हें आदर्श रूप से कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को मारना चाहिए था, अप्रभावी हो जाती हैं।इसके अलावा इन खोजों की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन (अंग प्रत्यारोपण) में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा कई इलाज अब क्लीनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं।

मेडिसिन के क्षेत्र में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को नोबेल मिल चुका है । उन्हें 1968 में यह सम्मान मिला था। उन्होंने जेनेटिक कोड से जुड़ी खोज की थी, जो यह बताती है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनते हैं। इस खोज ने चिकित्सा की दुनिया को बदल दिया और कैंसर, दवाओं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद की। उनकी खोज ने समझाया कि डीएनए कैसे प्रोटीन बनाता है, जो शरीर के लिए जरूरी है। इसने नई दवाएं और बीमारियों के इलाज का रास्ता खोला। भारत से जुड़े 12 लोग नोबेल जीत चुके हैं लेकिन मेडिसिन में सिर्फ हरगोबिन्द खुराना को यह अवॉर्ड मिला है। इसके बाद मेडिसिन के क्षेत्र में किसी भारतीय को नोबेल नहीं मिला। इसके पीछे मुख्य कारण है कि देश के विश्वविद्यालयों में शोध और अनुसंधान की क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार को अनुसंधान एवं विकास व्यय का बजट बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा देकर एक मजबूत इको-सिस्टम और पर्याप्त धन आवंटन करने के साथ-साथ निजि कम्पनियों को अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

इतिहास गवाह है, एक के बाद एक टैरिफ लगने से व्यापार युद्ध छिड़ता है, जिसमें जीतता कोई नहीं, पर उपभोक्ता पिस जाता है। -मार्क मैकिन्नन

साझेदारी का नया युग

ऐसे वक्त में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों में कुछ खिंचाव-सा दिख रहा है, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का भारत दौरा कई वजहों से ऐतिहासिक है। गौरतलब है कि यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद से स्टार्मर का पहला भारत दौरा है। उनके साथ 125 सदस्यीय भारी-भरकम व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी है, जो ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें वहां के अग्रणी उद्योगपति, उद्यमी, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं। स्टार्मर की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच महत्वाकांक्षी मिसाइल करार के अलावा सैन्य प्रशिक्षण समझौता भी हुआ है, जिसमें भारतीय वायु सेना के जांबाज ब्रिटेन के वायु सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे। इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के तकरीबन सभी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खुलने संबंधी समझौता देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दृष्टि से यकीनन महत्वपूर्ण है। भारत और ब्रिटेन ने जुलाई में जिस समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, उसे खुद स्टार्मर ने दूसरे देशों के साथ हुए ऐसे समझौतों से ज्यादा सशक्त और विकास का लॉन्चपैड तक बताया है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में, यह कह कर कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, स्टार्मर ने साफ संकेत दिया कि उन्हें इस यात्रा की अहमियत का भली-भांति अंदाजा है। संयुक्त घोषणा में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों में आयात की लागत घटेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि यह विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ भारतीय उत्पादों को भी विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा। जाहिर-सी बात है कि इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूती मिलेगी। हालांकि, दोनों देशों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि

छोटे और मध्यम उद्यमों को भी इस समझौते का फायदा हो, ताकि आर्थिक विकास समावेशी बन सके। अगर स्टार्मर वीजा के नियमों में राहत देने की भी घोषणा करते, तो यह अमेरिका द्वारा एच-1बी वीजा के नियमों को सख्त किए जाने से सबसे ज्यादा आहत भारतीयों के लिए राहत की बात होती, लेकिन ब्रिटेन की घरेलू राजनीति को देखते हुए इसकी उम्मीद वैसे भी कम ही थी।

टैरिफ के जवाब में नए बाजार की खोज

अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न रणनीतिक अनिश्चितता के जवाब में भारत बातचीत, बाजार विविधीकरण और घरेलू समर्थन पर केंद्रित एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। यह इसी रणनीति की ताकत है, जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अब तक के सबसे बड़े व्यापारी बेड़े के साथ भारत आने के लिए आकर्षित किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा 25 फीसदी शुल्क लगाने के बाद 25 फीसदी अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने से भारतीय निर्यात बाजार पर काफी गहरा असर पड़ा है, जो फिलहाल आंकड़ों में भले न दिख रहा हो। इसके कारण दोनों देशों के बीच व्यापार एक जटिल चुनौती में बदल गया है, जबकि कभी मजबूत व्यापारिक संबंध था। कुछ भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी तक शुल्क थोपे जाने से इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में पहले से ही महसूस किया जाने लगा है, जिसने केंद्र सरकार और उद्योग जगत को तेजी से आर्थिक गिरावट को कम करने के लिए रणनीतिक कदम उठाने पर मजबूर किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है, ऐसे में उच्च शुल्क ने विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाधाएं पैदा की हैं। समुद्री खाद्य (झींगा) निर्यात को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका भारतीय झींगे का सबसे बड़ा बाजार है। पारस्परिक व एंटी डंपिंग शुल्कों सहित बढ़ते टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातकों को अलाभकारी मूल्यों का सामना करना पड़ रहा है। झींगों को भेजे जाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिसके कारण बिना बिके माल का भंडार जमा हो रहा है और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार के नुकसान का जोखिम पैदा हो गया है। अमेरिकी खरीदार कथित रूप से वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश कर रहे हैं।

अजय बग्गा
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ

उच्च शुल्कों का सामना कर रहे तिरुपुर और सूरत जैसे विनिर्माण केंद्रों के निर्यातकों ने बताया कि वे प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण न कर पाने के कारण नए अमेरिकी ऑर्डर रोक रहे हैं। इससे रोजगार पर खतरा पैदा होता है और मौजूदा ऑर्डरों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। अमेरिका के भारतीय हीरे और जड़ाऊ आभूषणों का सबसे बड़ा बाजार होने के नाते रत्न एवं आभूषण का क्षेत्र लड़खड़ा रहा है, और उद्योग निकाय 50 फीसदी टैरिफ को 'कयामत का दिन' बता रहे हैं। निर्माता अपने कारोबार को बनाए रखने के लिए दुबई और मेक्सिको जैसे

वैकल्पिक विनिर्माण और व्यापार केंद्रों की तलाश कर रहे हैं। टैरिफ वृद्धि से भारत के ऑटो पाट्र्स निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होगा, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहनों और भारी मशीनरी के कलपुर्जे, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले काफी नुकसान होगा।

टैरिफ से निर्यात में कमी आने का खतरा है, जिससे घरेलू अधिशेष पैदा होगा और कृषि उत्पादों की कीमतें गिर सकती हैं। बासमती चावल और कपास जैसी वस्तुएं अत्यधिक जोखिम में हैं, और शुरुआती अनुमानों से निर्यात में कमी और भविष्य में उत्पादन क्षेत्र में कमी का संकेत मिल रहा है। मजबूत घरेलू मांग, लचीले सेवा निर्यात और कुल जीडीपी में निर्यात की अपेक्षाकृत छोटी हिस्सेदारी के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि पर समग्र रूप से मध्यम प्रभाव माना जा रहा है, पर रिजर्व बैंक और एडीबी जैसे प्रमुख संस्थानों ने 'टैरिफ के जोखिमों' का हवाला देते हुए विकास पूर्वानुमानों को घटाया है। अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न 'रणनीतिक अनिश्चितता' के जवाब में, भारत बातचीत, बाजार विविधीकरण और घरेलू समर्थन पर केंद्रित एक बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा व्यक्त भारत का आधिकारिक रुख 'रचनात्मक है, न कि आक्रामक', लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्र 'न तो झुकेगा और न ही कभी कमजोर दिखेगा।'

गतिरोध को सुलझाने और टैरिफ को कम करवाने के लिए भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि व्यापार वार्ता महत्वपूर्ण चरण में है। यह वार्ता जटिल है, जिसमें व्यापार से जुड़े पारस्परिक टैरिफ और भारत द्वारा रूस से तेल खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क जैसे दोहरे मुद्दे शामिल हैं।

भारत अमेरिका के साथ अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच जैसे पेचीदा मुद्दों पर बात कर रहा है। नई दिल्ली अपने घरेलू किसानों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। समग्र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए भारत अपनी टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रयास कर रहा है। एक ही प्रमुख बाजार पर निर्भरता के जोखिमों को समझते हुए भारत अपनी दीर्घकालीन रणनीति के तहत बाजार और उत्पाद का विविधिकरण कर रहा है।

भारतीय निर्यातक तेजी से नए गंतव्यों का रुख कर रहे हैं। इसमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, पश्चिम एशिया, आसियान और अफ्रीका जैसे बाजारों के साथ गहरा जुड़ाव भी शामिल है। सरकार अपने उत्पादों के लिए तरजीही पहुंच सुनिश्चित करने की खातिर यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दे रही है।

वैश्विक व्यापार व्यवस्था को सहयोगात्मक रूप से बहाल करने तथा वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिक्स जैसे संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की वकालत की जा रही है। सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और सॉफ्टवेयर, जो नए अमेरिकी टैरिफ से काफी हद तक अछूते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बफर प्रदान करते रहेंगे। कमजोर उद्योगों पर तत्काल प्रभाव को कम करने के लिए सरकार लक्षित राहत उपायों पर विचार कर रही है। हालांकि, कुछ निर्यातकों को बड़े वित्तीय सहायता पैकेज की उम्मीद थी, पर सरकार लक्षित हस्तक्षेप कर रही है।

विचाराधीन उपायों में कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार के लिए छोटे ऋण पैकेज, ब्याज-मुक्त ऋण, और लालफीताशाही कम करने तथा निर्यातकों की लागत कम करने के लिए नीतिगत सुधार शामिल हैं। उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' पहल जैसी नीतियों की जरूरत बढ़ रही है। इसका लक्ष्य उच्च तकनीक वाले आयातों का विकल्प बनने के लिए तकनीकी और विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक ज्यादा जरूरी कड़ी बनना है, जिससे पारंपरिक केंद्रों से हटकर विविधीकरण की इच्छुक कंपनियों को आकर्षित किया जा सके। भारत की मजबूत घरेलू खपत और मजबूत सार्वजनिक/निजी निवेश को आधारभूत ताकत के रूप में देखा जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों को सहने में सक्षम बनाएगी।

भारत की रणनीति की सफलता न केवल उसके प्रमुख निर्यात उद्योगों के तात्कालिक भाग्य को निर्धारित करेगी, बल्कि एक अधिक लचीले और रणनीतिक रूप से वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने की उसकी क्षमता को भी निर्धारित करेगी।

edit@amarujala.com

त्योहार

समय बदल रहा है पैमाने भी बदलें

करवा चौथ आस्था से जुड़ा पर्व है। इस पर सवाल उठाने के बजाय पैमाने बदलने पर बात होनी चाहिए, ताकि भविष्य में पर्वों की उजास तो बची रहे, पर उनसे जुड़ी बंदिशें टूटें।

पर्व-त्योहारों के मौसम में आस्था का रंग ही नहीं, उपहास का बेरंग बर्ताव भी खूब देखने को मिलता है। व्रत-उत्सवों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देने का व्यवहार बहुत आम है। अपनों की कुशलकामना से जुड़े उत्सवों को लेकर खूब नकारात्मकता देखने को मिलती है। कमोबेश हर त्योहारी रीति-रिवाज का मजाक बनाया जाता है। कभी महिलाओं के शोषण की बात, तो कभी पुरातनपंथी सोच का हवाला देकर इन अनुष्ठानों को उपहास का विषय बना दिया जाता है।

उपवास से बिगड़ती सेहत का हवाला देकर भी चेताया जाता है और रूढ़िवादी सोच की जकड़न के प्रति सजग रहने का भय भी परोसा जाता है। अफसोस कि जमीनी मुद्दों को छोड़ नकारात्मकता और विरोध का यह अजब-गजब कोलाहल तीज-त्योहारों का उपहास उड़ाने तक ही सिमट गया है।

यह सच है कि रूढ़िवादी सोच स्त्री जीवन के लिए दंश रही हैं। कई परंपरागत पर्वों के रिवाज महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखने की सोच से जुड़े रहे हैं, पर सच यह भी है कि समय के साथ ऐसे व्रत-उपवास करने से जुड़ी परंपराओं को निभाने के तरीके काफी बदल गए हैं। इनसे जुड़ी आस्था के मायने भी अब नए रंग में दिख रहे हैं। बावजूद इसके इन बदलावों को दिल से स्वीकारने के बजाय उससे जुड़े नकारात्मक पक्षों को साझा करने की मानो होड़ लगी रहती है। सोशल मीडिया के सभी मंचों पर अब स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दे कम और पर्व-त्योहारों के विरोध की बातें ज्यादा साझा की जाती हैं, जबकि ऐसे पर्वों को मनाने के मामले में आई सहजता को भी गहराई से समझा जाना चाहिए, जो महिलाएं मन से इन्हें मानना चाहती हैं, उनके विचारों का भी मान किया जाना चाहिए।

मोनिका शर्मा

दुखद है कि हम टूटते परिवारों और बिखरते सामाजिक ताने-बाने में संबंधों को थामने और साधने का काम कर रहे रीति-रिवाजों का सकारात्मक पक्ष देखना ही भूल रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य सहेजने के मोर्चे पर चिंता करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि सुखद दांपत्य भी भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। करवा चौथ जैसे पारंपरिक पर्व भी आपसी जुड़ाव को ही पोसते हैं। साथ ही परंपरागत रिवाजों से जुड़ाव रखना आज कोई मजबूरी नहीं है। अपनों और अपने परिवार की खुशहाली की कामना संग अगर त्योहार मन से मनाए जाते हैं, तो क्या बुरा है? खासकर तब, जबकि आज मान्यताओं के मायने भी बदल गए हैं। अहोई अष्टमी जैसा व्रत कभी बेटों के आयुष्य की कामना से जुड़ा था। आज माताएं बेटे-बेटी के भेद से दूर अपने बच्चों की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह अनुष्ठान करती हैं। करवा चौथ व्रत की परंपरा में भी सुखद परिवर्तन नजर आते हैं।

नई पीढ़ी के पति, अपनी पत्नी की निष्ठा, समर्पण और प्रेम की कद्र करना सीख गए हैं। घर-परिवार में पत्नी की भूमिका को खुलकर सराहने लगे हैं। पत्नी गृहिणी हो या कामकाजी, उसकी जद्दोजहद को समझते हैं। सुखद है कि औपचारिकताओं के परे हमारे परंपरागत पर्व मन की रीत से जुड़ गए हैं। वहीं विरोध की मानसिकता आज भी इन पर्वों के पुरातन स्वरूप तक ही सिमटी है। जरूरी है कि समय के साथ आए इन बदलावों को मान दिया जाए, ताकि भविष्य में पर्वों की उजास तो बची रहे, पर उनसे जुड़ी बंदिशें टूटें। ध्यान रहे कि तार्किक बातों के बजाय अंध विरोध करने की प्रवृत्ति भी स्त्री जीवन के लिए दंश ही है।

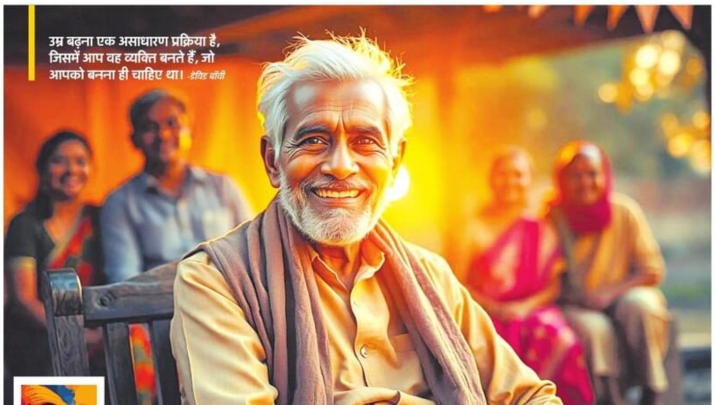

यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है

वृद्धावस्था कठिन समय नहीं है, बल्कि यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है, जो पहले के दिनों की बनावटी तात्कालिकताओं से मुक्त है। यह जीवन भर के विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ने का वक्त है।

अस्सी साल! मुझे यकीन नहीं होता। मैं अक्सर सोचता हूं कि जीवन अब शुरू होने वाला है, लेकिन फिर एहसास होता है कि यह लगभग खत्म हो चुका है। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ-न-कुछ सीखते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने जीवन को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।

ओलिवर सॉक्स

मैं उम्मीद करता हूं कि जब मेरा आखिरी समय आए, तो मैं फ्रांसिस क्रिक की तरह काम करते हुए मरूं। जब उन्हें बताया गया कि उनका कोलन कैंसर लौट आया है, तो उन्होंने बस एक मिनट के लिए दूर देखा और फिर अपने पुराने विचारों में डूब गए। कुछ हफ्तों बाद जब उनसे निदान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'जिस चीज की शुरुआत होती है, उसका अंत भी होता है।' जब उनकी मृत्यु 88 साल की उम्र में हुई, वह तब भी अपने सबसे रचनात्मक काम में पूरी तरह से डूबे हुए थे। मेरे पिता, जो 94 साल तक जिए, अक्सर कहते थे कि अस्सी का दशक उनके जीवन के सबसे आनंददायक दशकों में से एक था। मैं भी महसूस करने लगा हूं कि मानसिक जीवन और दृष्टिकोण में संकुचन नहीं, बल्कि विस्तार होता है। वृद्धावस्था तक पहुंचते-पहुंचते हम सफलताएं और त्रासदियां, उतार-चढ़ाव, क्रांतियां और युद्ध, महान उपलब्धियां और गहरी अस्पष्टताएं सब कुछ देख चुके होते हैं।

मुड़-मुड़ के देख

मैं कल्पना कर सकता हूं, कि एक सदी कैसी होती है, जो मैं 40 या 60 की उम्र में नहीं कर सकता था। मैं वृद्धावस्था को ऐसा कठिन समय नहीं मानता, जिसे किसी तरह झेलना पड़े, बल्कि यह अवकाश और स्वतंत्रता का समय है, जो पहले के दिनों की बनावटी तात्कालिकताओं से मुक्त है। अब मैं जो चाहूं उसे तलाश सकता हूं, और जीवन भर के विचारों और भावनाओं को एक साथ जोड़ सकता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं जीवन से थक गया हूं। इसके विपरीत, मैं बहुत जीवंत महसूस करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो समय बचा है, उसमें मैं अपनी दोस्ती को गहरा करूं, जिन्हें मैं प्यार करता हूं, उन्हें अलविदा कहूं, और लिखूं। अगर मुझमें ताकत है, तो यात्रा करूं, समझ और अंतर्दृष्टि के नए स्तर हासिल करूं।

दूसरी पारी

एफडी के अलावा भी कई विकल्प हैं

एफडी पर ब्याज दर घटने की चिंता के बीच विशेषज्ञ बता रहे हैं कि बुजुर्ग डेट फंड में निवेश कर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं

60 वर्षीय हरिया चाचा समेत कई बुजुर्ग पशोपेश में हैं। रेपो रेट घटने के बाद बैंकों ने एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज में कटौती कर दी है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए डेट फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं, जो इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माने जाते हैं।

साठ की उम्र पार कर चुके हरिया चाचा की जिंदगी पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज से चलती है। उनकी पुरानी एफडी मैच्योर हो चुकी है। नई एफडी कराने बैंक गए, तो पता चला कि ब्याज दर घट गई है। हरिया चाचा जैसे ही लाखों बुजुर्गों के मन में सवाल है कि एफडी नहीं, तो क्या?

रेपो रेट-एफडी कनेक्शन : बैंक एफडी लंबे वक्त से बुजुर्गों का भरोसेमंद साथी बना हुआ है। लेकिन ब्याज दरों में कमी से यह पहले जितना आकर्षक नहीं रह गया। रिजर्व बैंक ने 2025 में अब तक तीन बार में रेपो रेट में एक फीसदी की कटौती की। इससे रेपो रेट 6.5 से घटकर 5.5 फीसद पर आ गया। अगस्त की बैठक में नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट वह दर है, जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। जब ये दरें घटती हैं, तो बैंक ग्राहकों को सस्ता कर्ज देते हैं। लेकिन बचत करने वालों को जमा पर मिलने वाला ब्याज भी गिर जाता है।

एफडी के ब्याज में आगे और कटौती संभव: रेपो रेट में कटौती के साथ बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों पर कैंची चलाई। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, 2025 की कटौतियों से पहले बैंक आम नागरिकों को सात दिन से 10 साल तक की रेगुलर एफडी पर 3.5 से 7 फीसदी के बीच की ब्याज दे रहा था, जो अब 6.45 फीसदी पर आ गया है। एक से दो साल के बीच और दो से तीन साल के बीच की एफडी दरें 0.55 फीसदी घटकर अब क्रमशः 6.25 तथा 6.45 प्रतिशत रह गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों से 0.50 फीसदी तक अधिक ब्याज मिलता है। ये दरें तीन करोड़ रुपये से कम रकम की एफडी के लिए हैं। आम तौर पर बैंक

रेपो रेट में कटौती का प्रभाव धीरे-धीरे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अगर बैंक अपनी ब्याज दरों में रेपो रेट के बराबर कमी करते हैं, तो आने वाले वक्त में एफडी दरों में और कटौती संभव है।

रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बढ़ी : अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सितंबर में अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में 0.25 फीसदी (25 आधार अंक) की कटौती की, और संकेत दिया कि 2025 के अंत तक कुल 50 आधार अंक की अतिरिक्त ढील दी जा सकती है, जबकि 2026 में केवल 25 आधार अंक कटौती की उम्मीद है। फेड की कटौती और आगे के रोडमैप को देखते हुए रिजर्व बैंक पर एक बार फिर नीतिगत दरों को घटाने का दबाव बन सकता है। इसके अतिरिक्त, खुदरा महंगाई आरबीआई के 2-6 फीसदी के दायरे में बनी हुई है। यह भी रेपो रेट में कटौती की संभावना को मजबूत कर रही है।

एक्सपर्ट की सलाह : फिनवाइज की संस्थापक प्रतिभा गिरीश बताती हैं कि एफडी की ब्याज दरें घटने से डेट फंड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माने जाते हैं। एक से तीन साल तक के निवेश को डेट फंड, तीन से पांच साल में जरूरत पड़ने वाले पैसों को हाइब्रिड फंड और पांच साल या उसके बाद काम आने वाले पैसों को इक्विटी फंड में रखना चाहिए। नियमित आय या इमरजेंसी फंड के तौर पर बुजुर्ग एक से तीन साल के नजरिये से शॉर्ट टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। इनमें एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं।

-पवन पांडेय

क्या हैं डेट फंड?

डेट फंड, म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है, जो निश्चित आय वाले साधनों-जैसे कॉरपोरेट व सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। डेट फंड को निश्चित आय वाले फंड या बॉन्ड फंड भी कहते हैं। डेट फंड में निवेश करने पर कम लागत, स्थिर रिटर्न, अधिक लिक्विडिटी और उचित सुरक्षा जैसे फायदे मिलते हैं। डेट फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो नियमित आय चाहते हैं, लेकिन जोखिम से बचते हैं। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं।

बुजुर्गों के पास डेट फंड के विकल्प

सेबी के म्यूचुअल फंड स्कीम वर्गीकरण के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की लगभग 16 श्रेणियां हैं। इनमें ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड और गिल्ट फंड शामिल हैं।

कौन-सा फंड बेहतर?

16 फंडों में से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन-से फंड अच्छे हैं, यह जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश के समय और लक्ष्य पर निर्भर करता है। प्रतिभा गिरीश बताती हैं कि छोटी अवधि के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में निवेश किया जा सकता है। लंबी अवधि के लिए वरिष्ठ नागरिक 'इनकम प्लस आर्बिटाज फंड ऑफ फंड' में निवेश कर सकते हैं। यह हाइब्रिड म्यूचुअल फंड श्रेणी में आता है, जो डेट और आर्बिटाज म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करता है और डेट से बेहतर रिटर्न, इक्विटी जैसे टैक्सेशन और कम उतार-चढ़ाव का फायदा देता है। बुजुर्गों को लॉन्ग ड्यूरेशन फंड और गिल्ट फंड से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें उतार-चढ़ाव की ज्यादा आशंका है।

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश के जोखिम

- बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डिफॉल्ट का जोखिम, अगर जारीकर्ता ब्याज या मूलधन चुकाने में असमर्थ हो।
- फंड का रिटर्न महंगाई दर से कम होने पर आपके निवेश को नुकसान पहुंच सकता है।
- आर्थिक अनिश्चितता या नीतिगत बदलाव जैसी बाजार अस्थिरता डेट फंड को प्रभावित कर सकते हैं।
- डेट फंड सुरक्षित हैं, लेकिन वित्तीय सलाहकार से परामर्श के बाद ही निवेश करें। क्योंकि किसी निवेश से पहले उसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी होता है।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

गाजा में उम्मीद

गाजा में युद्धविराम का लागू होना पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। पूरे दो साल दो दिन बाद भयानक खूनखराबे का सिलसिला टूटता लग रहा है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही देना चाहिए। युद्धविराम कराने के लिए ट्रंप चेतावनी से धमकी तक चले गए थे, इसी का नतीजा है कि इजरायल और हमास, दोनों उनके शांति समझौते के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं। हालांकि, अनेक किंतुओं-परंतुओं का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। संघर्ष में स्थायी विराम के लिए अमेरिका अगर अपनी नीति को स्थिर रखे, तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में अमन-चैन को बल मिलेगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश है, जो इजरायल को संभाल सकता है, पर अब इजरायल को संभालने के लिए पश्चिमी देशों को भी अपनी निश्चित नीति के तहत व्यवहार करना होगा। इजरायल फूंक-फूंककर कदम उठाने के पक्ष में है और उसने कहा है कि समझौता तभी प्रभावी होगा, जब उसकी कैबिनेट मंजूरी देगी। हालांकि, इस मंजूरी में परेशानी नहीं आनी चाहिए।

गाजा के लोगों ने अगर दो साल तक खून के आंसू बहाए हैं, तो इसके लिए केवल इजरायल नहीं, हमास भी बहुत दोषी है। जिस तरह से 7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, वह सिवाय आतंकवाद के और कुछ भी नहीं था। कुछ ही घंटों में हमास ने 12 सौ इजरायलियों को मार डाला और करीब 250 को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। हमास ने यही सोचा था कि बंधकों की वजह से इजरायल हमलावर नहीं होगा और उसका भयादोहन किया जा सकेगा। हालांकि, हमास का दांव उल्टा पड़ गया। अब तक गाजा में 67 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं और एक लाख सत्तर हजार के करीब घायल हुए हैं। गाजा में हर दस में से एक आदमी या तो मारा गया है या घायल हुआ है। ऐसे में, हमास और उसके सहयोगी आतंकी संगठनों को यह जरूर सोचना चाहिए कि 7 अक्तूबर का हमला गाजा पर कितना भारी पड़ा है? संभव है, इजरायली बंधकों को अगर हमास पहले ही छोड़ देता, तो इतनी बड़ी संख्या में निरपराध लोग नहीं मारे जाते। बहुत गुहार के बावजूद हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया। हमास ने बंधकों की जो अमानवीय हालत बनाई है, उसकी केवल निंदा हो सकती है। यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि गाजा में नरसंहार के लिए कौन दोषी है? नरसंहार में शामिल तमाम लोग जब ईमानदारी से समीक्षा करेंगे, तभी पुख्ता समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस संघर्ष विराम के बाद जरूरी है कि हिंसा में शामिल पक्ष एक-दूसरे को दोषी ठहराने के बजाय तार्किक ढंग से विचार करें। आज गाजा को मानवीय बनाने की जरूरत है, तभी नफरत का मुकम्मल इलाज होगा और बदला लेने का दुष्चक्र टूटेगा। जरूरी है कि हमास बिना समय गंवाए बंधकों को रिहा करे और इजरायल गाजा से अपनी सेना हटाने की प्रक्रिया फौरन शुरू करे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उचित ही शांति समझौते के पहले चरण के समझौते को एक कूटनीतिक सफलता और इजरायल के लिए राष्ट्रीय व नैतिक जीत बता रहे हैं। इजरायल को बंधकों का इंतजार है, बंधक जिस हालत में रिहा होंगे, उससे भी गाजा के भविष्य का फैसला होगा। इस पूरे संघर्ष की संतुलित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सुधार के तौर-तरीके हासिल हों। कटुता, बबर्रता को भूलकर आगे बढ़ना होगा। इंसानियत की उम्मीद कभी एकतरफा पूरी नहीं होती। इंसानियत की राह पर सभी को चलना पड़ता है, तभी किसी समाज, देश या क्षेत्र में शांति बहाल होती है।

गाजा के लोगों ने अगर दो साल तक खून के आंसू बहाए हैं, तो इसके लिए केवल इजरायल नहीं, हमास भी दोषी है। खैर, अब अमन की कोशिशें कामयाब होनी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 अक्तूबर, 1950

मंडल का त्यागपत्र

पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार के कानून और श्रम मंत्री श्री जोगेन्द्रनाथ मण्डल ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। श्री मण्डल शुरू से ही मुस्लिम लीग के कृपा-पात्र रहे हैं। इसी कारण जब मुस्लिम लीग भारत की अन्तरिम सरकार में शामिल हुई, तो उसने मुसलमानों के लिए निर्धारित स्थानों में से एक स्थान श्री मण्डल को प्रदान किया था। उसके बाद पाकिस्तान बना और श्री मण्डल पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्रिमंडल में ले लिये गये। किन्तु उन्हें भी अब पाकिस्तान सरकार से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान में, खासकर पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों के प्रति होने वाले व्यवहार के विरोध में अपने पद से त्यागपत्र दिया है। वह अब तक अपने आप से संघर्ष करते रहे और जब उनके लिए अपनी आत्मा को धोखा दे सकना असंभव हो गया, तो वह बाहर निकल आये।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति जो दुर्व्यवहार होता रहा है, वह किसी से छिपा नहीं रहा है, किन्तु उसकी ऐसे क्षेत्र से पुष्टि हुई है, जिसकी मुश्किल से आशा की जा सकती थी। श्री मण्डल ने अपने त्यागपत्र में अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान की भीतरी नीति पर विशद प्रकाश डाला है। उनके कथनानुसार पाकिस्तान में हिन्दू रह नहीं सकते और उन्हें या तो पाकिस्तान से धीरे-धीरे खदेड़ दिया जायेगा अथवा धर्मान्तरण द्वारा हजम कर लिया जायेगा। पश्चिम पाकिस्तान में जो हरिजन रह गये थे, उनके उदाहरण में धर्म-परिवर्तन की पिछली क्रिया सम्पन्न हो चुकी है। श्री मण्डल ने इस्लामी राज्य की कल्पना की उतनी ही कड़ी टीका की है, जितनी उसका कट्टर से कट्टर विरोधी कर सकता था। वह उसे मानवता के लिए महान खतरा तथा समानता और विवेक के तमाम सिद्धांतों के विपरीत मानते हैं। श्री मण्डल जैसे व्यक्ति का, जिनकी गणना पाकिस्तान के कृपापात्रों में होती थी, इस निष्कर्ष पर पहुंचना कम आश्चर्य की बात नहीं है। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का उन्होंने बिल्कुल निराश होकर साथ छोड़ा है। उन्होंने देख लिया कि जिम्मेदारी के पद पर रहकर वह पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसी दशा में उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि पाकिस्तान के हिन्दू किसी गलत खयाल में रहें अथवा बाहर के लोग यह धारणा बनाकर चलें कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक अपनी जान-माल और धर्म के सम्बन्ध में सुरक्षित रह सकते हैं।

काश! यह दुस्साहस देश को जगा पाए

सांविधानिक महत्व के मुद्दों, नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और न्यायपालिका को जो भी कहना हो, वह स्पष्ट कहे। पर ऐसा हो नहीं रहा।

यहां स्कैन करें

कुमार प्रशांत | गांधीवादी चिंतक

जूता चलाने वाले ने जब अपना काम कर दिया, तब जिन पर जूता फेंका गया था, उन्होंने जूते को उसकी जगह दिखाकर, अपूर्व संयम दिखाते हुए अपना सामान्य काम शुरू कर दिया। हमारे प्रधान न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने ऐसा करके हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। प्रधान न्यायाधीश का यह स्थिरचित्त व्यवहार स्वप्नवत लगता है।

गुलिवर को लिलिपुट में भी ऐसे 'छोटे' लोग नहीं मिले होंगे, जैसे हमें मिले हैं। छोटा या नाटा होने और 'क्षुद्र' होने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस फर्क को इन दिनों जुमलेबाजी से ढकने की चातुरी दिखाई जा रही है। लेकिन छद्म भी इतना चरित्र शून्य नहीं होता है कि बहुत वक्त तक छद्म चलने दे। देखिए न, आज एक जूते ने उसे तार-तार कर दिया है। आज से आधी शती पहले, 1973 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो कहा था, वह आज के तंत्र से ऐसे चिपकता है, जैसे इसके लिए कल ही कहा गया हो : 'देश के राजनीतिक नेतृत्व की नैतिक हैसियत जब एकदम से बिखर जाती है, तब सभी स्तरों पर अनगिनत बीमारियां पैदा हो जाती हैं।' इसीलिए सारे देश को क्षुद्रता का डेंगू हुआ है। क्यों? क्योंकि आज के राजनीतिक वर्ग की नैतिक हैसियत एकदम बिखर गई है।

यह जूता किसी दलित पर नहीं फेंका गया है, जिस पर फेंका गया, वह संयोग से दलित है। सच यह है कि यह असहमति पर फेंका गया वह जूता है, जो सत्ता में बैठे लोग दशकों से लगातार फेंकते आ रहे हैं। घृणा इनके दर्शन की संजीवनी बूटी है। गवई साहब देश के प्रधान न्यायाधीश हैं। सभी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि वह दलित हैं। कोई यह क्यों नहीं कह रहा है कि न न्याय की कोई जाति होती है, न न्यायाधीश की? जब दिल और दिमाग से जाति-धर्म-संप्रदाय-लिंग-भाषा-प्रांत की लकीरें मिट जाती हैं, तब न्याय का ककहरा लिखने की शुरुआत होती है। इसलिए हमें कहना चाहिए कि गवई साहब न दलित हैं, न सवर्ण हैं, वह हमारी न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायमूर्ति हैं। हम इतना ही जानते हैं और उनकी योग्यता का मान करते हैं। हम संपूर्ण न्यायपालिका को ऐसे ही देखना चाहते हैं। हमारी चाह आप जानना चाहें, तो वह यह है कि सारा देश, संसार के सारे इंसान ऐसे ही हों; न हों तो ऐसे ही बनें, और उन्हें ऐसा बनाने में हम सब अपने मन-प्राणों का पूरा बल लगाएं।

हमें गहरा खेद है कि जिसका जूता था, उस वकील के पास अब वह जूता भी नहीं रहा। एक वही जूताग्रस्त मानसिकता तो थी उन जैसों के पास! पिछले कुछ सालों में इस तंत्र ने देश के हर नागरिक के हाथ में यही मानसिकता तो थमाई है कि अपना जूता दूसरों पर फेंको! बात पुरानी है, पर एकदम खरी है कि तुम जिनके साथ रहते हो, ठीक उनके जैसे होते चले जाते हो।

न्यायमूर्ति गवई ने प्रधान न्यायाधीश बनते ही कहा था कि वह डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को माथे पर धरकर चलते हैं। हमने कोई ऐतराज नहीं किया। हालांकि, होना तो यह चाहिए कि उनके व दूसरे किसी भी न्यायमूर्ति के माथे पर संविधान ही हो- न गांधी हों और न आंबेडकर! किसी भी मुकदमे के दौरान फैसलों से इतर हमारे न्यायाधीश जो टिप्पणियां करते हैं, वे बहुत मतलब की नहीं होती हैं। विष्णु की मूर्ति के संदर्भ में हमारे सर्वोच्च न्यायमूर्ति की वह टिप्पणी भी न जरूरी थी, न निर्दोष थी। हमारी न्यायपालिका आज भी ऐसे ही चल रही है, जैसे देश में कुछ भी असामान्य नहीं है। जिस संविधान और लोकतंत्र की वजह से न्यायपालिका का अस्तित्व है, उस पर रोज-रोज हमले हो रहे हैं, यह हमें दिखाई देता है, मगर अदालतों को नहीं।

सांविधानिक महत्व के मुद्दों को, नागरिक स्वतंत्रता के सवालों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और न्यायपालिका को जो भी कहना हो, वह स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा रवैया संविधान को मजबूत नहीं बनाता है, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर को जिंदा नहीं करता है। संविधान ने न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी है तथा यही उसके होने की सार्थकता भी है कि वह लोकतंत्र के साथ खड़ा रहे। आज के दौर में यह सबसे आसान काम है। आसान इसलिए कि आपके पास एक किताब है, जिसे आंबेडकर का लिखा संविधान कहते हैं। बस उस किताब को खोलिए और उसके आधार पर सही या गलत का फैसला कीजिए। न एक शब्द बदलना है आपको, न कुछ अलग या नया लिखना है।

आप वह मत करिए, जो आपके कमजोर प्रतिनिधियों ने पहले किया है। संविधान ने नहीं कहा है कि आपको संतुलन साधना है; कि आपको बीच का रास्ता निकालना है। सत्य या न्याय संतुलन से नहीं, संविधान के पालन से सिद्ध होता है। हमारे एक पूर्व न्यायाधीश ने हाल ही में शायद अपना एक पहलू ढकने के लिए एक बौद्धिक तीर चलाया था- हमारा संविधान नहीं कहता है कि हमारे जजों की निजी आस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हां, हमारे संविधान ने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन संविधान ने साफ शब्दों में कहा है कि आपकी निजी आस्था की छाया भी आपके फैसलों पर नहीं पड़नी चाहिए। यह आसान नहीं है, तो जज बनाना इतना आसान कहां है! जिस तरह सड़क पर चलता हर ऐरा-गैरा जज नहीं बन सकता, ठीक उसी तरह बड़ी शिक्षा पाकर या विदेशों से डिग्री लाकर या किसी पूर्व जज का परिजन होने से कोई जज नहीं बन जाता। जज की कुर्सी पर बैठने से भी लोग जज नहीं बन जाते, यह योग्यता और पात्रता संविधान के साथ खड़े होने की आपकी हिम्मत से आती है।

यह याद रखना चाहिए कि आपातकाल में पांच जज थे, जिनमें से चार ने संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंककर, सरकार की खैरख्वाही की थी। भारतीय न्यायपालिका का वह दाग आज तक नहीं धुला है। किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में फैसला देने की बात नहीं है, जो लिखा हुआ संविधान देश की जनता ने आपको सौंपा है, उसका पालन करने की बात है।

जूता चला, यह बहुत बुरा हुआ। लेकिन यही जूता वरदान बन जाएगा, यदि इसने हमारी न्यायपालिका को नींद से जगा दिया। जूता चलाने की असहिष्णुता जिसने समाज का स्वभाव बना दिया है, वह अपराधी पकड़ा जाए, इसके लिए सन्नद्ध व प्रतिबद्ध न्यायपालिका अपनी कमर सीधी कर खड़ी हो, तो जूते का क्या, वह फिर से पांव में पहुंच जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ब्रिटिश गुलामी का बोझ ढो रही हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं

यहां स्कैन करें

देविना मेहरा | संस्थापक, फर्स्ट ग्लोबल

मशहूर कहावत है, 'जो भी मापा जाता है, उसका प्रबंधन मुमकिन है।' इस सूक्ति को दुनिया भर में शिक्षा, नौकरी और मूल्यांकन में चरितार्थ होते देखा जा सकता है। हमारे देश में इन क्षेत्रों में जिस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वे प्रतिभागियों की तैयारी, प्रदर्शन व मूल्यांकन के तरीकों पर असर डालती हैं। सभी प्रबंधन सलाहकार ऐसा ही करने की सलाह देते है। विडंबना यह है कि प्रबंधन शिक्षा में भी कभी इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि जिस तरह प्रतिभागियों की कुशलता का परीक्षण किया जाता है, क्या वह सही तरीका है?

गौरतलब है कि कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) और प्रबंधन संस्थानों में प्रवेश के लिए दो बातों की जांच की जाती है- अंग्रेजी की समझ और गणित व समस्याओं का तार्किक ढंग से समाधान करने की योग्यता। इनमें भी गणित व तर्कशक्ति परीक्षण में यह देखा जाता है कि प्रतिभागी समस्या का हल कितनी तेजी से कर सकता है। इस तरह यह 'आईक्यू' का ही परीक्षण है। प्रबंधन के क्षेत्र में इसे सर्वोच्च कौशल माना जाता है। लेकिन यहां सवाल यह है कि तेज गति से काम करना ही क्या सबसे अहम है? मैं ऐसे एक भी व्यवसाय को नहीं जानती, जहां निर्णय लेने में कुछ मिनट का अंतर सफलता और विफलता का फैसला कर देती हो। धीरूभाई अंबानी या रिचर्ड ब्रैनसन जैसी दूसरी पीढ़ी के उद्यमियों ने तो कभी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा से लेकर ओयो के रितेश अग्रवाल तक उद्यमियों ने भी कभी प्रबंधन की शिक्षा नहीं ली।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षाओं का भी यही हाल है। इसके आभामंडल और इसकी हैसियत को परे रख दें, तो पाएंगे कि इसकी पूरी प्रणाली ही बेतुकी है। इसकी परीक्षाएं प्रतिभागियों से इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान की जानकारियां कंठस्थ रखने की अपेक्षा करती हैं। साथ ही कुछ विश्लेषणात्मक कौशल का परीक्षण करती हैं। इनकी पहली समस्या तो यही है कि ये परीक्षाएं अनेक तरह की विशेषज्ञता वाली नौकरियों के लिए भर्तियां करती है। यूपीएससी द्वारा चयनित अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आदि में जाते हैं। सफल प्रतिभागी किस सेवा में पहुंचते हैं, यह केवल परीक्षा में उनके रैंक पर निर्भर करता है। इससे विचित्र विसंगतियां पैदा होती हैं। साहित्यिक पृष्ठभूमि और रुचि के किसी व्यक्ति को राजस्व सेवा मिल सकता है, जहां उसे कर नीतियों की जटिलताओं या लेखा सेवा के आंकड़ों से उलझना है। इसी तरह, समाज का व्यावहारिक ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति पुलिस सेवा में अधिकारी बन सकता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा को आमतौर पर नौकरशाही की रीढ़ माना जाता है, लेकिन जब इसके अधिकारी अक्सर नई-नई सेवाओं में भेजे जाते हैं, तब यह मुख्य रूप से सत्ता का खेल होता है, जिसके लिए न तो कौशल, न ज्ञान और न ही विषय-वस्तु की जानकारी जरूरी है। कुछ सर्वेक्षणों में आईएएस अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि वे संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण की कमी के कारण खुद को असहज महसूस करते हैं। इसके विपरीत, अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा या विदेश विभाग जैसी संघीय एजेंसियां इस क्षेत्र में अनुभव व रुचि रखने वाले उम्मीदवारों में से चयन करती हैं। जैसे, कर अधिकारियों में लेखा-जोखा की क्षमता और विदेश सेवा के लिए कूटनीतिक योग्यता को परखा जाता है। अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध सिंगापुर की सिविल सेवा योग्यता परीक्षणों, साक्षात्कारों और संबंधित क्षेत्र में भूमिका के आधार पर मूल्यांकन करती है। वैश्विक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने मुझे बताया है कि भारतीय अधिकारी अक्सर कम सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता का अभाव होता है।

औपनिवेशिक काल की प्रथाओं पर आधारित भारत की वर्तमान सेवा प्रणाली कौशल के बजाय रटने और सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता देती है। अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा को विशेषज्ञों के बजाय वफादार प्रशासक तैयार करने के लिए डिजाइन किया था और यूपीएससी की परीक्षाएं इसी विरासत को ढो रही हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

अंगरेजों ने भारतीय सिविल सेवा को विशेषज्ञों के बजाय वफादार प्रशासक तैयार करने के लिए डिजाइन किया था, वही आज तक जारी है।

मनसा वाचा कर्मणा

जहां मृत्यु वहां धर्मगुरु

मैं एक छोटे से गांव में गया था। वहां एक नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा का समारोह चल रहा था। सैकड़ों पुजारी और संन्यासी इकट्ठे हुए थे। हजारों देखने वालों की भीड़ थी। धन मुक्त-हस्त से लुटाया जा रहा था। और सारा गांव इस घटना से चकित था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वह मंदिर बनवाया था और इस समारोह का आयोजन किया था, उससे ज्यादा कृपण व्यक्ति कोई और हो सकता है, यह सोचना भी उस गांव के लोगों के लिए कठिन था।

वह व्यक्ति कृपणता की साकार प्रतिमा था। उसके हाथों एक पैसा कभी छूटते किसी ने नहीं देखा था। फिर उसका यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? यही चर्चा और चमत्कार सबकी जुबान पर था। उस व्यक्ति के द्वार पर कभी भिखारी नहीं जाते थे, क्योंकि वह द्वार केवल लेना जानता था। देने से उसका कोई परिचय ही नहीं था। फिर यह क्या हो गया था? जो उस व्यक्ति ने कभी स्वप्न में भी न किया होगा, वह वस्तुतः आंखों के सामने होते देख सभी आश्चर्य से ठगे रह गए थे। एक वृद्ध ने मुझसे भी पूछा, 'इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या वह व्यक्ति बिल्कुल बदल गया है?'

मैंने उत्तर में एक घटना बताई- छोटे से बच्चे ने एक सिक्का गटक लिया था। उसे निकालने के लिए सब उपाय व्यर्थ हो गए थे। उसकी मां पति से बार-बार कह रही थी, 'जल्दी चिकित्सक को बुलाओ।' पति ने एक-दो बार सुना और सिक्का निकालने की कोशिश करते-करते बोला, 'चिकित्सक? मैं सोचता हूं कि धर्मगुरु को ही बुला लेना कहीं ज्यादा उचित है?'

पत्नी हैरान होकर बोली 'धर्मगुरु? क्या तुम सोचते हो कि मेरा बच्चा बच नहीं सकेगा, जो धर्मगुरु को बुलाना चाहते हो?' पति ने कहा, 'इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि किसी से भी रुपया निकलवा लेने में उनसे ज्यादा कुशल और कोई नहीं होता।'

फिर मैंने कहा, 'यह मत सोचना कि उस व्यक्ति का लोभ समाप्त हो गया। उसने मुझसे भी जानना चाहा है कि मंदिर बनवाने का परलोक में क्या फल होता है? यह सब दान-धर्म उसके लोभ का ही फैलाव है। यह उसकी पूर्व-वृत्ति का विरोध नहीं, वरन उसका और विस्तार है। जीवन हाथ में होता है, तो लोभ धन जोड़ता है। और जब मृत्यु निकट आती है, तो लोभ धर्म जोड़ता है। यह सब एक ही चित्त का खेल है। धर्मगुरु लोभ को नई दिशा दे देते हैं... मृत्यु धर्मगुरु की बड़ी सहयोगिनी है। वही उसके धंधे का मूलाधार है। उसकी छाया में ही उनका शोषण चलता है। वह व्यक्ति जरा भी नहीं बदला है। केवल उसके हाथों से जीवन बह चुका है। वह बूढ़ा हो गया है और मृत्यु की पद-ध्वनि उसे सुनाई पड़ने लगी है। और यह तो सर्वविदित ही है कि जहां मृत्यु है, वहां धर्मगुरु है।'

ओशो

जीवन हाथ में होता है, तो लोभ धन जोड़ता है। और जब मृत्यु निकट आती है, तो लोभ धर्म जोड़ता है। यह सब एक ही चित्त का खेल है। धर्मगुरु लोभ को नई दिशा देते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप | अमेरिकी राष्ट्रपति

इजरायल और हमास द्वारा शांति योजना पर हस्ताक्षर के साथ बंधकों की रिहाई व सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो गई है। यह महान दिन है। कतर, मिस्र और तुर्की के शांतिदूतों को धन्यवाद, जिन्होंने इस काम को संभव बनाया।

किसी से भी जीने का हक न छीना जाए

प्रत्येक मनुष्य को जीवन जीने का नैसर्गिक अधिकार है, यहां तक कि मुजरिमों को भी। किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देना उसके जीने के नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। हर कोई सोचता है कि मानव जीवन मूल्यवान है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि मानव जीवन इतना मूल्यवान है कि एक हत्यारे को भी उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अपराधी के जीवन का मूल्य उसके बुरे आचरण से नष्ट नहीं हो सकता। हम एक 'न्यायिक हत्या' के जरिये दूसरों को यह नहीं सिखा सकते कि हत्या करना गलत है। साथ ही, हत्या के दोषी की जान लेना बदला है, यह न्याय नहीं है।

मृत्युदंड के खिलाफ सबसे आम और ठोस तर्क तो यही है कि न्याय-प्रणाली की खामियों के कारण निर्दोष लोग भी सजा पा सकते हैं और किसी की जान लौटाई नहीं जा सकती। गवाह, अभियोजक और जूरी सदस्य, सभी गलतियां कर सकते हैं। मृत्युदंड राज्य द्वारा हिंसा के एक अपरिवर्तनीय कृत्य को वैध बनाता है और अनिवार्य रूप से निर्दोष पीड़ितों को इसका शिकार बनाता है। जब तक मानव न्याय त्रुटिपूर्ण बना रहेगा, निर्दोषों को फांसी देने का जोखिम कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि ये गलतियां संभव हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में 1973 से अब तक मृत्युदंड की सजा पाए 130 लोगों को निर्दोष पाया गया है और उन्हें मृत्युदंड से मुक्त कर दिया गया। बरी होने से पहले मृत्युदंड की सजा पर बिताए गए औसत समय 11 वर्ष था।

यहां यह भी सोचने की बात है कि गलत तरीके से मृत्युदंड पाए लोगों की यातनाएं विशेष रूप से भयानक हो जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि मृत्युदंड समाज में क्रूरता को ही बढ़ावा देता है और हत्या की दर में वृद्धि करता है। अमेरिका के उन राज्य में हत्याएं अधिक होती हैं, जहां पर मृत्युदंड की अनुमति है। साल 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, जिन राज्यों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है, वहां पर हत्या की दर प्रति 1,00,000 व्यक्तियों पर 4.01 प्रतिशत थी, जबकि जिन राज्यों में मृत्युदंड का प्रावधान है, वहां यह आंकड़ा पांच प्रतिशत था।

इसीलिए, जीवन को तब तक संरक्षित किया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा न करने का कोई ठोस कारण न हो। जो लोग मृत्युदंड के पक्ष में हैं, उन्हें अपनी बात को सही ठहराना चाहिए। आज विश्व मृत्युदंड निषेध दिवस है। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में विश्व मृत्युदंड निषेध गठबंधन द्वारा किया गया था। आइए, इस दिवस पर मृत्युदंड के उन्मूलन का अभियान चलाने और मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की दशा सुधारने पर गौर करें।

वेदांत कृष्ण, छात्र

अनुलोम-विलोम

मृत्युदंड निषेध दिवस

दुर्दांत अपराधी को मौत की सजा देना उचित

मृत्युदंड, जिसे फांसी की सजा भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा उसके गंभीर अपराधों के लिए दी जाने वाली कानूनी सजा है, जिसके कारण उस व्यक्ति को जीवन से वंचित कर दिया जाता है। भारत में अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही यह सजा दी जाती है। कानून का भय, निवारण और नागरिकों की सुरक्षा जैसी दलीलें मृत्युदंड को तर्कपूर्ण बनाती हैं।

अगर हमें अपने समाज को सभ्य वातावरण में रखना है, तो अपराधों के लिए उचित दंड की व्यवस्था भी बनाए रखनी होगी। इसी क्रम में ऐसे अपराधियों को, जो आदतन क्रूर हैं और उनमें सुधार के कोई लक्षण नहीं हैं, मौत की सजा देनी ही चाहिए। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क इस विचार से और अधिक प्रेरित होते हैं कि इस तरह की सजा समाज में अपराधों की रोकथाम है। यह प्रतिशोध और निवारण का साधन है। अगर एक अपराधी बिना कारण, धोखा देकर या बलात्कार के साथ हत्या करता है, तो उसे मृत्युदंड ही देना उचित है। एक अन्य उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि यदि कोई व्यक्ति जान लेता है, तो वह अपने जीवन के अधिकार को खो देता है और पीड़ित पक्ष के पास अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका हमलावर को मारना ही है। यह तर्क दिया जाता है कि अपराधी ने जो जघन्य अपराध किया है, वह मृत्युदंड का भागी है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। इस विचार के अनुसार, मृत्युदंड पाने के भय से लोग जघन्य अपराध करने से बचते हैं, जिससे अपराधों में कमी आती है। राज्य का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे और मृत्युदंड राज्य के लिए नागरिकों की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने का एक साधन है।

इसलिए, यदि कोई व्यक्ति समुदाय के लिए खतरनाक है और किसी पाप द्वारा उसे नष्ट कर रहा है, तो उसके साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए वह यह है कि सामाजिक भलाई को बनाए रखने के लिए मृत्युदंड दिया जाए। एक पापी को मारना उसी तरह उचित हो सकता है, जैसे एक जानवर को मारना। क्योंकि, जैसा कि अरस्तू ने बताया है एक बुरा आदमी एक जानवर से भी बदतर और अधिक हानिकारक होता है। विचारक थॉमस एक्विनास का कहना है कि कुछ संदर्भ एक बुरे कार्य (हत्या) को एक अच्छे कार्य (उस व्यक्ति की हत्या करना, जिसने हत्या करके अपनी प्राकृतिक योग्यता खो दी है) में बदल देते हैं।

इसलिए, जरूरी है कि न्याय को पुनः स्थापित करने के लिए की जाने वाली न्यायोचित हत्याओं, यानी मृत्युदंड की व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए।

रिंकल कुमारी, टिप्पणीकार

चिंतन की पतवार ही जीवन की नैया को आगे बढ़ाती है

गाजा में शांति की आस

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे बढ़ाए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए सहमति बन जाना इजरायल और फलस्तीन के लिए ही नहीं, पश्चिम एशिया और शेष विश्व के लिए भी राहत की खबर है। यदि इस समझौते के शेष चरणों के लिए भी इजरायल और हमास में सहमति बन जाती है तो गाजा में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशंसा के पात्र होंगे। उनके खाते में कम से कम एक संघर्ष तो खत्म करने का श्रेय जाएगा ही। ऐसा होने की उम्मीद में ही भारतीय प्रधानमंत्री समेत विश्व के अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि इन देशों में सऊदी अरब, मिस्र समेत वह कतर भी है, जो हमास को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। गाजा शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास करीब 20 बंधकों के साथ मारे गए अपहृत लोगों के शव इजरायल को सौंपेगा। इसके बदले इजरायल लगभग दो हजार फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें कई हमास आतंकी भी हैं। इसी के साथ गाजा में घुसी इजरायली सेना अपने कदम पीछे खींचेगी। ट्रंप की ओर से तय किया गया शांति समझौता 20 सूत्रीय है। इसके अनुसार हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में अपने प्रशासनिक दखल को समाप्त करना होगा। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। यदि वह इस्लामी और विशेष रूप से अरब देशों के दबाव में अपने हथियारबंद समूह को भंग करने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह इजरायल को नष्ट करने और वहां के लोगों यानी यहूदियों को मिटाने की अपनी घृणा का परित्याग करेगा। वास्तव में जब ऐसा होगा, तभी इजरायली और फलस्तीनी चैन से रह पाएंगे और पश्चिम एशिया में शांति कायम हो सकेगी। भविष्य में जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि दो वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजरायल में घुसकर जो कहर ढाया और जिसके नतीजे में 12 सौ लोग मारे गए, उसके जवाब में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में साठ हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। इजरायल की सैन्य कार्रवाई गाजा के साथ लेबनान, यमन और ईरान तक गई। इजरायल ने गाजा में अपनी कठोर सैन्य कार्रवाई इसलिए जारी रखी, क्योंकि हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इजरायल हमास के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान ही नहीं गई, इजरायल-ईरान के बीच के तनाव ने युद्ध का रूप लिया, जिसमें अमेरिका ने भी दखल दिया। इसके अतिरिक्त यमन में काबिज हाऊती विद्रोहियों की हरकतों से समुद्री व्यापार में बाधा पहुंची, जिसके नतीजे में तेल के दाम चढ़े।

कड़ी सजा मिले

राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार से बाज नहीं आ रहे। विशेष निगरानी इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक कार्यपालक अभियंता के ठिकानों से छापेमारी के दौरान नकदी, जेवरात और जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए। अभियंता पर अपनी नौकरी के 11 सालों में आय से अधिक 1.59 करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप है। उसी दिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने राजधानी पटना में विश्वैश्वरैया भवन स्थित निर्माण भवन के कोषागार से एक डाटा इंट्री आपरेटर को घूस की रकम के साथ गिरफ्तार किया। वह लिपिक का काम कर रहा था। उसने एक व्यक्ति से उसकी बकाया पेंशन राशि स्वीकृत करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचारियों को दबोचे जाने की कार्रवाई लगातार की जाती है, इसके बावजूद ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। तात्पर्य यह कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए इन कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा। साफ है, दंड का प्रविधान और कठोर बनाना होगा ताकि, ऐसे तत्वों का मनोबल टूट सके। साथ ही भ्रष्टाचार के नेटवर्क से जुड़े बिचौलियों की भी पहचान करनी होगी। विभाग के आला अधिकारियों को पारदर्शी व्यवस्था लागू कर कड़ी मानीटरिंग करनी होगी। पूर्व के ऐसे मामलों की समीक्षा करते हुए न्यायालय में जोरदार पैरवी की जानी चाहिए, जिससे आरोपित को यथाशीघ्र कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

भ्रष्ट कर्मियों के कारण आमलोग तो परेशान होते ही हैं, सरकार की छवि भी धूमिल होती है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ब्रिटिश पीएम स्टार्मर का भारत दौरा देश की अर्थव्यवस्था में वैश्विक भरोसे को दर्शाता है?

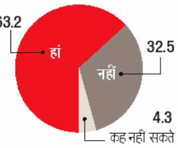

आज का सवाल

क्या बिहार में हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी यादव का वादा विश्वसनीय है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

दवाओं की गुणवत्ता से समझौता

आदित्य सिन्हा

कफ सीरप से मौतें यह कड़वा सच बताती हैं कि देश में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा

तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर के बाहरी इलाके में एक छोटे दवा कारखाने के दरवाजे अब बंद हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की इस कंपनी को लेकर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि उसने ड्रग्स और कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत 364 उल्लंघन किए। यहां बना कफ सीरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की जिंदगी लील गया। इस सीरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा विषैला तत्व मिला। यह किडनी और लिवर को क्षति पहुंचाता है। निर्माण के अलावा कंपनी के स्तर पर और भी लापरवाही बरती गई। जैसे पैकिंग पर अनिवार्य चेतावनी नहीं दी गई कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न करने दिया जाए। यह कोई पहली और अलग घटना नहीं है। गांबिया और उज्बेकिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक एक ही कहानी सामने आती है। इस कहानी में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले नियमों को धता बताते हैं, निगरानी कमजोर और मामला बिगड़ने पर प्रतिक्रिया धीमी होती है। यह मामला दर्शाता है कि भारत की विकेंद्रीकृत और अक्षम दवा नियामक प्रणाली खतरनाक रूप से पुरानी पड़ चुकी है। ऐसे मामले 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में पहचान बनाने वाले भारत की प्रतिष्ठा भी धूमिल करते हैं। करीब 200 से अधिक देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराकर भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी है। पीएम जन औषधि योजना की सफलता में जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका है। इसके तहत 5,600 करोड़ रुपये की दवाएं बेची गई हैं। पिछले एक दशक के दौरान इस योजना से लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। जेनेरिक दवाएं बड़ी आवश्यकता हैं। हालांकि गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना ऐसी किफायती दवाएं और घातक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तबके को राहत देने के लिए ये दवाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए ही आफत बन जाती हैं। कफ सीरप से बच्चों की मौतें इस कड़वी सच्चाई को ही उजागर करती हैं कि भारत में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

अक्सर यह सवाल उठता है कि जब जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं जैसे तत्व ही होते हैं तो कई बार वे अनुपयोगी क्यों साबित हो जाती हैं? इसका जवाब दवा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। दवा में मूलभूत तत्व या एपीआइ उसका केवल एक हिस्सा होता है। बाकी फार्मूलेशन में फिलर्स, बाइंडर्स और कोटिंग जैसे पहलू भी होते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि दवा कितनी जल्दी घुलती है और शरीर उनकी कितनी मात्रा अवशोषित करता है। इन पहलुओं में थोड़ा सा भी परिवर्तन दवा की प्रकृति एवं प्रभाव पर असर डाल सकता है। चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डाक्टरों ने 2024 के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया। एंटीफंगल दवा इट्राकोनाजोल के 22 जेनेरिक संस्करणों की तुलना में उन्होंने पाया कि केवल 29 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं ने दो सप्ताह में अपेक्षित स्तर हासिल किया, जबकि पेटेंट दवाओं में यह स्तर 73 प्रतिशत तक था। जेनेरिक दवाओं में छोटे-असमान आकार के पेलेट मिले, जो अवशोषण और प्रभावशीलता को प्रभावित करते थे। ये ऐसा अंतर नहीं, जो जानबूझकर छोड़ा जाए, बल्कि यह इसी को रेखांकित करता है कि असमान निर्माण मानक और कमजोर निगरानी परिणामों को कैसे प्रभावित करती है।

अवधेश राजपूत

इस मोर्चे पर समस्या गहरी और संस्थागत है। दवा निर्माण के लिए भारत का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ही व्यापक रूप से नियम निर्धारित करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देना, इकाइयों का निरीक्षण करना, नमूनों के परीक्षण जैसी अधिकांश शक्तियां राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों यानी एसडीआरए के पास हैं। निगरानी को लेकर विभिन्न राज्यों की क्षमताएं भी भिन्न हैं। कुछ राज्यों के पास सुदृढ़ प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षित निरीक्षक हैं, जबकि कई राज्यों में तमाम इकाइयों के लिए अत्यंत सीमित मानव संसाधन होता है। निर्माता इसी का फायदा उठाते हुए वहां उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, जहां नियामकीय ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यह नियामकीय तोड़ ही है। सीडीएससीओ ने 2018 में स्थिरता परीक्षण को अनिवार्य तो बनाया, पर कई राज्यों में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा ही नहीं है और यह नियम पुरानी दवाओं पर लागू भी नहीं होता। इससे भारत जैसी जलवायु वाले देश में एक बड़ा जोखिम पैदा होता है। भाटिया समिति (1954) से लेकर माशेलकर समिति (2003) ने यही सुझाया कि लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत लाया जाए, पर सुधारों की राह में राज्यों का रवैया अवरोध बना हुआ है।

श्रीसन मामला दिखाता है कि कैसे लापरवाहियों की अनदेखी होती है। यह 10 से भी कम कर्मियों के भरोसे चल रही थी। फिल्ट्रेशन सिस्टम और रिकाल तंत्र भी नहीं था। फिर भी उसे 2026 तक लाइसेंस हासिल था। पूर्ववर्ती कंपनी का सालों पहले वजूद खत्म होने के बावजूद सीमित निरीक्षण के जरिये उसने नया लाइसेंस हासिल कर लिया। नियम उल्लंघन का मामला तब तक सामने नहीं आया, जब तक कुछ नौनिहाल काल के गाल में नहीं समा गए।

भारत में कानूनों की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें ढंग से लागू करने की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की। समय आ गया है कि भारत में सीडीएससीओ के तहत एक केंद्रीकृत लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली बनाई जाए, जो प्रत्येक उत्पाद, परीक्षण और रिकाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग रजिस्ट्रार द्वारा संचालित हो। सभी नई-पुरानी दवाओं के लिए सालाना परीक्षण भी अनिवार्य करना होगा। ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे तत्वों की आपूर्ति श्रृंखलाओं का डिजिटल रिकार्ड बने और उन्हें कभी भी ट्रेस किया जा सके। राज्यों की शक्तियां उनके पास रहें, लेकिन मानकों के अनुपालन और सजा के प्रविधान पूरे देश में एकसमान हों। कफ सीरप सेवन से बच्चों की मौत को एक चेतावनी के रूप में लिया जाए। यदि सबक नहीं सीखे गए तो आगे और घातक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सर क्रीक को लेकर सचेत रहना होगा

डा. कृपा नौटियाल

सर क्रीक सीमा को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए आवश्यक है

सर क्रीक क्षेत्र भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सैन्य जमावड़े को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है, जो गुजरात में कच्छ के रण को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सर क्रीक विवाद की जड़ें 1908 से जुड़ी हैं, जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को लेकर असहमति उत्पन्न हुई। बांबे प्रेसीडेंसी द्वारा 1914 में एक प्रस्ताव के जरिये मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने एक अस्पष्टता पैदा कर दी। प्रस्ताव के एक खंड में सुझाव दिया गया कि सीमा क्रीक के बाहरी किनारे की ओर स्थित है, जबकि दूसरे में अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया, जिसके अलग निहितार्थ थे। यह मुद्दा 1965 के सशस्त्र संघर्ष के बाद फिर से उभरा, जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया। 1968 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रण के 90 प्रतिशत हिस्से पर भारत के दावे को बरकरार रखा, लेकिन सर क्रीक सीमा अनसुलझी रही। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान जोर देता है कि यह क्रीक के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अंतर निर्धारित करता है कि समुद्री सीमा अरब सागर में कैसे फैली हुई है, जो संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और दोनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अरबों डालर के सामुद्रिक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है।

साल 1989 से भारत और पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने के लिए ठोस प्रगति के बिना छह दौर की चर्चाएं कर चुके हैं। पाकिस्तान जोर देता है कि समुद्री सीमा के लिए आधार स्थापित करने के लिए पहले क्रीक में सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों को जोड़ता है। वहीं भारत ने परिसीमन, सीमांकन का प्रस्ताव रखा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों और राजनीतिक अविश्वास ने कार्यान्वयन को रोक दिया है। यह भारत के अपने अन्य पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के सफल समाधान के बिल्कुल विपरीत है।

सर क्रीक की सुरक्षा का अवलोकन करते रक्षा मंत्री • प्रेट्र

श्रीलंका के साथ 1974 और 1976 में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मालदीव के साथ त्रिबिंदु से लेकर पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में 200 समुद्री मील की सीमा तक फैली 288 किलोमीटर की समुद्री सीमा स्थापित की गई। बांग्लादेश के साथ दशकों की असफल बातचीत के बावजूद विवाद अंततः संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानूनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया। 2014 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने बंगाल की खाड़ी में विवादित 25,602 वर्ग किलोमीटर में से 19,467 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश ने इस बाध्यकारी निर्णय को स्वीकार किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तब समुद्री सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से संभव है।

सर क्रीक पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची इस विवादित सीमा से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां इसका प्राथमिक नौसैनिक अड्डा है। यहां भारतीय नौसैनिक उपस्थिति पाकिस्तान की व्यावसायिक जीवन रेखा और सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरे में डालती है। भारत के लिए सर क्रीक को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह और क्षेत्र को घुसपैठ गलियारा बनने से रोकने के लिए भी यह जरूरी है। सर क्रीक पर उठे विवाद को नए सिरे से 2019 के बाद के सैन्य गतिरोध और आपरेशन सिंदूर के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण जैसे कि स्वदेशी विमानवाहक पोत, उन्नत पनडुब्बियां और बढ़ी हुई तटीय निगरानी ने समुद्री शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया है। पाकिस्तान इसके जरिये नौसैनिक रणनीति को तेज करना चाहता है। वह उन्नत पनडुब्बियां और जहाज-रोधी मिसाइलें प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य सहायता का लाभ उठाना चाहता है। सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी दुस्साहसिक कार्रवाई उसे पीढ़ियों तक पछताने पर मजबूर कर सकती है।

सर क्रीक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ नियमित गश्त भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है। ये गश्त एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इससे दोनों देश विवादित जल पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और दोनों देशों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार करने से रोकते हैं। फिलहाल यह भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। सर क्रीक पर भारत की सीमाओं की दृढ़ता यह संदेश देती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हर इंच भूमि की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान यदि नए सिरे से राजनयिक पहल करे, आतंकवादियों को समर्थन बंद कर दे और अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी दिखाए तो सर क्रीक विवाद का समाधान निकल सकता है।

(लेखक भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विचार और स्वास्थ्य

तन एवं मन का गहरा संबंध है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। शरीर की स्थितियां बदलती हैं तो मन प्रभावित होता है और जब मन की भावनाएं असंतुलित होती हैं तो शरीर पर उसका सीधा असर दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण संभव है। केवल शरीर को बलिष्ठ और निरोगी बना लेने से स्वास्थ्य की पूर्णता नहीं मिलती, जब तक मन में शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का संचार न हो।

चिकित्सा विज्ञान भी यह स्वीकारता है कि नकारात्मक विचार, चिंता, भय और तनाव शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देते हैं। अनेक रोग केवल असंतुलित और अशांत मन की देन हैं। जिन व्यक्तियों का मन संतुलित रहता है, उनके जीवन में रोगों की आशंका कम होती है। प्रसन्नता को श्रेष्ठ रसायन कहा गया है, क्योंकि यह न केवल मन को हल्का करती है, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग में जीवनशक्ति का संचार करती है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही प्रसन्नता का प्रकाश जीवन की उदासी, भय और चिंता को मिटा देता है।

जीवन को चिंता एवं भय से मुक्त करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। चिंता एक ऐसा विष है, जो धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर देता है। भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है और उसके आत्मविश्वास को छीन लेता है। जबकि निडर और निश्चिंत जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। संतुलित विचार और सकारात्मक सोच मनुष्य को आंतरिक शक्ति देते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों ने हमेशा आनंद और प्रसन्नता को जीवन का आधार माना है। द्वेष, ईर्ष्या, चिंता और क्रोध जैसे विचार शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। इसके विपरीत मैत्री, करुणा, शांति और प्रसन्नता जैसे विचार रोगों के निवारण में औषधि का काम करते हैं। वास्तव में विचारों का स्वास्थ्य पर जितना गहरा असर है, उतना किसी औषधि का भी नहीं।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

तय हो जिम्मेदारी

'भरोसा डिगाने वाला रवैया' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़कर मन अत्यंत व्यथित हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विषाक्त कफ सीरप के सेवन से अब तक 25 से अधिक मासूम बच्चों की मौत होना न केवल दर्दनाक, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब नकली या जहरीली दवाइयों ने निर्दोष जानें ली हों और हर बार की तरह इस बार भी जांच और कार्रवाई का ढोल पीटा जा रहा है। दोष केवल उस दवा निर्माता कंपनी का नहीं है जिसने यह घातक सीरप बनाया, बल्कि उन अधिकारियों का भी है जिनकी निगरानी में यह सब हुआ। सरकारें इन अधिकारियों पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं, परंतु जब जिम्मेदारी की घड़ी आती है तो ये या तो मौन रहते हैं या लीपापोती में लग जाते हैं। बिना मिलीभगत के इतनी बड़ी लापरवाही संभव ही नहीं। समय आ गया है कि ऐसे मामलों में सख्त और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की जाए। दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को दवा निर्माण, परीक्षण और वितरण प्रणाली को तकनीकी निगरानी से जोड़ना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मासूम जान भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट न चढ़े। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे वसूली का चलन समाप्त हो सके।

sureshgoyal8@gmail.com

युवा करें संस्कृति का संरक्षण

मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर समृद्ध परंपराओं, लोककला और लोकगीतों के कारण पूरे देश में विशेष पहचान रखती है। आधुनिकता और पश्चिमी प्रभाव के कारण आज यह सांस्कृतिक धरोहर धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही है। ऐसे समय में युवा पीढ़ी पर संस्कृति संरक्षण का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इनमें झिझिया नृत्य व सामा-चकेवा पर्व का विशेष स्थान है। ऐसे पर्व न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। बल्कि सामाजिक सौहार्द और सामूहिक आनंद का संदेश भी देते हैं। युवा पीढ़ी इन परंपराओं को केवल उत्सव तक सीमित न रखे। बल्कि इन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व भी निभाए।

प्रभात कुमार भारती, झंझारपुर, मधुबनी

प्रत्याशियों का चयन

हमारी लोकसभा एवं विधानसभाएं कैसी होंगी, यह इस बात पर निर्भर है कि राजनीतिक दलों ने कैसे प्रत्याशियों का चयन किया। विधायिका के सदस्यों के चुनाव का मतलब होता है, एक साथ प्रधान कार्यकारी व विधायी शक्तियों का चुनाव। इससे यह समझना आसान है कि विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव का हर किसी के जीवन में कितना महत्व है। उपयुक्त उम्मीदवारों को नहीं देख मतदाता नोटा का बटन दबाने को बाध्य होता है। यह लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। सवाल है कि अच्छे उम्मीदवार का मानक क्या है? वह विविध क्षेत्रों और अनुभवों व जन सरोकार वाला व्यक्ति हो सकता है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

आर्थिक वृद्धि का लांचपैड

'एक-दूसरे की जरूरत बने भारत- ब्रिटेन' शीर्षक आलेख में हर्ष वी. पंत ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत के लिए आर्थिक वृद्धि का लांचपैड कहा है। ब्रिटेन के साथ व्यापार तेज व सस्ता होने वाला है, इससे उत्पन्न अवसर बेजोड़ होंगे। इस वर्ष जुलाई में लंदन में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से दोनों देशों के बीच आयात आसान होगा। इससे कारोबार बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इंडो-पेसिफिक, पश्चिम एशिया और यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा की। वहीं, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन ने सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग प्रशिक्षक अब ब्रिटेन की रायल एयरफोर्स में ट्रेनर के रूप में काम करेंगे। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब ब्रिटेन की नौ यूनिवर्सिटी भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन भारत में इंटरनेशनल एजुकेशन पहुंचाएगा। दोनों प्रधानमंत्री विजन 2035 के तहत भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी तय करेंगे।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

अगर विश्व कप में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बल्ले से रन नहीं निकलते तो भारत के लिए खिताबी जीत का सफर मुश्किल होता जाएगा।

बोरिया मजूमदार@BoriaMajumdar

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए और नए जोड़े गए लोगों का विवरण मांगा है। यह ब्योरा तो आयोग को स्वयं सार्वजनिक कर देना चाहिए था।

आरके विज@ipsvijrk

जोहो का स्वदेशी एप अरट्टई गूगल प्लेस्टोर और एपल एप स्टोर पर शीर्ष पर पहुंच गया है। करीब एक करोड़ डाउनलोड। हालांकि भारत में वाट्सएप का विकल्प बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन यह शुरुआत बहुत बढ़िया है।

मिन्हाज मर्चेंट@MinhazMerchant

वैसे तो नेता सत्ता पाने के लिए बड़े-बड़े वादे करते हैं, पर तेजस्वी यादव ने सबको पीछे छोड़ दिया। नीतीश सरकार ने एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए तो उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी का नतीजा है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं।

हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

जनपथ

बंदर को दे उस्तरा ट्रंप बढ़ाएं रार,
भारत संग स्टार्मर बढ़ा रहे व्यापार।
बढ़ा रहे व्यापार स्वयं भारत में आकर,
ट्रंप कर रहे लंच साथ गुंडे बैठाकर!
पा मुनीर का साथ ट्रंप बन रहे सिकंदर,
दुनिया आगे जाय आप बस पालो बंदर!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 177

****

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मायावती ने गंवाया मौका

उत्तरप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की मुखिया बहन मायावती ने गुरुवार को खुद अपनी साख पर बड़ा बट्टा लगा लिया। मायावती कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तो लगातार निशाना लगाती ही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सपा और कांग्रेस की आलोचना के साथ भाजपा शासन की तारीफ की और योगी सरकार का आभार भी जता दिया। गौरतलब है कि मायावती के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वे भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करती हैं। अर्थात सीधे-सीधे न सही लेकिन चुनावों में वे इस तरह पांसे बिछाती हैं, जिससे भाजपा को फायदा हो, और सपा, कांग्रेस या अन्य भाजपा विरोधी दलों को नुकसान हो। जबकि जिस दलित पृष्ठभूमि से मायावती आती हैं और दलित राजनीति के बूते ही वे सत्ता तक भी पहुंची, उस दलित समुदाय की घोर उपेक्षा भाजपा के शासनकाल में हो रही है, इसके गवाह दलित उत्पीड़न के आंकड़े भी दे रहे हैं। जब भी दलित को प्रताड़ित करने की कोई बड़ी घटना होती है, तो बहनजी से स्वाभाविक तौर पर उम्मीद की जाती है कि वे कोई बयान देंगी। लेकिन मोदी शासनकाल में मायावती ने मानो सरकार के खिलाफ बोलना छोड़ ही दिया है। उनके इस रवैये के कारण बसपा की प्रासंगिकता भी कम होती गई, चुनावी नतीजे इसका प्रमाण हैं। लेकिन अब भाजपा की तारीफ कर बहनजी ने जो थोड़ी बहुत उम्मीद दलितों को उनसे थी, वो भी खत्म कर दी है।

पाठक जानते हैं कि पिछले 13 सालों से मायावती सत्ता से बाहर हैं, लेकिन उत्तरप्रदेश में दलितों का यकीन उन पर अब भी बना हुआ है, ऐसा तब लगा जब गुरुवार को लखनऊ में हुई महारैली में बड़ी भीड़ जुटी। कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर मायावती ने ये महारैली की थी, जिसका असली मकसद 2027 के चुनावों की तैयारी थी और इसके अलावा अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से सार्वजनिक तौर पर उत्तराधिकारी बताना था। हालांकि बड़ी संख्या में दलित जुटे, तो इसकी वजह यही थी कि वे फिर से उस आत्मसम्मान को वापस पाने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसे भाजपा सरकार में लगातार कुचला जा रहा है। चुनावों के वक्त भाजपा के नेता, मंत्री दलितों के घर खाना खाते हुए तस्वीरें तो बहुत खिंचाते हैं, लेकिन जिन चमकते बर्तनों में वे भोजन करते हैं और जितने तरह के व्यंजन परोसे हुए होते हैं, उसे देखकर समझ आता है कि ये सारा तामझाम कुछ घंटों के वीडियो और तस्वीरें बनाने का है। जिसमें सब कुछ नाटकीय है, असलियत नहीं है। अगर दलितों को सवर्ण तबका अपने बराबर की सामाजिक स्वीकार्यता देता तो फिर इस तरह किसी को किसी के घर भोजन करने न जाना पड़ता।

भाजपा सरकार में दलितों का अपमान, बाबा अंबेडकर से नफरत और संविधान को खत्म करने की जो कोशिशें लगातार चल रही हैं, उन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मायावती ने गुरुवार को योगी सरकार की तारीफ की तो वहीं सपा पर जमकर हमला बोला। जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि क्योंकि 'उनकी' अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी।

बता दें कि मायावती ने रैली की शुरुआत में कहा कि अभी मैंने सुना कि अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर कांशीराम का स्मारक बनाने की बात कही लेकिन जब सत्ता में थे तो कभी ऐसा नहीं किया। ये लोग जब सत्ता में नहीं होते हैं तो इन्हें बसपा के नेता और दलित समाज के संतों की याद आती है जब सत्ता में आते हैं तो कुछ नहीं याद रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बसपा की सरकार रहते हुए मैंने जिन स्मारकों का नाम कांशीराम जी के नाम पर रखा उन्हें सपा की सरकार आने पर बदल दिया गया। मायावती ने कहा कि बसपा सरकार में कांशीराम के सम्मान में स्मारक स्थल बनाया गया था। उन्होंने योगी सरकार का भी आभार जताया और कहा कि स्मारक के देखने आने वालों की टिकट से आया पैसा इस सरकार ने सपा की सरकार की तरह टिकट का पैसा दबाकर नहीं रखा। भाजपा सरकार ने ऐसा नहीं किया बल्कि स्मारक के रखरखाव के लिए खर्च किया।

हालांकि मायावती को इस पर विचार करना चाहिए कि दलित स्मारक से ज्यादा उन मूल्यों के लिए कांशीरामजी का सम्मान करते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने दलित समाज में चेतना भरी और उन्हें हक के लिए खड़े होना सिखाया। अगर मायावती योगी सरकार का आभार जताने के साथ यह सवाल भी करतीं कि रायबरेली में दलित को क्यों पीट-पीट कर मारा गया, क्यों दलित वर्ग से आने वाले मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, उप्र में देश भर में सबसे अधिक दलित उत्पीड़न के मामले क्यों हो रहे हैं, तब तो समझ आता कि बहनजी वाकई दलितों की रहनुमा हैं। लेकिन इस समय वे भाजपा की सहयोगी की तरह बर्ताव कर रही हैं। जैसे नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर उन ताकतों से हाथ मिलाते हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाया है।

उप्र में भी आई लव मुहम्मद के बवाल पर मायावती खुलकर भाजपा की आलोचना नहीं कर सकीं, उन्होंने केवल यही कहा कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय, कुछ शरारती और स्वार्थी तत्व धर्म, देवी-देवता और खुदा के नाम पर विवाद और हिंसा पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इन मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को भारतीय संविधान और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस वाले संविधान हाथ में रखकर नाटकबाजी करते हैं जबकि इमरजेंसी के दौरान ही संविधान पर हमला हुआ था। यह बिल्कुल भाजपा की भाषा है।

बहरहाल, मायावती ने दावा किया कि 2027 में उप्र में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने पार्टी नेता आकाश आनंद की तारीफ करते हुए कहा कि आकाश बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए मेरे दिशानिर्देशन में लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबकि इन्हीं आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी में किनारे किया था।

कुल मिलाकर मायावती ने अपनी साख को फिर से हासिल करने का एक मौका गंवा दिया। किसी अन्य दल की तारीफ या निंदा उनका अपना नजरिया है, लेकिन उनका मतदाता भी फिर सोचेगा कि अगर घूम फिर कर भाजपा की विचारधारा में ही रहना है तो फिर सीधे भाजपा को ही वोट दें, मायावती को क्यों दें। अगर इसके खिलाफ जाना है तो फिर इंडिया गठबंधन का विकल्प भी मतदाता के पास है।

बागराम एयरबेस पर नई कूटनीति: भारत-तालिबान की नज़दीकी से बदलेगा क्षेत्रीय समीकरण

■ भाषा सिंह

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना अपने आप में बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ा घटनाक्रम है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अफगानिस्तान के बागराम एयरबेस को कब्जे में लेने का भारत द्वारा विरोध करना। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर ख़ान मुत्ताक़ी का भारत आना, अपने आप में बड़ी खलबली पैदा करने वाली खबर है। भारत ने इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन व रूस के अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन का समर्थन किया, जिसमें बिना बागराम एयरबेस का नाम लिये हुए अमेरिकी मंशा का विरोध किया गया है। इस तरह से अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का यह दूसरा बड़ा कदम है, जो सीधे-सीधे अमेरिकी हित से टकराता है। इससे पहले चीन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भी भारत ने इजराइल के खिलाफ जारी बयान में हस्ताक्षर किये थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर में चीन जाना और शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खासी नाराजगी जताई थी। हालांकि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान के शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है लेकिन मानवतावादी व विकास संबंधी कार्यों में भारत अफगानिस्तान को सहयोग कर रहा है। इस लिहाज से भी तालिबान के विदेश मंत्री का पहली बार भारत आना एशिया के देशों में नये किस्म के संवाद व साझेदारी की शुरूआत का संकेत हो सकता है।

रूस की राजधानी मॉस्को में हुई मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान की सातवीं बैठक में भारत, अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल ने भी शिरकत की। यहां जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, वह विश्व कूटनीति में अमेरिका को सीधे चुनौती देने वाला नजर आता है। इसमें कहा गया कि, 'अफगानिस्तान व पड़ोसी देशों में अन्य देशों द्वारा अपने सैन्य ढांचे (मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर) तैनात करने की कोशिशें स्वीकार नहीं हैं क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के हित में नहीं हैं।'

यह वक्तव्य 7 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। मजेदार बात है कि इसमें सीधे-सीधे बागराम पर अमेरिकी कब्जे की चाह का जिक्र नहीं है, लेकिन निशाना बिल्कुल साफ है। इसमें यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान को स्वंतत्र, एकीकृत व शांतिपूर्ण देश के तौर पर स्थापित करने के लिए भी काम करेंगे। इसके अलावा एक और बात जो सीधे अमेरिकी वर्चस्व को सीधे चुनौती देने वाली इसमें शामिल है, वह है कि ये तमाम देश अफगानिस्तान की जमीन को पड़ोसी देशों और आसपास के इलाके की सुरक्षा के लिए किसी भी किस्म का खतरा पेश करने के किसी भी प्रयास के लिए उपयोग नहीं होने देंगे। यानी बिना कहे यह कह दिया कि बागराम एयरबेस को अमेरिका के पास वापस जाने के खिलाफ दुनिया के ये देश एकमत है। इसमें भारत का चीन-रूस-पाकिस्तान के संग खड़ा होना क्षेत्रीय गठबंधन की ओर इशारा करने वाला है।

> **कितनी तेजी से दुनिया के इस हिस्से में कूटनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इसका आभास मॉस्को में हुई इस बैठक में साफ-साफ दिख रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ख़ान मुत्ताक़ी के नेतृत्व में पहली बार अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने इस तरह की किसी भी बैठक में भागीदारी की। रूस के अफगानिस्तान में अपने हित है।**

कितनी तेजी से दुनिया के इस हिस्से में कूटनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इसका आभास मॉस्को में हुई इस बैठक में साफ-साफ दिख रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ख़ान मुत्ताक़ी के नेतृत्व में पहली बार अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने इस तरह की किसी भी बैठक में भागीदारी की। रूस के अफगानिस्तान में अपने हित है। सोवियत संघ के विघटन से पहले यानी 1991 से पहले अफगानिस्तान में उसकी सीधी प्रभावशाली भूमिका था और पूरे इलाके में उसका दबदबा था। फिर 2001 में अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला बोला, उसे तबाह किया। बीस साल तक चले इस संघर्ष के बाद 2021 में अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं रहा। वापस शासन तालिबान को सौंप कर अमेरिकी सत्ता ने हाथ झाड़ दिये। फिर अचानक 18 सितंबर 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार उन्हें बागराम एयरबेस वापस कर दे।

कितनी बड़ी विडंबना है कि पांच साल पहले ट्रंप ने ही तालिबान से समझौता करके अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी करवाई थी। ट्रंप की इस मांग ने दुनिया भर में खासतौर से अफगानिस्तान में बैचेनी पैदा कर दी। जिस अंदाज में ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार बागराम एयरबेस को वापस लेने की कोशिश कर रही है, हमने उन्हें यूं ही दे दिया और अब हम उसे वापस चाहते हैं। इसके बाद से ही यह साफ हो गया कि अमेरिकी अफगानिस्तान में इस एयरबेस को हासिल करके इस इलाके में दोबारा अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। दरअसल बागराम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस देश का सबसे बड़ा एयरबेस हैं, जहां पर बड़े मिलिट्री प्लेन व हथियार डिलिवरी करने वाले हवाई जहाज उतारे जा सकते हैं। इसमें दो बड़े रनवे हैं, जो 3.6 किलोमीटर व 3 किलोमीटर लंबे हैं।

ट्रंप के इस प्रस्ताव को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सिरे से नकार दिया था। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था, 'अफगान किसी भी सूरत में अपनी जमीन को किसी को नहीं सौंपेंगे।' शायद जिस समय अफगानिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया था, उस समय यह अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इस तरह से भारत सहित तमाम देश अफगानिस्तान के पक्ष में उतरेंगे और ट्रंप की इस मनमानी का विरोध करेंगे।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं।)

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

स्वस्थ तन में होता हैं स्वस्थ मन का निवास

■ डॉ अशोक कुमार वर्मा

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 जुलाई 2025 को सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 लाइव लॉ (एससी) 740 में एक निर्णय में मानसिक स्वास्थ्य को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित किया है अर्थात मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पाना एक संवैधानिक अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करे।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है, जो मौलिक अधिकार के रूप में सभी नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है। इस अधिकार के दायरे में स्वास्थ्य, चिकित्सा, आश्रय और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है, और यह जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने की क्षमता की रक्षा करता है।

> **भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करता है, जो मौलिक अधिकार के रूप में सभी नागरिकों और विदेशियों को समान रूप से उपलब्ध है। इस अधिकार के दायरे में स्वास्थ्य, चिकित्सा, आश्रय और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल है।**

यद्यपि भारत में 7 अप्रैल 2017 को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पारित किया गया था जो 29 मई 2018 को अस्तित्व में आया। इस अधिनियम ने आत्महत्या के प्रयास को प्रभावी रूप से अपराधमुक्त कर दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या एक दंडनीय अपराध था। इस अधिनियम में मानसिक बीमारी दौरान ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पूर्ति करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान हैं। इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के पश्चात पूर्व में लागू मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 को निरस्त कर दिया गया है जो 22 मई 1987 को पारित किया गया था।

आज भौतिकतावाद के युग में मानसिक समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं एक सीमा तक ही वह सफल हो पाता है और जहां उसे सफलता नहीं मिलती वहां से अवसाद आरम्भ होता है। अवसाद एक मनोदशा विकार है जिसमें निरंतर उदासी, निराशा, और किसी भी चीज़ में रुचि की कमी महसूस होती है, जिससे व्यक्ति की सामान्य दैनिक गतिविधियों को करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति हफ्ते या महीने भर तक रह सकती है और शारीरिक व भावनात्मक दोनों तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है। अवसाद के कारण व्यक्ति कुसंग का शिकार हो सकता है। आज के समय में व्यक्ति एकाकी होकर रह गया है। आज किसी के पास समय नहीं है। मोबाइल की लत ने इसे और अधिक भयंकर रूप दे दिया है। नशे की और आकर्षण भी इस अवसाद का ही कारण है। वास्तव में ये सब मानसिक रोग की श्रेणी में आते हैं।

अवसाद के एक उदाहरण में कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्रा कृति का स्वलिखित सुसाइड नोट भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय को इंगित करता है जिसमें वह कह रही है कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा न मरे तो जितनी जल्दी हो सके इन कोचिंग संस्थानों को बंद करवा दें। ये कोचिंग छात्रों को खोखला कर देते हैं। पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। कृति ने लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाईड करने से रोकने में सफल हुई लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। अपनी मां के लिए उसने लिखा कि-आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रहीं लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं।

दूसरी और लोगों के पास बहुत धन और सुख-सुविधाएं होने पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। यहां पर संत कबीरदास की पंक्तियां वर्णनीय है जिसमें उन्होंने लिखा है-

गौ धन, गज धन, बाजि धन और रत्न धन खान।
जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान।

संत कबीरदास जी इस दोहे के द्वारा यह सन्देश दे रहे हैं कि सच्चा धन भौतिक संपदा नहीं हैं बल्कि मानसिक तृप्ति और संतोष है। वे कहते हैं कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड में वर्णन मिलता हैं जब हनुमान जी मां सीता की खोज में समुद्र पार कर रहे थे तब सुरसा ने हनुमान जी का मार्ग रोक दिया और हनुमान जी को खाने के लिए आतुर हुई। हनुमान जी ने अपने शरीर का आकार बड़ा कर लिया। सुरसा ने अपने मुख का आकार और बढ़ा दिया। अंत में हनुमान जी ने अपना लघु रूप बना लिया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और बाहर निकल आए। इसी प्रकार माया रूपी संसार में तृष्णा का रूप सुरसा के समान हैं। मनुष्य अपनी तृष्णा को लघु करके इस माया रूपी भव सागर से पार जा सकता हैं अर्थात तृष्णा से मुक्ति के बिना संतोष नहीं मिल सकता। जो संतोष धारण कर लेता है, वही वास्तव में सुखी और धनवान है।

यहां पर स्वास्थ्य ही धन है का वर्णन करना भी अत्यावश्यक हैं। यदि मनुष्य स्वस्थ होगा तो उसे संसार के सभी भौतिक सुख उसे अच्छे लगेंगे लेकिन यदि व्यक्ति अस्वस्थ होगा तो उसको प्रिय पकवान भी नहीं भाएंगे अर्थात अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरी और यही बात मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू होती हैं क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सभी धर्म इसीलिए मनुष्य को स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि मनुष्य का मानसिक विकास हो और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि हो।

अंत में किसी पंजाबी कवि ने लिखा है-
बन्दे दी आसां कदे हुन्दियां न पूरियां।
तड़पदा बहुतेरा फिर भी रहन्दियां अधूरियां।

इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तैयार हो जाती है यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती हैं।

ललित सुरजन की कलम से

राजनीति में वंचित समाज के लिए जगह कहाँ?

'यदि तर्क के लिए मान लिया जाए कि आदिवासी अथवा वंचित समाज के नेताओं में काबिलियत का अभाव है तो सवाल उठता है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए उनकी पार्टी ने क्या किया। क्या यह दोष उन लोगों का नहीं है जिसके हाथ में देश की राजनीति की बागडोर है? यहां हम जमुनादेवी और रेशमलाल जांगड़े के उदाहरण ले सकते हैं। एक आदिवासी महिला और एक दलित- इन दोनों ने 1952 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। जमुना देवी का पिछले साल ही निधन हुआ और उन्हें म.प्र. विधानसभा में विपक्ष के नेता से बड़ा कोई पद नहीं मिल पाया, जबकि श्री जांगडे को लोकसभा के साठ साल होने पर सम्मानित होने का अवसर तो मिला लेकिन वे भी राजनीति में पूरी जिन्दगी बिताने के बाद कोई खास पहचान नहीं बना पाए। कारण साफ है। इन्हें जानबूझकर आगे बढने से रोका गया। इस आरोप के समर्थन में सबसे बडा प्रमाण बाबू जगजीवन राम के रूप में हमारे सामने है। वे तो हर दृष्टि से एक योग्य और कुशल राजनेता और प्रशासक थे। आज जिस तरह प्रणब मुखर्जी की खूबियां को गिना-गिना कर उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सर्वथा उपयुक्त प्रत्याशी माना जा रहा है, तो जगजीवन राम उनसे भी कहीं यादा योग्य थे, लेकिन न कांग्रेस और न जनता दल (जिसमें तब का जनसंघ और आज की भाजपा शामिल थी) ने उन्हें न तो राष्ट्रपति बनाने की सोची, न प्रधानमंत्री पद पर उनकी उम्मीदवारी स्वीकार की।'

(देशबन्धु में 05 जुलाई 2012 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2012/07/blog-post.html

पावन प्रसंग

करवा चौथ: प्रेम और विश्वास का प्रतीक

हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी को जब शाम का सूरज डूबता है, तो भारत के कोने-कोने में सजी-संवरी महिलाएं थाली में दीप, छलनी और करवा सजाकर चांद के दर्शन करती हैं। उनके माथे पर लाल बिंदी, हाथों में मेंहदी, आंखों में इंतज़ार और होठों पर एक ही सवाल—'चांद निकला क्या?' करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। परंपरा के अनुसार यह व्रत सुहाग की स्थिरता और पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, और दिनभर की तपस्या के बाद जब चांद निकलता है तो पत्नी छलनी से पति का चेहरा देख कर व्रत तोड़ती है।

भारतीय समाज में स्त्री के जीवन को सुहाग से जोड़ा गया है—उसकी खुशी, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी पहचान तक। विवाह के बाद उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका पति माना गया, और उसकी मृत्यु को अभिशाप समझा गया। ऐसे में करवा चौथ जैसे व्रत स्त्री के समर्पण, त्याग और सहनशीलता का उत्सव बन गए।

आज की पढ़ी-लिखी स्त्री जब करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसके कारण परंपरागत नहीं भी हो सकते। कई महिलाओं के लिए यह पति के प्रति प्रेम का, साथ निभाने का, रिश्ते में सामंजस्य का प्रतीक बन चुका है। वहीं कई पुरुष भी अब पत्नी के साथ समान भाव से व्रत रखने लगे हैं—यह बदलाव सकारात्मक है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि करवा चौथ आज एक कल्चरल इवेंट बन गया है—टीवी धारावाहिकों, फिल्मों और सोशल मीडिया पर यह व्रत जितना ग्लैमरस दिखाया जाता है, उतनी ही गहराई में उसका मूल अर्थ खोता जा रहा है।

कभी यह व्रत गांव की औरतों के बीच अपनापन और सहयोग का प्रतीक था। महिलाएं एक-दूसरे के घर जातीं, मिट्टी के करवे (घड़े) में जल भरतीं, गीत गातीं—करवा चौथ का व्रत है भाई, करवा लाना भूली न जाई...। यह त्यौहार उनके लिए आपसी मिलन का अवसर था, जहां वे जीवन की तकलीफ़ों को साझा करतीं।

फिर भी, परंपराओं को केवल अंधविश्वास कहकर नकार देना भी उचित नहीं। हर संस्कृति की अपनी आत्मा होती है। करवा चौथ के पीछे जो भाव है—प्रेम, समर्पण और आस्था का—उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम परंपरा को आधुनिक दृष्टि से देखें। आज जब हम समानता, स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान की बात करते हैं, तो यह व्रत भी एकतरफा नहीं रहना चाहिए। यदि पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो पति भी पत्नी की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए समान भाव से प्रार्थना करे—यही सच्चा प्रेम और समानता है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

आपके पत्र

टिकिट वितरण सारे कयास फेल कर सकता है, रहें सावधान!

बिहार में चुनाव की घोषणा के साथ ही अब इंडिया गठबंधन और एनडीए में टिकिट वितरण परीक्षा का दौर सही तरीके से सम्पन्न होता नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह दमदार लोग अपने उम्मीदवारों के लिए भीड़ लगाए हुए हैं यह दृश्य देखकर लगता है कि दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है। जबकि पहले टिकिट मांगने वालों की संख्या ही यह संकेत कर देती थी कि किस पार्टी की जीत तय है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की सभाओं को देखकर और मोदी सरकार के विरुद्ध देश भर में खड़े हुए जनांदोलन यह बता रहे हैं कि यदि टिकिट वितरण में घमासान नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की त्रयी का जीतना आसान होगा। इसके लिए एक तय आधार होना चाहिए उस कसौटी पर जो सही उतरे उसे टिकिट मिले और विरोध की कोई गुंजाइश न रहे। सीपीआईएमएल ने पांच वर्ष की गई सेवाओं को आधार बनाया है।

यह सबसे महत्वपूर्ण वक्त होता है उचित प्रत्याशी के चयन का। गठबंधन के सभी पार्टी सदस्यों को यदि इस गहरे संकट के समय देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बचाए रखना है तो इस वक्त यदि कुछ ग़लत भी हो जाए तो उसे सहजता से लेना होगा। क्योंकि दूसरा पक्ष रुष्ट व्यक्तियों को भाजपा में शामिल करने तैयार बैठा है और हम सब भली-भांति जानते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कभी भी ऐसे व्यक्ति का खुलकर विरोध नहीं किया बल्कि विजयी ही बनाया है। इस अनुशासन का सबक अन्य दलों को सीखना होगा। यदि टिकिट वितरण में सहिष्णुता का परिचय दिया जाता है तो आधी जीत पक्की मान लेनी चाहिए। क्योंकि ये लोगों के खरीद फ़रोख्त का दौर है और किसी भी व्यक्ति का विश्वास करना आसान नहीं रहा। इसीलिए विश्वास बनाने का प्रयास कीजिए। यदि यहां सफल होते हैं तो दिल्ली दूर नहीं होगी तथा भाजपा सिमटती चली जाएगी।

जहां तक एनडीए की एकजुटता का सवाल है उनमें कितने भी अन्तर्विरोध हों वे साम-दाम- दंड-भेद समायोजन कर ही लेते हैं। सत्ता उनके पास है। जनता के करोड़ों रुपए थमाकर उनके विरोध को वे थाम लेते हैं। उदाहरणस्वरूप तेलगु देशम और जदयू के नेताओं को हमने देखा ही है फिर वे चिराग पासवान हों या प्रशांत किशोर सब सरेंडर करने वाले लोग हैं। इसलिए इस सत्ता की ताकत और जनता के पैसों पर इतराने वाले लोगों की सच्चाई से जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। प्रशांत किशोर विश्वास के योग्य नहीं है उन्हें बीजेपी की बी टीम मानकर चलिए। उनके द्वारा किए जा रहे सरकार के भ्रष्टाचार भ्रमित कर जनता के वोट हथियाने की साज़िश के तहत है।

आज इस चुनाव में चुनाव आयोग ने शातिराना ढंग से एक विशेष कौम और महिलाओं के नाम मतदाता सूची से काटकर जो नागरिकों के मत देने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है उसका जवाब देना ही बिहार के लोगों का पुनीत कर्तव्य बन जाता है। बिहार राज्य में अब तक यह भाईचारा सुरक्षित है उसे बचाने आपको तैयार रहना होगा। राहुल गांधी ने वर्तमान सरकार को वोट चोर होने की जो प्रामाणिक पुष्टि की है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है।

इसलिए यदि परस्पर इंडिया गठबंधन के लोग लड़ते हैं एवं सौहार्द्र का परिचय नहीं देंगे तो जीत हार में परिणत हो सकती है। सावधान रहें अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। आगे भी कठिन लड़ाई है।

- सुसंस्कृति परिहार

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

अफगान विदेश मंत्री के भारत आने के मायने

एक ही दिन में दो खबरें आईं, दोनों का मजबून अलग-अलग है, लेकिन मूल एक ही है। पहली खबर है कि अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखकर आगाह किया है कि भारत से तुरंत संबंधों को सुधारें नहीं तो वो रूस और चीन के नजदीक चला जाएगा। दूसरी खबर है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर पहुंचे। हालांकि भारत ने अभी तक अफगान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में लगातार सुधार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह अफगान की तालिबान सरकार भारत के समर्थन में खड़ी हुई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने भी क्रिकेट से लेकर निर्माण तक में अफगान की मदद की। भारत, पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब अफगानिस्तान के करीब आने से साउथ एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत दौरे से पहले अफगानी मंत्री रूस की राजधानी मॉस्को भी पहुंचे। यहां वे 'मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन' की बैठक में शामिल हुए, जिसमें भारत उनके सपोर्ट में दिखा। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस प्लान का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने और तालिबान की सरकार बनने के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था। तब से दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता भी नहीं दी है। हालांकि भारत लंबे वक्त से अफगानिस्तान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करता रहा है। अब तालिबान सरकार के करीब 5 साल के शासन के बाद विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि उनकी विदेश मंत्री एस.जयशंकर से भी मुलाकात होगी, जिसमें दोनों के देशों के संबंधों के अलावा अफगान को मान्यता देने पर भी बात होगी। इससे साफ संदेश जाता है कि भारत अब तालिबान सरकार को गंभीरता से ले रहा है और उसे अफगानिस्तान के प्रतिनिधि संस्था के तौर पर स्वीकार कर रहा है। भारत को ये अंदाजा हो गया है कि तालिबान अफगानिस्तान में लंबे वक्त तक रह सकता है इसलिए उनके साथ बातचीत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान में आंतरिक संघर्ष खत्म हो चुका है और तालिबान की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया है। अब ऐसा तालिबान सत्ता में आया है, जो करीब-करीब सारे गुटों को साथ लेकर चल रहा है। इससे पहले हामिद करजई की सरकार थी। उसके बारे में यही कहा जाता था कि वो काबुल के चेयरमैन हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो पूरी तरह से विदेशी सहायता पर निर्भर थे। इसी के चलते पाकिस्तान को अफगान में दखल का मौका मिल रहा था। अब तालिबान सरकार पूरी तरह से एकजुट दिख रही है। इसके चलते पाक को अफगान से सीधा मुकाबला भी मिल रहा है। अब जबकि अफगानी विदेश मंत्री भारत दौरे पर है तो पाकिस्तान की नींद खराब होना तय है। वहीं, अफगान के जिस बगराम एयरबेस को वापस लेने का भारत ने विरोध किया है, उस पर चीन और पाकिस्तान ने भी भारत का समर्थन करके अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत से संबंधों में सुधार नहीं किया गया तो साउथ एशिया में उसके लिए हालात विकट हो सकते हैं। भारत के मुकाबले कमजोर पाकिस्तान पर भरोसा करना उसे महंगा पड़ सकता है। चीन पहले से ही अमेरिका को आंखें दिखा रहा है।

बढ़ती दुश्वारियां बनी किसानों की नियति

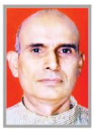

प्राकृतिक आपदा
अखिलेश आर्येन्दु

> इस साल बरसात से जान-माल, बादल फटने और बाढ़ से जो नुकसान हुआ, इसका अभी सरकारी अनुमान लगाया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनियाभर के किसानों के ऊपर हर साल आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक असर पड़ रहा है। इससे वह कई बीमारियों के चपेट में आ जाता है। यह चपत किसान को बर्बादी के कगार पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों पर पड़ रही यह भयंकर मार वैश्विक स्तर पर कृषि-क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के करीब पांच फीसदी है। गौरतलब है प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पिछले तीस वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं जो चिंता पैदा करने वाली हैं।

इस साल पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उतराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, दिल्ली सहित दक्षिण के तमाम राज्यों में औसत से ज्यादा बरसात हुई है। इसकी वजह से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गये और हजारों हेक्टेयर खरीफ की फसल बर्बाद हो गई। लाखों-करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की घटनाओं से जान-माल का नुकसान तो हुआ ही, लाखों हेक्टेयर खेत में खड़ी फसल व फल बर्बाद हो गए। केंद्र ने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित अतिवृष्टि व बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत कार्यों और लोगों के क्षतिग्रस्त मकान–दुकानों के लिए जरूरी राहत धनराशि मुहैया कराई है, जिससे उनको फिर से बगैर जोखिम उठाए बरसात से हुए नुकसान से उबारा जा सके। फिर भी, किसानों को इससे थोड़ी ही राहत हुई है। जितना नुकसान हुआ और परिवार को जो पीड़ाएं और परेशानियां हुई, उनको समझने वाला कोई नहीं है। इसे किसानों की नियति कहेंगे या कुछ और। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी सामने मुंह बाए खड़ी दिखती है।

पिछले साल वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (डब्ल्यू.डब्ल्यू.ए) और क्लाईमेट सेंट्रल की संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसके मुताबिक मानव-जनित जलवायु परिवर्तन की वजह से उच्च तापमान के कारण 2024 में बाढ़ तूफान, सूखा, जंगल की आग और गर्मी की लहरों का आगाज लगातार बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 24 मौसम घटनाओं में 3,700 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। इस रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है। इस साल बरसात से जान-माल, बादल फटने और बाढ़ से जो नुकसान हुआ, इसका अभी सरकारी अनुमान लगाया जा रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के कारण दुनियाभर के किसानों के ऊपर हर साल आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक असर पड़ रहा है। इससे वह कई बीमारियों के चपेट में आ जाता है। यह चपत किसान को बर्बादी के कगार पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों पर पड़ रही यह भयंकर मार वैश्विक स्तर पर कृषि-क्षेत्र के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के करीब पांच फीसदी है। गौरतलब है प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं पिछले तीस वर्षों में तेजी से बढ़ी हैं जो चिंता पैदा करने वाली हैं। ऋतु-चक्र में आया यह बदलाव कई तरह की दुश्वारियां, संकट, परेशनियां और बीमारियां पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारणों से दुनिया में तमाम तरह की दुश्वारियां, बीमारियां, संकट और ऋतु-चक्र में अनुमान से ज्यादा बदलाव देखे जा रहे हैं। जो प्राकृतिक कारण जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं उनमें वायु प्रदूषण, सूर्य में परिवर्तन, ज्वालामुखियों में उत्सर्जन और लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते जाना, जीवाश्म ईंधन का अधिक मात्रा में जलना, वनों की कटाई, पहाड़ों का लगातार क्षरण, औद्योगिक-क्षेत्र से लगातार बढ़ता जहरीला कचरा, खेती प्राणालियों से ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ते जाना और वाहनों की बढ़ती तादाद प्रमुख है। इतनी सारी वजहों के अलावा लगातार युद्धों से जहरीली गैसों का उत्सर्जन, परमाणु कचरा, प्लास्टिक व माइक्रोप्लास्टिक भी ऋतु-चक्र और मौसम का लगातार बेईमान होने की वजह बन रहा है। वैज्ञानिकों

का मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या लगातार बढ़ रही है।

सवाल यह है जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए जान-माल और खेती-बागवानी के नुकसान का रहनुमा कौन है? और सवाल यह भी है जिस किसान के ऊपर अन्न, सब्जी, फल, दूध, ऊन पैदा करने की जिम्मेदारी है उस किसान की हालात कब तक ऐसी बनी रहेगी? क्या सरकारी राहत से किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई हो पाती है? भारत में तो नहीं होती। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर किसानों पर हुआ है। कृषि-क्षेत्र में किसानों की रुचि वैश्विक स्तर पर लगातार कम हो रही है। एफएओ के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 23 वर्षों में कृषि में श्रम बल 40 से घटकर 26 फीसदी पहुंच गया। आंकड़े के अनुसार जहां साल 2000 में करीब 102.7 करोड़ लोग यानी वैश्विक श्रम बल का करीब 40 फीसदी हिस्सा कृषि से जुड़ा था, वह 2021 में घटकर महज 26 फीसदी ही रह गया। यानी अब केवल 87.3 करोड़ से कम लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। भारत में जिस तेजी से लोगों में खेती-बागवानी और पशुपालन में रुचि और रोजगार की निर्भरता लगातार कम हो रही है, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बहुत चिंता की बात है।

खाद्य एवं कृषि संगठन की नई स्टैटिस्टिकल ईयर बुक : वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 के अनुसार 1991 से 2021 के दौरान किसानों को बाढ़, तूफान, ओला, अकाल और बादल फटने की घटनाओं से फसलों के नुकसान और पशुधन की मौत से करीब 321,6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है। इन आपदाओं का सबसे ज्यादा खामियाज़ा भारत सहित पूरे एशिया के किसानों को भुगतना पड़ा। यह बहुत बड़ी चपत है। 2021-25 के अगस्त माह तक तकरीबन 200 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। किसी और सेक्टर में इतनी बड़ी चपत आमतौर पर देखने में नहीं आती। यदि आती भी है तो, उन देशों की सरकारें उनके साथ हर हालत में खड़ी रहती हैं। इसलिए उन देशों में कृषि घाटे का कार्य नहीं है। इसलिए पलायन की समस्या वहां के गांवों में न के बराबर है। कृषि के अलावा दूसरे सेक्टरों में काम कर रहे व्यक्ति को घाटा लगने पर सरकार उसका पूरा भरपाई करती है, लेकिन भारत के किसानों को भरपाई के नाम पर लॉलीपाप थमाया जाता है। आजादी के सतहत्तर सालों में किसानी सबसे मजबूरी वाला क्षेत्र रहा है। किसान और खेतिहर मजदूरों की दशा सबसे अधिक दयनीय रही है।

यही वजह है सबसे अधिक घाटे वाला, पीड़ादायक और खून सुखा देने वाला रहा है। आत्महत्या सबसे ज्यादा किसान और उसके परिवारी-जन करते हैं। लागत, मेहनत, परेशानी, अनिश्चितता सबसे ज्यादा और इज्जत के नाम पर प्रताड़ना किसान की नियति का खेल नहीं तो क्या है? रिपोर्ट बताती है कि भारत सहित एशिया के किसानों को पिछले तीन दशकों के दौरान करीब 143.2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं पर अमेरिका और यूरोप अपने कृषि क्षेत्र के संबंध में आनुपातिक रूप से अधिक प्रभावित हुए हैं। भारत के लाखों किसान जहां तमाम आर्थिक समस्याओं में उलझे रहते हैं वहीं पर पारिवारिक समस्याओं से भी परेशान रहते हैं। खेती की तरफ किसानों की रुचि लगातार कम होने को लेकर सरकारों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि लोगों में कृषि की तरफ रुचि फिर से पैदा हो और बेरोजगारी की विकराल समस्या से लोगों को छुटकारा मिले। कृषि में छुपी लागत किसान के लिए सबसे चिंता का विषय है। इसलिए सरकार को विशेषज्ञों से सलाह ले ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इस बाबत किसानों को होने वाली परेशानियां कम से कम हो।

(लेखक पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे
विवेक शुक्ला

सबको ठीक करने वाले ही खुद हो रहे बीमार

क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमें बीमारियों से बचाते हैं, वो खुद कितने बीमार हो रहे हैं? जी हां, भारत के मेडिकल प्रोफेशनल्स, डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ वर्कर्स भी मेंटल हेल्थ का शिकार हो रहे हैं। ये लोग दिन-रात मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते। हाल के सालों में ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि कई डॉक्टर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और यहां तक कि सुसाइड तक के शिकार हो रहे हैं। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है; ये एक बड़ा मुद्दा है जो पूरे हेल्थ सिस्टम के लिए चुनौती बन गया है। ये समस्या क्यों हो रही है? डॉक्टरों की जिंदगी आसान थोड़े ही है। लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली से जुड़े रहे प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉ. सुनील मित्तल कहते हैं कि अस्पतालों में ड्यूटी के घंटे इतने लंबे होते हैं कि नींद पूरी नहीं हो पाती। कभी-कभी 36-48 घंटे की लगातार शिफ्ट! सोचिए, इतने समय तक काम करने से इंसान कितना थक जाता होगा। ऊपर से मरीजों की भीड़, इमरजेंसी केस, और वो सारा प्रेशर कि हर मरीज को बचाना है। एक स्टडी में पाया गया कि कोविड के दौरान 37% हेल्थ वर्कर्स को एंग्जाइटी हुई, 33% डिप्रेशन और 23% स्ट्रेस। ये आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि ये लोग हमारी जान बचाते हैं, लेकिन खुद की सेहत का क्या? और सिर्फ काम का प्रेशर ही नहीं, मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम भी बड़ा दोषी है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टरों को एग्जाम की इतना टेंशन रहती है कि नींद उड़ जाती है। मेडिकल कॉलेजों में हैरासमेंट भी कम नहीं। सीनियर-जूनियर का ईगो क्लैश, बुलिंग, और वो 'सुपीरियर-इनफीरियर' वाला ऐटिट्यूड। आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला कि पिछले 5 सालों में 191 मेडिकल स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, और 1166 ने कॉलेज छोड़ दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि कॉलेज 'हब ऑफ हैरासमेंट' बन चुके हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो हालत और भी बुरी लगती है। भारत में साइकिएट्रिक डिसॉर्डर्स की दर 9.5 से 370 प्रति 1000 लोग है, लेकिन डॉक्टरों में ये ज्यादा है। एक सर्वे में पाया गया कि 34.9% डॉक्टर अनलाद के शिकार हैं, 39.5% को एंग्जाइटी और 32.9% को स्ट्रेस। इन सब का असर क्या होता है? सबसे पहले, डॉक्टरों की पर्सनल लाइफ बर्बाद। फैमिली टाइम नहीं, लव लाइफ नहीं, यहां तक कि पैरेंट्स की उम्र बढ़ने का टेंशन। तो समाधान क्या? सबसे जरूरी है जागरूकता। डॉक्टरों के लिए अस्पतालों में काउंसलिंग सेंटर बनें। गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, ड्यूटी घंटे कम करें, जैसे यूरोप में 48 घंटे का मैक्सिमम। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय अग्रवाल कहते हैं कि ये याद रखा जाना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं। अगर वो खुश और सेहतमंद नहीं रहेंगे, तो हम कैसे रहेंगे? सरकार, अस्पताल और हम सबको मिलकर इस समस्या को हल करना होगा। छोटे-छोटे कदम जैसे दोस्तों से बात करना, योग करना, या हेल्पलाइन पर कॉल करना – ये सब मदद कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक विकारों से अधिक प्रभावित होते हैं। शहरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक है पर्यावरणीय प्रदूषण। वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण और विषाक्त पदार्थों का संपर्क मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे तनाव और अवसाद बढ़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक अलगाव। शहरों में लोग व्यस्त जीवनशैली के कारण परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं, जिससे अकेलापन बढ़ता है। अपराध दर, असमानता और हिंसा जैसे कारक भी चिंता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, तेज गति वाला जीवन, लंबे काम के घंटे, ट्रैफिक जाम और आर्थिक दबाव मानसिक थकान पैदा करते हैं। शहरों में हरे-भरे क्षेत्रों की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रकृति से संपर्क मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। गरीबी और बेरोजगारी जैसे सामाजिक कारक पूर्व-मौजूदा जोखिमों को बढ़ाते हैं, विशेष रूप से युवाओं में। शहरीकरण के साथ लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन बेहतर अवसरों की तलाश में होता है, लेकिन यहां का तनावपूर्ण वातावरण उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नियमित व्यायाम, ध्यान और योग जैसे अभ्यास तनाव कम करने में मददगार हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ाना, जैसे क्लब ज्वाइन करना या दोस्तों से मिलना, अकेलेपन को दूर करता है। शहरों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए, जैसे किफायती काउंसलिंग सेंटर और हेल्पलाइन। कुल मिलाकर, बात ये है कि मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसकी चपेट में डॉक्टर भी आ रहे हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

संकीर्णता अधर्म है विष है

संकलित
दर्शन

पानी छोटे से पोखर में भी पाया जाता है किन्तु वह प्रायः गन्दा और दुर्गन्ध पूर्ण होता है किन्तु सरोवर में पाया जाना वाला पानी स्वच्छ और अधिक उपयोगी होता है। पोखर छोटा और सरोवर विशाल होता है। मानव का मन भी प्रायः दो तरह का होता है। क्षुद्र और विशाल। क्षुद्र हृदय व्यक्ति बहुत सीमित दायरे में सोचता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः कट्टर होते है वे औरों के प्रति असहनशील और ईर्ष्या ग्रस्त होते हैं। सरोवर की तरह उदार हृदय व्यक्ति विशाल दृष्टि कोण लेकर चलते हैं सहिष्णुता उनकी मुख्य विशेषता होती है। वे अपना ही नहीं सभी का अभ्युदय चाहते हैं। संकीर्ण मनोवृत्ति से दूर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज और मानवता के लिए वरदान स्वरुप होते हैं। धर्म मूलत, विशाल हृदयी व्यक्ति तैयार करने का काम करता है। मित्ति में सव्व भूएसु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम्-जैसे धर्म के मौलिक सूत्र है जिन में संकीर्णता का कोई नामो निशान नहीं है किन्तु जब से धर्म में संप्रदायें प्रबल हुई है। धर्म के स्वरुप को भी संकीर्ण बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। संकुचित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति साम्प्रयादिकता के ज्यादा पक्ष घर बने रहे उन्होंने धर्म की सारी व्यवस्थाओं को कट्टरता और संकीर्णता के घेरे में बांध लिया। केवल हम और हमारा ये ही ठीक है शेष सभी व्यर्थ है। संकीर्णता की इस भावना ने धर्म की सार्वभौमिकता को तोड़ कर जन जन में भेद भाव की खाई खड़ी कर दी। अन्य धर्म संप्रदायों की बात छोड़िये।

ईर्ष्यालु व्यक्ति सुखी-संपन्न नहीं देख सकता

संकलित
प्रेरणा

एक महिला कुबड़ी थी जिसकी वजह से वह झुककर चलती थी। सभी लोग उसका उपहास उड़ाते थे। बच्चे तो जब-तब उसे 'कुबड़ी-कुबड़ी' कहकर परेशान करते रहते थे। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि सहसा रास्ते में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। नारद ने उस महिला पर तरस खाते हुए कहा, 'आओ बहन! मेरे पास आओ। मैं अपने योगबल से तुम्हारा कूबड़ ठीक कर दूंगा।' महिला बोली, 'भगवान! आप अंतर्यामी हैं। आप तो जानते ही है कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। मुझे सदैव यह कहकर चिढ़ाते रहते हैं कि, देखो वह कुबड़ी जा रही है। यदि आप मुझ पर मेहरबानी कर ही रहे हैं तो मेरे कूबड़ की फिक्र मत कीजिए। आप बस इतना कर दीजिए कि जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, उन सबके भी कूबड़ निकल आए।' नारद जी ने उस महिला का उत्तर सुना तो हक्के-बक्के रह गए। आश्चर्यचकित होकर बोले, 'बहन, दूसरों के कूबड़ निकल आने से तुम्हें क्या मिलेगा।' बुढ़िया बोली, 'मैं उन्हें भी अपनी तरह चलते और दूसरों द्वारा उपहास होते देखूंगी तो मन को शांति मिलेगी।' नारद जी सोचने लगे यह महिला चाहती तो मेरी कृपा से अपना कूबड़ ठीक करा सकती थी। लेकिन उसने हाथ आए अवसर को दूसरों के नुकसान के रूप में ही भुनाने की कामना की। ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रकृति यही होती है कि वह दूसरों को सुखी-संपन्न देखकर उनके जैसा उन्नत, संपन्न और सुखी होने की प्रेरणा ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुखी लोगों को दुखी करने और नीचे गिराने का प्रयास करता है। बुढ़िया का मनोरथ पूरा करने का उनका कोई इरादा नहीं था।

अंतर्मन

आज की पाती

दुखदायी है आत्महत्या की घटना

कभी-कभी किसी घटना की ख़बर केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वह पूरे समाज के भीतर छिपे हुए असंतुलन, दबाव और संवेदनहीनता का दर्पण बन जाती है। हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ऐसी ही एक घटना है, जो केवल पुलिस विभाग की त्रासदी नहीं, बल्कि उस मानसिक, प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे की विफलता का प्रतीक है जिसमें पद और प्रतिष्ठा के बावजूद इनसान अकेला और असहाय महसूस करने लगता है। पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ स्थित उनके घर के तहखाने में मिला, जहां बताया गया कि वह कमरा पूरी तरह ध्वनि-रोधक था। उनके पास से सरकारी पिस्तौल बरामद हुई। उनकी पत्नी अमनीत कौर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं, जो उस समय जापान में थीं। आत्महत्या की यह घटना दुखदायी है। *– पंकज सक्सेना, दुर्ग*

करंट अफेयर

गाजा में 55,000 बच्चों के कुपोषित होने की आशंका

इजराइल और हमास के बीच दो साल से जारी युद्ध और भोजन की भारी कमी के कारण गाजा में पांच साल से कम उम्र के संभवत : 54,600 से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इनमें से 12,800 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित है। संयुक्त राष्ट्र के एक नये अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। फलस्तीनी शरणार्थियों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्था 'यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट' के विश्लेषण के अनुसार, अगस्त की शुरुआत तक गाजा में छह महीने से लेकर पांच साल तक के लगभग 16 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के एक जानलेवा रूप से पीड़ित थे। इस जानलेवा कुपोषण को 'अत्यधिक दुर्बलता' (वेस्टिंग) कहा जाता है।

इनमें से लगभग चार प्रतिशत बच्चे 'गंभीर दुर्बलता' का शिकार हैं। दुर्बलता (वेस्टिंग) के इलाज के लिए कई हफ्तों तक विशेष पोषण वाले भोजन की जरूरत होती है और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है। लेखकों के अनुसार, बुधवार को 'द लैंसेट' पत्रिका में छपा यह अध्ययन इस इलाके में भुखमरी से पीड़ित बच्चों के संबंध में किया गया अब तक का सबसे व्यापक अध्ययन है। यह जनवरी 2024 से लेकर अगस्त के मध्य तक गाजा के दर्जनों स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा स्थलों पर लगभग 2,20,000 बच्चों की जांच पर आधारित था।

ऑफ बीट

बाथरूम की ये तीन चीजें बिल्कुल भी साझा न करें

कल्पना कीजिए कि आप घर से बाहर हैं, लेकिन अपना तौलिया, रेज़र या टूथब्रश पैक करना भूल गए हैं। क्या आपको दूसरों का यह सामान इस्तेमाल करना चाहिए? यहां बताया गया है कि इसकी आदत न डालना ही बेहतर है। सूक्ष्मजीव कुछ समय तक सक्रिय रह सकते हैं। बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे कि तौलिया, रेज़र और टूथब्रश पर लंबे समय तक जीवित रहने वाले रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, ये सूक्ष्मजीव कपड़े, प्लास्टिक और धातु की सतहों पर कई दिनों से लेकर महीनों या वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एस्परजिलस नामक फफूंद का बैक्टीरिया

कपड़े और प्लास्टिक पर एक महीने से अधिक समय तक जीवित रह सकता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया वर्षों तक सक्रिय रह सकते हैं। कई वायरस सिरेमिक, धातु, कपड़े और प्लास्टिक जैसी सतहों पर घंटों से लेकर महीनों तक संक्रमण फैलाने में सक्षम रहते हैं। तौलिया साझा करना जोखिमपूर्ण अध्ययन बताते हैं कि उपयोग किए गए तौलिये को साझा करने से त्वचा के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में हाईस्कूल फुटबॉल खिलाड़ियों के एक समूह में स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस (स्टैफ) के संक्रमण का प्रकोप सामने आया।

ट्रेंड

नतीजे उत्साहवर्धक

जब देशवासियों का जीवन अधिक से अधिक आसान बनाने की इच्छाशक्ति हो, तो नतीजे भी बहुत उत्साहवर्धक मिलते हैं। बीते 11 वर्षों में हमारी हवाई सेवा से जुड़ी इंडस्ट्री का विकास और विस्तार इसका बहुत बड़ा प्रमाण है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

क्वांट

पुरानी सरकारों ने पंजाब के घर-घर में नशा पहुँचाया, पंजाब की जवानी बर्बाद कर दी। अब भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। बड़े-बड़े तस्कर जेल में हैं। जो पंजाब में नशा बेचेगा, वो बख्शा नहीं जाएगा।

-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

जिले का नाम क्यों बदला

मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूं कि अगर मान्यवर कांशीराम साहब के प्रति इतना ही आदर सम्मान था तो आपने उनके नाम पर रखे जिले का नाम बदलकर कासगंज क्यों कर दिया?

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

गेस्ट हाउस कांड

यूपी ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में सपा शासन में गेस्ट हाउस कांड निहायत ही एक ऐसा काला धब्बा है जिसे सपा की लाल टोपी से ढका नहीं जा सकता और न ही उसे किसी प्रकार के मुशायरों से भुलाया जा सकता है।

-केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, उप्र

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

पायनियर
नई दिल्ली, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025

न्यायपालिका पर हमला

घटती सहिष्णुता

समाज में सहिष्णुता तेजी से कम होती जा रही है। असहमत लोग अपना गुस्सा जाहिर करने या उस व्यक्ति पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते जिससे वे सहमत नहीं हैं। हाल ही में सार्वजनिक जीवन एक जोखिम भरा काम बन गया है, जिसमें चेहरे पर स्याही फेंकने से लेकर थप्पड़ मारने और जूता फेंकने तक की घटनाएं हो रही हैं। शरारती तत्व आगे हैं और अगर उन्हें इसके लिए फटकार भी लगाई जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है; वे बेफि क्र हैं (जिससे उन्हें दृढ़ विश्वास मिलता है), कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसा करते हैं, तो कुछ अपने विश्वासों से बचने के लिए, लेकिन असर एक ही है - सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार की धज्जियाँ उड़ जाती हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पवित्रता पर एक जबरदस्त हमले में, एक वकील ने सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। इस कृत्य के बाद, हमलावर ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और ईश्वरीय इच्छा का दावा किया, जो दुखद और परेशान करने वाला है। वकील इस बात से परेशान थे कि मुख्य न्यायाधीश ने मॉरीशस में कुछ ऐसा कहा था जो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्हें लगा कि मुख्य न्यायाधीश ने उनकी 'सनातन' भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

यह एक ऐसा कृत्य है जिसकी सभी को निंदा करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से एक वर्ग ऐसा भी है जो उनके कार्यों का समर्थन कर रहा है। आपका धार्मिक या राजनीतिक रुझान चाहे जो भी हो, सभ्य समाज में इस तरह की असहमति जायज नहीं है। निंदा एक संवैधानिक अनिवार्यता है। न्यायालय तर्क का स्थान है, आक्रामकता का नहीं। न्यायाधीशों को व्यक्तिगत हमले के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी तरह, असहमति रखने वालों को भी निर्णयों और संस्थाओं पर सवाल उठाने का अधिकार है - लेकिन वैध और तार्किक अभिव्यक्ति के माध्यम से।

जूते फेंकना असहमति नहीं, बल्कि धमकी है। इसका उद्देश्य बहस करना नहीं, बल्कि अपमान और दबाव डालना है, न्यायपालिका की गरिमा और नैतिक अधिकार पर सीधा हमला। जब कोई व्यक्ति किसी न्यायाधीश पर हमला करता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत अपमान होता है, बल्कि व्यवस्था की जड़ पर एक प्रतीकात्मक प्रहार होता है। इस तरह की कार्रवाइयों को हानिरहित नाटक मानने से अदालतों के प्रति शत्रुता को सामान्य बनाने का जोखिम है और लोकतंत्र को बनाए रखने वाले संस्थागत सम्मान के नाजुक ताने-बाने को कमजोर करता है। हमलावर का यह औचित्य कि उसने सनातन धर्म की रक्षा में कार्रवाई की, एक और भी कपटी चुनौती को उजागर करता है। चाहे वह किसी संगठित हिंदुत्व समूह से संबंधित हो या नहीं, उसकी भाषा एक वैचारिक माहौल को दशार्ती है जो संस्थानों को ₹धार्मिक भावना₹ के अधीन करने की कोशिश करती है। जब आस्था हिंसा का औचित्य बन जाती है, तो असहमति जबरदस्ती में बदल जाती है। जिस क्षण विचारधारा संवाद के बजाय समर्पण की माँग करती है, लोकतंत्र का पतन शुरू हो जाता है। विरोध करने के अधिकार में धमकाने का अधिकार शामिल नहीं है।

इस तरह की हरकतें असहमति को भीड़ के न्याय में बदलने का खतरा पैदा करती हैं - एक ऐसा रास्ता जो न केवल न्यायाधीशों को, बल्कि हर नागरिक के निष्पक्ष निर्णय के अधिकार को खतरे में डालता है। इसलिए प्रतिक्रिया दृढ़ और स्पष्ट होनी चाहिए। अवमानना, आपराधिक हमले और पेशेवर कदाचार के लिए कानूनी कार्रवाई जरूरी है। साथ ही, न्यायपालिका और बार को जनता की पहुँच को बाधित किए बिना अदालत कक्ष की सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। नागरिक समाज और राजनीतिक नेताओं को यह बात दोहरानी होगी कि हिंसा, चाहे वह आस्था के आवरण में ही क्यों न हो, सहिष्णुता और वाद-विवाद के भारतीय लोकाचार के साथ असंगत है।

तीव्र होता वैश्विक जलवायु संकट

चूंकि कमजोर राष्ट्रों को अस्तित्व संबंधी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, बेलेम में होने वाला आगामी संयुक्त राष्ट्र सीओपी 30 शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना कर रहा हैः क्या वैश्विक नेता अंततः जलवायु चुनौती का सामना कर पाएंगे, या अपर्याप्त प्रतिबद्धताएं मानवता को खतरे में डालती रहेंगी?

बीके सिंह
लेखक, कर्नाटक फॉरेस्ट फोर्स के पूर्व प्रमुख हैं।

हाल के महीनों में, देशों में भीषण गर्मी, जंगल की आग, सूखे और भारी बारिश से लेकर भूस्खलन और बाढ़ जैसी लगातार और विनाशकारी जलवायु घटनाओं ने जीवन और आजीविका को अस्त-व्यस्त कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हर जगह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर में गिरावट आई है। विश्व के नेताओं ने आयात पर ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के खिलाफ कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन पर्यावरण पर उनके हमले के खिलाफ कोई भी उचित कदम नहीं उठा पाया है। शीर्ष अर्थशास्त्री कैथरीन एल क्लिंग, स्टीफन पोलास्की और कैथलीन सेगरसन ने दुनिया भर के अपने साथियों से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से जनता को शिक्षित करके पर्यावरण कानूनों पर ट्रम्प के लगातार हमले का विरोध करने का आह्वान किया है। पर्यावरणीय आपदाएं आर्थिक दक्षता को कम करने की ओर अग्रसर हैं और अमेरिकियों सहित सभी लोगों के लिए खतरा हैं। ट्रम्प द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम हैं - पेरिस जलवायु समझौते से हटना, संघीय नीति में किसी भी विचार से जन कल्याण पर जलवायु परिवर्तन के सुस्थापित प्रभावों को हटाना, पर्यावरण और जलवायु पर अनुसंधान निधि को समाप्त करना, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को प्राथमिकता देने वाला कार्यकारी आदेश ₹ड्रिल बेबी ड्रिल₹, और पीने के पानी में सीसा और अन्य रसायनों की उपस्थिति से निपटने वाले निवेश और नियमों को कम करना।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में 24 सितंबर को दिए गए उनके भाषण, जलवायु परिवर्तन अब तक का सबसे बड़ा धोखा है, नवीकरणीय ऊर्जा एक मजाक है, ये काम नहीं करतीं, श्रोताओं में मौजूद कई विश्व नेताओं के विचारों से मेल नहीं खाता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ट्रंप की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, द्वीपीय राष्ट्र पलाऊ की राजदूत इलाना सीड ने कहा कि उन्हें ट्रंप से इससे बेहतर की उम्मीद नहीं थी और चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई न करना ₹सबसे कमजोर लोगों के साथ विश्वासघात होगा₹।

ट्रंप ने अपने संबोधन में कोयले को 'स्वच्छ' बताया, कोयला शब्द का कभी इस्तेमाल न करें, और केवल 'स्वच्छ, सुंदर कोयला' शब्दों का ही प्रयोग करें। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, है ना? उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को 'बुरे इरादों वाले लोगों द्वारा गढ़ा गया एक धोखा' भी कहा। इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, टेक्सास ए एंड एम विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक एंड्रयू डेसलर ने कहा कि यह शब्द तेल कंपनियों द्वारा गढ़ा गया था और हो सकता है कि इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने की ज़िम्मेदारी निगमों से हटाकर व्यक्तियों पर डालने के लिए डिजाइन किया गया हो। ट्रम्प के व्हाइट हाउस में दोबारा आने के बाद, रोडियम समूह के पूवार्नुमान से पता चलता है कि अमेरिका में उत्सर्जन में कटौती पिछले दो दशकों में हासिल की गई दर से आधी रह गई है और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने का अनुमान है।

ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक चीन ने हाल ही में जलवायु संकट पर चर्चा के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में उत्सर्जन में कटौती की अपनी भविष्य की योजना की भी घोषणा की है। देश ने 2035 तक उत्सर्जन में 7 से 10 प्रतिशत की कटौती करने की योजना बनाई है, जबकि कम से कम 30 प्रतिशत की कटौती संभव है, जो ग्रह के तापमान में वृद्धि को धीमा करने के लिए नितांत आवश्यक भी है। विशेषज्ञों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि ग्रह अपेक्षाकृत सुरक्षित तापमान सीमा के भीतर नहीं रह सकता, और जलवायु आपदाएँ और समुद्र के स्तर में वृद्धि मानवता के लिए खतरा बनी रहेगी।

हालांकि, शी जिनपिंग ने अमेरिका का परोक्ष रूप से उल्लेख करते हुए कहा, ₹कुछ देश जलवायु चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सही दिशा में ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। [देशों] को अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। विकासशील देशों के अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। चीन की विशाल शक्ति प्रदूषणकारी उद्योगों (सिलिकॉन वेफर्स, रेयर अर्थ्स आदि) को अपनाने की उसकी इच्छाशक्ति से आई है, जो आधुनिक उद्योग और अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, मिसाइल, रक्षा उपकरण आदि सभी प्रदूषणकारी उद्योगों के उत्पादों पर निर्भर हैं। यदि इनमें से कुछ अपरिहार्य हैं, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से बचना होगा। यदि दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ अमेरिका और चीन स्वयं को कार्बन-मुक्त न करने में उनसे प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो वैश्विक दक्षिण और द्वीपीय राष्ट्रों जैसे कमजोर देशों के पृथ्वी के चेहरे से लुप्त होने का खतरा है।

ई3जी थिंक-टैंक में जलवायु कूटनीति और शासन की एसोसिएट डायरेक्टर केसी ब्राउन ने कहा, ₹चीन का 2035 का लक्ष्य जरूरत से बहुत कम है। यह न तो चीन के आर्थिक कार्बन-मुक्ति के लक्ष्य के अनुरूप है, न ही उसके अपने 2060 के कार्बन तटस्थता लक्ष्य के। निकट भविष्य में मजबूत महत्वाकांक्षा के बिना, चीन बहुपक्षवाद और स्वच्छ अर्थव्यवस्था में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के अपने दावे को कमजोर करने और वैश्विक बाजारों को मिले-जुले संकेत भेजने का जोखिम उठा रहा है।

चीन में कोयले की खपत साल दर साल बढ़ रही है। 2024 में देश की कोयले की खपत 4.2 अरब टन रही है और इस साल यह 4.5 अरब टन तक पहुँचने की राह पर है। चीन के कोयला क्षेत्र को शी जिनपिंग सरकार के भीतर मजबूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। 2021 में ग्लासगो कॉप 26 में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को 'चरणबद्ध तरीके से कम' करने के वादे के बावजूद, नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र अभी भी विकसित किए जा रहे हैं। बेशक, कॉप 26 के ₹चरणबद्ध तरीके से कम₹ प्रस्ताव को 2022 में शर्म अल शेख में कॉप 27 में ₹जीवाश्म ईंधन से दूर जाने₹ में संशोधित कर दिया गया।

यूरोपीय और मध्य पूर्व के देश युद्ध की स्थिति में हैं। यूक्रेन और रूस एक-दूसरे के ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को निशाना बना रहे हैं। रिफाइनरियों, तेल और गैस पाइपलाइनों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और कोयला आधारित संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है।

यदि तेल और गैस भंडार पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला होता है, तो यह आग की चपेट में आ जाता है और हानिकारक गैसें निकलती हैं जिससे वायुमंडल में उड2 की सांद्रता बढ़ जाती है। ईरान और रूस, दोनों को अपनी युद्ध मशीनरी तेल और गैस बेचकर चलानी पड़ती है और जब भंडार में आग लग जाती है, तो उन्हें माँग पूरी करने के लिए और अधिक खनन करना पड़ता है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था युद्ध पर आधारित है। सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा रक्षा निर्माण और जीवाश्म ईंधन की बिक्री से आता है। ये अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं और युद्ध जितने लंबे समय तक चलते हैं, पृथ्वी उतनी ही गर्म होती जाती है और लगातार विनाशकारी जलवायु आपदाएँ लाती है। क्या विश्व नेता पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए युद्धों को रोकने हेतु अपनी शक्ति लगा सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन, कॉप 30, नवंबर के मध्य में प्रशांत तट पर स्थित ब्राजील के शहर बेलेम में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बेलेम में की जाने वाली प्रतिबद्धताएँ, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने के लिए आवश्यक उत्सर्जन कटौती से कम होंगी, जो दस साल पहले 2015 में पेरिस में की गई थी।

कॉप के सामने यह दिखाने का काम होगा कि पेरिस समझौते को पूरा करने के लिए इन अपर्याप्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, बाकू में उडढ 29 विफल रहा, क्योंकि विकसित देशों ने वैश्विक दक्षिण में अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं जताई। क्या इस बार नेता ज्यादा विचारशील हो सकते हैं?

राजस्थान में जहरीली लापरवाही

डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड युक्त जहरीली कफ सिरप, केसन फार्मा द्वारा निर्मित की गई थी, जो पहले 40 से ज्यादा गुणवत्ता जांचों में विफल होने के कारण काली सूची में डाली जा चुकी है।

ब्रजेंद्र सिंह
लेखक, लोकसभा सांसद हैं।

इलाज के लिए बनाई गई दवा मौत का कारण बन जाए, तो यह कोई दुखद दुर्घटना नहीं है; यह शासन और नियमन में व्यवस्थागत सड़न का प्रमाण है। यह घोर भ्रष्टाचार भी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दूषित कफ सिरप पीने से राजस्थान में हाल ही में हुई तीन बच्चों की मौत ने हमारे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह कोई नियति नहीं थी। इसे रोका जा सकता था। और इसकी ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जिन्हें दवा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी।

डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड युक्त जहरीली कफ सिरप, केसन फार्मा द्वारा निर्मित की गई थी, जो पहले 40 से ज्यादा गुणवत्ता जांचों में विफल होने के कारण काली सूची में डाली जा चुकी है। इस कंपनी का घटिया दवाएँ बनाने का एक पुराना इतिहास रहा है। हैरानी की बात यह है कि इसे राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम (आरएमएससी) द्वारा एक नया सरकारी टेंडर दिया गया, जबकि यह वही एजेंसी है जिसे केवल सत्यापित, गुणवत्ता-सुनिश्चित दवाएँ खरीदकर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है।

इससे एक गंभीर और अपरिहार्य प्रश्न उठता हैः हमारी नियामक एजेंसियाँ क्या कर रही थीं? आरएमएससी अधिकारियों, राज्य औषधि नियंत्रण संगठन और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की सतर्कता कहाँ थी? इतने दागदार रिकॉर्ड वाली कंपनी को हमारे बच्चों के लिए दवाइयाँ आपूर्ति करने का काम कैसे सौंपा जा सकता है?

तथ्य चौंकाने वाले हैं। बच्चों की पहली मौत सितंबर की शुरूआत में बयाना और सीकर ज़िलों से हुई थी। वितरण तुरंत रोकने के बजाय, सरकार की प्रतिक्रिया एक कनिष्ठ अधिकारी को निलंबित करने और एक नियमित जाँच समिति गठित करने की थी। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जहरीला सिरप उपलब्ध रहा। सरकार की प्रतिक्रिया के लिए सिरप पीने वाले एक डॉक्टर की

सार्वजनिक रूप से बेहोशी की हालत ₹इसकी सुरक्षा साबित करने₹ के बाद आई, लेकिन तब तक भरतपुर का एक दो साल का तीसरा बच्चा मर चुका था।

यह केवल कुप्रबंधन नहीं है; यह आपराधिक लापरवाही है। सीडीएससीओ और राज्य प्राधिकरण जून 2023, अगस्त 2024 और अप्रैल 2025 में डेक्सट्रोमेथॉर्फन फॉर्मूलेशन और उनके जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हुए तीन परामर्श जारी कर चुके थे। फिर भी, उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। खरीद प्रक्रिया ही समझौतापूर्ण प्रतीत होती है। जब निविदाएँ काली सूची में डाली गई फर्मों को दी जाती हैं, जब घटिया दवाएँ बिना जाँच के सार्वजनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पहुँच जाती हैं, और जब गुणवत्ता परीक्षण तंत्र विफल हो जाते हैं या उनकी अनदेखी की जाती है, तो यह केवल एक चूक नहीं है; यह शासन की विफलता का एक पैटर्न है।

राजस्थान में हुई मौतें अकेली नहीं हैं। ये मौतें एक परेशान करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न का अनुसरण करती हैं, मध्य प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर, गाम्बिया और उज्बेकिस्तान तक, जहाँ डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) जैसे घातक संदूषकों वाले जहरीले सिरप ने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली है, 20 बच्चों की मौत से लेकर, जहाँ इन त्रासदियों से सीखने के बजाय, नियामक जड़ता जारी है।

हम जो देख रहे हैं वह जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। आरएमएससी, राज्य औषधि नियामक और खरीद एजेंसियां न केवल अपने कर्तव्य में विफल रही हैं; बल्कि उन्होंने इस मूल सिद्धांत का भी उल्लंघन किया है कि जन स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य जीवन की रक्षा करना है, न कि उन्हें खतरे में डालना।

इस मामले में निम्न की आवश्यकता हैः एक कार्यरत या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में एक न्यायिक जाँच आयोग। राज्य योजनाओं के तहत दवा खरीद प्रक्रियाओं का पूर्ण फोरेंसिक ऑडिट। खरीद, परीक्षण और नियामक स्तर पर हर उस अधिकारी की पहचान और अभियोजन जिसने इस जहर को सार्वजनिक आपूर्ति लाइनों में प्रवेश करने दिया।

राजस्थान के बच्चों को दवा की आड़ में मौत के घाट उतार दिया गया। उनके माता-पिता को न केवल बेईमान निमार्ताओं ने, बल्कि उन्हीं संस्थानों ने भी धोखा दिया, जिनका काम उनकी रक्षा करना था। जब तक पूरी जवाबदेही नहीं होगी, न्याय अधूरा रहेगा और राजस्थान के लोगों की सुरक्षा खतरे में रहेगी।

राजस्थान से एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, मैं आगामी संसद सत्र में इस मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाऊँगा। देश को यह सुनना होगा कि कैसे लापरवाही, भ्रष्टाचार और आत्मसंतुष्टि ने हमारे बच्चों की जान ले ली, और क्यों ज़िम्मेदार लोग अब फाइलों और समितियों के पीछे छिप नहीं सकते। खोई हुई जानें हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में जवाबदेही के लिए निर्णायक मोड़ बननी चाहिए।

आप की बात

नकली दवा निर्माताओं पर हो कार्रवाई

नकली कफ सिरप कोलड्रिफ पीने से बीस बच्चों की मौत हो गई। सबसे अधिक मौतें मध्यप्रदेश में हुई। इन बच्चों के माता-पिता को नहीं पता था कि वे अपने बच्चों को अपने ही हाथों से दवा के स्थान पर विष पिला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाएं देश में पहली बार हुई है, ऐसा पहले भी होता रहा है। इस जघन्य अपराध की दोषी केवल दवा कम्पनियां ही नहीं हैं। ड्रग कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग, सम्बन्धित चिकित्सक व मैडिसन विक्रेता भी दोषी हैं। लेकिन ड्रग कंट्रोलर का दोष सर्वाधिक इसलिए है कि उनका काम ही यह है कि वे कम्पनी से बाहर आने वाली हर औषधि का परीक्षण करके ही उसे बाजार में उतरने दें। किन्तु चन्द पैसों के लालच में वो अमूल्य मानव जीवन से खिलवाड़ कर बैठते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मन्त्रियों को भी दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता। यदि वे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें तो दवा कम्पनियां नकली दवा बनाने का दुःसाहस नहीं कर सकती। कफ सिरप के अलावा बाजार नकली दवाओं से पटा पड़ा है। बात केवल नकली दवाओं की नहीं है, मूल्यों की भी है। कम्पनियां मनमाने ढंग से दवाओं के मूल्य उन पर मुद्रित करती हैं। जिसका एक बहुत बड़ा भाग चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों को जाता है। जिससे एक गरीब के लिए इलाज करवाना दूर की कोड़ी हो जाता है।

- **डॉ नरेन्द्र टोंक**, मेरठ

सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी

भारत अब तक दुनिया से 600 से अधिक सांस्कृतिक धरोहरें वापस ला चुका है, जिनमें 559 केवल अमेरिका से मिली हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुआ है। देश में लगभग एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं, जो ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, वस्त्र और चर्मपत्र जैसे विविध माध्यमों पर सुरक्षित हैं। ये ग्रंथ न केवल ज्ञान के स्रोत हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा हैं। दुर्भाग्यवश, विदेशी आक्रांताओं और औपनिवेशिक इतिहासकारों ने इस ज्ञान को नष्ट या विकृत किया, जबकि स्वतंत्रता के बाद भी इनके संरक्षण को वह प्राथमिकता नहीं मिली, जिसकी यह पात्र थीं। औपनिवेशिक इतिहासलेखन ने भारतीय चिंतन, दर्शन और जीवनदृष्टि को हाशिये पर डाल दिया। लेकिन अब भारतीय समाज अपने इतिहास को नई दृष्टि से देख रहा है। पुरातात्विक खोजों, पांडुलिपियों और वैज्ञानिक शोधों के आधार पर भारतीय इतिहास के अनेक नए आयाम सामने आ रहे हैं। आधुनिक इतिहासकार अब भारत की लोक चेतना, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टि और प्रकृति-सामंजस्यपूर्ण जीवनदर्शन को केंद्र में रखकर इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस दिशा में नई ऊर्जा दी है। अब विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोधपीठें स्थापित हो रही हैं।

- **विभुक्ति बुपक्या**, विधि छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय

हथियार खरीद रहा पाकिस्तान

भारी आर्थिक बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान को अपने हालात में सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक बार फिर एक अरब डालर की मदद दी है , परंतु पाकिस्तान उस राशी से हथियारों की खरीदारी में जूट गया है कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हाल हि में पाकिस्तान को2.5 अरब डॉलर मूल्य के एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अतः कह सकते हैं कि इसके साथ ही भारत की इस आशंका को बल मिला है कि जब भी पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पेकेज दिया जाता है तो वह इसका इस्तेमाल हथियार खरीदने में करता है जबकि आईएमएफ की शर्तों की बात करें तो पाकिस्तान सीधे-तौर पर उससे मिली आर्थिक मदद से रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकता लेकिन पुराने रिकार्ड कुछ और ही संकेत देते हैं, कारण रिसर्च डाटा तो यही बताता है कि वर्ष 1980-2023 के बीच जब भी पाकिस्तान को आईएमएफ से आर्थिक मदद दी गई है तब उसका हथियार आयात 20% तक बढ गया है,अतः कह सकते हैं कि जब जब बदहाली दूर करने के नाम पर आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद की है उसने इस मदद की राशी का हथियार खरीद में ही अवश्य किया है। यही कारण है कि इतनी बार सहायता मिलने के बाद भी पाकिस्तान आज भी कंगाल का कंगाल हि बना हुआ है एवं उसके देश के नागरिक आज भी भीख मांग कर हि अपना गुजार बसर कर रहे हैं।

- **मनमोहन राजावतराज**, शाजापुर

मायावती की महारैली

बहुजन समाज के शिल्पकार मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित श्रद्धांजलि सभा ऐतिहासिक, विराट एवं बेहद सफल रही जिसके माध्यम से काशीराम के लाखों अनुयायियों में जोश पैदा करने का कार्य भी किया है। काशीराम स्मारक स्थल में आयोजित भीड़ इस कदर थी कि जितने संख्या में लोग स्मारक के अंदर थे इतनी संख्या में लाखों लोग लखनऊ के अंदर और स्मारक के बाहर कांशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए हुए थे। इस अवसर पर लखनऊ पूरी तरह नीला हो चुका था। मेरा मानना है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण बहुजन समाज पार्टी के लिए नई संजीवनी लेकर आया है जिसने 2027 में उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की सरकार बनाने के सपने को जगा दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, बीजेपी और सपा को आड़े हाथों लिया और दलित विरोधी करार दिया है। लंबे अरसे के बाद हुई इस महारैली के राजनीतिक मायने हैं।

- **वीके जाटव**, नई दिल्ली

पाठकगण अपने विचार **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
चिंतन की पतवार ही जीवन की नैया को आगे बढ़ाती है

गाजा में शांति की आस

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे बढ़ाए गए गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लागू करने के लिए सहमति बन जाना इजरायल और फलस्तीन के लिए ही नहीं, पश्चिम एशिया और शेष विश्व के लिए भी राहत की खबर है। यदि इस समझौते के शेष चरणों के लिए भी इजरायल और हमास में सहमति बन जाती है तो गाजा में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशंसा के पात्र होंगे। उनके खाते में कम से कम एक संघर्ष तो खत्म करने का श्रेय जाएगा ही। ऐसा होने की उम्मीद में ही भारतीय प्रधानमंत्री समेत विश्व के अन्य देशों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि इन देशों में सऊदी अरब, मिस्र समेत वह कतर भी है, जो हमास को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। गाजा शांति समझौते के पहले चरण के तहत हमास करीब 20 बंधकों के साथ मारे गए अपहृत लोगों के शव इजरायल को सौंपेगा। इसके बदले इजरायल लगभग दो हजार फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें कई हमास आतंकी भी हैं। इसी के साथ गाजा में घुसी इजरायली सेना अपने कदम पीछे खींचेगी।

ट्रंप की ओर से तय किया गया शांति समझौता 20 सूत्रीय है। इसके अनुसार हमास को हथियार डालने होंगे और गाजा में अपने प्रशासनिक दखल को समाप्त करना होगा। इस पर फिलहाल कुछ कहना कठिन है कि क्या हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार होगा। यदि वह इस्लामी और विशेष रूप से अरब देशों के दबाव में अपने हथियारबंद समूह को भंग करने के लिए तैयार भी हो जाए तो भी इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह इजरायल को नष्ट करने और वहां के लोगों यानी यहूदियों को मिटाने की अपनी घृणा का परित्याग करेगा। वास्तव में जब ऐसा होगा, तभी इजरायली और फलस्तीनी चैन से रह पाएंगे और पश्चिम एशिया में शांति कायम हो सकेगी। भविष्य में जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि दो वर्ष पहले 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने इजरायल में घुसकर जो कहर ढाया और जिसके नतीजे में 12 सौ लोग मारे गए, उसके जवाब में इजरायल की सैन्य कार्रवाई में साठ हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। इजरायल की सैन्य कार्रवाई गाजा के साथ लेबनान, यमन और ईरान तक गई। इजरायल ने गाजा में अपनी कठोर सैन्य कार्रवाई इसलिए जारी रखी, क्योंकि हमास 7 अक्टूबर के हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इजरायल हमास के बीच की लड़ाई में हजारों लोगों की जान ही नहीं गई, इजरायल-ईरान के बीच के तनाव ने युद्ध का रूप लिया, जिसमें अमेरिका ने भी दखल दिया। इसके अतिरिक्त यमन में काबिज हाऊती विद्रोहियों की हरकतों से समुद्री व्यापार में बाधा पहुंची, जिसके नतीजे में तेल के दाम चढ़े।

आयोग की कार्यप्रणाली

उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय समूह-ग की परीक्षा के दौरान एक केंद्र से प्रश्न पत्र के कुछ अंश बाहर आने के बाद से प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता का विषय चर्चा के केंद्र में है। यद्यपि, अभी तक पेपर लीक की बात साबित नहीं हुई है। प्रकरण एक व्यक्ति तक ही सीमित दिख रहा है और मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एसआइटी इस प्रकरण की जांच में जुटी है। एकल सदस्यीय जांच आयोग भी जनसुनवाई कर रहा है। हाल में देहरादून में हुई जनसुनवाई में जो बातें निकलकर आईं, वह चौंकाने वाली हैं। इसमें आयोग की कार्यप्रणाली में झोल ही झोल दिखते हैं। ऐसे में आयोग की ओर से अब तक कराई गई प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी यक्ष प्रश्न खड़े हो गए हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के संपन्न होने के बाद वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली आंसर शीट में आयोग सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया है। यही नहीं, कुछ प्रश्नों के दो-दो उत्तर सही ठहराए गए हैं। ऐसी एक नहीं कई खामियां जनसुनवाई के दौरान सामने आईं। यह परिदृश्य बताता है कि आयोग अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए व्यवस्थित स्वरूप और मानक तय नहीं कर पाया है। इसके साथ ही परीक्षाओं के लिए ठोस पैटर्न भी नहीं बन पाया है। इसे देखते हुए आयोग को अब गहन मंथन कर परीक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करना होगा। ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बनानी होगी, जिस पर भविष्य में किसी प्रकार के प्रश्न खड़े न होने पाएं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता के दृष्टिगत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अपनी कार्यशैली में सुधार लाना होगा

दवाओं की गुणवत्ता से समझौता

आदित्य सिन्हा

कफ सीरप से मौतें यह कड़वा सच बताती हैं कि देश में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा

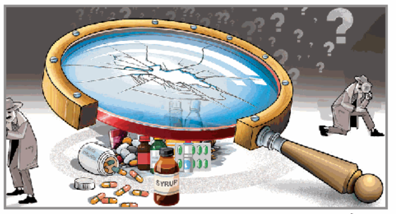

अवधेश राजपूत

तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर के बाहरी इलाके में एक छोटे दवा कारखाने के दरवाजे अब बंद हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स नाम की इस कंपनी को लेकर तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पाया कि उसने ड्रग्स और कास्मेटिक्स अधिनियम के तहत 364 उल्लंघन किए। यहां बना कफ सीरप कोल्ड्रिफ मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 बच्चों की जिंदगी लील गया। इस सीरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल जैसा विषैला तत्व मिला। यह किडनी और लिवर को क्षति पहुंचाता है। निर्माण के अलावा कंपनी के स्तर पर और भी लापरवाही बरती गई। जैसे पैकिंग पर अनिवार्य चेतावनी नहीं दी गई कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न करने दिया जाए। यह कोई पहली और अलग घटना नहीं है। गांबिया और उज्बेकिस्तान से लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा तक एक ही कहानी सामने आती है। इस कहानी में छोटे स्तर पर उत्पादन करने वाले नियमों को धता बताते हैं, निगरानी कमजोर और मामला बिगड़ने पर प्रतिक्रिया धीमी होती है। यह मामला दर्शाता है कि भारत की विकेंद्रीकृत और अक्षम दवा नियामक प्रणाली खतरनाक रूप से पुरानी पड़ चुकी है। ऐसे मामले 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में पहचान बनाने वाले भारत की प्रतिष्ठा भी धूमिल करते हैं। करीब 200 से अधिक देशों को किफायती दवाएं उपलब्ध कराकर भारत वैश्विक जेनेरिक दवा बाजार का अग्रणी खिलाड़ी है। पीएम जन औषधि योजना की सफलता में जेनेरिक दवाओं की अहम भूमिका है। इसके तहत 5,600 करोड़ रुपये की दवाएं बेची गई हैं। पिछले एक दशक के दौरान इस योजना से लोगों को करीब 30,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। जेनेरिक दवाएं बड़ी आवश्यकता हैं। हालांकि गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना ऐसी किफायती दवाएं और घातक हो सकती हैं, क्योंकि जिस तबके को राहत देने के लिए ये दवाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए ही आफत बन जाती हैं। कफ सीरप से बच्चों की मौतें इस कड़वी सच्चाई को ही उजागर करती हैं कि भारत में सस्ती दवाएं तो उपलब्ध हुई हैं, पर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा।

अक्सर यह सवाल उठता है कि जब जेनेरिक दवाओं में ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं जैसे तत्व ही होते हैं तो कई बार वे अनुपयोगी क्यों साबित हो जाती हैं? इसका जवाब दवा निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ा है। दवा में मूलभूत तत्व या एपीआइ उसका केवल एक हिस्सा होता है। बाकी फार्मूलेशन में फिलर्स, बाइंडर्स और कोटिंग जैसे पहलू भी होते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि दवा कितनी जल्दी घुलती है और शरीर उनकी कितनी मात्रा अवशोषित करता है। इन पहलुओं में थोड़ा सा भी परिवर्तन दवा की प्रकृति एवं प्रभाव पर असर डाल सकता है। चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डाक्टरों ने 2024 के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया। एंटीफंगल दवा इट्राकोनाजोल के 22 जेनेरिक संस्करणों की तुलना में उन्होंने पाया कि केवल 29 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं ने दो सप्ताह में अपेक्षित स्तर हासिल किया, जबकि पेटेंट दवाओं में यह स्तर 73 प्रतिशत तक था। जेनेरिक दवाओं में छोटे-असमान आकार के पेलेट मिले, जो अवशोषण और प्रभावशीलता को प्रभावित करते थे। ये ऐसा अंतर नहीं, जो जानबूझकर छोड़ा जाए, बल्कि यह इसी को रेखांकित करता है कि असमान निर्माण मानक और कमजोर निगरानी परिणामों को कैसे प्रभावित करती है।

इस मोर्चे पर समस्या गहरी है। दवा निर्माण के लिए भारत का केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ ही नियम निर्धारित करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देना, इकाइयों का निरीक्षण करना, नमूनों के परीक्षण जैसी अधिकांश शक्तियां राज्य औषधि नियामक प्राधिकरणों यानी एसडीआरए के पास हैं। निगरानी को लेकर विभिन्न राज्यों की क्षमताएं भी भिन्न हैं। कुछ के पास सुदृढ़ प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षित निरीक्षक हैं, जबकि कई राज्यों में अत्यंत सीमित मानव संसाधन होता है। निर्माता इसी का फायदा उठाते हुए वहां उत्पादन को प्राथमिकता देते हैं, जहां नियामकीय ढांचा अपेक्षाकृत कमजोर होता है। यह नियामकीय तोड़ ही है। सीडीएससीओ ने 2018 में स्थिरता परीक्षण को अनिवार्य तो बनाया, पर कई राज्यों में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा ही नहीं है और यह नियम पुरानी दवाओं पर लागू भी नहीं होता। इससे भारत जैसी जलवायु वाले देश में एक बड़ा जोखिम पैदा होता है। भाटिया समिति (1954) से लेकर माशेलकर समिति (2003) ने यही सुझाया कि लाइसेंसिंग और गुणवत्ता नियंत्रण को एक राष्ट्रीय ढांचे के तहत लाया जाए, पर सुधारों की राह में राज्यों का रवैया अवरोध बना हुआ है।

श्रीसन मामला दिखाता है कि कैसे लापरवाहियों की अनदेखी होती है। यह 10 से भी कम कर्मियों के भरोसे चल रही थी। फिल्ट्रेशन सिस्टम और रिकाल तंत्र भी नहीं था। फिर भी उसे 2026 तक लाइसेंस हासिल था। पूर्ववर्ती कंपनी का सालों पहले वजूद खत्म होने के बावजूद सीमित निरीक्षण के जरिये उसने नया लाइसेंस हासिल कर लिया। नियम उल्लंघन का मामला तब तक सामने नहीं आया, जब तक कुछ नौनिहाल काल के गाल में नहीं समा गए।

भारत में कानूनों की कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें ढंग से लागू करने की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने की। भारत में सीडीएससीओ के तहत एक केंद्रीकृत लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली बनाई जाए, जो प्रत्येक उत्पाद, परीक्षण और रिकाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय डिजिटल ड्रग रजिस्ट्रार द्वारा संचालित हो। सभी नई-पुरानी दवाओं के लिए सालाना परीक्षण भी अनिवार्य करना होगा। ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे तत्वों की आपूर्ति शृंखलाओं का डिजिटल रिकार्ड बने और उन्हें कभी भी ट्रेस किया जा सके। राज्यों की शक्तियां उनके पास रहें, लेकिन मानकों के अनुपालन और सजा के प्रविधान पूरे देश में एकसमान हों। कफ सीरप सेवन से बच्चों की मौत को एक चेतावनी के रूप में लिया जाए। यदि सबक नहीं सीखे गए तो आगे और घातक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

सर क्रीक को लेकर सचेत रहना होगा

डा. कृपा नौटियाल

सर क्रीक सीमा को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा और घुसपैठ रोकने के लिए आवश्यक है

सर क्रीक क्षेत्र भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक बार फिर तनाव का केंद्र बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में सैन्य जमावड़े को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। यह एक 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है, जो गुजरात में कच्छ के रण को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सर क्रीक विवाद की जड़ें 1908 से जुड़ी हैं, जब कच्छ और सिंध के शासकों के बीच क्षेत्रीय विभाजन को लेकर असहमति उत्पन्न हुई। बांबे प्रेसीडेंसी द्वारा 1914 में एक प्रस्ताव के जरिये मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने एक अस्पष्टता पैदा कर दी। प्रस्ताव के एक खंड में सुझाव दिया गया कि सीमा क्रीक के बाहरी किनारे की ओर स्थित है, जबकि दूसरे में अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लेख किया गया, जिसके अलग निहितार्थ थे। यह मुद्दा 1965 के सशस्त्र संघर्ष के बाद फिर से उभरा, जब पाकिस्तान ने कच्छ के रण के आधे हिस्से पर दावा किया। 1968 में एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने रण के 90 प्रतिशत हिस्से पर भारत के दावे को बरकरार रखा, लेकिन सर क्रीक सीमा अनसुलझी रही। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीच से होकर गुजरती है, जबकि पाकिस्तान जोर देता है कि यह क्रीक के पूर्वी तट पर स्थित है। यह अंतर निर्धारित करता है कि समुद्री सीमा अरब सागर में कैसे फैली हुई है, जो संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और दोनों देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अरबों डालर के सामुद्रिक संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है।

साल 1989 से भारत और पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने के लिए ठोस प्रगति के बिना छह दौर की चर्चाएं कर चुके हैं। पाकिस्तान जोर देता है कि समुद्री सीमा के लिए आधार स्थापित करने के लिए पहले क्रीक में सीमा का सीमांकन किया जाना चाहिए, जो भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों को जोड़ता है। वहीं भारत ने परिसीमन, सीमांकन का प्रस्ताव रखा, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों और राजनीतिक अविश्वास ने कार्यान्वयन को रोक दिया है। यह भारत के अपने अन्य पड़ोसियों के साथ समुद्री सीमाओं के सफल समाधान के बिल्कुल विपरीत है।

सर क्रीक की सुरक्षा का अवलोकन करते रक्षा मंत्री। प्रेट्र

श्रीलंका के साथ 1974 और 1976 में द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मालदीव के साथ त्रिबिंदु से लेकर पाक स्ट्रेट, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में 200 समुद्री मील की सीमा तक फैली 288 किलोमीटर की समुद्री सीमा स्थापित की गई। बांग्लादेश के साथ दशकों की असफल बातचीत के बावजूद विवाद अंततः संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक कानूनों के तहत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के माध्यम से हल किया गया। 2014 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने बंगाल की खाड़ी में विवादित 25,602 वर्ग किलोमीटर में से 19,467 वर्ग किलोमीटर बांग्लादेश को प्रदान किया। भारत और बांग्लादेश ने इस बाध्यकारी निर्णय को स्वीकार किया और इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अवसर के रूप में उपयोग किया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तब समुद्री सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत या मध्यस्थता के माध्यम से संभव है।

सर क्रीक पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा शहर कराची इस विवादित सीमा से केवल 60 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां इसका प्राथमिक नौसैनिक अड्डा है। यहां भारतीय नौसैनिक उपस्थिति पाकिस्तान की व्यावसायिक जीवन रेखा और सैन्य बुनियादी ढांचे को खतरे में डालती है। भारत के लिए सर क्रीक को सुरक्षित करना गुजरात की तटरेखा की रक्षा के लिए आवश्यक है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कांडला बंदरगाह और क्षेत्र को घुसपैठ गलियारा बनने से रोकने के लिए भी यह जरूरी है। सर क्रीक पर उठे विवाद को नए सिरे से 2019 के बाद के सैन्य गतिरोध और आपरेशन सिंदूर के व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण जैसे कि स्वदेशी विमानवाहक पोत, उन्नत पनडुब्बियां और बढ़ी हुई तटीय निगरानी ने समुद्री शक्ति संतुलन को मूल रूप से बदल दिया है। पाकिस्तान इसके जरिये नौसैनिक रणनीति को तेज करना चाहता है। वह उन्नत पनडुब्बियां और जहाज-रोधी मिसाइलें प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य सहायता का लाभ उठाना चाहता है। सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की कोई भी दुस्साहसिक कार्रवाई उसे पीढ़ियों तक पछताने पर मजबूर कर सकती है।

सर क्रीक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ नियमित गश्त भारतीय तटरक्षक बल और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा संचालित की जाती है। ये गश्त एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इससे दोनों देश विवादित जल पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और दोनों देशों से मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को अनजाने में पार करने से रोकते हैं। फिलहाल यह भारत की समुद्री सुरक्षा नीति का अहम हिस्सा बना हुआ है। सर क्रीक पर भारत की सीमाओं की दृढ़ता यह संदेश देती है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और हर इंच भूमि की सुरक्षा के लिए भारत प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान यदि नए सिरे से राजनयिक पहल करे, आतंकवादियों को समर्थन बंद कर दे और अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी दिखाए तो सर क्रीक विवाद का समाधान निकल सकता है।

(लेखक भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक रहे हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

विचार और स्वास्थ्य

तन एवं मन का गहरा संबंध है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। शरीर की स्थितियां बदलती हैं तो मन प्रभावित होता है और जब मन की भावनाएं असंतुलित होती हैं तो शरीर पर उसका सीधा असर दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण संभव है। केवल शरीर को बलिष्ठ और निरोगी बना लेने से स्वास्थ्य की पूर्णता नहीं मिलती, जब तक मन में शांति, स्थिरता और प्रसन्नता का संचार न हो।

चिकित्सा विज्ञान भी यह स्वीकारता है कि नकारात्मक विचार, चिंता, भय और तनाव शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देते हैं। अनेक रोग केवल असंतुलित और अशांत मन की देन हैं। जिन व्यक्तियों का मन संतुलित रहता है, उनके जीवन में रोगों की आशंका कम होती है। प्रसन्नता को श्रेष्ठ रसायन कहा गया है, क्योंकि यह न केवल मन को हल्का करती है, बल्कि शरीर के प्रत्येक अंग में जीवनशक्ति का संचार करती है। जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही प्रसन्नता का प्रकाश जीवन की उदासी, भय और चिंता को मिटा देता है।

जीवन को चिंता एवं भय से मुक्त करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। चिंता एक ऐसा विष है, जो धीरे-धीरे शरीर को खोखला कर देता है। भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है और उसके आत्मविश्वास को छीन लेता है। जबकि निडर और निश्चिंत जीवन जीने वाला व्यक्ति परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। सकारात्मक सोच मनुष्य को आंतरिक शक्ति देते हैं। महापुरुषों ने हमेशा आनंद और प्रसन्नता को जीवन का आधार माना है। द्वेष, ईर्ष्या, चिंता और क्रोध शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। इसके विपरीत मैत्री, करुणा, शांति और प्रसन्नता जैसे विचार रोगों के निवारण में औषधि का काम करते हैं। वास्तव में विचारों का स्वास्थ्य पर जितना गहरा असर है, उतना किसी औषधि का भी नहीं।

ललित गर्ग

साइबर सुरक्षा बने हर घर की प्राथमिकता

सुनीता मिश्रा

आज डिजिटल दुनिया में जितनी तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है

हाल में बालीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुंबई में आयोजित 'साइबर सुरक्षा जागरूकता माह' के उद्घाटन समारोह में अपनी बेटी के साथ आनलाइन गेमिंग के दौरान हुई एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आनलाइन गेम खेलते वक्त उनकी 13 साल की बेटी से न्यूड तस्वीरें मांगी गईं। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों से सुरक्षित रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार से स्कूलों में साप्ताहिक साइबर पीरियड शुरू करने का आग्रह भी किया।

आज बच्चों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। उनके लिए आनलाइन गेम और इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स में अक्सर साइबर अपराध का खतरा होता है। ऐसे में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन को मिलकर बच्चों को सुरक्षित आनलाइन व्यवहार, पासवर्ड सुरक्षा और संदिग्ध संदेशों की पहचान सिखाने की जरूरत है। देश के हर स्कूल में इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे आनलाइन खतरों, अपराधियों से खुद को बचाने के तरीके सीख सकेंगे। अभिभावक भी बच्चों को घर पर क्या सावधानियां बरतें, इसके बारे में जागरूक करें। वे उन्हें बताएं कि इंटरनेट से फ्री के नाम पर कोई भी गेम डाउनलोड न करें। ईमेल, वाट्सएप पर आने वाले किसी भी लिंक के जरिए गेम डाउनलोड करने से बचें। इतना ही नहीं, गेम खेलते समय किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। उसे अपना नाम, घर का पता, उम्र, स्कूल, निजी तस्वीरें और कोई भी व्यक्तिगत जानकारी न दें। खासतौर पर बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी बिल्कुल शेयर न करें। मल्टीप्लेयर गेम्स में अनजान लोगों से चैटिंग न करें। अगर कोई प्लेयर डराए, धमकाए या फिर फोटो-वीडियो मांगे तो रिपोर्ट करें और उसे तुरंत ब्लाक करें। इसके अलावा आनलाइन गेमिंग के दौरान वाइस चैट या वेबकैम (एक डिजिटल वीडियो कैमरा) प्रयोग न करें। आनलाइन गेमिंग में अक्सर साइबर अपराधी ही प्लेयर बनकर गेम खेलते हैं।

भारत में 2022 में 10.29 लाख साइबर अपराध दर्ज किए गए, जो 2024 में बढ़कर 22.68 लाख तक हो गए। ऐसे में माता-पिता को बच्चों की आनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। अगर बच्चे को गेम खेलने की लत है तो उसे इसके नुकसान से अवगत कराएं। प्राइवेसी सेटिंग में कुछ चीजों का बदलाव करें, जिससे हर कोई आपको मैसेज नहीं भेज सकेगा। जब भी आपको महसूस हो कि चैटिंग में कोई अनुचित बात कर रहा है या गलत मैसेज भेज रहा है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें, ताकि ऐसे यूजर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। साइबर अपराध समाज के लिए खतरा है। इससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा हर घर की प्राथमिकता होनी चाहिए।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)

मेलबाक्स

तय हो जिम्मेदारी

'भरोसा डिगाने वाला रवैया' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़कर मन अत्यंत व्यथित हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विषाक्त कफ सीरप के सेवन से अब तक 25 से अधिक मासूम बच्चों की मौत होना न केवल दर्दनाक, बल्कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब नकली या जहरीली दवाइयों ने निर्दोष जानें ली हों और हर बार की तरह इस बार भी जांच और कार्रवाई का ढोल पीटा जा रहा है। दोष केवल उस दवा निर्माता कंपनी का नहीं है जिसने यह घातक सीरप बनाया, बल्कि उन अधिकारियों का भी है जिनकी निगरानी में यह सब हुआ। सरकारें इन अधिकारियों पर करोड़ों रुपये खर्च करती हैं, परंतु जब जिम्मेदारी की घड़ी आती है तो ये या तो मौन रहते हैं या लीपापोती में लग जाते हैं। बिना मिलीभगत के इतनी बड़ी लापरवाही संभव ही नहीं। समय आ गया है कि ऐसे मामलों में सख्त और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कार्रवाई की जाए। दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को दवा निर्माण, परीक्षण और वितरण प्रणाली को तकनीकी निगरानी से जोड़ना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई मासूम जान भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट न चढ़े। सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे वसूली का चलन समाप्त हो सके।

sureshgoyal8@gmail.com

योग्य उम्मीदवार उतारें दल

हमारी लोकसभा और विधानसभाओं का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक दल किस तरह के प्रत्याशियों का चयन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका पर आधारित होता है, क्योंकि मंत्री इन्हीं सदनों के सदस्य होते हैं। इस कारण चुनाव केवल प्रतिनिधियों का नहीं, बल्कि शासन की दिशा और नीति का भी चुनाव होता है। जब दल योग्य उम्मीदवार नहीं उतारते, तब मतदाता विकल्पहीन हो जाता है और कभी-कभी नोटा दबाने के लिए मजबूर होता है। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्थिति है। अच्छे उम्मीदवार का अर्थ केवल शिक्षित या संपन्न व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो समाज की समस्याओं को समझे, जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनसेवा की भावना रखे। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे टिकट वितरण में जाति, धनबल या बाहुबल के बजाय नैतिकता, ईमानदारी और जनसेवा को प्राथमिकता दें। साथ ही, मतदाताओं को भी अपने अधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। भावनाओं या प्रलोभनों से ऊपर उठकर उस उम्मीदवार को चुनना चाहिए। लोकतंत्र तभी सशक्त बनेगा जब दल योग्य उम्मीदवारों को आगे बढ़ाएं और जनता सजग होकर मतदान करे। आखिर लोकतंत्र केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम है।

mananmk8155@gmail.com

नकली दवाओं पर सख्त जरूरी

हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सीरफ से हुई बच्चों की मौतों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना ने दवा कंपनियों पर लोगों के भरोसे को हिला दिया है। एक कंपनी की लापरवाही ने पूरे उद्योग की साख को नुकसान पहुंचाया है। दोष केवल कंपनियों का नहीं है; समाज में भी गलत आदतें हैं। छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी जैसी सामान्य बीमारियों में भी एंटीबायोटिक देना आम बात हो गई है। यह प्रवृत्ति न केवल शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करती है, बल्कि जीवन के लिए खतरा भी बन सकती है। भारत में आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय सहज रूप से उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए, ताकि वे "अपना डाक्टर खुद" बनने की प्रवृत्ति छोड़ें और चिकित्सक की सलाह से ही दवा लें। साथ ही, नकली और घटिया दवाओं पर सख्त निगरानी रखी जाए। देश की सेहत की रक्षा तभी संभव है जब जनता जिम्मेदार बने और प्रशासन सतर्क। भरोसे की रक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों की जिम्मेदारी हम सबकी है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****